राष्ट्रीय संस्करण

वर्ष 3 अंक 81

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 30 अगस्त 2019

दैनिक जागरण

www.jagran.com

पृष्ठ 16

ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स क्रिकेट से बड़े : सहवाग >>14

सरोकार

कुल्हार को लाखों गैलन पानी का वरदान दे गई रेलवे लाइन

विदिशा : रेलवे को तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए मुरुम (बजरी) की जरूरत थी और ग्रामीणों को खेती के लिए पानी की। एक तरकीब ने दोनों की जरूरतों को पूरा कर दिया। यह सफल प्रयोग विदिशा, मप्र के छोटे से गांव कुल्हार में हुआ। (पेज-10)

जागरण विशेष

पैसों के पीछे भागते कोचिंग सेंटर्स को दिखा रहे आईना

जेएनएन : बिहार के भागलपुर और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से ऐसे दो शिक्षकों की कहानी, जो बिना कोई फीस लिए युवाओं का भविष्य गढ़ रहे हैं। इनके मार्गदर्शन में अनेक युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में बाजी मार कर बड़े अफसर बने हैं। यह सिलसिला सालों से चल रहा है। (पेज-10)

विश्वास.News

फलस्तीन की तस्वीर कश्मीर के नाम से वायरल ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज 10

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 4

हुड्डा की मुश्किलें बढ़ीं, ईडी ने अटैच किए 14 औद्योगिक प्लॉट

चंडीगढ़ : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंचकूला के औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में उन सभी 14 प्लॉटों को अटैच कर दिया है, जिन्हें हुड्डा ने अपने संबंधियों, जान पहचान के लोगों को आवंटित किया था।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 6

रूस से 21 मिग-29 और 12 सुखोई-30 खरीदने की योजना

नई दिल्ली : भारतीय वायु सेना 33 और नए लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रही है। इनमें 21 मिग-29 और 12 सुखोई-30 एमकेआइ विमान शामिल हैं। वायु सेना के इस प्रस्ताव पर अगले कुछ हफ्तों में रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में विचार किया जाएगा। विभिन्न दुर्घटनाओं के चलते वायु सेना के पास लड़ाकू विमानों की संख्या कम हुई है। इस कमी को दूर करने की तैयारी है।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

चीन ने हांगकांग में आंदोलन दबाने के लिए भेजी सेना

हांगकांग, रायटर : हांगकांग में पूर्ण लोकतंत्र की मांग को लेकर आंदोलनकारियों की 'लांग मार्च' की योजना के दृष्टिगत चीन ने सेना को सक्रिय कर दिया है। आठ से दस हजार सैनिकों को चीन से हांगकांग भेजा गया है, जो जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए बिना देरी के हरकत में आ जाएं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि सेना हांगकांग में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देगी और वहां की संपन्नता को बरकरार रखेगी।

सरकार चाहती है लेस-कैश, लेकिन 17 फीसद बढ़ गया नकदी का चलन

खूब बढ़े नकली नोट

आरबीआइ की रिपोर्ट से पता चलता है कि बैंकिंग तंत्र में पकड़े गए 500 रुपये और 2,000 रुपये के नकली नोटों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 में 500 रुपये के 21,865 नकली नोट पकड़े गए, जबकि 2017-18 में यह संख्या 9,892 थी। 2,000 रुपये के नकली नोट की संख्या भी लगभग 22 परसेंट बढ़ी है। वर्ष 2017-18 में 2,000 रुपये के 17,929 नकली नोट पकड़े गए थे जबकि 2018-19 में यह आंकड़ा बढ़कर 21,847 हो गया है।

500 के नोटों के चलन में बढ़त आ गई है, 2000 के नोटों के इस्तेमाल में आई कमी

2000 रुपये के नए नोट की छपाई में रिजर्व बैंक ने कर दी है भारी कटौती

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली

सरकार ने इकोनॉमी को लेस-कैश बनाने के इरादे से नोटबंदी की थी, लेकिन नकदी का चलन घटने के बजाय काफी बढ़ गया है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मार्च 2019 के अंत में चलन में बैंक नोटों का मूल्य बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है, जो नोटबंदी के ठीक बाद मार्च 2017 में 13 लाख करोड़ रुपये से कुछ ही ज्यादा था। इस तरह, महज दो वर्षों में चलन में आए बैंक नोटों का मूल्य 61 परसेंट बढ़ा है। करेंसी नोट को जल्द खराब होने से रोकने के लिए रिजर्व बैंक परीक्षण के तौर पर 100 रुपये के वार्निश्ड बैंक नोट शुरू करने जा रहा है।

रिजर्व बैंक ने बुधवार अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 जारी की, जिसमें चलन में करेंसी नोट का ब्योरा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 2018 के अंत में चलन में बैंक नोटों का कुल मूल्य 18.03 लाख करोड़ रुपये था जो 17.0 परसेंट बढ़कर मार्च, 2019 के अंत में 21.1 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

ज्ञात हो, मोदी सरकार ने आठ नवंबर, 2016 को नोटबंदी का फैसला करते हुए 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने और 500 रुपये तथा दो हजार रुपये के नए नोट जारी करने का फैसला किया था। सरकार ने यह फैसला अर्थव्यवस्था को लेस-कैश बनाने यानी रोजमर्रा की जरूरतों में नोटों का चलन कम करने के इरादे से किया था। नोटबंदी के तत्काल बाद इसमें कमी भी आई और चलन में बैंक नोट का मूल्य घटकर मार्च 2017 के अंत में 13.1 लाख करोड़ रुपये रह गया, लेकिन उसके बाद इसमें तेजी से वृद्धि हुई है। आरबीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च, 2019 के अंत में चलन में बैंक नोटों का जो मूल्य है उसमें 2,000 रुपये के नोट ही हिस्सेदारी घटकर 31.1 परसेंट रह गई है, जबकि मार्च 2018 के अंत में यह 37.3 परसेंट और मार्च 2017 के अंत में 50.2 परसेंट थी। वर्ष 2016-17 में रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये के 350 करोड़ (संख्या) नए नोट छपवाए थे। जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में यह आंकड़ा घटकर 15.1 करोड़ और 2018-19 में मात्र 4.7 करोड़ रह गया है। हालांकि 500 रुपये के नये नोट की छपाई बढ़ाई गई है। वर्ष 2016-17 में रिजर्व बैंक ने 500 रुपये के 726 करोड़ नए नोट छपवाए थे, जबकि 2017-18 में यह आंकड़ा बढ़कर 969 करोड़ और 2018-19 में 1,146 करोड़ पहुंच गया।

ढंग का पड़ोसी बने पाकिस्तान : भारत

नसीहत ▸ गैरजिम्मेदार बयानों से माहौल खराब करने की कोशिश बंद करे इमरान सरकार

रवीश कुमार बोले, पाक की चाल दुनिया समझ चुकी, भारत में हिंसा भड़काने की कर रहा कोशिश

नई दिल्ली, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से गैरजिम्मेदाराना व भड़काऊ बयान देने वाले पाकिस्तान को भारत ने ढंग का पड़ोसी बनने की नसीहत दी है। भारत ने उम्मीद जताई है कि वह भारत में हिंसा भड़काना, आतंकवाद फैलाना और घुसपैठ कराना बंद करके सामान्य पड़ोसी जैसा व्यवहार करेगा। भारत ने कहा कि उसने जो हालात दिखाने की कोशिश की है, वे जमीनी हकीकत से बहुत दूर हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पत्रकारों से कहा, 'हम भारत के अंदरूनी मामलों के बारे में पाक नेतृत्व के अति गैरजिम्मेदाराना बयानों की कड़ी भर्त्सना करते हैं। ऐसे भड़काऊ बयान आ रहे हैं जिसमें भारत में हिंसा को उकसाना और जिहाद का आह्वान करना शामिल है।' जम्मू-कश्मीर को लेकर पाक से आने वाले बयानों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से 40-50 बयान आ गए हैं। ये ऐसे बयान हैं जो बेहद गैरजिम्मेदाराना हैं। इनका मकसद क्षेत्र में गंभीर स्थिति का माहौल पेश करना है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार। फाइल

वे (पाकिस्तानी नेतृत्व) मामले को तूल देना चाहते हैं ताकि दुनिया को लगे कि कुछ हो रहा है, लेकिन वास्तव में स्थिति अलग है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। उनकी (पाकिस्तान) ओर से जो भी कहा जा रहा है, वह झूठ और मनगढ़ंत है। पाक को समझना चाहिए कि दुनिया उसके झूठ को छल को जान चुकी है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को सरकारी नीति के हिस्से के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हमने इस बारे में अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। हमें खबर मिली है कि पाक आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान आतंकवादियों पर ठोस कार्रवाई करे ताकि वे दोबारा घुसपैठ नहीं कर सकें। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना पाकिस्तान का दायित्व भी है। रवीश कुमार ने कहा, 'हम चाहते हैं कि पाक आतंकवादियों की घुसपैठ न कराए बल्कि सामान्य पड़ोसी की तरह व्यवहार करे। सामान्य पड़ोसी ऐसा व्यवहार नहीं करते जैसा कि पाकिस्तान कर रहा है।' उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता संपन्न सतह से सतह तक मार करने वाली 'गजनवी' मिसाइल के परीक्षण के बारे में भारत को स्थापित चलन के अनुरूप सूचित किया था।

जम्मू-कश्मीर की स्थिति का जिक्र करते हुए रवीश कुमार ने कहा कि अगर आप पांच अगस्त के बाद से अभी की स्थिति को देखें तो इसमें निरंतर सकारात्मक सुधार हुआ है। उस क्षेत्र की तुलना देश के अन्य हिस्सों से न करें। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल की ओर से राज्य में सरकारी विभागों में 50 हजार रिक्तियां भरने सहित सेब के उत्पादन के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव अक्टूबर में पूरा करने सहित अन्य घोषणाओं का जिक्र किया।

पाकिस्तान की ओर से एयर स्पेस बंद करने की खबर के संबंध में प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से इस बारे में आधिकारिक बयान नहीं आया है जिससे इसकी पुष्टि होती हो। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता एवं अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन का पक्षधर है।

भारत में मानवाधिकार से जुड़े विषयों के बारे में कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों की चिंता पर रवीश कुमार ने कहा कि भारत इन अपुष्ट बयानों को पूरी तरह खारिज करता है। ये तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा यूएनएचआरसी को लिखे पत्र को भारत महत्व नहीं देना चाहता।

आइबी का अलर्ट, समुद्र के रास्ते पाक कर सकता है नापाक हरकत पेज>>5

आज कश्मीरियों के प्रति एकजुटता का ढोंग करेगा पाकिस्तान

इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुरुवार को कहा कि उनका देश अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के एकपक्षीय फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा और कश्मीर भाइयों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करेगा। कश्मीर पर एक संसदीय समिति को संबोधित करते हुए कुरैशी ने कहा कि संसद की सलाह पर ये विरोध प्रदर्शन हर शुक्रवार को 12 बजे पूरे पाकिस्तान में किए जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री इमरान खान ने टीवी के जरिये राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी घोषणा की थी।

सोने ने 40 हजार का आसमान छुआ, चांदी 49 हजार के पार

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले कुछ सत्रों से 40,000 रुपये के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करने की सोने की कोशिश आखिरकार गुरुवार को रंग लाई। दिन के कारोबार में सोना पहली बार 40,220 रुपये प्रति 10 ग्राम की नई ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा। चांदी के भाव में भी गुरुवार को 200 रुपये का उछाल आया और वह 49,000 रुपये प्रति किलोग्राम से 50 रुपये ऊपर बंद हुई। इसी सप्ताह सोमवार को सोना एक बार 40 हजार के ऊपर गया था। लेकिन उस दिन बाजार बंद होते समय यह 39,670 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। नई दिल्ली में 99.9 फीसद खरा सोना 40,220 रुपये, जबकि 99.5 फीसद खरा सोना 40,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। आठ ग्राम सोने की गिन्नी का भाव भी 400 रुपये के उछाल के साथ 30,200 रुपये पर जा पहुंचा। चांदी के सिक्कों का भाव प्रति सैकड़ा 3,000 रुपये चढ़कर पहली बार 1.01 लाख रुपये खरीद और 1.02 लाख रुपये बिक्री के स्तर पर जा पहुंचा।

इसलिए आई तेजी

- आगामी त्योहारी सीजन से पहले कारोबारी जमकर खरीद रहे सोना
- न्यूयॉर्क समेत प्रमुख विदेशी बाजारों में सोने और चांदी के भाव में तेजी

पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश की टिप्पणी पर भर्त्सना के लिए बैठी 11 जजों की विशेष बेंच

- न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर टिप्पणी करने वाले जस्टिस राकेश कुमार को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से हटाया गया
- जस्टिस राकेश की टिप्पणी पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह न्यायपालिका के लिए सबसे अंधेरा दिन

राज्य ब्यूरो, पटना

पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश राकेश कुमार की न्यायपालिका के बारे में की गई टिप्पणी ने न्यायपालिका को हिलाकर रख दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश एपी शाही की अध्यक्षता में ग्यारह जजों की विशेष बेंच बैठी, जिसने गुरुवार को कहा कि भारतीय न्यायपालिका के लिए आज सबसे अंधेरा दिन है। बेहद दुखी मन से एक साथ 11 जजों को जस्टिस राकेश कुमार के फैसले की भर्त्सना करनी पड़ रही है।

बता दें कि बुधवार को जस्टिस राकेश कुमार ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था-'भ्रष्टाचारियों को न्यायपालिका से भी संरक्षण मिलता है।' जबसे न्यायाधीश पद की शपथ ली है, तब से देख रहा हूं कि सीनियर जज भी मुख्य न्यायाधीश के आगे पीछे घूमते हैं। ताकि उनसे 'फेवर' लिया जा सके।' उनकी इस टिप्पणी पर गुरुवार को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'ऐसा लगता है कि पूरे देश में वही सबसे ईमानदार जज हैं। संभव है कि वह व्यक्तिगत कारणों से क्षुब्ध हों, जिस कारण उन्होंने पूरी न्यायपालिका की गरिमा पर सवाल खड़ा कर दिया। यह बेहद आश्चर्यजनक बात है कि जो मुकदमा एक साल पहले निष्पादित कर दिया गया था, उसे क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उन्होंने अपनी अदालत में सूचीबद्ध करा लिया। वह ऐसा नहीं कर सकते थे।'

> अगर भ्रष्टाचार को उजागर करना अपराध है तो मैंने यह अपराध किया है। मैं अपनी बात पर कायम हूं। मैंने न्यायपालिका को बचाने के लिए जो भी किया है उसके लिए मुझे पछतावा नहीं है। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकता। अगर मुख्य न्यायाधीश को लगता है कि वह मुझे न्यायिक कार्य से अलग रख कर खुश हैं तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैंने किसी के प्रति दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्य नहीं किया है। – जस्टिस राकेश कुमार, पटना हाई कोर्ट

मुकदमे की सुनवाई से रोका गया राकेश कुमार को : इसके पूर्व बुधवार देर रात हाई कोर्ट प्रशासन ने नोटिस जारी कर जस्टिस कुमार केनाम को सिंगल जज के रूप में सूचीबद्ध मामलों पर सुनवाई करने से मना कर दिया। उन्हें डिवीजन बेंच में केस की सुनवाई करने को कहा गया था। गुरुवार को जस्टिस राकेश पूरे दिन चैंबर में बैठे रहे। मुख्य न्यायाधीश ने हाई कोर्ट रजिस्ट्री को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि किस क्षेत्राधिकार से निष्पादित मामले को एकल पीठ की सूची में लाया गया।

आदेश को किया निलंबित पेज>>6

रिश्वत नहीं मिली तो बिहार में नहर परियोजना के चीफ इंजीनियर ने ठेकेदार को जिंदा फूंका

- 60 लाख रुपये भुगतान के लिए 15 लाख घूस मांग रहा था इंजीनियर
- गोपालगंज जिले में गंडक नहर परियोजना के कार्यालय क्षेत्र में हुई वारदात

जागरण संवाददाता, गोपालगंज

रिश्वतखोरों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी बानगी गुरुवार को बिहार के गोपालगंज में देखने को मिली। यहां चीफ इंजीनियर (मुख्य अभियंता) ने ठेकेदार को सिर्फ इसलिए जला दिया कि उसे 15 लाख रुपये की रिश्वत नहीं मिली। और यह सब हुआ मुख्य अभियंता के आवास पर। ठेकेदार को जलाकर अभियंता अपने आवास पर ताला लगा फरार हो गया। उधर इलाज के दौरान ठेकेदार की गोरखपुर के अस्पताल में मौत हो गई। ठेकेदार के पुत्र राणा सिंह ने आरोप लगाया है कि 60 लाख रुपये के भुगतान के लिए मुख्य अभियंता 15 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा था। नहीं देने पर जला दिया गया। जिस मुख्य इंजीनियर ने ठेकेदार को जलाया है, वह गंडक नहर परियोजना से जुड़ा है। घटना को गोपालगंज में गंडक परियोजना के कैंपस में ही अंजाम दिया गया।

झुलस गए ठेकेदार की चीख सुनकर आवास के बाहर खड़े उनके करीबी लोगों ने उन्हें गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया।

चीफ इंजीनियर के सरकारी आवास पर जांच पड़ताल करने पहुंची पुलिस टीम। जागरण

गोरखपुर ले जाने के कुछ देर बाद इलाज के दौरान ठेकेदार की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मुख्य अभियंता के आवास के ड्राइंग रूम से एक खाली गैलन बरामद किया है। आशंका है कि इसी में करोसिन पदार्थ रखा गया था।

भुगतान के लिए चक्कर लगा रहा था ठेकेदार : परिजनों का कहना है कि भवन निर्माण के ठेकेदार रामाशंकर सिंह ने गंडक परियोजना परिसर में 2.25 करोड़ की लागत से एक भवन का निर्माण कराया है। इनका 60 लाख रुपया भुगतान बकाया था। भुगतान के लिए सिंह लंबे समय से गंडक परियोजना के मुख्य अभियंता मुरलीधर राम के कार्यालय तथा आवास का चक्कर लगा रहे थे। गुरुवार दोपहर ठेकेदार रामाशंकर सिंह अपने कुछ करीबी के साथ भुगतान कराने के सिलसिले में मुख्य अभियंता के आवास पर उनसे मिलने गए थे। भुगतान को लेकर ठेकेदार का मुख्य अभियंता के साथ बहस हो गई। इसके बाद ठेकेदार के शरीर पर केरोसिन डालकर आग लगा दी गई।

वाराणसी में भी ठेकेदार ने कर ली थी आत्महत्या : बुधवार को उप्र के वाराणसी में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। वहां कमीशनखोरी के कारण बिल भुगतान में हो रही देरी के चलते आर्थिक तंगी व मानसिक तनाव झेल रहे ठेकेदार अवधेश श्रीवास्तव ने बुधवार को लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर) के केबिन में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

'फिट इंडिया मूवमेंट'

राष्ट्रीय खेल दिवस पर मोदी ने लांच किया फिट इंडिया मूवमेंट, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज को नए भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का रास्ता बताया

पीएम के 'मन की बात', मैं फिट तो इंडिया फिट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

स्वच्छ भारत अभियान के जरिये जन-जन में स्वच्छता की अलख जगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब स्वस्थ भारत का बीड़ा उठाया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर मोदी ने 'फिट इंडिया मूवमेंट' की शुरुआत की। इंदिरा गांधी स्टेडियम में जुटे लोगों को फिटनेस के लिए प्रेरित करते समय मोदी में देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि जनता के अभिभावक की झलक दिख रही थी। उन्होंने देश के लोगों को अपना फिटनेस मंत्र देते हुए कहा, 'मैं फिट तो इंडिया फिट'।

मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को 'राष्ट्रीय खेल दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर मोदी ने कहा, 'आज का दिन युवा खिलाड़ियों को बधाई देने का दिन है जो दुनिया के मंच पर तिरंगे का परचम लहरा रहे हैं। बैडमिंटन हो, टेनिस, एथलेटिक्स या कुश्ती हो, भारतीय खिलाड़ियों का पदक उनकी तपस्या का परिणाम है, साथ ही इसमें नए भारत के नए जोश और नए आत्मविश्वास की झलक है।' इसके बाद फिटनेस की चर्चा करते हुए मोदी ने उन वास्तविकताओं को छुआ, जिनसे हर युवा का सामना होता है। साथ ही ऐसे उदाहरण भी सामने रखे जो बड़ी उम्र के लोगों के अनुभवों का हिस्सा रहे हैं। मोदी ने कहा कि हमें सिखाया जाता था कि स्वास्थ्य से ही सब प्राप्त होता है। अब कहा जाने लगा है कि स्वार्थ से ही सब मिलता है। इस स्वार्थभाव से स्वास्थ्यभाव तक की यात्रा पर बढ़ने की जरूरत है। फिटनेस को व्यक्तिगत के साथ-साथ परिवार और देश की सफलता का मानक बनाना होगा।

नई दिल्ली में गुरुवार को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत के मौके पर फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के अभिवादन का जवाब देते प्रधानमंत्री मोदी। प्रेट्र

हंसते-हंसाते सिखाए गुर : आधे घंटे के भाषण में लोग हंसते भी रहे और बहुत कुछ सीखते भी रहे। मोदी ने गुजरात के व्यंग्यकार ज्योतींद्र भाई दवे का किस्सा भी सुनाया। मोदी बोले, 'दवे जी बहुत पतले थे। उन्हें किसी ने व्यायाम की सलाह दी और कहा कि कम से कम पसीना आने तक जरूर व्यायाम करना। दवे जी जैसे ही व्यायामशाला में गए, वहां लोगों को कुश्ती लड़ता देख उन्हें पसीना आ गया और उन्होंने सोचा कि व्यायाम पूरा हुआ।' इस किस्से को सुनते ही सभागार हंसी से गूंज उठा। मोदी ने 'बॉडी फिट तो माइंड हिट', 'जीरो इनवेस्टमेंट, 100 परसेंट रिटर्न' जैसे वाक्यों का प्रयोग करते हुए कहा, हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को इसे जीवन का हिस्सा बनाने की जरूरत है। आज इस अभियान की जरूरत इसीलिए पड़ रही है, क्योंकि समाज तेजी से बदला है। कुछ दशक पहले व्यक्ति सामान्य स्थिति में भी दिन में आठ से 10 किमी तक पैदल चल लेता था। आज हाथ में गैजेट पहनकर लोगों को अपने कदम गिनने पड़ रहे हैं। कई देश अपने यहां लोगों को फिट रखने का लक्ष्य तय कर रहे हैं। भारत में भी इसे जन अभियान बनाना होगा।

कश्मीर में मस्जिदों से हुआ एलान- बाहरी को न दें मकान और दुकान

- गैर कश्मीरियों को निशाना बनाने की साजिश, अपना एजेंडा विफल होता देख आतंकी संगठनों का नया पैंतरा

नवीन नवाज, श्रीनगर

जिहादी और अलगाववादी एजेंडे को नाकाम होते देख हताश राष्ट्र विरोधी तत्वों ने अब वादी में गैर कश्मीरी नागरिकों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। कई जगह मस्जिदों में किसी बाहरी व्यक्ति को मकान-दुकान किराए पर न देने का फरमान जारी किया गया है। कुछ आतंकी भी मस्जिदों में यह फरमान सुनाने पहुंचे हैं। इन फतवों से प्रशासन के लिए नई चुनौती पैदा हो गई है। वहीं, वादी में बचे हुए गैर कश्मीरी भी सहमे हुए हैं।

आतंकियों ने दुष्प्रचार के लिए लगाए पोस्टर : 370 खत्म होने के बाद कई जगह बाहरी लोगों को कथित तौर धमकाने और मारपीट के मामले भी सामने आए। दुष्प्रचार किया जा रहा है कि बाहरी लोगों को बसाकर हमारी रिवायतों और मजहब को कमजोर करने की साजिश चल रही है। इसलिए कोई किसी बाहरी को मकान या दुकान किराये पर न दे, न ही किसी बाहरी को जमीन या मकान बेचेगा। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और पुलवामा में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने इस तरह के पोस्टर लगाकर जहर फैलाने की साजिश रची है।

एक अनुमान के अनुसार, 5 अगस्त से पूर्व घाटी में देश के अन्य भागों से आए करीब साढ़े पांच लाख लोग काम कर रहे थे। इनमें से अधिकांश हलवाई, नाई, पलंबर, राज मिस्त्री, ठेलों में सब्जियां और अन्य सामान बेचने का धंधा करते थे। राज्य के पुनर्गठन के फैसले से पूर्व प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इन लोगों को घाटी छोड़ने की नसीहत दी थी। इसके बाद अब वादी में बाहरी राज्यों के एक हजार से भी कम श्रमिक हैं। शेष केंद्रीय कर्मी, सुरक्षाबल या फिर विभिन्न संस्थानों के कर्मी हैं।

दिखने लगा दुष्प्रचार का असर पेज>>5

38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान। यह सामान्य से चार डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक है। दिन भर उमस से लोग परेशान रहे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 30 अगस्त 2019

बार से बाहर होगी तीन दिन पुरानी बीयर और आठ दिन पुरानी शराब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- 31 अगस्त के बाद तीन दिन पुरानी बीयर, वाइन, शैंपेन को करना होगा नष्ट
- दिल्ली सरकार के एक्साइज, एंटरटेनमेंट एंड लक्जरी टैक्स डिपार्टमेंट ने अधिसूचना जारी की

दिल्ली के होटल, पब और बार में अब तीन दिन पुरानी बीयर और आठ दिन पुरानी व्हिस्की नहीं मिलेगी। बार में एक बार बीयर, वाइन, शैंपेन और शराब के आने के बाद अगर वह तीन से आठ दिन में नहीं बिकती है तो उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। कोई भी बार संचालक बार में एक बार आ चुकी शराब या बीयर को फिर से स्टॉक में नहीं दिखा सकेगा। यह अधिसूचना दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज, एंटरटेनमेंट एंड लक्जरी टैक्स ने होटलों और रेस्तरां के लिए जारी की है। हालांकि रेस्तरां और होटल में बार संचालक इसे मनमाना निर्णय बता रहे हैं।

दिल्ली सरकार के एक्साइज, एंटरटेनमेंट एंड लक्जरी टैक्स डिपार्टमेंट ने 26 अगस्त को अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, बार में रखी जाने वाली शराब की अवधि निर्धारित करना शराब की चोरी और उसमें मिलावट को रोकना है। आबकारी विभाग के पुलिस आयुक्त रंजीत सिंह ने कहा है कि कोई भी रेस्तरां या होटल अपने बार शेल्फ पर तीन से आठ दिनों तक ब्रांड और कीमत के आधार पर शराब रख सकता है। 31 अगस्त से सुबह दस बजे से बीयर, वाइन, शैंपेन और एल्कोपॉप को तीन दिन से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकेगा। शराब उसकी कीमत और ब्रांड के आधार पर पांच से आठ दिनों से अधिक नहीं रखी जाएगी। यहां तक कि सिंगल माल्ट व्हिस्की की एक बोतल को भी आठ दिनों के बाद नष्ट करना होगा। आदेश में कहा गया है कि शराब को नष्ट करने की समय अवधि उस स्टॉक पर लागू होगी, जो स्टोर से बार के लिए जारी किया गया है। समय सीमा खत्म होने पर कोई भी स्टॉक जो अनियंत्रित रहेगा उसे नष्ट कर दिया जाएगा और जो बार काउंटर में होगा, उसे वहां से हटाया जाएगा। शराब को इंवेंट्री एंट्री करने के सात दिनों के भीतर नष्ट कर दिया जाएगा।

हालांकि रेस्तरां और होटल में बार संचालकों का कहना है कि मिलावट व शराब की चोरी रोकने के उद्देश्य से आबकारी विभाग के इस प्रयास का स्वागत करते हैं, लेकिन इस निर्णय से प्रतिमाह करीब 20 लाख रुपये की शराब प्रत्येक बार से नाली में बहाई जाएगी। इससे बार संचालकों को खासा नुकसान होगा। कई जगह तो स्थिति यह होगी कि अधिकांश बार संचालकों को अपना आधे से अधिक बार को खत्म करना पड़ेगा। एक रेस्तरां के बार संचालक का कहना है कि इस समय जो भी शराब बार के सामने लोगों को दिखाने के लिए रखी जाती है, वह हर दिन नहीं बिकती है। अगर आठ दिन तक बार में रखी शराब को नष्ट करना पड़ा तो कुछ महीनों में ही बार बंद करने की नौबत आ जाएगी।

ऐसे तय होगा समय

रेस्तरां या बार के स्टोर द्वारा एक बोतल जारी किए जाने के समय से उसका बार में रखे जाने का समय शुरू होगा। बार या रेस्तरां जो भी शराब परोसता है, उसके परिसर में स्टोर है और एक लॉगबुक या रजिस्टर में बार को जारी की गई शराब की पूरी जानकारी रखनी होगी। आबकारी विभाग के अनुसार शराब में मिलावट और एक्सपायरी डेट की शराब की बिक्री की शिकायत मिलने पर समय सीमा निर्धारित की गई है। समय अधिक बढ़ाने पर एक्सपायरी डेट की बीयर और शराब की बोतलों को दोबारा भरने या उनमें मिलावटी शराब भरे जाने की आशंका है। अधिकारियों ने दावा किया है कि कोई भी बड़ा होटल जो करोड़ों रुपये की शराब रखता है, वह बिना बिके शराब को बाहर निकालने से रोकने के लिए ब्रांड की संख्या को कम करने का विकल्प चुन सकता है। हाल ही में द्वारका स्थित एक नामी होटल के नाइट क्लब में एक्सपायरी डेट की बीयर मिलने के बाद आबकारी विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई है।

चाइनीज मांझे ने हेलमेट को काट माथे को किया लहूलुहान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

विकास गुप्ता। सोशल मीडिया

- बाइक से सोनिया विहार घर लौटते वक्त हुआ हादसा
- राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया, 18 टांके लगे

यमुनापार में चाइनीज मांझे का कहर जारी है। दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद एक बार फिर चाइनीज मांझे से एक व्यक्ति की जिंदगी की डोर कटते-कटते बची है। ताजा मामला उस्मानपुर इलाके का है। चाइनीज मांझा ने पहले बाइक सवार के हेलमेट को काटा और उसके बाद माथे को काटकर लहूलुहान कर दिया। अन्य वाहन चालकों ने गंभीर रूप से घायल विकास गुप्ता (20) को इलाज के लिए शास्त्री पार्क के जग प्रवेशचंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया। विकास के माथे पर 18 टांके लगे हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस केस दर्जकर मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, विकास परिवार के साथ सोनिया विहार के सभापुर गांव में रहते हैं। वह गांधी नगर में एक सीए फर्म में काम करते हैं। बुधवार शाम सात बजे वह गांधी नगर से घर जा रहे थे। जब वह उस्मानपुर जीरो पुश्ता पहुंचे, अचानक उनके हेलमेट में चाइनीज मांझा आकर फंस गया। बाइक की गति तेज थी इसलिए विकास को बाइक रोकने में थोड़ा समय लगा। पहले विकास ने पीछे से आ रही गाड़ियों को हाथ दिखाया और बाइक साइड लगाई। तब तक मांझा विकास को बुरी तरह से घायल कर चुका था। राहगीरों ने उन्हें पहले एक क्लीनिक में भर्ती करवाया। हालत बिगड़ने पर उन्हें जग प्रवेश चंद्र अस्पताल भेज दिया गया। विकास का कहना है कि अगर उन्होंने हेलमेट न लगाया होता तो शायद ही वह आज जिंदा होते। मांझे की तेज धार ने हेलमेट को काट दिया।

हाल ही में हुए हादसे

- 2 अप्रैल 2019 : बुराड़ी में चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से युवक की मौत।
- 11 जुलाई 2019 : बदरपुर फ्लाईओवर पर
- बाइक सवार चाचा : भतीजी चाइनीज मांझे की चपेट में आने से हुए घायल। बच्ची दीप्ती (3) की मौत।
- 21 अप्रैल 2019 : निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में असिस्टेंट प्रोग्रामर रजनीश की लाल किला के पास गर्दन कटी, 36 टांके लगे।
- 15 अगस्त 2019 : पश्चिम विहार में इंजीनियर की चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से मौत।
- 24 अगस्त 2019 : पिता के साथ बाइक पर पूजा करने हनुमान मंदिर जा रही साढ़े चार साल की बच्ची की चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से मौत।

एयरफोर्स डे के दिन हिंडन एयरपोर्ट से पहली उड़ान

जासं, साहिबाबाद : दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाद एनसीआर के दूसरे एयरपोर्ट हिंडन से उड़ान सेवा जल्द ही शुरू होने जा रही है। आठ अक्टूबर एयरफोर्स डे पर एक ओर हिंडन एयरबेस में वायुसेना अपनी ताकत दुनिया को दिखाएगी, वहीं एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट पिथौरागढ़ के लिए यात्रियों को लेकर रवाना होगी। यह फ्लाइट नौ सीटर होगी जिसका प्रति यात्री किराया 2500 रुपये होगा। जल्द ही इसकी टिकटों के लिए बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के अनुसार हिंडन से नौ शहरों के लिए उड़ान शुरू होंगी। सबसे पहले उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जाने वाले लोगों को यहां से सुविधा मिल सकेगी। एयर हेरिटेज नामक कंपनी अपना नौ सीटर विमान पिथौरागढ़ के लिए रवाना करेगी। पिथौरागढ़ के छोटे रनवे को देखते हुए नौ सीटर विमान भेजने का निर्णय लिया गया है। आठ अक्टूबर को यह पहली बार जाएगा। उधर, उड़ान की तैयारियों को देखते हुए एयरपोर्ट पर अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है। एयरपोर्ट डायरेक्टर को पहले ही तैनात किया जा चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही उड़ान शुरू होने की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी।

पिथौरागढ़ के उप्र के फैजाबाद, उत्तराखंड के देहरादून, गुजरात के जामनगर, हिमाचल के शिमला, महाराष्ट्र के नासिक, कर्नाटक के हुबली, कन्नूर और गुलबर्गा के लिए यहां से उड़ान मिल सकेंगी। सफल संचालन के बाद गोरखपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ आदि रूटों पर भी उड़ान शुरू की जाएंगीं।

दिल्ली-एनसीआर में 29 अक्टूबर से मुफ्त बस यात्रा कर सकेंगी महिलाएं

योजना ▶ कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव मंजूर, डीटीसी रेग्युलेशन एक्ट में बदलाव का दिया निर्देश

डीटीसी और क्लस्टर बसों में मिलेगी सुविधा, कंडक्टर जारी करेंगे सिंगल जर्नी पास

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

महिलाओं को 29 अक्टूबर से दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर की सुविधा के लिए दिल्ली सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी। बसों में मुफ्त सफर के लिए महिला यात्रियों को सिंगल जर्नी पास जारी किए जाएंगे। ये पास कंडक्टर से ही मिलेंगे। गुलाबी रंग के इस टोकन की कीमत 10 रुपये होगी, जिसका खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। दिल्ली सरकार इसके लिए 140 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही कर चुकी है।

कैबिनेट बैठक के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि यह योजना दिल्ली में सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में लागू होगी। यह सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि एनसीआर के शहरों में जाने वाली बसों में भी लागू होगी। फायदा भी पूरे एनसीआर की महिलाओं को मिलेगा। सरकार ने डीटीसी को मुफ्त सफर के लिए डीटीसी रेग्युलेशन एक्ट 1985 के नियमों में जरूरी बदलाव का निर्देश भी जारी कर दिया है, जिससे जल्द से जल्द इसे लेकर अधिसूचना जारी की जा सके। इसके अलावा सरकार मुफ्त सफर योजना की निगरानी के लिए जांच टीम भी तैनात करेगी, जिससे टोकन का दुरुपयोग न हो सके।

दिल्ली सचिवालय में पत्रकार वार्ता करते मंत्री कैलाश गहलोत। केजरीवाल सरकार महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के लिए 140 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही कर चुकी है। जागरण

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में ट्वीट कर कहा, 'मुझे यकीन है जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, वे भविष्य में देखेंगे कि महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में यह कदम एक मील का पत्थर साबित होगा।

सरकारी सेवारत महिलाओं ने की मुफ्त यात्रा तो नहीं मिलेगा भत्ता

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार की ओर से डीटीसी और क्लस्टर बस सेवा को टिकट चेकिंग व्यवस्था भी दुरुस्त करने को कहा गया है ताकि मुफ्त यात्रा सुविधा का दुरुपयोग न किया जा सके। दिल्ली सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों व निगमों में कार्यरत महिलाएं अगर मुफ्त बस यात्रा सुविधा का लाभ उठाएंगी तो उन्हें यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा।

सरकार और निगम महिला कर्मचारियों से लिखित जानकारी प्राप्त कर लेगी कि वे इस फ्री सेवा का लाभ नहीं ले रही हैं। दिल्ली सरकार इस योजना को लागू करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय को पत्र भी लिखेगी कि वह केंद्र सरकार में कार्यरत महिला कर्मियों को भी इसी दायरे में रखे व लिखित जानकारी प्राप्त करे। मुफ्त बस यात्रा योजना के लिए सैद्धांतिक अनुमति देने पर वित्त विभाग ने असहमति जताई थी। वित्त विभाग ने महिलाओं को छमाही या वार्षिक पास जारी करने को कहा था ताकि दैनिक पास जारी करने पर वित्तीय अनियमितता न हो।

दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पद से मुक्त होना चाहता हूं : चाको

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

पीसी चाको। फाइल फोटो

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की तलाश के बीच प्रदेश प्रभारी पीसी चाको ने अपने इस पद से मुक्त होने की इच्छा जताई है। हालांकि जागरण से बातचीत में गुरुवार रात उन्होंने इसका खंडन किया कि इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोई पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है और न ही किसी को कोई पत्र लिखा है। हाल ही में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान बस इतना कहा था कि मेरा कार्यकाल पूरा हो गया है। मैं इस पद से अब मुक्त होना चाहता हूं। साथ ही चाको ने यह भी कहा कि अगले दो-तीन दिन में प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है।

सूत्रों की मानें तो चाको की इस इच्छा के पीछे कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि शीला गुट की उनके प्रति जबरदस्त नाराजगी। शीला गुट लगातार उन्हें हटाने की मांग करता रहा है। इस गुट का आरोप है कि पिछले साढ़े चार साल में जब से चाको यहां पर प्रभारी रहे हैं, पार्टी सभी चुनाव हार गई है इसलिए उन्हें हटाना चाहिए। सोनिया गांधी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद यह कयास और तेज हो गए हैं कि प्रदेश प्रभारी पद से उन्हें हटाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने खुद पहल करते हुए पद से मुक्ति की मांग रख दी है। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि अब वह अपने गृह क्षेत्र केरल की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं।

पार्टी के नेताओं का कहना है कि दिल्ली को एक ऐसा प्रभारी चाहिए तो यहां के लोगों की नब्ज को समझ सके। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी जिन पांच विधानसभा में टॉप पर रही थी, वह अल्पसंख्यक समुदाय वाले इलाके हैं। ऐसे में किसी अल्पसंख्यक नेता को भी प्रभारी पद दिए जाने की संभावना है। जहां तक अध्यक्ष की बात है तो सूत्रों का कहना है कि चाको की रायशुमारी में पूर्व अध्यक्ष अजय माकन का नाम ही सबसे ऊपर चल रहा है। बेशक माकन स्वयं इस जिम्मेदारी को वापस लेने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हों, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर नेताओं ने उन्हें ही इस पद के सर्वथा उपयुक्त बताया है। हालांकि सोनिया गांधी इससे इतर भी निर्णय ले सकती हैं और प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में और भी कई नाम विचाराधीन हैं।

सिविल डिफेंस भर्ती में गड़बड़ी का आरोप

शुजाउद्दीन, नई दिल्ली

शाहदरा जिले में सिविल डिफेंस भर्ती में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी कुलदीप पाकड़ सवालों के घेरे में हैं। उन पर आरोप लगा है कि वह नियम के विरुद्ध दूसरे राज्यों के लोगों को दिल्ली में भर्ती कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस वाले दिन जिलाधिकारी कार्यालय में बने आधार कार्ड केंद्र को खुलवाया और अपने लेटर हेड के माध्यम से उन लोगों के घर के पते बदलवाए। यह गड़बड़ी सामने आने पर डिविजनल कमिश्नर ने सिविल डिफेंस की भर्ती पर रोक लगा दी है। इससे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में होने वाली मार्शल की तैनाती फिलहाल कुछ समय के लिए टल गई है।

करोलबाग में रहने वाले एक व्यक्ति ने 20 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शिकायत पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था कि शाहदरा के जिलाधिकारी कुलदीप पाकड़ पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गत 11 और 12 अगस्त को सरकारी छुट्टी थी, इसके बावजूद जिलाधिकारी ने कार्यालय में बने आधार कार्ड केंद्र को खुलवाया और अपने लेटर हेड पर गारंटी लेकर राजस्थान के 250 लोगों के पते आधार कार्ड में बदलवाए। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों के घर के पते आधार कार्ड में बदले गए, वे सभी राजस्थान के थे और मीणा जाति से संबंध रखते हैं, जिलाधिकारी भी इसी जाति के हैं। आगे आरोप लगाया कि प्रत्येक आवेदक से भर्ती के नाम पर एक लाख रुपये लिए गए हैं। साथ ही राजस्थान से आने वाले सभी लोगों के रुकने का इंतजाम अशोक नगर के एक बारात घर में किया गया था। इस पर संज्ञान लेते हुए डिविजनल कमिश्नर ने 21 अगस्त को आदेश जारी करके भर्ती पर रोक लगा दी।

सूत्रों का कहना है कि जिलाधिकारी ने अपने गांव के लोगों से वादा किया था कि वह उनकी नौकरी लगवाएंगे, इसलिए उन्होंने नियम के विरुद्ध जाकर इतना बड़ा कदम उठाया।

भर्ती होने पर डीटीसी की बसों में लगते मार्शल : एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार डीटीसी और क्लस्टर बसों में लोगों की सुरक्षा के लिए मार्शल रखना चाहती है। इसके लिए डीटीसी ने जिला प्रशासन से सिविल डिफेंस वालंटियर मांगे हैं। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में सबसे ज्यादा वालंटियर 1735 शाहदरा जिले से मांगे गए थे। इसमें कुछ नए लोगों की भर्ती होती और कुछ पुराने भेजे जाते। गत 16 अगस्त को इनकी ट्रेनिंग मंडोली के एक स्कूल में करवाई गई थी और 22 अगस्त को इनका साक्षात्कार जीटीबी एंक्लेव के सरकारी स्कूल में होना था। ट्रेनिंग लेने के बाद लोग जब साक्षात्कार देने पहुंचे तो उन्हें जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि 21 अगस्त को डिविजनल कमिश्नर ने इस भर्ती पर रोक लगा दी है। इसके बाद वहां अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था।

जल्द हो सकती है कार्रवाई : सूत्रों के अनुसार, जिलाधिकारी के इस कदम से उपराज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव बेहद नाराज हैं। मामला तूल पकड़े उससे पहले ही वह जिलाधिकारी का तबादला कर सकते हैं। जिलाधिकारी पाकड़ का कहना है कि उन्होंने भर्ती से जुड़े सारे कागजात दोनों अधिकारियों को भेज दिए हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है। बता दें कि जिलाधिकारी अगले वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

विधानसभा में होगी धांधली की जांच

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : महिला सुरक्षा के लिहाज से डीटीसी और कलस्टर बसों में मार्शलों की भर्ती करने के लिए निवास प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया में हुई धांधली की जांच अब दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति करेगी। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को शिकायत प्राप्त हुई है। इस पर संज्ञान लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने मामले को जांच के लिए याचिका समिति को सौंप दी है। इस मामले में दिल्ली के परिवहन एवं राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि बसों में मार्शल नियुक्त करने के मुद्दे पर अनियमितता की बात सामने आई है। शाहदरा जिले में यह शिकायत मिली है। जांच के लिए राजस्व विभाग के तहत भी एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी कुछ दिन में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। हालांकि कुलदीप पक्कड़ ने अपने खिलाफ ऐसे किसी आरोप से मना किया है।

दिल्ली में 24 घंटे मिल रही सबसे सस्ती बिजली : संजय सिंह

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : बिजली की दरों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन के आरोपों को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने निराधार बताते हुए कहा कि दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है और देश में सबसे सस्ती बिजली मुहैया कराई जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली के लिए एक भी रुपया नहीं देना पड़ता, जबकि अन्य राज्यों में 1000 से 1500 रुपये के बीच में भुगतान करना होता है। इसी तरह 400 यूनिट बिजली के दाम देखें तो हरियाणा में 1820, उत्तर प्रदेश में 2480, महाराष्ट्र में 3310, कर्नाटक में 2910, बिहार में 2950, तेलंगाना में 2307, पश्चिम बंगाल में 2946, मध्य प्रदेश में 2430 रुपये, पंजाब में 2870, राजस्थान में 3277 रुपये देने पड़ते हैं। दिल्ली में 400 यूनिट के लिए केवल 1075 रुपये देने पड़ते हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में 2010 से 2013 तक बिजली के दाम 100 फीसद बढ़े थे, जबकि आम आदमी पार्टी के समय में बिजली के दाम 100 फीसदी घटे हैं। कांग्रेस के समय में 2010 में 200 यूनिट तक बिजली के दाम 539 रुपये थे। 2013 तक यह बढ़कर 988 रुपये हो गए। कांग्रेस के शासन काल में लगभग 100 फीसद का इजाफा हुआ। हमने 200 यूनिट तक बिजली के दाम जीरो कर दिए। संजय सिंह ने कहा कि माकन को बताना चाहिए कि दिल्ली में बिजली के निजीकरण के पीछे कौन सा खेल खेला था?

'सिर्फ 17 फीसद को मिला बिल माफी का लाभ'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

कांस्टीट्यूशन क्लब में दिल्ली में पावर सेक्टर की सच्चाई को लेकर पत्र दिखाते दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री अजय माकन (बाएं से दूसरे) और अन्य। जागरण

- अजय माकन ने बिजली की दरों पर आप सरकार को किया कठघरे में खड़ा
- कहा, 200 यूनिट खर्च करने वाले महज 6.87 एवं 400 यूनिट वाले 11.41 फीसद

दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी सरकार बिजली बिल माफी का जो ढिंढोरा पीट रही है, उसका लाभ केवल 17 फीसद लोगों को ही मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही बिजली की दरों में सब्सिडी देकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन सच्चाई यह है कि 0-200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता महज 6.87 फीसद हैं, जबकि 200-400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या केवल 11.41 फीसद है। 83 फीसद उपभोक्ताओं को इस सब्सिडी का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने इन आरोपों के मद्देनजर ही 'द ट्रूथ ऑफ पावर सेक्टर इन दिल्ली' नामक एक बुकलेट भी जारी की है।

कांस्टीट्यूशन क्लब में माकन ने एक प्रेजेंटेशन देकर बताया कि केजरीवाल ने अपने चुनावी घोषणापत्र में कहा था कि वह सब्सिडी बिजली कंपनियों को नहीं देकर सीधे दिल्ली ट्रांस्को को देंगे। लेकिन पिछले पांच सालों में 8532.64 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली कंपनियों को ही दी गई। उन्होंने पूछा कि आप सरकार इतनी ही पारदर्शी है तो फिर सब्सिडी सीधा बिजली उपभोक्तओं के बैंक खाते में क्यों नहीं भेज रही है? एलपीजी की सब्सिडी जब केंद्र सरकार सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में डाल सकती है, तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं? उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के लोगों की मेहनत की कमाई में से निकले 8532.64 करोड़ रुपये का सरकार के पास कोई हिसाब-किताब नहीं है।

माकन ने यह भी कहा कि दिल्ली में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे सस्ती नहीं, बल्कि सबसे महंगी बिजली दी जा रही है। बिजली के प्रति यूनिट दामों का औसत 2018-2019 में प्रति यूनिट 8.45 रुपये है। मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि दिल्ली में पूरे देश की तुलना में बिजली के दाम सबसे कम हैं। सच्चाई यह है कि सूरत में औसत 6.41 रुपये प्रति यूनिट है और मुंबई (टीपीसी-डी) में 7.51 रुपये। मध्य प्रदेश में 6.59 रुपये, अहमदाबाद में 6.60 रुपये, पंजाब में 6.63 रुपये, मध्य प्रदेश में 6.59 रुपये, मुंबई वेस्ट में 6.94 रुपये, राजस्थान में 7.04 रुपये, हरियाणा में 7.05 रुपये, बंगलौर में औसत 7.37 रुपये प्रति यूनिट की दर से उपभोक्ता दे रहे हैं।

माकन ने कहा कि वर्ष 2014-2015 के मुकाबले में बिजली कंपनियों के द्वारा बिजली के दामों में बढ़ोतरी से आए पैसे को देखा जाए तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आते हैं। 2014-2015 में यह राशि 1455.70 करोड़ थी, तो 2018-2019 में बढकर 3019.20 करोड़ हो गई। माकन ने कहा कि उन्होंने एक आरटीआइ भी लगाई है कि केजरीवाल 8532 करोड़ की सब्सिडी की जानकारी दें कि इसका फायदा किसे हुआ, क्योंकि इसका लाभ आम आदमी नहीं, बल्कि निजी कंपनियों को दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि 94 फीसद घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिल रही। यह धोखा है। पिछले पांच सालों में निजी बिजली कंपनियों ने जो 9999.25 करोड़ रुपये कमाए, वह दिल्ली वासियों को वापस मिलने चाहिए।

तैयारी

प्रकृति की गोद में लगेगा जायके का तड़का

सभी जिला उद्यानों में डीडीए आरंभ करेगा हरित रेस्तरां, प्रतियोगिता के माध्यम से डिजाइनरों से मांगे गए डिजाइन, जल्द शुरू होगा काम

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

जल्द ही दिल्लीवासियों को हरियाली के बीच विभिन्न व्यंजनों का स्वाद भी मिलेगा। इसके लिए उन्हें कहीं दूर भी नहीं जाना, बल्कि अपने घर के आसपास स्थित किसी भी जिला उद्यान का रुख करना है। जी हां, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अब प्रकृति की गोद में व्यंजनों का तड़का भी लगाएगा। फिलहाल इसके लिए डिजाइनिंग का काम चल रहा है, कुछ ही माह में निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा।

दरअसल, डीडीए ने अपने सभी जिला उद्यानों में हरित रेस्तरां खोलने का निर्णय किया है। इन रेस्तरांओं की खासियत यह होगी कि खाना तो यहां पसंद का मिलेगा ही, लेकिन रेस्तरां की डिजाइनिंग प्राकृतिक होगी। फर्नीचर भी लकड़ी से बना होगा और वहां परोसे जाने वाले व्यंजन भी घर जैसा स्वाद लिए होंगे।

डीडीए ने इन रेस्तरां की डिजाइनिंग के लिए भी एक अनूठा तरीका निकाला है। 'डिजाइनिंग विद नेचर- इंटीग्रेटेड रेस्टोरेंटस इन अर्बन ग्रींस' नाम से एक प्रतिस्पर्धा शुरू की है। इसके तहत उभरते कलाकारों, डिजाइनरों और आर्किटेक्टों से इनके लिए डिजाइन मांगे गए हैं। डिजाइन भेजने की अंतिम तारीख चार सितंबर है। डीडीए का योजना विभाग इन डिजाइनों में से कुछ बेहतरीन डिजाइन चयनित करेगा। इसके बाद उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और बाद में इन्हीं डिजाइनों पर विभिन्न जिला उद्यानों में रेस्तरां बनाए जाएंगे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के उद्यान की फोटो। जागरण

> सभी जिला उद्यानों में हरित रेस्तरां खोलने के कंसेप्ट पर काम किया जा रहा है। ऐसे जिला उद्यानों की संख्या 35 से 40 है। जल्द ही इनके डिजाइन बन जाएंगे। चयनित डिजाइनों पर आगे का काम भी कुछ ही माह में शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि यह अनूठा प्रयोग सभी को पसंद आएगा।
>
> -तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए

डीडीए अधिकारियों के मुताबिक बहुत साल पहले कुछ जिला उद्यानों में रेस्तरां खोले भी गए थे। लेकिन व्यवस्थाओं के अभाव में धीरे-धीरे सभी बंद हो गए। ये पार्क इतने बड़े और सुविधा संपन्न हैं कि यहां पर लोग केवल सुबह-शाम सैर करने के लिए ही नहीं आते, बल्कि दिन में पिकनिक मनाने भी आ जाते हैं। छुट्टी के दिन तो इन उद्यानों में दिन भर खासी चहल-पहल रहती है। ऐसे में खाने- पीने का कोई स्टॉल न होना लोगों को अखरता है। इसी को ध्यान में रखते हुए डीडीए ने यह योजना तैयार की है।

मुफ्त की घोषणाओं से आप को नहीं होगा लाभ : पुरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली के चुनाव सह प्रभारी और केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक देखकर मुख्यमंत्री लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी का बकाया बिल माफ करने सहित मुफ्त की अन्य घोषणाओं से उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है। वह एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सीएम अपनी घोषणाओं से लोगों को गुमराह करते रहे हैं। वहीं, केंद्र सरकार जो कहती है, उसे पूरा भी करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के सर्वे के काम को भी दिल्ली सरकार कई वर्षों से टाल रही थी। शुरू में केंद्र सरकार ने भी उन पर विश्वास कर लिया। लेकिन अब केंद्र अपने स्तर पर कॉलोनियो का सर्वे करा रही है। अगले कुछ सप्ताह में यह कार्य पूरा हो जाएगा। पक्की रजिस्टरी होने से इन कॉलोनियों में रहने वालों को लाभ मिलेगा। अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के मामले का दिल्ली विधानसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है।

कथित पत्रकार के खिलाफ एक और मुकदमा हुआ दर्ज

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

- गाजियाबाद की महिला ने चंदन राय पर लगाया घर पर कब्जे का आरोप

एक महिला ने कथित पत्रकार चंदन राय पर किराये पर घर लेकर कब्जा करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पत्रकार होने की धौंस दिखाते हुए उसका एक लाख 64 हजार रुपये किराया भी देने से इन्कार कर दिया था। पुलिस ने जांच के दौरान पीड़िता से लिए गए लिखित बयानों के आधार पर सूरजपुर कोतवाली में आरोपित के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस रिमांड पर लिए गए चंदन राय की प्रापर्टी के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि उसने गाजियाबाद के जिस मकान में अपना ऑफिस बनाया हुआ है, वह उसके द्वारा किराये पर लेकर कब्जाया गया है। ऐसे में पुलिस ने दक्षिण गांधी मैदान पटना निवासी मकान मालिक प्रमिला गुप्ता से बात की। उन्होंने पुलिस को दिए अपने लिखित बयान में कहा है कि उनका गाजियाबाद के वसुंधरा में प्लॉट नंबर 61 पर दो मंजिला मकान है। पत्रकार चंदन राय ने नवंबर 2017 में परिवार को रखने के लिए उनके मकान को किराये पर लिया था। इसके लिए 12 हजार रुपये मासिक किराया तय किया गया था। आरोप है कि कुछ दिन तक चंदन ने मकान का किराया समय से दिया। उसके बाद किराया देने के नाम पर टाल मटोल करना शुरू कर दिया और मकान में अपना ऑफिस बना लिया। इसी बीच आरोपित चंदन ने मकान के निचले हिस्से को भी अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी होने पर जब उसके द्वारा ऐसा किए जाने के बारे में पूछा और अपना बकाया किराया एक लाख 64 हजार रुपये देने की मांग की तो उसने अपने पत्रकार होने की धौंस दिखाते हुए भगा दिया। सूरजपुर कोतवाली प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

31 अगस्त को होगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) का अंतिम प्रकाशन। एनआरसी भारतीय नागरिकों के नाम की सूची है, जिसे पहली बार 1951 में तैयार किया गया था। घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए असम में इसे अपडेट किया जा रहा है।

इस्लामिक कानून के तहत विवादित ढांचा मस्जिद नहीं

- अखिल भारत श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने रखीं दलीलें
- अदालत में इस्लाम के विशेषज्ञ विद्वानों की गवाही का दिया हवाला

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बनाए गए विवादित ढांचे को इस्लामिक कानून में मस्जिद नहीं माना जा सकता क्योंकि मस्जिद न तो जबरदस्ती कब्जा की गई जगह पर बनाई जा सकती है और न ही मंदिर तोड़कर बनाई सकती है। यह भी साबित नहीं हुआ कि बाबर ने इसे अल्लाह को समर्पित किया था। ये दलीलें गुरुवार को अखिल भारत श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गईं। यह भी कहा गया कि 1992 में ढहाया गया ढांचा मंदिर था, जहां रामलला विराजमान स्थापित हैं, वह बाबरी मस्जिद नहीं थी।

समिति के वकील पीएन मिश्रा और रंजना अग्निहोत्री ने हाई कोर्ट में दी गई मुस्लिम विद्वानों की गवाही का हवाला देकर गुरुवार को यह साबित करने की कोशिश की कि विवादित ढांचा मस्जिद नहीं था। दिनभर चली दलीलों पर पीठ की ओर से भी कई सवाल पूछे गए। कोर्ट ने कहा कि 500 साल बाद कोर्ट के लिए यह तय करना थोड़ा मुश्किल होगा कि बाबर ने उसे अल्लाह को समर्पित किया था कि नहीं। पीएन मिश्रा की बहस शुक्रवार को भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि राम जन्मस्थान के राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ हुई है और समय कम होने के कारण वह शुक्रवार को इस बारे में कोर्ट में ब्योरा पेश करेंगे। मिश्रा ने मस्जिद के बारे में इस्लाम के विशेषज्ञ के तौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से पेश किए गए गवाह मुहम्मद इदरिश और बुहरानुद्दीन की हाई कोर्ट मे हुई गवाही और जिरह का हवाला दिया। दोनों विद्वानों ने उसमें कहा है कि इस्लाम में कुरान और हदीस के मुताबिक, मस्जिद खाली जगह पर बनवाई जाती है। मस्जिद के लिए वक्फ बनाना जरूरी है और वाकिफ उस जमीन का मालिक होना चाहिए। जहां देवी-देवता या स्त्री-पुरुष, पशु की मूर्तियां हों वहां पढ़ी गई नमाज नाजायज होती है। मिश्रा ने कहा कि विवादित ढांचे में वराह की मूर्ति बनी थी।

मिश्रा ने हाई कोर्ट के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा, हाई कोर्ट ने बहुमत से माना है कि मुस्लिम पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि वहां बाबर ने मस्जिद बनवाई थी और न ही यह साबित हुआ कि बाबर उस जमीन का मालिक था। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने फैसले का अगला खंड पढ़ाया जिसमें बाबर द्वारा मस्जिद बनाए जाने की बात थी। मिश्रा ने कहा कि जस्टिस एसयू खान के फैसले में विरोधाभासी बातें दर्ज हैं जिससे पीठ के न्यायाधीशों ने भी सहमति जताई। जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि यहां तीन बातें मुख्य हैं कि क्या वहां कोई ढांचा था। क्या वह ढांचा मस्जिद थी। और क्या वह ढांचा अल्लाह को समर्पित किया गया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, यहां सवाल यह नहीं है कि किसने उसे बनवाया था और उसे अल्लाह को समर्पित किया गया था। सवाल यह है कि लोग उसे क्या मानते हैं? जैसे तिरुपति का मंदिर कब बना यह अहम नहीं है बल्कि लोग उसे क्या मानते हैं वह अहम है। मिश्रा ने कहा कि यहां हिंदू उसे मंदिर कहते है और मुसलमान मस्जिद बताते हैं। वहां 1934 के बाद सिर्फ शुक्रवार को नमाज होती थी। इस्लामिक कानून में जहां दो वक्त अजान नहीं होती उसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता।

शासक भी धर्म के अधीन है : इस्लाम में शासक कितना भी स्वतंत्र क्यों न हो लेकिन वह धर्म के अधीन होता है। बाबर ने अगर उस ढांचे को अल्लाह को समर्पित नहीं किया था तो उसे मस्जिद नहीं माना जाएगा, उसे बाबर की हवेली कहा जा सकता है। जस्टिस बोबडे ने पूछा, क्या कोई राजा राज्य की संपत्ति को वक्फ कर सकता है? मिश्रा ने कहा-नहीं। उन्होंने इस बारे में मदीना की मस्जिद के लिए जमीन लेने और ताजमहल बनवाने के लिए राजा जयसिंह से जमीन खरीदने के शाहजहां के फरमान का भी जिक्र किया।

किस्सों पर मुस्लिम पक्ष ने उठाई आपत्ति

मुस्लिम पक्ष के वकील ने मिश्रा की दलीलों पर आपत्ति उठाते हुए कहा कि वह अभी तक की बहस में 24 ऐसे किस्से–कहानियों का जिक्र कर चुके हैं जो केस का हिस्सा नहीं हैं। मिश्रा ने कहा कि वह अपने ढंग से बहस करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि कोर्ट ने सीधे तौर पर मिश्रा से कुछ नहीं कहा।

कोल ब्लॉक घोटाले में पूर्व सचिव एचसी गुप्ता बरी

- अदालत ने कहा, आरोप साबित करने में विफल रही सीबीआइ, दिल्ली की कंपनी को भी अदालत ने किया बरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव और दिल्ली की पुष्प स्टील एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (पीएसएमपीएल) को राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने कहा कि सीबीआइ एचसी गुप्ता और कंपनी पर लगाए गए आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा है।

एचसी गुप्ता 31 दिसंबर 2005 से नवंबर 2008 तक कोयला मंत्रालय के सचिव थे। यह मामला फर्म को कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित था। कंपनी को दुर्ग जिले में प्रस्तावित स्पंज आयरन एंड यूज प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया था। अदालत ने कहा कि सीबीआइ धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश के अपराध, धारा 13 (1) के तहत आपराधिक कदाचार, धारा 13 (1) (डी) के तहत भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम और धारा 409 के तहत किसी लोक सेवक द्वारा विश्वास के आपराधिक उल्लंघन का आरोप साबित नहीं कर सकी। ऐसे में दोनों अभियुक्तों को बरी किया जाता है। अभियुक्तों ने अधिवक्ता रजत माथुर के माध्यम से अपील याचिका दायर कर आरोपों से इन्कार करते हुए सीबीआइ पर झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि कंपनी को छत्तीसगढ़ सरकार से सिफारिश के आधार पर खनन का पट्टा दिया गया था, जबकि उसके पास कोई अनुभव नहीं था और खनन कार्य शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी की कमी थी। सीबीआइ ने दावा किया था कि ब्रह्मपुरी कोयला ब्लॉक का आवंटन कथित झूठी सूचना के आधार पर किया गया था।

मनी लांड्रिंग देश के खिलाफ अपराध

शिकंजे में चिदंबरम ▶ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, चिदंबरम से हिरासत में पूछताछ की जरूरत

अग्रिम जमानत पर पांच सितंबर को फैसला सुनाएगी शीर्ष अदालत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सीबीआइ और ईडी की गिरफ्त में उलझे कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं। गुरुवार को असाधारण घटनाक्रम में चिदंबरम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ओर से ही दो सितंबर तक सीबीआइ हिरासत में बने रहने की पेशकश की जबकि यह हिरासत शुक्रवार को खत्म हो रही है। शायद यह भविष्य का दांव था ताकि फिर से निचली अदालत का चक्कर न लगाना पड़े। सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया। वहीं, ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में पुख्ता सबूत होने का दावा ही नहीं किया बल्कि मनी लांड्रिंग को समाज और देश के खिलाफ अपराध बताते हुए सीलबंद लिफाफे में सुबूत पेश कर गिरफ्तारी को जरूरी बताया। सुनवाई पांच सितंबर को होगी। तब तक ईडी की गिरफ्तारी से चिदंबरम को राहत है।

चिदंबरम की सीबीआइ हिरासत की अवधि शुक्रवार को खत्म हो रही है और उन्हें फिर से विशेष अदालत में पेश किया जाना है, लेकिन गुरुवार को जब कोर्ट ने उन्हें हिरासत में भेजने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दो सितंबर को सुनवाई करने की बात कही तभी चिदंबरम के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम दो सितंबर तक सीबीआइ हिरासत में रहने को तैयार हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पेशकश का विरोध करते हुए कहा कि रिमांड का फैसला कोर्ट लेगा। अगर शुक्रवार को वह विशेष अदालत में ऐसी पेशकश करते हैं तो उन्हें आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आज उन्हें आपत्ति है। दरअसल यह कानूनी पेंच है। कानून की तय प्रक्रिया में अभियुक्त की हिरासत खत्म होने के बाद उसे संबंधित अदालत में पेश किया जाता है। अदालत मामले पर विचार करने के बाद फैसला करती है कि क्या फिर से हिरासत में भेजना है। ऐसे में अगर शुक्रवार को चिदंबरम को विशेष जज के समक्ष पेश किया जाता और उन्हें फिर से हिरासत में भेजने का आदेश हो जाता तो दो तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में राहत मांगने की गुंजाइश घट जाएगी।

खैर, ईडी के मामले में कहा गया कि मनी लांड्रिंग की साजिश का पता लगाने के लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करनी होगी। दूसरी ओर चिदंबरम की ओर से ईडी की दलीलों का विरोध करते हुए कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर पांच सितंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने ईडी को चिदंबरम के खिलाफ एकत्रित सामग्री सीलबंद कवर में देने का आदेश दिया और कहा कि वह इस सामग्री पर विचार करेगा या नहीं इसका फैसला भी पांच सितंबर के आदेश में होगा।

जब चिदंबरम की ओर से सीलबंद लिफाफे में पेश दस्तावेजों पर कोर्ट के विचार करने का विरोध किया गया तो मेहता ने कहा कि अगर यह दलील स्वीकार की गई तो इसका असर विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, जाकिर नाइक के मामले में भी पड़ सकता है।

इंद्राणी मुखर्जी ने चिदंबरम की गिरफ्तारी को बताया अच्छी खबर

- कहा, कार्ति चिदंबरम की जमानत भी होनी चाहिए रद

मुंबई, प्रेट्र : शीना वोरा हत्या मामले में प्रमुख अभियुक्त इंद्राणी मुखर्जी ने आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार एवं मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी को अच्छी खबर करार दिया है।

आइएनएक्स मीडिया ग्रुप के प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी और उसके पति पीटर मुखर्जी ही थे। फिलहाल दोनों शीना वोरा हत्या मामले में जेल में बंद हैं। शीना इंद्राणी की ही बेटी थी। इसी मामले में गुरुवार को उसे विशेष सीबीआइ अदालत में पेश किया गया। अदालत के बाहर पत्रकारों के सवालों के जवाब में इंद्राणी ने कहा, 'उनकी (चिदंबरम) गिरफ्तारी अच्छी खबर है। अब वह चारों तरफ से घिर गए हैं।' इंद्राणी ने आगे कहा कि कार्ति चिदंबरम को प्रदान की गई जमानत भी रद की जानी चाहिए।

आइएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति भी आरोपित है। बता दें कि पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम के मामले में इंद्राणी इसी साल जुलाई में सरकारी गवाह बन गई थी और उसने अपना इकबालिया बयान दर्ज कराया था।

बयान में इंद्राणी ने कहा था कि उसने और उसके पति ने तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से उनके नॉर्थ ब्लॉक स्थित कार्यालय में मुलाकात की थी। आइएनएक्स मीडिया को एफआइपीबी मंजूरी देने के बदले चिदंबरम ने अपने बेटे कार्ति के कारोबार में मदद करने और विदेशी खाते में धन भेजने के लिए कहा था।

ईडी के सामने पेश हुए अहमद पटेल के बेटे फैजल

नई दिल्ली, एएनआइ : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी नेता और पार्टी के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल से गुरुवार को फिर पूछताछ की। उनका बयान मनी लांड्रिंग रोधी एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है। इससे पहले अहमद पटेल के दामाद इरफान सिद्दिकी से भी केंद्रीय जांच एजेंसी पूछताछ हो चुकी है। स्टर्लिंग बायोटेक घोटाले में इन दोनों पर मनी लांड्रिंग का आरोप है। पिछले महीने स्टर्लिंग बायोटेक बैंक घोटाले और मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड अभिनेता डीनो मोरिया और डीजे अकील से भी पूछताछ की थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक 14,500 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में मुख्य आरोपित गुजरात की कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक के मालिक नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा और दीप्ति संदेसरा हैं, जो फरार हैं।

पूर्व में सरकारें सिर्फ चलती थीं, मोदी ने देश को सुधारा : अमित शाह

शत्रुघ्न शर्मा, गांधीनगर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि 2014 से पहले देश में सरकारें सिर्फ चला करती थीं, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को सुधारने का काम हुआ। शाह ने देश की आर्थिक सेहत तंदुरुस्त होने का दावा करते हुए कहा, आज भारत दुनिया के सामने वैश्विक ताकत बनकर खड़ा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब जम्मू-कश्मीर का विकास होगा।

अमित शाह गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के सातवें दीक्षा समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक इच्छाशक्ति से फैसले करते हैं, भले उसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े। इस संदर्भ में उन्होंने रिलायंस समूह के अध्यक्ष मुकेश अंबानी की जीएसटी को लेकर कही एक बात को याद करते हुए कहा, मुकेश भाई कहते थे जीएसटी हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन राजनीतिक रूप से आपको नुकसान करेगा। मोदी ने देश की अखंडता के लिए जम्मू-कश्मीर से एक झटके में अनुच्छेद 370 व 35ए को हटाने का काम किया। अब कश्मीर के लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार उपलब्ध होगा, राज्य में पर्यटन व उद्योगों का विकास होगा। अमित शाह ने कहा, आज 130 करोड़ लोगों का विश्वास जीतकर मोदी दुनिया में भारत की मजबूती की धमक दिखा रहे हैं। कुछ साल पहले तक देश में कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि भारत का कोई नेता दुनिया में ताकतवर बनकर उभरेगा, लेकिन आज मोदी विश्व आर्थिक मंच को भी हिंदी में संबोधित करके देश की बढ़ रही ताकत का अहसास कराते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विकास दर आठ प्रतिशत तक लानी होगी। फिलहाल देश की विकास दर सात प्रतिशत है। दुनिया की रेटिंग एजेंसियों ने देश की रेटिंग में सुधार किया है, देश में निवेश व बिजनेस करना आसान हो गया। शाह ने कहा दुनिया में तेल, गैस, ऊर्जा ही अर्थव्यवस्था को चलाती हैं। मोदी ने 12 साल पहले पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की स्थापना के साथ ही गुजरात को पेट्रोलियम राजधानी बनाने का सपना देखा था जिसे पूरा करना अब इस संस्थान के छात्रों का भी कर्तव्य है। समारोह में रिलायंस समूह के अध्यक्ष मुकेश अंबानी भी मौजूद थे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उद्योगपति मुकेश अंबानी ने गुरुवार को गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के सातवें दीक्षा समारोह में हिस्सा लिया। एपी

सीबीआइ ने मांगी तृणमूल के तीन सांसदों पर केस चलाने की अनुमति

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में तृणमूल कांग्रेस के तीन मौजूदा व एक पूर्व सांसद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। इनमें मौजूदा सांसद सौगत राय (73), काकोली घोष (59), प्रसून बनर्जी (64) तथा पूर्व सांसद सुवेंदु अधिकारी (48) शामिल हैं। इस मामले के आरोपितों को पांच से सात साल की सजा हो सकती है।

राय दमदम, घोष बारासात तथा बनर्जी हावड़ा से सांसद हैं, जबकि अधिकारी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में मौजूदा परिवहन मंत्री और तामलुक लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं। सूत्रों ने बताया कि अगर जांच एजेंसी को अनुमति मिल जाती है तो वह अपने आरोप पत्र में इन चारों नेताओं का नाम शामिल कर लेगी। अधिकारियों ने बताया कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन तृणमूल के कुछ राजनीतिज्ञों और बंगाल शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित है। एक पत्रकार ने खुद को एक निजी कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए इस रिश्वतखोरी का पर्दाफाश किया था। हाई कोर्ट के आदेश पर करीब एक महीने लंबी चली जांच के बाद सीबीआइ ने चारों नेताओं को 16 अप्रैल 2017 को मुकदमे में नामजद किया था। सीबीआइ इस मामले में तृणमूल के सांसद व राज्य सरकार के मंत्रियों समेत 12 शीर्ष नेताओं और एक आइपीएस अधिकारी पर मुकदमा दर्ज कर चुकी है।

अधिकारी ने बताया कि एजेंसी इस मामले में तृणमूल के राज्यसभा सदस्य केडी सिंह से भी पूछताछ कर चुकी है। सीबीआइ को शक है कि सिंह ने उस खोजी पत्रिका में निवेश किया था, जिसने चारों तृणमूल नेताओं का स्टिंग ऑपरेशन किया था। वर्ष 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले नारदा के पत्रकार मैथ्यू सैमुएल ने स्टिंग के वीडियो को कई चैनलों पर प्रसारित किया। उन्होंने ही सीबीआइ को कथित रूप से राजनीतिज्ञों और बंगाल शासन के वरिष्ठ अधिकारियों का रिश्वत लेते हुए वीडियो सौंपा है।

सीबीआइ की रिपोर्ट के अनुसार, स्टिंग ऑपरेशन में निजी कंपनी के प्रतिनिधि बने पत्रकार से राय, घोष और अधिकारी पांच-पांच लाख रुपये तथा बनर्जी चार लाख रुपये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने रिश्वत की राशि नए कारोबार की स्थापना में मदद करने के एवज में ली।

18 करोड़ हुई भाजपा के सदस्यों की संख्या दिसंबर में होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव

- अभियान में लक्ष्य से तीन गुना ज्यादा सदस्य बनाने में मिली सफलता
- दुनिया के केवल सात देशों की जनसंख्या भाजपा सदस्यों से ज्यादा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा ने अब सदस्यों के मामलों में भी नया कीर्तिमान रच दिया है। 11 करोड़ सदस्यों के साथ पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी भाजपा सदस्यता अभियान में सात करोड़ नए लोगों को जोड़ने में सफल रही है। इसके साथ ही पार्टी के सदस्यों की संख्या 18 करोड़ हो गई। अब दुनिया के केवल सात देश- चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील और नाइजीरिया ही ऐसे हैं, जिनकी जनसंख्या भाजपा के सदस्यों की संख्या से ज्यादा है। सदस्यता अभियान पूरा हो जाने के बाद अब भाजपा में सभी स्तरों पर संगठनात्मक चुनावों का दौर शुरू हो जाएगा और सबसे अंत में दिसंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां छह जुलाई से 20 अगस्त तक चले सदस्यता अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी ने केवल दो करोड़ 20 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा था, लेकिन लक्ष्य से तीन गुना से भी अधिक नए सदस्य बनाने में सफलता मिली है। इस दौरान भाजपा की ऑनलाइन सदस्यता 5,81,34,242 रिकॉर्ड की गई, वहीं ऑफलाइन फॉर्म भरकर 62,34,967 नए सदस्य जुड़े हैं। इनमें कई स्थान ऐसे भी हैं, जहां सर्वर कमजोर था और मिस्ड कॉल को डिजिटली कैप्चर नहीं किया जा सका, उसे भी अब डिजिटली अपग्रेड किया जा रहा है। छह जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर अलग-अलग स्थानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष व गृहमंत्री अमित शाह तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया था।

नड्डा ने कहा कि आज भाजपा का विस्तार कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामाख्या तक हो गया है। यही नहीं, सदस्यता अभियान को देश के सभी वर्गों का साथ मिला और सदस्यता के आंकड़े इसके गवाह हैं। सेना के रिटायर्ड अधिकारी, खिलाड़ी, लेखक, बुद्धिजीवी वर्ग, युवा, महिलाओं सहित समाज के प्रतिष्ठित हस्तियों ने उत्साह के साथ बड़ी संख्या में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अब अलग-अलग राज्यों में संगठन चुनाव होंगे और दिसंबर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। माना जा रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा ही नए अध्यक्ष होंगे।

बंगाल में लक्ष्य से आठ गुना मिली सफलता, जम्मू–कश्मीर ने भी दिखाया उत्साह

नड्डा ने कहा कि बंगाल और जम्मू–कश्मीर जैसे राज्यों में भी भाजपा के प्रति लोगों में विशेष रुझान देखा गया। बंगाल में 10 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि यह आंकड़ा 80 लाख को पार कर गया है और अब एक करोड़ की ओर अग्रसर है। इसी तरह भारत–पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित जम्मू–कश्मीर के करना विधानसभा क्षेत्र के 6059 मतदाताओं ने एक साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। गुजरात के पाटन जिले के चाणस्मा नगर के 14 बूथ के सभी 10,600 मतदाताओं ने एक साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे हाई कोर्ट के चार मुख्य न्यायाधीश

- सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम केंद्र से इनके नाम की करेगा सिफारिश

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने शीर्ष अदालत में जज बनाने के लिए चार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के नाम की केंद्र से सिफारिश करने का फैसला किया है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के अध्यक्ष हैं। जिन नामों की सिफारिश करने का फैसला किया गया है उनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब व हरियाणा, राजस्थान और केरल के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं।

जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जबकि, जस्टिस कृष्ण मुरारी पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रविंद्र भट हैं। वहीं जस्टिस ऋषिकेश रॉय केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इन जजों की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो जाएगी, जो उसकी निर्धारित संख्या है। पहले सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 थी, जिसे केंद्र सरकार ने हाल ही में बढ़ाकर 34 कर दी थी, जिसमें प्रधान न्यायाधीश भी शामिल हैं।

समाचार एजेंसी आइएनएस के मुताबिक कोलेजियम ने केंद्र से इनके नामों की सिफारिश कर दी है। जस्टिस रामसुब्रमण्यम 22 जून, 2019 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। इससे पहले वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट में जज रहे थे। 30 जून, 1958 को पैदा हुए जस्टिस रामसुब्रमण्यम ने चेन्नई के विवेकानंद कॉलेज से विज्ञान में स्नातक और मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की थी।

नौ जुलाई, 1958 को पैदा हुए जस्टिस मुरारी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री लेने के बाद 22 साल तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत की थी। सात जनवरी, 2004 को उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज बनाया गया था। वह दो जून, 2018 को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। जस्टिस भट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा हासिल करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत से करियर की शुरुआत की थी। 1958 में पैदा हुए जस्टिस भट को 2004 में दिल्ली हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया था।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

यू टर्न लेते-लेते कहीं वह फिर से अध्यक्ष की कुर्सी पर न जा बैठें

बड़ा कदम

केंद्र सरकार ने देश में हरियाली बढ़ाने के लिए अपना खजाना खोल दिया है, फिलहाल राज्यों को धनराशि कैंपा फंड के तहत दी गई है

हरियाली बढ़ाने को राज्यों को 47 हजार करोड़

- केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जावडेकर ने दी मंजूरी, जारी की राशि
- कहा, 2030 तक ढाई से तीन सौ करोड़ टन अतिरिक्त कार्बन सिंक का लक्ष्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

हरियाली बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। राज्यों को इसके लिए 47 हजार करोड़ का विशेष पैकेज जारी किया है जो राज्यों को वनों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाले बजट के अतिरिक्त होगा। इसके तहत सबसे ज्यादा करीब छह हजार करोड़ की राशि अकेले ओडिशा को दी गई है, जबकि छत्तीसगढ़ को करीब 57 सौ करोड़ और मध्य प्रदेश को करीब 52 सौ करोड़ रुपये दिए गए। इसके साथ ही झारखंड को 41 सौ करोड़, उत्तराखंड को करीब 26 सौ करोड़ और उत्तर प्रदेश को करीब 18 सौ करोड़ रुपये दिए गए, जबकि बिहार को 522 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने गुरुवार को राज्यों के वन एवं पर्यावरण मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इस पैकेज का एलान किया। साथ ही सभी 27 राज्यों को यह राशि जारी भी कर दी गई है। फिलहाल राज्यों को यह राशि कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी (कैंपा) के तहत दी गई है। यह राशि विकास योजनाओं में नष्ट होने वाले जंगलों की भरपाई के लिए संबंधित एजेंसियों की ओर से जमा कराई जाती है। यह पैसा बाद में केंद्र की ओर से राज्यों को वन क्षेत्र को बढ़ाने सहित पर्यावरण से जुड़ी दूसरी गतिविधियों को संचालित करने के लिए दिया जाता है। खास बात यह है कि कैंपा के तहत राज्यों की दी गई राशि का इस्तेमाल सिर्फ वनीकरण पर ही खर्च किया जा सकता है। वेतन भुगतान, यात्रा भत्ते, चिकित्सा व्यय आदि जरूरतों के लिए इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है।

केंद्रीय मंत्री ने इसके साथ ही राज्यों को कार्बन सिंक के लक्ष्य की भी जानकारी दी। इसके तहत 2030 तक ढाई से तीन सौ करोड़ टन कार्बन डाइआक्साइड का अवशोषण का लक्ष्य रखा गया है। इस पूरी कवायद को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। मंत्रालय के मुताबिक इस राशि का जिन कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है, उनमें क्षतिपूरक वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र में सुधार, वन्यजीव प्रबंधन, वनों में लगने वाली आग की रोकथाम, वन में मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण कार्य, जैव विविधता तथा वन अनुसंधान आदि शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार देश में वन क्षेत्रफल में इजाफे के लिए तमाम प्रयास कर रही है। इसी क्रम में नई योजनाएं पेश की जा रही हैं।

प्रमुख राज्य और उन्हें दी गई राशि (रुपये में)

राज्य	राशि
उत्तर प्रदेश	1819 करोड़
झारखंड	4158 करोड़
उत्तराखंड	2675 करोड़
हिमाचल प्रदेश	1660 करोड़
मध्य प्रदेश	5196 करोड़
छत्तीसगढ़	5791 करोड़
हरियाणा	1282 करोड़
पंजाब	1040 करोड़
बिहार	522 करोड़
पश्चिम बंगाल	236 करोड़

5 लाख रुपये का जुर्माना और दो साल की सजा का प्रावधान किया गया है हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन करने पर पकड़े जाने पर। राज्य में बढ़ रहे अवैध खनन को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने नियम सख्त किए हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 30 अगस्त 2019

सपा सांसद आजम खां पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

मुस्लेमीन, रामपुर

- जमीन कब्जाने और किताबें चोरी के मामले में अग्रिम जमानत याचिका हो चुकी है खारिज
- डकैती, गैर इरादतन हत्या, हत्या के प्रयास जैसी संगीन धाराओं में भी मुकदमे दर्ज हो गए

जमीन कब्जाने और किताब चोरी के 29 मामलों में जमानत खारिज होने के बाद सपा सांसद आजम खां मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने अब उनके खिलाफ डकैती के चार मुकदमे भी दर्ज कर लिए हैं। एक मामले में महिला की गैर इरादतन हत्या का भी आरोप है। इसके अलावा उनके भाई और बेटे पर भी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें भी आजम नामजद हैं। इस बार उनके खिलाफ संगीन धाराएं लगी हैं। इसलिए उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

लोकसभा चुनाव के दौरान ही आजम खां के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए थे। आचार संहिता उल्लंघन और आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में उनके खिलाफ रामपुर के विभिन्न थानों में 15 मुकदमे दर्ज कराए गए, जबकि एक मामला कानपुर की मेयर ने दर्ज कराया। इन सभी मुकदमों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भी दर्ज है केस : लोकसभा चुनाव के बाद आजम के खिलाफ जमीन कब्जाने के आरोप में 30 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दो और किताब चोरी के आरोप में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है।

चुनाव से पहले 10 और बाद में 54 मुकदमे हुए दर्ज : जमीने कब्जाने के 28 और किताब चोरी के एक मामले में बुधवार को अदालत ने आजम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अगले दिन ही उन पर डकैती के चार मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर ली। इनमें एक मामले में हत्या का भी आरोप है। आजम के खिलाफ चुनाव के दौरान से अब तक 54 मुकदमे थानों में दर्ज हो चुके हैं, जबकि 10 मुकदमे चुनाव से पहले के हैं।

आजम खां फाइल

सांसद आजम खां के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। 29 मामलों में जिला जज की अदालत से उनकी अग्रिम जमानत भी खारिज हो चुकी है। इसके अलावा डकैती और गैर इरादतन हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों में भी उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। इनमें उनकी गिरफ्तारी भी संभव है।
डॉ. अजय पाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक

डकैती और हत्या के चार नए केस हुए दर्ज

जागरण संवाददाता, रामपुर

- तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खां पर भी आई आंच

उत्तर प्रदेश पुलिस ने सपा सांसद आजम खां पर हत्या और डकैती के चार और मुकदमे दर्ज किए हैं। उन पर पहले ही 60 मुकदमे दर्ज हैं। चार नए मुकदमे दर्ज होने से सांसद की मुश्किलें बढ़नी तय हैं।

रामपुर निवासी नन्ने ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि 15 अक्टूबर 2016 को तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खां, एसओजी सिपाही धर्मेंद्र, ठेकेदार इस्लाम, वीरेंद्र गोयल, फसाहत अली खां शानू व 20-30 अन्य लोग उनके घर पर आए और कहा कि यह जगह आजम खां ने ले ली है। यहां उनका स्कूल बनना है। फौरन यह जगह खाली कर दो, वर्ना फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिए जाओगे। नन्ने ने बताया कि इन लोगों ने हमें बुरी तरह मारा-पीटा। महिलाओं के भी कपड़े फट गए। उनके घर में रखा सामान, चार तोले सोने के जेवर और दो हजार रुपये भी लूट लिए। इसके बाद घर पर बुलडोजर चलवा दिया।

मां को पीटकर घायल किया, दो दिन बाद हुई मौत

नन्ने के मुताबिक, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और धमकाकर थाने से भगा दिया। इसी तरह मन्ने, मुबारक अली, आसिफ अली ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई है। आसिफ का आरोप है कि उनकी मां को पीटकर घायल कर दिया, जिससे उनकी दो दिन बाद मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक डॉ. अजय पाल शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट जांच पड़ताल के बाद दर्ज की गई हैं। विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

विपक्षियों की धुलाई को भाजपा के पास गुजरात का वाशिंग पाउडर : दानवे

- केंद्रीय मंत्री ने गुजरात से आए मोदी और शाह के नेतृत्व की तारीफ की

मुंबई, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रमुख अमित शाह की ओर इशारा करते हुए केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने कहा कि भाजपा के पास 'गुजरात का वाशिंग पाउडर' है जो पार्टी में शामिल होने से पहले कांग्रेस और राकांपा के नेताओं की धुलाई करता है।

दानवे ने गुजरात से आए मोदी और शाह के नेतृत्व के गुणों का बखान करते हुए कहा कि भाजपा के पास एक वाशिंग मशीन है जो दूसरे दल से आए नेताओं को उस मशीन में डालकर साफ कर देती है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के पास गुजरात का वाशिंग पाउडर भी है। उल्लेखनीय है कि विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं कि अन्य दलों के भ्रष्ट नेता भी भाजपा में आकर सही हो जाते हैं।

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उनके चुनाव क्षेत्र जालना में एक रैली को संबोधित करते हुए दानवे ने राकांपा पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस महाजनादेश यात्रा कर रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं। दूसरी तरफ राकांपा की रैली है जिसमें 'अंतिम यात्रा' निकाली जा रही है। लोग प्रायः शव यात्रा में जरूर शामिल होते हैं, लेकिन राकांपा की रैली में तो पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता भी शामिल होने से बच रहे हैं।

रावसाहेब दानवे फाइल

उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री दानवे के हमलों का राकांपा नेता धनंजय मुंडे ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री दानवे ठीक कह रहे हैं। राकांपा की यात्रा दरअसल असंवेदनशील और किसान विरोधी भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार की अंतिम यात्रा है। उन्होंने कहा कि मैं दानवे की गलती सुधारना चाहता हूं। लोग शिवस्वराज यात्रा में राज्य सरकार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

न्यूज गैलरी

उप्र में राज्यसभा की दो सीटों पर उप चुनाव अगले माह 23 को

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की उन दो सीटों के लिए उप चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है, जो समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर व संजय सेठ के इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई थीं। दोनों नेताओं ने सपा से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। दोनों का कार्यकाल वर्ष 2022 तक था, लेकिन उन्होंने पहले ही राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि इन दोनों ही सीटों पर मतदान 23 सितंबर को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक होगा। इन सीटों के लिए 12 सितंबर को नामांकन पत्र भरा जाएगा। 13 को नामांकन पत्र की जांच होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 16 सितंबर होगी। 23 सितंबर को ही पांच बजे से वोटों की गिनती की जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। (जाब्यू)

योगी पर टिप्पणी में खुर्शीद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

फर्रुखाबाद : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दिया विवादित बयान 'रिश्ते में तो हम उनके बाप लगते हैं' पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की मुसीबत बन गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है। खुर्शीद ने लोकसभा चुनाव के दौरान बतौर कांग्रेस प्रत्याशी यह बयान दिया था। उस वक्त यह बयान मीडिया की सुर्खियों में रहा था। इसको लेकर शहर कोतवाली के शिवनगर कॉलोनी निवासी भाजपा समर्थक अनूप मिश्र ने खुर्शीद के खिलाफ वर्ग विशेष की भावनाएं भड़काने व आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने जांच के बाद पांच अगस्त को सलमान खुर्शीद के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मानकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने एफआइआर दर्ज होने के बाद अपने जूनियर वकीलों संग पत्रकार वार्ता कर मुकदमे की धाराओं पर आपत्ति जताई थी। उनका दावा था कि बयान में कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। उन्होंने मामले को उच्च न्यायालय ले जाने की चेतावनी भी दी थी। (जासं)

अतीक से गुजरात में पूछताछ करेगी सीबीआइ

देवरिया : जिला कारागार में लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी की पिटाई मामले की जांच कर रही सीबीआइ जल्द ही बाहुबली अतीक से पूछताछ करने गुजरात जाएगी। अतीक इस समय गुजरात की जेल में बंद है। सीबीआइ ने अतीक के नजदीकी रहे देवरिया जिले के कुछ लोगों का डिटेल भी खंगाला है। उनसे भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। जिला कारागार में निरुद्ध रहने के दौरान अतीक के बैरक से मई 2018 में डीएम व एसपी की छापेमारी में मोबाइल फोन, पेन ड्राइव समेत कई अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुए थे। अब सीबीआइ इन सामानों को भी अपने कब्जे में लेकर जांच करेगी। यह भी जांचेगी कि वह मोबाइल किसका है। (जासं)

ईडी ने हुड्डा के करीबियों के 14 प्लॉट किए अटैच

कार्रवाई ▸ हरियाणा के पूर्व सीएम ने 2012 में आवंटित किए थे पंचकूला में प्लॉट

30 करोड़ 34 लाख रुपये के हैं प्लॉट, मनी लांड्रिंग के मामले में की गई कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की लड़ाई में उलझे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदेश की सियासत में टकराव को शांत करने के इरादे से गुरुवार को हुड्डा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने गए थे। वहीं, दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंचकूला के औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में उन सभी 14 प्लॉटों को अटैच कर दिया, जिन्हें हुड्डा ने अपने संबंधियों, जान पहचान के लोगों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों को आवंटित किया था। 30 करोड़ 34 लाख रुपये कीमत के ये प्लॉट मनी लांड्रिंग मामले में अटैच किए गए हैं। ईडी ने अपने ट्विटर हेंडल पर इस कार्रवाई की पुष्टि की है।

जनवरी-2012 में किए गए थे अलॉट: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने पंचकूला में औद्योगिक प्लॉट जनवरी-2012 में अलॉट किए थे। मुख्यमंत्री एचएसवीपी के पदेन चेयरमैन होते हैं। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के नाते एचएसवीपी के चेयरमैन थे। आरोप है कि उन्होंने अपने करीबियों और चहेतों को औद्योगिक प्लॉट अलॉट किए। नियमों के साथ न केवल छेड़छाड़ की गई, बल्कि उन्हें अलॉटियों के हिसाब से बदला भी गया। यह प्लॉट 496 वर्गमीटर से लेकर 1280 वर्गमीटर साइज के थे। प्राधिकरण ने प्लॉट आवंटन के लिए पहले आवेदन मांगे गए थे। कुल 582 आवेदन आए थे। इनमें से ही 14 का चयन किया गया।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा फाइल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने यह केस स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दिया और उसकी रिपोर्ट पर सीबीआइ के हवाले कर दिया। सीबीआइ ने प्रारंभिक जांच के बाद 19 दिसंबर, 2015 को केस दर्ज किया। बाद में ईडी ने भी केस दर्ज किया।

इन करीबियों को आवंटित हुए थे प्लॉट : हुड्डा के अधिकतर करीबियों को प्लॉट आवंटित हुए थे। इनमें हुड्डा के ओएसडी रहे बीआर बेरी की पुत्रवधू मोना बेरी, पूर्व सीएम के सचिव रहे राम सिंह के बेटे प्रदीप कुमार, थानेसर से पूर्व विधायक रमेश गुप्ता के बेटे अमन गुप्ता, वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे नरेंद्र हुड्डा की पत्नी नंदिता हुड्डा, मनजोत कौर, सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल रहे रोहतक निवासी सुनील कत्याल के बेटे डागर कत्याल, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के करीबी ओपी दहिया शामिल थे। हुड्डा परिवार की नजदीकी रेणु हुड्डा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति रहे डीडीएस संधू के पारिवारिक सदस्य कंवरप्रीत सिंह संधू, संजीव भारद्वाज के बेटे सिद्धार्थ भारद्वाज की कंपनी, पीजीआइ चंडीगढ़ में ईएनटी के प्रोफेसर रहे डॉ. गणेश दत्त को भी प्लॉट आवंटित किए गए।

सोनिया गांधी ने दी हुड्डा को गुटबाजी दूर करने की नसीहत

बिजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

- 10 जनपथ पर हुई हुड्डा और सोनिया गांधी की मुलाकात

हरियाणा कांग्रेस की कमान अब अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं मिलेगी। गुरुवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुड्डा की मुलाकात के दौरान यह लगभग साफ हो गया। सोनिया ने स्पष्ट नसीहत दी कि पहले प्रदेश कांग्रेस के नेता गुटबाजी दूर करें।

10 जनपथ पर सोनिया गांधी के साथ हुड्डा की करीब आधे घंटे की मुलाकात के दौरान पार्टी के हरियाणा प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर को हटाने की जिद पर अड़े हुड्डा ने मुलाकात के बाद मीडिया से कोई बात नहीं की। उनके चेहरे पर खुशी के भाव नहीं थे। हुड्डा सीधे अपने 9 पंत मार्ग स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने नजदीकी कुछ नेताओं से मंत्रणा की और फिर शाम तक कई अन्य बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात का सिलसिला जारी रहा।

आलाकमान की तरफ से ही होगी गुटबाजी दूर करने की पहल : हुड्डा समर्थक कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल ने कहा कि पार्टी नेताओं की गुटबाजी दूर करने संबंधी प्रस्ताव तो रोहतक की परिवर्तन महारैली में पारित किया जा चुका है। सोनिया गांधी ने हुड्डा के इस प्रस्ताव को एक तरह से मंजूरी दी है और अब आलाकमान की तरफ से ही नेताओं के बीच समन्वय बनाने की दिशा में पहल की जाएगी। पार्टी सूत्र बताते हैं कि हुड्डा आलाकमान द्वारा नेताओं गुटबाजी दूर करने की पहल के लिए भी ज्यादा समय इंतजार नहीं करेंगे। माना जा रहा है कि शुक्रवार नई दिल्ली में राज्य कांग्रेस के सभी नेताओं के बीच प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी का संदेश रखेंगे।

सामूहिक नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस : राज्य में होने वाला विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी नेताओं के सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ेगी। अकेले हुड्डा को प्रदेश कांग्रेस की कमान दिया जाना अब संभव नहीं है। पार्टी सूत्र यह जरूर मानते हैं कि हुड्डा को चुनाव के दौरान पार्टी का बड़ा चेहरा रखा जाएगा मगर हुड्डा के साथ अशोक तंवर, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी, कुमारी सैलजा, कैप्टन अजय यादव, महेंद्र प्रताप सिंह को भी संगठन में अहम स्थान दिया जाएगा।

रोहतक रैली के बाद तंवर ने अपनाया है कड़ा रुख : हुड्डा की रोहतक रैली के बाद प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर ने अब कड़ा रुख अपनाया हुआ है। उन्होंने बीते दिनों यहां तक कह दिया कि हुड्डा जितना जोर उन्हें हटाने में लगा रहे हैं, यदि इतना जोर भाजपा को उखाड़ने में लगाया होता तो कांग्रेस सरकार बनाने के नजदीक होती।

नैनीताल में मान्य नहीं होगा टैक्सियों का ऑल इंडिया परमिट : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नैनीताल : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि टैक्सियों का ऑल इंडिया परमिट नैनीताल में मान्य नहीं होगा। कोर्ट ने शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए 25 सीटर क्षमता से अधिक वाले वाहनों को प्रवेश न देने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही नैनीताल में पर्यटकों की सुविधा के लिए ट्रैफिक नियंत्रित करने, इसके लिए आइआइटी दिल्ली की सलाह लेने व अवैध रूप से भवनों का निर्माण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के ताजा आदेश से शहरवासियों में खलबली मचना तय है।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने नैनीताल निवासी पर्यावरणविद प्रो. अजय रावत की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अनिल जोशी को छूट दी है कि आदेश की अवहेलना होने पर कोर्ट को अवगत करा सकते हैं। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए कि आदेश की एक कॉपी डीएम नैनीताल को आवश्यक कार्रवाई के लिए उपलब्ध कराएं। इस आदेश से नैनी झील के कैचमेंट एरिया यानी सूखाताल झील के अस्तित्व में आने की उम्मीद जग गई है।

कोर्ट ने आदेश में कहा है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ कमेटी की ईको-सेंसेटिव जोन की संस्तुति करने संबंधी निर्देश मंत्रालय दे सकता है। याचिका में इसकी मांग की गई थी।

10 और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को निजी हाथों को सौंपेगा रेलवे

नई दिल्ली, प्रेट्र : मुंबई-अहमदाबाद के अलावा देश के दस और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को रेलवे ने निजी हाथों को सौंपने के लिए चिह्नित किया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने गुरुवार को कहा कि रेलवे की 508 किलोमीटर लंबी मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन परियोजना का कार्य बिना रुकावट तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों के बीच टक्कर को रोकने के लिए रेलवे अगले पांच वर्षों में अपनी पूरी सिग्नल प्रणाली को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया में जुटा है। इसमें ट्रेनों की टक्कर रोधी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 70 हजार किलोमीटर लंबे भारतीय रेलवे के नेटवर्क की सिग्नल प्रणाली अभी भी आधुनिक नहीं है। ट्रेनों का परिचालन निजी हाथों को सौंपने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पहली बार हम दिल्ली-लखनऊ मार्ग की तेजस ट्रेन को आइआरसीटीसी को सौंप रहे हैं।

मुंबई-दिल्ली, दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर 160 की रफ्तार से चलेंगी ट्रेनें : उन्होंने कहा कि हमने पूरे रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की योजना बनाई है। 15 दिनों पहले कैबिनेट ने मुंबई-दिल्ली और दिल्ली-हावड़ा मार्ग को 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों के संचालन के लायक बनाने की योजना को हरी झंडी दी। हम इस परियोजना को अगले चार वर्षों में पूरा कर लेंगे।

अंतर्कलह घटी तो पनपने लगा बिहार कांग्रेस में असमंजस

एसए शाद, पटना

- सबसे बड़ी दुविधा राजद के साथ रहें या अकेले लड़ें चुनाव
- संगठन विस्तार के लिए अबतक नहीं बन सकी कार्य योजना

पिछले दो दशक से अंतर्कलह से परेशान रही बिहार कांग्रेस अब एक नई समस्या से ग्रस्त हो गई है। पार्टी में 'असमंजस' पनपने लगा है। सबसे बड़ी दुविधा राजद को लेकर है। पार्टी नेता यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस को राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है या अकेले ही आगे बढ़ना है। ऐसे मसलों पर प्रदेश अध्यक्ष का स्पष्ट रुख सामने नहीं आने के कारण वरिष्ठ नेताओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसकी झलक दो दिन पूर्व पार्टी की सलाहकार समिति की बैठक में साफ दिखाई दी।

प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा की उपस्थिति में हुई इस बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने के उपाय ढूंढ़ने से अधिक वरिष्ठ नेता इस बात पर उलझे रहे कि पार्टी को राजद के साथ तालमेल करना चाहिए या नहीं। लेकिन कोई एक राय नहीं बन पाई। केवल तालमेल ही नहीं, बल्कि संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान, अन्य दलों से आए नेताओं और चुनाव के दौरान पार्टी से निलंबित किए गए नेताओं को लेकर भी असमंजस की स्थिति है। सूत्रों ने बताया कि इस असमंजस के कारण ही यह तय नहीं हो पा रहा कि सभी 243 सीटों पर संगठन को लेकर सक्रियता बनाई जाए या उन सीटों पर ही फोकस किया जाए जिनपर पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में लड़ी थी। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 41 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इस वर्ष लोकसभा चुनाव के समय शत्रुघ्न सिन्हा, पप्पू सिंह, तारिक अनवर जैसे दूसरे दल के कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा था, मगर चुनाव में उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। प्रदेश नेतृत्व अभी तय नहीं कर पा रहा है कि बाहर से आए इन नेताओं को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए या पुराने कांग्रेसियों को सक्रिय किया जाए। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवारों में सिर्फ कांग्रेस के डॉ. मु. जावेद किशनगंज से विजयी हुए थे। इसे आधार मान कांग्रेस विधानमंडल के नेता सदानंद सिंह कांग्रेस को राजद से बड़ी पार्टी बता रहे हैं। हालांकि राजद के पास सबसे अधिक 80 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास मात्र 27 विधायक ही हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए पूर्व मंत्री डॉ. शकील अहमद और विधायक भावना झा को कांग्रेस से निलंबित किया था। इस मामले में भी प्रदेश कांग्रेस में असमंजस की स्थिति है।

भाकपा, तृणमूल और राकांपा के राष्ट्रीय दल के दर्जे पर खतरा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को चुनाव आयोग ने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अगले महीने बुलाया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

आयोग ने तीनों दलों को पहले नोटिस जारी कर पूछा था कि लोकसभा चुनाव में उनके प्रदर्शन के बाद उनका राष्ट्रीय दल का दर्जा क्यों न वापस ले लिया जाए। आयोग के इस नोटिस के बाद राकांपा, तृणमूल और भाकपा के सामने राष्ट्रीय दल का दर्जा खो जाने की आशंका पैदा हो गई है।

सूत्रों ने बताया कि नियमों के अनुसार तीनों दलों को नौ सितंबर को चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष पेश करने का मौका दिया गया है। इस महीने के प्रारंभ में तीनों ने नोटिस का जवाब दिया था और राष्ट्रीय पार्टी के अपने दर्जे का बचाव किया था। भाकपा ने कहा कि कांग्रेस के बाद देश में वह सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है जो लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल रह चुकी है। भले ही उसने हाल के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो लेकिन वह कई राज्यों में सत्ता में रही है और संविधान को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। सूत्रों के मुताबिक, तृणमूल ने कहा है कि उसे 2014 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया और कम से कम 2024 तक यह दर्जा जारी रहना चाहिए।

आम कारोबारी एफडीआइ में छूट से होंगे तबाह : कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अर्थव्यवस्था की मंदी को लेकर सरकार पर लगातार प्रहार कर रही कांग्रेस ने अब विदेशी कंपनियों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के नियमों में रियायत देने को लेकर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि विदेशी कंपनियों को एफडीआइ नियमों में भारी छूट देकर भाजपा सरकार ने करीब तीन करोड़ दुकानदारों और व्यापारियों के साथ उनके यहां काम करने वाले 15 करोड़ लोगों के हित पर सीधे चोट किया है। पार्टी ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा है कि सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी कंपनियों के लिए छूट की घोषणा कर मोदी सरकार ने आम कारोबारियों की तबाही का रास्ता खोल दिया है।

कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने बयान जारी कर कहा है कि सरकार के फैसले से विदेशी कंपनियों की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है। एफडीआइ नियमों में रियायत के बाद विदेशी कंपनियां भारत में सिंगल ब्रांड रिटेल का अपना आउटलेट खोलने से दो साल पहले ही ऑनलाइन बिक्री करनी शुरू कर देंगी। उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियां आउटलेट बनाती तो हमारे यहां जमीन, भवन निर्माण, किराए से लेकर स्टोर से जुड़े रोजगार के अवसर पैदा होते। मगर अब विदेशी कंपनियां ऑनलाइन ही 130 करोड़ के भारत के विशाल बाजार में अपना माल सीधे बेच सकेंगी। अभी तक कंपनियों को आउटलेट खोलने के बाद ही ऑनलाइन बिक्री की इजाजत थी।

सुरजेवाला ने कहा कि सिंगल ब्रांड रिटेल में 30 फीसद लोकल सोर्सिंग के नियम में ढील भी विदेशी कंपनियों के फायदे के लिए दी गई है। निर्यात के लिए खरीद को भी लोकल सोर्सिंग में शामिल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब जरूरी नहीं होगा कि जो सामान आप भारत में बेच रहे हों, वह यहीं से खरीदा जाए। विदेशी कंपनियां भारत में 100 फीसद आयातित माल बरोक-टोक बेच सकेंगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि हैरान करने वाली बात यह है कि मोदी सरकार ने लोकल सोर्सिंग की हर साल समीक्षा करने की बजाए पांच साल में इसकी व्यवस्था कर दी है। इस वजह से विदेशी सिंगल-ब्रांड रिटेलरों से करीब सात साल तक लोकल सोर्सिंग के बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकेगा। इसका नुकसान छोटे-मझोले उपक्रमों, ग्रामीण उद्योगों व कारीगरों को होगा जो अभी तक लागू 30 फीसद लोकल सोर्सिंग के नियमों की वजह से कारोबार कर रहे हैं। नए उदार नियम से छोटे-मझोले कारोबारियों को आघात लगना तय है और बदलाव का सबसे बड़ा फायदा विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को होगा। इन कंपनियों का भारत के खुदरा व्यापार पर कब्जा हो जाएगा।

जमीनी हकीकत

छत्तीसगढ़ में 2018–19 में कुपोषण मुक्ति पर खर्च किए गए 454 करोड़, फिर भी हालात अच्छे नहीं

रोज एक करोड़ से ज्यादा खर्च फिर भी पांच लाख बच्चे कुपोषित

संजीत कुमार, रायपुर

छत्तीसगढ़ में कुपोषण की जंग में बीते वित्तीय वर्ष (2018-19) में करीब 454 करोड़ रुपये खर्च किए गए। प्रतिदिन एक करोड़ से ज्यादा रुपये खर्च करने के बावजूद प्रदेश में करीब पांच लाख बच्चे कुपोषित रह गए हैं।

सरकार ने पूरक पोषण आहार पर करीब चार लाख रुपये से अधिक प्रतिदिन खर्च किए। इससे बच्चों को मीठा और पौष्टिक दूध पिलाया गया। इस दौरान जनजागरुकता के लिए सुपोषण चौपाल सहित अन्य आयोजनों पर करीब 12 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके बाद जब इस वर्ष कुपोषित बच्चों की खोज शुरू हुई तो पांच लाख से अधिक बच्चे इसके शिकार मिले। पांच वर्ष से कम उम्र के 37.60 फीसद बच्चे कुपोषित मिले। 15 से 49 वर्ष की 41.50 फीसद बेटियां एवं माताओं में खून की कमी मिली।

बिलासपुर में सर्वाधिक 35 हजार कुपोषित: बिलासपुर में कुपोषण का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। यहां 35 हजार से अधिक बच्चे कुपोषित मिले हैं। इनमें 102 विशेष संरक्षित जनजाति (पहाड़ी कोरवा) बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि, जनसंख्या की तुलना में कुपोषित बच्चों का औसत राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में अधिक है। राज्य में फरवरी 2019 में हुए वजन त्योहार से यह आंकड़ा निकलकर आया है। सरकार कुपोषण की जांच के लिए वजन त्योहार का आयोजन करती है। वर्ष 2018-19 में फरवरी 2019 में आयोजित वजन त्योहार के दौरान राज्य में कुल चार लाख 92 हजार 176 बच्चे कुपोषित मिले हैं।

37.60 फीसद पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे कुपोषित

41.50 फीसद 15 से 49 वर्ष की बेटियां और माताएं एनीमिया से पीड़ित

35000 से अधिक बच्चे बिलासपुर में कुपोषित हैं। इनमें 102 विशेष संरक्षित जनजाति के हैं

छग सरकार ने पूरक पोषण आहार पर करीब चार लाख से अधिक प्रतिदिन खर्च किए। प्रतीकात्मक

कुपोषण नियंत्रण पर खर्च की गई राशि

योजना	खर्च की गई राशि
सुपोषण चौपाल	9,93,04,276
महतारी जनत योजना	2,19,97,477
वजन त्योहार व अन्य	2,69,70,816
मुख्यमंत्री अमृत योजना	14,38,09,718
पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	4,05,05,17,351
कुल व्यय	4,54,05,76,938

(नोट– आंकड़े फरवरी 2019 तक के)

जनमत मुद्दा

क्या गुणवत्ता से भरपूर मोटे अनाजों के प्रति हमारी नकारात्मक और अज्ञान सोच ने देश को सुपोषण से वंचित रखा है?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। MUDDA लिखें, स्पेस देकर YES या NO लिखकर 57272 पर भेजें।

मिड डे मील में भेदभाव वाले वीडियो पर मायावती का ट्वीट

जागरण संवाददाता, बलिया

- वीडियो में दिखाया गया, उच्च जाति के बच्चे लाते बर्तन और अलग करते भोजन
- डीएम ने की जांच, कहा– विद्यालय की ओर से नहीं किया गया भेदभाव

उत्तर प्रदेश के बलिया में प्राथमिक विद्यालय रामपुर नंबर-एक पर मिड डे मील मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर इस भेदभाव को खेदपूर्ण बताया और भेदभाव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। यह मामला 27 अगस्त का बताया जा रहा है।

वायरल वीडियो के मुताबिक, स्कूल में उच्च जाति के कुछ छात्र अपने घर से बर्तन लाकर अनुसूचित जाति के बच्चों से अलग बैठकर खाते हैं। ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर देख मायावती ने ट्वीट कर खलबली मचा दी है। स्कूल के एक छात्र ने पूछने पर बताया कि वह घर से खाने का बर्तन लाता है। स्कूल में जिस प्लेट में खाना दिया जाता है, उसमें सभी बच्चे खाते हैं। वह उसमें नहीं खा सकते।

जांच में जातिगत भेदभाव गलत : जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत गुरुवार को मामले की जांच करने विद्यालय पर पहुंचे। वहां उन्होंने सभी बच्चों से बातचीत की। छात्रों की उपस्थिति आदि भी देखी। बच्चों ने बताया कि सभी एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इस विद्यालय में 42 बच्चों का नामांकन है। इसमें मंगलवार को सिर्फ 18 बच्चे थे। जिलाधिकारी ने बताया कि मामले की गहन जांच के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट समस्त छात्रों के अभिभावकों से भी बातचीत करेंगे।

स्कूल की ओर से भेदभाव नहीं : स्कूल के प्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम कुमार गुप्त ने बताया कि बच्चों के अलग बैठकर खाना खाने की बात सच है, लेकिन स्कूल की ओर से भेदभाव नहीं किया जाता है। विद्यालय में सभी से समान व्यवहार होता है। बीएसए सुभाष गुप्ता ने बताया कि जांच में कोई भेदभाव नहीं पाया गया।

1500 के करीब नेता हिरासत या नजरबंद हैं जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से। इनमें दो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं।

कश्मीरी नेताओं के बदले एजेंडों से अवाम का किनारा

नवीन नवाज, श्रीनगर

बदली परिस्थितियों में स्थानीय सियासतदानों ने अपना पैंतरा बदल लिया है। पहले ऑटोनामी और सेल्फ रूल जैसे मुद्दों पर सियासत करने वाले नेता अब स्टेटहुड और अनुच्छेद-370 की बहाली के नाम पर डोरे डाल रहे हैं, लेकिन आम कश्मीरी अब उनके पीछे चलने को तैयार नहीं नजर आ रहा। वह आतंक का खात्मा और अमन चाहता है।

गत पांच अगस्त को जम्मू- श्मीर में अलग संविधान और अलग निशान की व्यवस्था समाप्त हो गई। मुख्यधारा की सियासत करने वाले क्षेत्रीय दलों के नेता परोक्ष रूप से अलगाववादियों की जमात में खड़े रहकर ब्लैकमेल की सियासत करते थे, ताकि सत्तासुख लेते रहें। नेशनल कांफ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स कांफ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट समेत कश्मीर केंद्रित सियासत करने वाले मुख्यधारा के सभी राजनीतिक दलों ने ऑटोनामी, सेल्फ रूल, अचीवेबल नेशनहुड और खुद मुख्तारी जैसे एजेंडों को आगे बढ़ाते हुए आम लोगों को गुमराह किया। अब भी उनका मकसद वही है। बताया जा रहा है कि नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने अपने चंद मिलने वालों से कहा है कि हमें जम्मू-कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा दिलाने के लिए मूवमेंट खड़ी करनी होगी। नेकां सांसद अकबर लोन कह रहे हैं कि कश्मीरियों को बाहर आने का मौका मिलने दो, फिर पता चलेगा। निशात करालसंगरी में अपने घर में नजरबंद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के संरक्षक मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि जो हुआ गलत हुआ है। केंद्र शासित राज्य में विधानसभा की हैसियत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कुछ ही ज्यादा होगी। इसलिए ऐसी विधानसभा का सदस्य बनना गंवारा नहीं कर सकता। उन्होंने तो सक्रिय राजनीति छोड़ने तक की बात कही, लेकिन इस पर जोर दिया कि अवाम को पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए खड़ा होना चाहिए।

डल झील स्थित सेंटूर होटल में बंद जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के चेयरमैन और पूर्व आइएएस अधिकारी शाह फैसल से मिलने के बाद उनके एक समर्थक ने कहा कि हमारे नेता को यह बदलाव मंजूर नहीं है। हमने अदालत का सहारा लिया है। हम राज्य का दर्जा बहाल कराने के साथ ही अनुच्छेद-370 को वापस लेकर रहेंगे।

हकीकत नहीं समझ रहे : कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ मुख्तार अहमद का कहना है कि इन नेताओं को अभी तक हकीकत समझ में नहीं आई है। अगर ऑटोनामी और सेल्फ रूल इनका एजेंडा था तो अब उससे पीछे हटते क्यों नजर आ रहे हैं, क्यों लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र शासित राज्य की विधानसभा की कोई हैसियत नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधि ही कानून बनाएंगे और वही कानून बनाएंगे जो राज्य के लिए बेहतर होंगे। दरअसल, ये नेता आज सदमे में हैं। ये खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए लोगों को गुमराह कर अपनी दुकान और सियासत को बचाना चाहते हैं। लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए जनांदोलन की सलाह दे रहे हैं। मुख्तार कहते हैं कि अगर लोग इन नेताओं के एजेंडे के साथ चलने वाले होते तो आज प्रशासनिक पाबंदियों के बावजूद पूरा कश्मीर जल रहा होता। केंद्र सरकार ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि वह जम्मू-कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रयासरत है।

दुआ करो कि यहां कोई अब गुमराह न हो

उदारवादी हुर्रियत के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के राजौरीकदल स्थित पुश्तैनी मकान के बाहर चौक में खड़े आसिफ बाबा कहते हैं कि 70 सालों से यहां ऑटोनामी, रायशुमारी, सेल्फ रूल के नाम पर कई लोगों ने वोट मांगे तो कुछ ने आजादी के नाम पर यहां कब्रिस्तान बनवा डाले। दुआ करो कि अब कोई गुमराह न हो, वरना युवा पहले भी मारा गया और फिर खाली हाथ मारा जाएगा। बुजुर्ग मुहम्मद रफीम ने कहा कि कश्मीर में कुछ नया होने वाला है। अब यहां आतंक का नामोनिशान मिट जाएगा।

उर्मिला मांतोडकर को सताई सास-ससुर की चिंता

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- कहा, अनुच्छेद 370 हटाना सही, पर तरीका गलत
- कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकीं सिने अभिनेत्री

कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकीं सिने अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को कश्मीर में रह रहे अपने सास-ससुर की चिंता सताने लगी है। इसका जिक्र उन्होंने गुरुवार को नांदेड़ में कांग्रेस की एक सभा में किया।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण के गृह जनपद नांदेड़ में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों के जीवन में सुधार होगा, वहां विकास होगा, यह अच्छी बात है, लेकिन सरकार का तरीका ठीक नहीं है। इस दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण भी मंच पर मौजूद थे।

उर्मिला ने आगे कहा कि प्रश्न केवल अनुच्छेद 370 हटाने का नहीं है, बल्कि इसे हटाने के तरीके का भी है। उर्मिला ने इसे अमानवीय करार देते हुए कहा, 'मेरे सास-ससुर कश्मीर में रहते हैं। दोनों डायबिटीज और उच्च रक्तचाप के मरीज हैं। आज 22वां दिन है। मेरी और मेरे पति की उनसे बात नहीं हो पा रही है। उन्हें जिन दवाओं की जरूरत होती है, जो इंजेक्शन चाहिए, वो उनके पास हैं कि नहीं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं हो पा रही है।'

बता दें कि उर्मिला मातोंडकर ने कश्मीर मूल के मोहसिन अख्तर मीर से विवाह किया है। वह गत लोकसभा चुनाव उत्तर मुंबई से कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुकी हैं, जिसमें उन्हें भाजपा उम्मीदवार गोपाल शेट्टी के सामने करारी हार का मुंह देखना पड़ा था।

चुनाव से पहले उन्होंने क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि वह जीतें या हारें, राजनीति छोड़ने वाली नहीं हैं। माना जा रहा है कि अब कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी हिंदी-मराठी में धाराप्रवाह बोलने वाली इस अभिनेत्री का भरपूर उपयोग करेगी।

फेसबुक पर संवेदनशील टिप्पणी के आरोप में पांच के खिलाफ मामला दर्ज

जासं, राजौरी : सोशल मीडिया फेसबुक पर कुछ संवेदनशील टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह पांचों राजौरी व पुंछ जिले के निवासी हैं और जम्मू-कश्मीर से बाहर काम कर रहे हैं।

एसएसपी जुगल मन्हास ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर नियमित निगरानी के दौरान पांच फेसबुक प्रोफाइल ऐसी नजर आई, जिन पर पांच अगस्त से कुछ संवेदनशील अपडेट किए जा रहे थे। यह शांति और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बने हुए थे। इन फेसबुक अकाउंट्स की पहचान राजौरी निवासी जहीर चौधरी, पुंछ के जाकिर शाह बुखारी, मंजकोट, राजौरी निवासी इमरान काजी, पुंछ के नाजिक हुसैन और सरदार तारिक खान के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि पांचों आरोपी जम्मू-कश्मीर के बाहर काम कर रहे हैं। उनके फर्जी अपडेट, पोस्ट और टिप्पणियों से शांति भंग होने की संभावना है। इससे राजौरी और पुंछ जिलों में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है।

समुद्र के रास्ते पाक कर सकता है नापाक हरकत

आइबी का अलर्ट ▸ गुजरात में कांडला व मुंद्रा बंदरगाहों और प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाई गई

सीमा सुरक्षा बल और कोस्ट गार्ड समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

भुज, प्रेट्र : कश्मीर को लेकर विलाप कर रहा पाकिस्तान मुंबई जैसे हमले करने की फिराक में है। उसकी रहनुमाई में पलने वाले आतंकी संगठनों के समुद्री दस्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश में हैं और प्रमुख बंदरगाहों को निशाना बनाना चाहते हैं। समुद्र के रास्ते आतंकियों की संभावित घुसपैठ की खुफिया जानकारी के बाद गुजरात के कच्छ जिले में स्थित कांडला व मुंद्रा बंदरगाहों (पोर्ट) और प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सख्त कर दी गई है।

हाल ही में नौसेना ने भी समुद्र के रास्ते आतंकी हमले के खतरे को लेकर चेतावनी जारी की थी। तब नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा था कि नौसेना किसी भी तरह के दुस्साहस का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुलिस महानिरीक्षक (सीमा क्षेत्र) डीबी वघेला ने कहा कि आतंकियों की संभावित घुसपैठ को लेकर समय-समय पर खुफिया जानकारी मिलती रहती है और कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों समेत कच्छ जिले में सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि आतंकियों के गुजरात में घुसपैठ की कोई पुख्ता सूचना तो नहीं है, लेकिन यह जानकारी है कि आतंकी समुद्र के रास्ते घुसपैठ कर सकते हैं।

अंजार के पुलिस उपाधिक्षक धनंजय वाघेला ने बताया कि राज्य के पुलिस महानिदेशक के निर्देशों और खुफिया सूचनाओं के बाद कच्छ जिले में सभी अहम स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने गश्त तेज कर दी है। समुद्री पुलिस बल को भी सतर्क कर दिया गया है।

अडानी ग्रुप का है मुंद्रा बंदरगाह : कांडला सरकारी क्षेत्र का बंदरगाह है, जबकि मुंद्रा बंदरगाह निजी क्षेत्र के अडानी ग्रुप का है। मुंद्रा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पिछले साल यहां से सबसे ज्यादा आयात-निर्यात हुआ था। अरब सागर में कच्छ की खाड़ी में स्थित ये दोनों ही बंदरगाह पाकिस्तान से करीब पड़ते हैं। कांडला बंदरगाह का संचालन करने वाले ट्रस्ट के सचिव वेणु गोपाल ने आतंकी हमले के खतरे को लेकर खुफिया सूचना मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सूचना के आधार पर संबंधित विभागों और अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। अडानी ग्रुप ने भी बंदरगाह की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें शिपिंग एजेंटों और लोगों से अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके अलावा इस क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर स्थित रिफाइनरी और द्वारका जिले के वाडिनार स्थित रूसी कंपनी रोसनेफ्ट द्वारा संचालित रिफाइनरी भी है। इनकी सुरक्षा को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है।

गुजरात स्थित मुंद्रा बंदरगाह (पोर्ट) की फाइल फोटो। रायटर

छोटी नौकाओं से आतंकी कर सकते हैं घुसपैठ : समाचार एजेंसी एएनआइ ने खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान की सेना से प्रशिक्षित स्पेशल सर्विस ग्रुप (एसएसजी) कमांडो या आतंकी छोटी नौकाओं के जरिए कच्छ की खाड़ी और सर क्रीक क्षेत्र से समुद्र के रास्ते भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। आइएएनएस ने तो कहा है कि कुछ आतंकी कच्छ की खाड़ी में घुसपैठ कर चुके हैं। एएनआइ ने 21 अगस्त को भी सूचना दी थी कि पाकिस्तानी सेना ने गुजरात में सर क्रीक क्षेत्र के पास एसएसजी कमांडो को तैनात कर रखा है।

समुद्र के रास्ते मुंबई में हुआ था हमला : पाकिस्तानी आतंकियों ने 2008 में समुद्र के रास्ते घुसपैठ कर मुंबई में बड़े हमले को अंजाम दिया था। उस समय 10 आतंकी छोटी नौका के जरिए ही समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे थे। ताज होटल, रेलवे स्टेशन, अस्पताल और अन्य जगहों पर आतंकियों के हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान का रहने वाला आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था, जिसे बाद में फांसी दे गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की शर्तों पर बीमार तारीगामी से मिले येचुरी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- माकपा महासचिव को कड़ी सुरक्षा के बीच नजरबंद तारीगामी के घर ले जाया गया
- अनुच्छेद 370 हटने के बाद किसी विपक्षी दल के नेता की पहली श्रीनगर यात्रा

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीता राम येचुरी गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अपने बीमार मित्र और राजनीतिक सहयोगी मुहम्मद यूसुफ तारीगामी का कुशलक्षेम जानने पहुंचे। पांच अगस्त के बाद कश्मीर में दिल्ली से किसी विपक्षी दल के नेता की यह पहली श्रीनगर यात्रा है। राज्य विधानसभा में चार बार विधायक चुने जाने वाले तारीगामी को कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने चार अगस्त की रात से उनके घर में नजरबंद रखा हुआ है। हृदयरोग से पीड़ित तारीगामी का स्वास्थ्य कई दिनों से खराब चल रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद येचुरी सुबह करीब साढ़े दस बजे श्रीनगर एयरपोर्ट पर दिल्ली से पहुंचे। एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें किसी से कोई बातचीत नहीं करने दी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुपकार स्थित तारीगामी के घर लाया। उन्हें जिस वाहन में लाया उसके आगे पीछे सुरक्षाबलों की करीब 10 गाड़ियां थीं। माकपा नेता के साथ कोई मीडियाकर्मी नहीं मिल सके इसके लिए गुपकार रोड पर किसी को दाखिल नहीं होने दिया। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि वह दिनभर तारीगामी के साथ रहे। इसके बाद वह सर्किट हाउस में रुके।

मीडिया से बात करने की है मनाही : येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) नेता डी राजा ने जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक पाबंदियों को लागू किए जाने के चंद दिन बाद दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे थे। उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस दिल्ली भेज दिया था। इसके बाद वह 24 अगस्त को कांग्रेस पूर्वाध्यक्ष राहुल गांधी संग फिर कश्मीर पहुंचे थे। उन्हें भी श्रीनगर एयरपोर्ट से ही लौटना पड़ा था। इसके बाद येचुरी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि वह श्रीनगर में नजरबंद तारीगामी से मिलना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका स्वीकारते हुए कहा कि वह श्रीनगर जाएं और अपने मित्र व पार्टी सहयोगियों से जरूर मिलें, पर वहां किसी तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के हालात पर बयानबाजी वहां से लौटने के बाद ही करेंगे।

पाकिस्तान पर गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ पूछा- कश्मीर उसका था ही कब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से तल्ख हुए भारत-पाक रिश्तों की तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। नियंत्रण रेखा पर पाक के सीजफायर उल्लंघन के बीच लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। जम्मू-कश्मीर को लेकर राग अलाप रहे पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर उसका आखिर था ही कब कि वो घड़ियाली आंसू बहा रहा है। रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए एक बार फिर साफ कर दिया कि पाकिस्तान का कश्मीर पर कोई हक नहीं है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के एक कार्यक्रम में लेह पहुंचे राजनाथ ने स्पष्ट कहा कि कश्मीर हमेशा से ही भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान का कश्मीर पर कोई हक नहीं है।' उन्होंने कहा, 'कश्मीर हमेशा से ही हमारे साथ रहा है और आगे भी रहेगा।' इससे पहले परमाणु हथियारों की भारत की नो फर्स्ट यूज यानि पहले प्रयोग नहीं करने की नीति की जरूरत पड़ने पर समीक्षा करने की बात कह राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की हवा निकाल दी थी। रक्षा मंत्री ने वर्ष 1994 में संसद में पारित प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा कि गिलगिट-बलटिस्तान समेत पाकिस्तान के कब्जे वाला पूरा गुलाम कश्मीर (पीओके) भारत का हिस्सा है।

उसे पहले गिलगिट-बलटिस्तान समेत पूरे गुलाम कश्मीर (पीओके) पर अपने गैर कानूनी कब्जे को लेकर बात करनी होगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर बात करने के बजाय पाकिस्तान को अपने कब्जेवाले गुलाम कश्मीर के नागरिकों के मानवाधिकारों के हनन पर ध्यान देना चाहिए। लेह लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली बार लेह पहुंचे राजनाथ ने दो टूक कहा कि हम पाकिस्तान से बात कैसे कर सकते हैं, जब वह आतंकवाद का इस्तेमाल कर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहता है।

लद्दाख के लेह में गुरुवार को 26वें 'किसान-जवान-विज्ञान' मेले में कृषि उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एएनआइ

अमेरिकी रक्षा मंत्री ने रणनीतिक मुद्दे पर राजनाथ सिंह से की बात

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा है कि भारत के साथ रणनीतिक क्षेत्र में उठाए जाने वाले कदमों को लेकर उनकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत हुई है। पिछले महीने रक्षा मंत्री बनने वाले एस्पर ने 20 अगस्त को राजनाथ सिंह से टेलीफोन पर बात की थी। पेंटागन में पत्रकारों से बातचीत में एस्पर ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत बहुत अच्छी रही। इससे पहले, नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि एस्पर ने जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार के रुख की सराहना की और जम्मू-कश्मीर को लेकर लिए गए फैसले को भी भारत का आंतरिक मामला बताया।

पाक सेना ने पुंछ में फिर की गोलाबारी

जागरण संवाददाता, पुंछ : अनुच्छेद 370 हटाने से बौखलाया पाकिस्तान सीमा पार से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। कश्मीर में पटरी पर लौट रहा जनजीवन भी उसे रास नहीं आ रहा। अब पाकिस्तानी सेना आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए सीमा पार से लगातार कोशिश कर रही है। उसकी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के हालात को खराब किया जा सके।

गुरुवार सुबह साढ़े 11 बजे के करीब पाक सेना ने पुंछ के मेंढर, मनकोट और बालाकोट सेक्टर में गोलाबारी शुरू कर दी। पहले तो उसने सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया, लेकिन थोड़ी देर में उसने रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए मोर्टार दागना शुरू कर दिए। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी सेना को कड़ा जवाब दिया। पाक सेना ने दोपहर बाद तीन बजे तक लगातार गोलाबारी जारी रखी। सूत्रों ने बताया कि वह आतंकियों के दल को भारतीय क्षेत्र में दाखिल करवाने का प्रयास कर रही थी, जिसे भारतीय सेना ने विफल कर दिया।

पिछले कुछ दिन से खासकर पुंछ में पाकिस्तानी सेना लगातार गोलाबारी कर रही है। उसका प्रयास है कि गोलाबारी की आड़ में अधिक से अधिक आतंकियों को भारतीय क्षेत्र में भेजा जा सके। मगर पाक की चाल को भारतीय सेना सफल नहीं होने दे रहे हैं। इसी कारण पाक सेना कभी एक सेक्टर में तो कभी दूसरे सेक्टर में गोलाबारी कर रही। हर बार भारतीय सेना पाक सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन पाक सेना लगातार गोलाबारी को स्थायी तौर पर बंद नहीं कर रही है।

कश्मीरी छात्रों को जितेंद्र सिंह ने बताए 370 हटाने के फायदे

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में कश्मीर के छात्रों के एक दल से मुलाकात की। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद एक तरफ जहां विकास योजनाओं का रोडमैप तैयार किया जा रहा है वहीं कश्मीरियों से संपर्क और संवाद की पहल भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने अनुच्छेद 370 के हटने के बाद राज्य और खासकर वहां के युवाओं पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानना चाहा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश के साथ एकीकृत होने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के युवाओं को लाभ मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रियों को अधिक-से-अधिक कश्मीरी जनता तक पहुंचकर उन्हें सच्चाई से अवगत कराने को कहा था।

जितेंद्र सिंह ने छात्रों को समझाया कि किस तरह अब युवाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान राज्य के सरकारी कर्मचारियों को लाभ उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि विकास के नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए युवाओं को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर के विकास में अनुच्छेद 370 की बाधा के बारे में बताते हुए उन्होंने आइआइटी जम्मू का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मंजूरी मिलने के बाद भी राज्य के हालात के कारण आइआइटी को निदेशक नहीं मिल सका।

111 में से 96 पुलिस थाना क्षेत्रों से हटाईं दिन की पाबंदियां

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : कश्मीर में गुरुवार को लगातार 25वें दिन भी तनाव के बावजूद स्थिति लगभग शांत रही। सड़कों पर वाहनों और आम लोगों की आवाजाही रही, लेकिन बाजार बंद रहे। विभिन्न स्थानों पर प्राइमरी और हाई स्कूल खुले। हालांकि छात्रों की कम संख्या रही। वहीं, स्थिति में सुधार को देखते हुए प्रशासन धीरे धीरे प्रशासनिक पाबंदियों में राहत दी है। मंगलवार को पूरी वादी में 111 में से 96 पुलिस थाना क्षेत्रों में दिन की निषेधाज्ञा नहीं थी। इसका असर स्थानीय जनजीवन पर भी देखने को मिला। सड़कों पर आम लोगों की आवाजाही बीते दिनों की अपेक्षा ज्यादा रही। मुख्य बाजार बंद रहे सिर्फ सुबह-शाम कुछ देर के लिए रोजमर्रा के साजो सामान के अलावा कुछ अन्य दुकानें खुलीं। सभी सरकारी कार्यालय निर्धारित समय पर ही खुले। आम लोगों की आवाजाही कार्यालयों में नाममात्र ही थी, लेकिन कर्मियों की उपस्थिति सामान्य रही। नागरिक सचिवालय में 95 प्रतिशत के करीब कर्मचारियों की उपस्थिति रही। अलबत्ता, शैक्षिक गतिविधियों को बहाल करने की प्रशासनिक पहल ज्यादा आगे बढ़ती नजर नहीं आई। जिन इलाकों में निषेधाज्ञा नहीं थी, वहां सभी सरकारी प्राइमरी, मिडिल व हाई स्कूल खुले। कई जगह कुछ निजी स्कूल भी खुले, लेकिन निजी स्कूलों में जहां छात्र पूरी तरह नदारद थे।

प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया हुआ है। हालांकि देर शाम को कुछेक इलाकों में हुई पथराव की छिट-पुट घटनाओं को अलावा स्थिति पूरी तरह शांत रही।

बदले हालात

जरूरी सामान खरीदने के लिए दुकानदारों को फोन कर रहे हैं लोग, शरारती तत्वों के डर से दुकानें कर रखी हैं बंद, शटर पर चस्पा किए नंबर

कश्मीर में फोन कॉल पर खुल रहीं दुकानें, हो रही खरीदारी

नवीन नवाज, श्रीनगर

कश्मीर की धड़कन लाल चौक की सड़कों पर वाहनों और लोगों की आवाजाही है, लेकिन अधिकांश दुकानें बंद हैं। दुकानों के शटर पर पोस्टर चस्पा हैं। उनपर दुकानदारों के घर का पता और मोबाइल नंबर है। यानी जो सामान चाहिए फोन करो जरूर मिलेगा। यह दुकानदार अलगाववादियों के समर्थक नहीं हैं, लेकिन उन्होंने शरारती तत्वों की तोड़फोड़ से बचने के लिए दुकानें बंद कर रखी हैं। मौजूदा समय में कश्मीर में शादियों का सीजन चल रहा है। कपड़ों से लेकर खाने-पीने की चीजों की जरूरत है। ऐसे में यह पोस्टर अलगाववादियों, आतंकियों और बंद समर्थकों को बता रहे हैं कि कश्मीरी व्यापारी और दुकानदार उनकी हड़ताली सियासत का समर्थक नहीं है बल्कि वे अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सेब का ठेला लगाने वाले युसुफ ने कहा कि यहां दुकानें बंद हैं तो क्या हुआ, धंधा तो चालू है। यहां बरसों से हड़ताल और बंद के माहौल में दुकान कैसे चलानी है, हम सीख गए हैं। उन्होंने कहा कि लोग बंद दुकानों के बाहर फोन नंबर और घर का पता लगाकर चले जाते हैं।

कश्मीर में हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। प्रशासनिक पाबंदियां हटाई जा रही हैं। शरारती तत्वों से बचने के लिए कई दुकानें बंद हैं, लेकिन उन्होंने बंद दुकानों के बाहर शटर पर एक पेज चस्पा कर अपना नंबर लिखा है ताकि ग्राहकों को वे घर से सामान उपलब्ध करवा दें। जागरण

बंद दुकान से हो गई 40 हजार की खरीदारी : झेलम दरिया पर बने अमीराकदल पुल के पार स्थित गनीखान बाजार में भी विरानी है। अचानक एक गाड़ी से दो लोग निकले और तेजी से दुकानों का शटर उठाया। पीछे कुछ महिलाएं और बुजुर्ग भी दुकान में घुसे। आधा घंटा लोग दुकान में रहे और फिर हाथों में थैले लिए निकले। दुकानदार अल्ताफ जरगर ने कहा कि शटर पर पर्ची लगाकर रखी थी इसे पढ़कर यह लोग हमारे घर पहुंचे और फिर मैं यहां इनके साथ आया हूं। इनकी बेटी की शादी है। 40 हजार के कपड़े खरीदे हैं।

दुकानों का समय बदला है : राजबाग, डलगेट, पोलो व्यू, बुलवर्ड रोड सहित कई प्रमुख जगहों पर पहले दुकानें सुबह नौ बजे खुलकर शाम को नौ बजे तक खुली रहती थी। अब सुबह छह बजे से दस बजे तक, फिर शाम को छह बजे खुलती है और रात साढ़े आठ बजे बंद हो जाती है। राजबाग में कपड़ों के शोरूम के मालिक जहूर बट ने कहा कि शादियों का सीजन है। डर है कि अगर दुकान खोलूं तो तोड़फोड़ शुरू नहीं हो जाए। मैं और मेरा बेटा शोरूम के पास मौजूद रहते हैं। जब कोई आकर पूछता है तो आधा शटर खोल जल्दी से सामान देते हैं।

पुलवामा से देर रात हो रही दूध की सप्लाई : श्रीनगर में बेकरी न खुलने के कारण कई जगह ब्रेड की थोड़ी कमी भले ही है लेकिन दूध की कहीं भी कमी नहीं है। पुलवामा में ग्रामीण रात में ही दूध भरकर श्रीनगर पहुंच रहे हैं। सुबह आठ बजने से पहले पुलवामा वापस चले जा रहे हैं। वहीं, फल और सब्जियों का भी अभाव नहीं है।

दिखने लगा दुष्प्रचार का असर

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

इस दुष्प्रचार का कई स्थानों पर असर भी दिखा। श्रीनगर के बाहरी इलाके में रहने वाले एक युवक ने कहा कि हमने किसी से मारपीट नहीं की। लेकिन हमने यहां आए श्रमिकों को जाने के लिए कहा है। हम नहीं चाहते कि यहां हम लोगों की रिवायतों और मजहब को नुकसान हो। उत्तर प्रदेश में मेरठ के रहने वाले शफीक ने कहा कि मैं यह सोचकर रुक गया था कि जल्द हालात सुधर जाएंगे। लेकिन अब दुकान पर जाने से डरता हूं। मकान मालिक ने मुझे मकान खाली करने के लिए सीधे तौर पर नहीं कहा है, लेकिन तरह-तरह की बातें सुन परेशान हूं।

ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो : पेशे से बिल्डर फिरोज अहमद फाफू ने कहा कि मुझे भी अपनी पहचान और संस्कृति प्यारी है लेकिन किसी को डराकर इसका संरक्षण नहीं हो सकता। ऐसे तत्व कश्मीर और कश्मीरियों को ही बदनाम कर रहे हैं। साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। श्रमिकों के पलायन से विकास योजनाएं ठप हैं। सरकार को इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।

मोहम्मद अकबर को मजाक महंगा पड़ा : खनयार में दो दशक से हलवाई की दुकान चला रहा मोहम्मद अकबर ने केंद्र के फैसले के बाद मजाक में अपने पड़ोसी से कह दिया अब मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता। बस यह बात फैली और कुछ ही देर में दुकान और मकान का मलिक आ पहुंचे। उसे 24 घंटे का समय देते हुए निकल जाने को कहा। इसके बाद उसे कश्मीर से 20 साल का नाता तोड़ बिजनौर लौटना पड़ा।

वहीं. बसपोरा में एक मस्जिद में 32 साल इमाम रहे एक व्यक्ति ने कोई मजाक भी नहीं किया, लेकिन कुछ लड़के आए और उसे अपना बोरिया बिस्तर समेटने या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा। उसने इस्लाम का वास्ता दिया, लेकिन बात नहीं बनी और उसे परिजनों संग एक ट्रक में सामान लेकर भागना पड़ा।

45 वें स्थान पर है दुनिया के सुरक्षित शहरों के सूचकांक में मुंबई। वहीं, देश की राजधानी दिल्ली 52वें स्थान पर है। इकोनामिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक जापान की राजधानी टोक्यो दुनिया में सर्वाधिक सुरक्षित शहर है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 30 अगस्त 2019

मप्र में बच्चों से साफ कराया शौचालय कलेक्टर ने कहा–कुछ गलत नहीं

चिंताजनक ▶ खंडवा जिले का है मामला, वीडियो वायरल, सफाई करवाने पर अभिभावक आक्रोशित

अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी से बात करने की बात कही

नईदुनिया, खंडवा

मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के गांव सिहाड़ा की प्राथमिक बालक शाला में बच्चों से स्कूल का शौचालय साफ करवाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे। प्रधानाध्यापक से चर्चा करने पर उन्होंने साफ मना कर दिया। इससे अभिभावक बुरी तरह आक्रोशित हो गए। उन्होंने इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से करने की बात कही है। उधर, कलेक्टर ने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है।

मामला सोमवार का बताया जा रहा है। एक ग्रामीण स्कूल परिसर में पहुंचा तो उसे शौचालय से बच्चों की आवाज सुनाई दी। उसने अंदर जाकर देखा तो बच्चे शौचालय के फर्श पर पानी डालकर उसे झाड़ू से साफ करते नजर आए। ग्रामीण ने बच्चों का वीडियो बनाकर स्कूल की प्रधानाध्यापक गुलाब सोनी को जानकारी दी। इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर वीडियो वायरल कर दिया गया। इसकी जानकारी मिलते ही जनप्रतिनिधियों के साथ ही बड़ी संख्या में अभिभावकों और ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर सोनी के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई। वीडियो में नजर आए कक्षा चौथी के छात्र पीयूष के नाना रामचरण भामदरे ने उनसे कहा कि हम बच्चे से घर का कोई काम नहीं करवाते हैं। उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं और आप उससे शौचालय साफ करवाने का काम करवाते हो। कुछ अभिभावकों ने बच्चों को परीक्षा में नंबर अधिक देने का लालच देकर शौचालय साफ करवाने की बात भी कही। चर्चा के दौरान सोनी अपने ऊपर लग रहे आरोपों को नकारती रहीं। इस दौरान वीडियो में नजर आए बच्चे भी काफी सहमे हुए थे। पूर्व जनपद सदस्य प्रणय श्रीमाली, नासिर खान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी जीएल रघुवंशी से शिकायत करने की बात कही है।

आरोप निराधार : सोनी: इस संबंध में प्रधानाध्यापक सोनी का कहना है कि बच्चे छुट्टी के समय शौचालय गए थे। एक बच्चा फर्श पर कीचड़ होने की वजह से गिर गया था। इसके बाद कुछ बच्चों ने फर्श को झाड़ू से साफ किया होगा। बच्चों को परीक्षा में अधिक नंबर देने का आरोप निराधार है। महीने में दो बार स्वीपर द्वारा शौचालय की सफाई करवाई जाती है।

जापान में बच्चे स्कूल का हर काम करते हैं : कलेक्टर

स्कूलों में विद्यार्थियों से सफाई कराने के मामले में कलेक्टर तन्वी सुंद्रियाल का कहना है कि सफाई करने में कुछ गलत नहीं है। जापान में बच्चे स्कूल का हर काम करते हैं। जब बच्चे सफाई कार्य में लगेंगे तो ग्रामीण और पंचायत को भी लगेगा कि वहां सफाई रखना चाहिए। स्कूल समाज का है अगर यहां बच्चे सफाई कर रहे हैं तो इसे सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए। हम स्कूलों, आंगनबाड़ियों और कॉलेजों में जाकर देख रहे हैं कि वहां किन व्यवस्थाओं की जरूरत है। कैसे वहां सुविधाएं बेहतर की जा सकती हैं।

तीन गुना बढ़ी भारत में जंगल की आग

अमेजन के वर्षावनों में लगी आग ने दुनिया के पर्यावरणविद् और वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, जंगल की आग अमेजन के लिए नई नहीं है। भारत में भी जंगल की आग पिछले कुछ सालों में लगभग तीन गुना बढ़ गई है। इस साल 1 जनवरी से 16 जून तक एमओडीआइएस सेटेलाइट का उपयोग करके भारत के वन क्षेत्र में लगी आग की कुल 28,252 घटनाओं का पता लगाया गया है।

7,08,273 वर्ग किमी
भारत में कुल वनाच्छादित क्षेत्र

24.39%
देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों की हिस्सेदारी

64.29%
वन क्षेत्र के वे हिस्से जो आग से संवेदनशील हैं

प्रमुख संवेदनशील क्षेत्र

उत्तराखंड
उत्तराखंड के जंगलों में आग एक वार्षिक घटना है। लेकिन 1995 की गर्मियों के दौरान (जब यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था) यहां के जंगलों में सबसे गंभीर आग देखी गई। इसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और 3,75,000 हेक्टेयर वन भूमि को मिटा दिया। 2000 में अपने गठन के बाद से, उत्तराखंड में आग लगने से 44,518 हेक्टेयर वन भूमि गायब हो गई है।

हिमाचल प्रदेश
2010 में हिमाचल के जंगलों में आग ने कहर बरपाया था। 19,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल की जमीन इससे नष्ट हो गई थी।

महाराष्ट्र
2008 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मेलाघाट क्षेत्र में आग लग गई थी, जिससे लगभग 10,000 हेक्टेयर वन भूमि नष्ट नष्ट हो गई।

जंगल में आग की घटनाएं

वर्ष	घटनाएं
2011	13,898
2012	29,362
2013	18,451
2014	19,054
2015	15,937
2016	24,817
2017	35,888
2018	37,059

शॉर्ट सर्किट से तेलंगाना एक्सप्रेस में लगी आग

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद) : हैदराबाद से दिल्ली आ रही तेलंगाना एक्सप्रेस में गुरुवार सुबह पौने आठ बजे जाजरू गांव के फाटक पास एसी के वायर में शार्ट सर्किट होने से पैंट्री कार सहित दो एसी कोच में भीषण आग लग गई। उस समय अधिकतर यात्री सो रहे थे। उन्हें तत्काल ट्रेन से उतार दिया गया। दमकल गाड़ियों के समय पर न पहुंचने के कारण ट्रेन के डिब्बे करीब डेढ़ घंटे तक जलते रहे। करीब तीन घंटे तक अप एवं डाउन मेन लाइन पर रेल यातायात बंद रहा। साढ़े दस बजे यातायात सुचारू हो सका।

बताते हैं कि तेलंगाना एक्सप्रेस (12723) पियाला ठहराव पर गांव जाजरू फाटक के नजदीक पहुंची तो ड्यूटी पर तैनात गेटमैन विशंभर ने रसोईयान कक्ष के डिब्बे में धुआं उठते देखा। इसकी सूचना तुरंत चालक को दी। उसने एमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। टिकट निरीक्षकों के माध्यम से ट्रेन में सो रहे यात्रियों को आग की सूचना देकर ट्रेन से नीचे उतारा गया। आग को अन्य डिब्बों में फैलने से बचाने के लिए ट्रेन को तीन हिस्सों में कर दिया गया। रेल प्रशासन ने सभी यात्रियों को अगले नौ डिब्बों में बिठाकर दिल्ली रवाना कर दिया। आग से प्रभावित डिब्बों को असावटी रेलवे स्टेशन भेजा गया। टिकट निरीक्षक बीपी सिंह ने बताया कि ऐसी के वायर में शार्ट सर्किट होने से आग लगी है। डीआरएम एससी जैन ने बताया कि वे घटना की जांच कर रहे हैं।

उप्र में नौ दिन लगातार सुनवाई के बाद दुष्कर्मी को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, औरैया

चार वर्षीय मासूम से दुष्कर्म मामले में लगातार आठ दिनों तक सुनवाई कर विशेष न्यायालय (पॉक्सो) ने आरोपित को दोषी करार दिया और नौवें दिन उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में यह फैसला इतिहास बन गया, क्योंकि पहली बार घटना के महज 28 दिन में गुनहगार को सजा सुनाई गई। इस फैसले को लेकर पूरे दिन चर्चा होती रही। प्रदेश में इतने कम दिन में किसी मामले में फैसला आने की यह पहली घटना है।

औरैया के बेला थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने पुलिस को बताया था कि उसकी चार वर्षीय बेटी पड़ोसी श्यामवीर के घर के पास खेल रही थी। श्यामवीर बच्ची को अपने घर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। किसी तरह छूटकर घर आई लहूलुहान बच्ची ने घटना की जानकारी मां को दी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया था। मामले में विवेचक ने महज 20 दिन में जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। जिसके बाद मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हो गई।

विशेष लोक अभियोजक पाक्सो जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि एक दिन में तीन-तीन गवाहों की गवाही हुई। नौ गवाहों के बयान दर्ज कर न्यायालय ने सजा सुना दी। दोष सिद्ध होने के बाद ही श्यामवीर को इटावा जेल भेज दिया गया था। न्यायालय ने जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय व्यय एवं पुनर्वासन के लिए देने का भी आदेश दिया। फैसले के समय दोनों पक्ष मौजूद नहीं थे। श्यामवीर के परिवारीजनों ने मामले में पैरवी नहीं की।

पहली बार

- आठ दिन में दोषी साबित कर नौवें दिन सजा सुना रचा इतिहास
- घर के बाहर खेल रही बच्ची को अगवाकर किया था दुष्कर्म

गवाह के लिए भेजी गाड़ी

इस मामले में एक गवाह बारिश के चलते फंस गया था। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक सुनीति को हुई तो उन्होंने उसके लिए तुरंत गाड़ी भेजी और उसे बुलवाकर कोर्ट में गवाही के लिए प्रस्तुत किया।

वकील नहीं, न्यायमित्र नियुक्त

आरोपित श्यामवीर की ओर से इस मामले में कोई वकील नहीं था। उसकी पैरवी के लिए न्यायमित्र प्रीती गुप्ता को शासन ने अधिकृत किया था।

उप्र में पिछले दस वर्षों के अकादमी पुरस्कार घोषित

जागरण संवाददाता, लखनऊ : लखनऊ की संगीत नाटक अकादमी की ओर से दिए जाने वाले संगीत अकादमी पुरस्कारों की घोषणा के दो माह बाद कलाकारों के नामों की सूची गुरुवार को जारी की गई। 2009 से 2018 तक अकादमी पुरस्कार के साथ अकादमी रत्न, 2017 व 2018 के सफदर हाशमी व बीएम शाह पुरस्कारों के लिए नामों की घोषणा हुई। अकादमी की अध्यक्ष पूर्णिमा पांडेय ने पत्रकारों को बताया कि अकादमी अवॉर्ड के लिए 500 से अधिक आवेदन आए थे। इनमें 106 अकादमी अवॉर्ड और पांच रत्न सदस्यों को चुना गया। कलाकारों का चयन समिति के द्वारा हुआ है। अकादमी पुरस्कार विजेताओं को 10 हजार रुपये की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिह्न दिया जाएगा।

वहीं, इस बार कई सालों से रुके हुए सफदर हाशमी व बीएम शाह अवॉर्ड भी फिर से शुरू किए जा रहे हैं। इनमें 2017 व 2018 के ही पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार वितरण अक्टूबर में करने की योजना है। पूर्णिमा पांडेय ने लिस्ट जारी करने में हुई देरी के सवाल पर बताया कि पिछले दस वर्षों से अकादमी के पास बजट का अभाव था।

बंगाल के वीरभूम में तृणमूल नेता के घर में बम धमाका

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- भाजपा का आरोप–आतंक फैलाने के लिए तृणमूल नेता ने घर में जमा कर रखे थे बम
- तृणमूल ने बताया भाजपा की साजिश, कहा–भाजपावालों ने बम रख के फंसाया

बंगाल के वीरभूम में गुरुवार को तृणमूल नेता के घर में हुए धमाके के मामले में पुलिस ने नेता को ही गिरफ्तार कर लिया है। धमाके की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें घर की पूरी छत उड़ कर 100 मीटर दूर जा गिरी। साथ ही घर का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना में आरोपित नेता बदरुद्दोजा शेख सहित दो लोग घायल हुई हैं। उधर, घटना के बाद भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि बदरुद्दोजा शेख ने अपने घर में ही देसी बम जमा कर रखे थे, जबकि तृणमूल ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया है।

गौरतलब है कि बदरुद्दोजा शेख की बेटी हितुन्नेशा खातून स्थानीय साहापुर ग्राम पंचायत की प्रधान है। घटना कोलकाता से लगभग 212 किमी दूर वीरभूम जिले के सदाईपुर इलाके के रेनगुनी गांव में स्थित बदरुद्दोजा के घर पर घटी। सदाईपुर थाने के अधिकारी ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब छह बजे हुए धमाके के बाद पुलिस ने उक्त बदरुद्दोजा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में बदरुद्दोजा के साथ एक आम नागरिक भी घायल है, वह घर की उड़ी छत की चपेट में आ गया था। वीरभूम के एसपी श्याम सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। फारेंसिक टीम भी जल्द घटनास्थल का दौरा करेगी।

गौरतलब है कि पांच दिन पहले ही इसी जिले के कंकड़टाला इलाके के बारा गांव में तृणमूल नेता शेख महिबुल के घर भी ऐसा ही हादसा हुआ था।

घटना के बाद से इलाके का राजनीतिक माहौल गर्म है। बयानबाजी का दौर चरम पर है। वीरभूम भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामकृष्ण रॉय ने आरोप लगाया कि यह साफ हो गया है कि इलाके में दहशत फैलाने के उद्देश्य से तृणमूल के लोगों ने घर में देसी बम जमा कर रखे थे। उधर, तृणमूल जिला परिषद के अध्यक्ष विकास राय चौधरी ने उल्टे भाजपा नेताओं को पर वहां बम जमा कर तृणमूल नेताओं को फंसना का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि धमाके के पीछे भाजपा के लोग हैं। उन्होंने साजिश के तहत घर में बम रखे और अब घटिया राजनीति पर उतर आए हैं।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जिले में ऐसी घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं। जुलाई में मीरबांध इलाके के एक स्वास्थ भवन में धमाके से पूरा कमरा ध्वस्त हो गया था। जून के आखिरी दौर में मल्लारपुर के एक समुदायिक भवन में धमाका हुआ, जिसमें इमारत का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया था।

नौकरी नहीं दी, अब भरपाई के लिए नीलाम होगी कलेक्टर की कार

जागरण संवाददाता, जयपुर: राजस्थान में भरतपुर जिला प्रशासन द्वारा मनरेगा में पात्र महिला को जिला ग्राम रोजगार सहायक पद पर नियुक्ति नहीं देने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सख्त रूख अपनाया है। मजिस्ट्रेट ने भरतपुर जिला कलेक्टर आरूषी ए.मलिक की कार और जिला परिषद के फर्नीचर को कुर्क कराने के आदेश जारी किए हैं। गुरुवार को कोर्ट के सेल अमीन ने दोनों पर कुर्की का वारंट चस्पा कर दिया। अगर एक महीने में पात्र महिला चंचल शर्मा को नियुक्ति नहीं दी गई तो उनकी नीलामी की जाएगी।

अधिवक्ता श्रीनाथ शर्मा ने बताया कि 2008 में भरतपुर जिले के खोखर गांव निवासी चंचल शर्मा ने मनरेगा (उस वक्त नरेगा) में जिला ग्राम रोजगार सहायक पद के लिए आवेदन किया था। इसके लिए वह पूरी तरह से पात्रता रखती थीं, लेकिन किसी कथित उच्च सिफारिश को आधार मानकर 'अपात्र महिला' का चयन कर उसे नियुक्ति दे दी गई। चंचल शर्मा ने अपने साथ हुए अन्याय की अपील कोर्ट में करते हुए परिवाद प्रस्तुत किया। कोर्ट ने चार महीने पहले उनको पात्र मानते हुए उन्हें नियुक्ति देकर ज्वॉइन कराने के निर्देश दिए। आदेश के बाद भी पात्र महिला को नौकरी नहीं देने पर कोर्ट ने इसे न्यायालय की अवमानना मानते हुए जिला कलेक्टर की कार और जिला परिषद के फर्नीचर को कुर्क कर नीलामी राशि से पीड़िता को भुगतान करने के निर्देश दे दिए।

रूस से 21 मिग-29 और 12 सुखोई-30 खरीदने की योजना

नई दिल्ली, एएनआइ : भारतीय वायु सेना 33 और नए लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रही है। इनमें 21 मिग-29 और 12 सुखोई-30 एमकेआइ विमान शामिल हैं। वायु सेना के इस प्रस्ताव पर अगले कुछ हफ्तों में रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में विचार किया जाएगा।

सरकार के सूत्रों ने बताया कि विभिन्न दुर्घटनाओं के चलते वायु सेना के पास लड़ाकू विमानों की संख्या कम हुई है। इस कमी को दूर करने के लिए 12 सुखोई-30 एमकेआइ विमान खरीदने की योजना बनाई जा रही है। इन 12 अतिरिक्त सुखोई की खरीद से वायु सेना अपने 272 सुखोई-30 एमकेआइ विमानों के बेड़े को बरकरार रख पाएगी। भारत ने 272 सुखोई-30 विमानों की खरीद का ऑर्डर दिया है, जो 10-15 साल के दौरान मिलने हैं।

वायु सेना रूस से जिन 21 मिग-29 विमान खरीदने की योजना बना रही, उसे बेचने का प्रस्ताव रूस ने ही किया था। ये विमान अत्याधुनिक होंगे। इसके राडार और अन्य उपकरण भी अत्याधुनिक होंगे।

सूत्रों ने बताया कि मिग-29 विमानों की खरीद के लिए बातचीत अग्रिम दौर में है। वायु सेना को जल्द ही सौदा पक्का हो जाने की उम्मीद है। भारतीय वायु सेना पहले से ही मिग-29 विमानों का उपयोग कर रही है। वायु सेना के पायलट इसे अच्छी तरह से उड़ाते भी हैं। हालांकि, अब जो मिग-29 विमान खरीदने की योजना है वो पहले की तुलना में अलग है। भारतीय नौसेना भी मिग-29 के विमान का उपयोग करती है।

भारतीय वायु सेना के पास मिग-29 के तीन स्क्वाड्रन है, जिसे अपग्रेड किया जा रहा है। एक स्क्वाड्रन में 16-18 लड़ाकू विमान होते हैं। इसके अलावा दो ट्रेनिंग विमान भी होते हैं। वैसे कुछ-कुछ स्क्वाड्रन में एक-दो ज्यादा विमान भी होते हैं।

एस-400 के लिए रूस को मिला अग्रिम भुगतान: रूस के दैनिक अखबार स्पुतनिक ने गुरुवार को बताया कि रूस को एस-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए भारत से अग्रिम भुगतान प्राप्त हो गया है। पांच एस-400 की खरीद के लिए नई दिल्ली में पांच अक्टूबर, 2018 को भारत और रूस के बीच लगभग 37 हजार करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर हुए थे।

मास्को में चल रहे एमएकेएस-2019 एयर शो के दौरान संघीय सैन्य-तकनीकी सहयोग सेवा ने कहा, 'एस-400 के लिए जहां तक भारत से अग्रिम भुगतान का मामला है, यह सुलझ गया है।

मोती व सीप से बनाए गणपति...

देशभर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दो सितंबर से शुरू होने वाले इस त्योहार के लिए मुंबई में एक आर्टिस्ट ने मोती और सीप की मदद से भगवान गणपति की विशाल प्रतिमा तैयार की है। एएनआइ

एयर इंडिया की उड़ानों में बंद होगा प्लास्टिक का उपयोग

जासं, नई दिल्ली

- दो अक्टूबर से लागू होगी व्यवस्था, कागज और पर्यावरण अनुकूल प्लेट का होगा प्रयोग

एयर इंडिया ने अपनी उड़ानों में प्लास्टिक का उपयोग बंद करने का ऐलान किया है। आगामी 2 अक्टूबर से इसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस और एलायंस एयर की उड़ानों में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होगा। इसकी जगह कागज और पर्यावरण अनुकूल प्लेट इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा।

एयर इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अश्विनी लोहानी ने कहा कि देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के मकसद से एयर इंडिया ने प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में एयर एक्सप्रेस और एलायंस एयर की उड़ानों में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। दूसरे चरण में एयर इंडिया की सभी उड़ानों में भी प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रियों को परोसे जाने वाले नाश्ते के लिए विभिन्न बदलाव किए गए हैं।

प्लास्टिक के पाउच में दिए जाने वाले केले के चिप्स और सैंडविच को अब बटर पेपर पाउच में और केक स्लाइस को स्नैक्स बॉक्स की बजाय मफिन में लपेट करके दिया जाएगा। यात्रियों की तरफ से ऑर्डर किए जाने वाले स्पेशल मील को ईको फ्रेंडली वुडन कटलरी प्लेट में सर्व किया जाएगा।

एयर इंडिया का विमान। फाइल फोटो

क्रू मील के लिए दी जाने वाली कटलरी की बजाय अब लाइट वेट स्टील कटलरी यूज की जाएगी। पानी के लिए पेपर के गिलास इस्तेमाल में लाए जाएंगे। प्लास्टिक वाले चाय के कप की जगह मोटे कागज के कप दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री के प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ जनआंदोलन के फैसले के बाद एयर इंडिया की तरफ से इस दिशा में यह कदम उठाया गया है।

संसद में हिंदी को मिले बढ़ावा : विद्यासागरजी

नसीहत

आचार्यश्री से मिलने देवास स्थित सिद्ध तीर्थ क्षेत्र पहुंचे थे ओम बिरला, आचार्यश्री ने कहा कि मातृभाषा में जो भाव हम प्रकट कर सकते हैं, वह किसी और भाषा में नहीं कर सकते हैं

नईदुनिया, देवास

मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित नेमावर के सिद्धोदय सिद्ध तीर्थ क्षेत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को पहुंचे। उन्होंने यहां चातुर्मास कर रहे आचार्यश्री विद्यासागरजी महाराज का आशीर्वाद लिया। करीब एक घंटे तक आचार्य श्री व लोकसभा अध्यक्ष के बीच चर्चा हुई। इस दौरान आचार्यश्री ने हिंदी भाषा के ज्यादा से ज्यादा उपयोग पर जोर दिया। कहा कि संसद में भी हिंदी के शब्दों का उपयोग होना चाहिए। इस संबंध में आचार्यश्री ने 'अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल' पुस्तक लोकसभा अध्यक्ष बिरला को भेंट की। आचार्य श्री ने कहा कि मातृभाषा में जो भाव हम प्रकट कर सकते हैं, वह भाव किसी और भाषा में नहीं कर सकते हैं।

लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने बांग्लादेश के इतिहास को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक शिष्टमंडल बांग्लादेश गया था। वहां चर्चा हुई और इतिहास के बारे में जाना। बांग्लादेश को आजाद कराने में हिंदुस्तान का बड़ा योगदान है और यह बात इसी सदी की है, लेकिन वहां के इतिहास में इसका जिक्र तक नहीं किया गया। इस पर आचार्यश्री ने कहा कि अध्ययन नहीं करना और अध्ययन होते हुए भी उसे छुपाना ठीक नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस पर कहा कि कई ऐसी चीजें हैं, जो आज भी चल रही है। इतिहास लिखने वाले लोग वही थे और उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास लिख दिया।

भारत ही बोला जाना चाहिए: भारत को इंडिया कहने पर भी आचार्यश्री ने कहा कि भारत का हजारों साल पुराना इतिहास है। उस समय से देश का नाम भारत है। इसलिए भारत ही बोला जाना चाहिए।

लोकसभा और विधानसभा सत्रों की संख्या बढ़ानी जरूरी : बिरला

ओम बिरला ने इंदौर में मीडिया से चर्चा में कहा कि यह बहुत जरूरी है कि लोकसभा और विधानसभा के सत्र सुचारू रूप से चलें। चिंता की बात यह है कि विधानसभाओं के सत्रों की संख्या और समय लगातार कम हो रहा है। इसे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि विधायक अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के सामने रख उनका समाधान करा सकें। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया है कि दो समितियां बनाई जाएं, जो विधानसभा अध्यक्षों से चर्चा कर इस संबंध में आचार संहिता बना सकें, ताकि विधानसभा की कार्रवाई निर्बाध रूप से चलती रहे। समितियों की अनुशंसा लागू होने से विधानसभाओं के कामकाज में एकरूपता आ सकेगी।

ओम बिरला फाइल फोटो

आदेश को किया निलंबित

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

न्यायाधीश राकेश कुमार के बुधवार को पारित किए गए आदेश को 11 जजों की स्पेशल बेंच ने गुरुवार को निलंबित कर दिया। अब पूर्व आइएएस अधिकारी केपी रमैया को चाहे जिस भी परिस्थिति में जमानत मिली थी, उसकी जांच नहीं होगी। राकेश कुमार की एकलपीठ ने पटना के जिला जज को तीन सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था कि निगरानी के स्पेशल जज के अनुपस्थित रहने के बाद इंचार्ज जज विपुल कुमार सिन्हा ने किस क्षेत्राधिकार से रमैया को जमानत दे दी थी? इसके साथ-साथ जिला अदालत में रिश्वत के मामले में घिरे 17 कर्मियों के खिलाफ सीबीआइ जांच भी नहीं होगी। स्टिंग ऑपरेशन में 17 कोर्ट कर्मियों को रिश्वत लेते दिखाया गया था।

मुख्य न्यायाधीश के कक्ष में 11 न्यायाधीशों के बैठने की व्यवस्था: गुरुवार को अदालत का कामकाज शुरू होते ही मुख्य न्यायाधीश के कक्ष में 11 न्यायाधीशों के बैठने की व्यवस्था कर दी गई। जानकारी मिली कि जस्टिस राकेश कुमार के आदेश की समीक्षा करने को 11 जजों की स्पेशल बेंच बैठेगी। ऐसा मौका सिर्फ केशवानंद भारती के मामले में ही हुआ था। अदालत में 'दैनिक जागरण' सहित कुछ अखबारों की खबर को लेकर सुनवाई शुरू की गई। महाधिवक्ता ललित किशोर बुलाए गए। उनसे राकेश कुमार की अदालत में हुई घटना की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि आदेश की प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है। सिर्फअखबार में छपी खबर से अवगत हैं। मुख्य न्यायाधीश शाही ने कहा कि पूरी घटना बहुत दुखद है। जस्टिस राकेश कुमार ने पूरी न्यायपालिका को ही कठघरे में खड़ा कर दिया है। हमलोग उनके आदेश की भर्त्सना करते हैं। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए कहा कि अब हमलोग प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्यवाही करेंगे।

उप्र और राजस्थान में बनेगी 'इंटरस्टेट कॉर्डिनेशन सेल'

नईदुनिया, ग्वालियर: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की आपस में जुड़ती सीमा पर स्थित जिलों में अपराधियों की आवाजाही और अपराध पर रोकथाम के लिए 'इंटरस्टेट कॉर्डिनेशन सेल' बनाई जाएगी। यह निर्णय गुरुवार को ग्वालियर में हुई अंतरराज्यीय समन्वय बैठक में हुआ। बैठक में तीनों राज्यों के प्रमुख पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

अंतरराज्यीय सीमा का फायदा उठाकर बदमाश न बच सकें, इसके लिए जल्द ऐसे जिलों में बेहतर तालमेल के लिए 'इंटरस्टेट कॉर्डिनेशन सेल' बनाने का प्रस्ताव आइजी ग्वालियर जोन राजाबाबू सिंह ने रखा, जिस पर सभी ने सहमति दी। नोडल ऑफिसर इस सेल का मुखिया होगा, जो एडिशनल एसपी रैंक का अफसर होगा। साथ ही इंटरस्टेट वॉट्सएप ग्रुप की मदद से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस आपस में इंटरस्टेट अपराधियों की सूची साझा करेंगे। साथ ही बदमाशों के मूवमेंट पर एक-दूसरे की मदद से धरपकड़ करेंगे।

8 किलो सोने के साथ राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) की कोलकाता जोनल यूनिट ने तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान मुनव्वर आलम, मुहम्मद फैजल और अलताफ के रूप में हुई

पहाड़ी से पत्थर गिरने से हाईवे बंद बदरीनाथ में तीन हजार श्रद्धालु फंसे

बुरा हाल ▸ चमोली में सोनला के पास जेसीबी मशीन पहाड़ी से आए मलबे में दब गई

पूरे दिन पैदल यात्रा भी रोकी गई, शुक्रवार को कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना

जागरण संवाददाता, देहरादून

पहाड़ी से भूस्खलन के कारण बदरीनाथ हाईवे गुरुवार को पूरे दिन बाधित रहा। पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों को देखते हुए जिला प्रशासन ने पैदल यात्रा भी नहीं चलने दी। यहां विभिन्न पड़ावों पर तकरीबन एक हजार यात्री रोके गए हैं। बदरीनाथ धाम में लगभग दो हजार यात्री हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हाईवे खोलने और सुरक्षित पैदल रास्ता बनाने का कार्य चल रहा है। गंगोत्री हाईवे भी चुंगी बड़ेथी में दिनभर बंद रहा, हालांकि यहां पैदल यात्रा जारी है। केदारनाथ और यमुनोत्री हाईवे सुचारु रहे। दूसरी तरफ, राज्य मौसम केंद्र ने शुक्रवार को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

बुधवार से चमोली में मौसम साफ था, लेकिन रात लामबगड़ में पहाड़ी से काफी मात्रा में मलबा आने से बदरीनाथ हाईवे बंद हो गया। इसी बीच भारी भरकम चट्टान टूटकर आ गिरी, संयोग से उस वक्त वहां से कोई नहीं गुजर रहा था। चट्टान से लगभग 50 मीट हाईवे ध्वस्त हो गया। भूस्खलन की वजह से लामबगड़ परगासी पैदल मार्ग व अलकनंदा किनारे बनाए गए पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गए। परगासी गांव के पास भूमि में दरारें आ गईं। चमोली में बदरीनाथ हाईवे पर सोनला के पास जेसीबी मशीन पहाड़ी से आए मलबे में दब गई।

हाईवे बाधित होने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बदरीनाथ जा रहे यात्रियों को पांडुकेश्वर, गोविंदघाट, जोशीमठ में ही रोक दिया, इनकी संख्या लगभग एक हजार बताई जा रही है।

बदरीनाथ धाम में बुधवार को दर्शनों के लिए पहुंचे तकरीबन दो हजार यात्री वहीं फंसे हुए हैं। ये पूरे दिन हाईवे खुलने का इंतजार करते रहे। नायब तहसीलदार बल्लू लाल का कहना है कि पैदल मार्ग बनाने व सड़क खोलने का कार्य चल रहा है। चमोली के पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि स्लाइडिंग जोन में एसडीआरएफ और पुलिस के जवान स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। यात्रियों को खतरों से भी आगाह करा रहे हैं। हाईवे शुक्रवार तक खुलने की संभावना जताई जा रही है।

चमोली में गुरुवार को लामबगड़ के पास भूस्खलन होने से बदरीनाथ हाईवे बंद हो गया। हाईवे दिनभर बंद रहा और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जागरण

आराकोट नहीं पहुंच पाई टीम

मौसम की खराबी की वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र आराकोट नहीं पहुंच पाई। गृह मंत्रालय भारत सरकार आपदा प्रबंधन के संयुक्त सचिव संजीव कुमार जिंदल के नेतृत्व में सात सदस्यीय टीम को गुरुवार सुबह हेलिकॉप्टर से आराकोट पहुंचना था, लेकिन आराकोट में मौसम खराब होने के कारण यह संभव नहीं हो पाया। इसके चलते टीम देहरादून से सड़क मार्ग से ही रवाना हुई। देर शाम को यह टीम त्यूणी पहुंची, जो शुक्रवार को आराकोट पहुंचेगी। आराकोट में 18 अगस्त को आई आपदा में जानमाल का नुकसान हुआ था। इसके बाद यहां राहत कार्यों में जुटा हेलिकॉप्टर भी क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट समेत तीन की मौत हो गई थी।

हाई कोर्ट ने कहा, मालेगांव धमाके की सुनवाई शीघ्र पूरी करे एनआइए कोर्ट

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने एनआइए अदालत को सितंबर 2008 के मालेगांव धमाके की सुनवाई शीघ्र पूरी करने को कहा है। इस मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी आरोपित हैं।

जस्टिस रंजीत मोरे की पीठ गुरुवार को इस मामले के आरोपित समीर कुलकर्णी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें दावा किया गया था कि इस मामले की सुनवाई बेहद धीमी हो रही है, क्योंकि अभियोजन ने रोजाना सिर्फ एक गवाह को समन किया है। कुलकर्णी ने कहा, 'अगर कोई गवाह कोर्ट में उपस्थित होने में विफल रहता है तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। यहां तक कि आरोपित भी कुछ न कुछ आवेदन करते रहते हैं, जिस कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है।' राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के वकील संदेश पाटिल ने कोर्ट को बताया कि अब तक 128 गवाहों के बयान हो चुके हैं, जबकि 369 के बाकी हैं। दोनों पक्षों की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने विशेष कोर्ट को शीघ्र से शीघ्र मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए कहा। याचिका का निस्तारण करते हुए कोर्ट ने कहा, 'हम भी नहीं चाहते हैं कि अभियोजन या आरोपित कोई भी ऐसा प्रयास करे जिससे सुनवाई पूरी होने में देरी हो।'

उल्लेखनीय है कि 29 सितंबर 2008 को उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव की एक मस्जिद के पास धमाका हो गया था। इसमें छह लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और इस मामले के अन्य आरोपितों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून समेत आइपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

कोर्ट ने टॉल्सटाय की नहीं, माओवादियों की 'वार एंड पीस' का जिक्र किया था

राज्य ब्यूरो, मुंबई

▸ बांबे हाई कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान स्पष्ट हुई स्थिति

बांबे हाई कोर्ट ने बुधवार को भीमा कोरेगांव मामले के एक आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए महान लेखक लियो टॉल्सटाय लिखित 'वार एंड पीस' का नहीं, बल्कि माओवादियों पर लिखे एक निबंध संग्रह 'वार एंड पीस इन जंगलमहल : पीपुल, स्टेट एंड माओइस्ट' का जिक्र किया था। यह बात गुरुवार को हुई इसी मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट हो गई।

बुधवार को यलगार परिषद-भीमा कोरेगांव मामले के एक आरोपित वी. गोंजाल्विस की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसके घर से पुणे पुलिस द्वारा बरामद साहित्य कि सूची पढ़ते हुए जस्टिस सारंग कोतवाल के मुंह से 'वार एंड पीस' शब्द निकला था। गलत रिपोर्टिंग के कारण इसे न सिर्फ महान लेखक लियो टॉल्सटाय की मशहूर कृति 'वार एंड पीस' समझा गया बल्कि सोशल मीडिया पर बांबे हाई कोर्ट और न्यायाधीश की खिल्ली उड़ाने का सिलसिला भी चल निकला। जबकि यह कृति बिश्वजीत रॉय द्वारा संपादित निबंध संग्रह 'वार एंड पीस इन जंगलमहल : पीपुल, स्टेट एंड माओइस्ट' थी जिसमें माओवादियों से संबंधित निबंधों का संग्रह किया गया है। यह स्पष्टीकरण गुरुवार को इसी मामले की एक और आरोपित सुधा भारद्वाज के वकील युग चौधरी ने कोर्ट में दिया। चौधरी ने कोर्ट को बताया कि मीडिया द्वारा पुस्तक का नाम गलत लिखे जाने के कारण यह विवाद पैदा हुआ, जबकि पुलिस के पंचनामे में दर्ज पुस्तक बिश्वजीत रॉय द्वारा संपादित निबंध संग्रह थी। मीडिया द्वारा की गई रिपोर्टिंग पर खेद जताते हुए जस्टिस कोतवाल ने कहा कि इस प्रकार की गई रिपोर्टिंग बांबे हाई कोर्ट जैसी संस्था की छवि को ठेस पहुंचाने वाली है। मुझे यह रिपोर्ट देखकर धक्का लगा।

बता दें कि बुधवार को जस्टिस कोतवाल के मुंह से वार एंड पीस का जिक्र तब आया जब गोंजाल्विस के वकील ने तर्क दिया कि आरोपित के घर से बरामद कोई भी पुस्तक सीआरपीसी की धाराओं के तहत सरकार द्वारा प्रतिबंधित साहित्य में नहीं आती। गुरुवार को जस्टिस कोतवाल ने बुधवार की घटना को याद करते हुए कहा कि आप जब बता रहे थे कि पुस्तक प्रतिबंधित नहीं है तो मैं आरोपपत्र में दी गई पूरी सूची पढ़ रहा था। यह बहुत ही बुरी हस्तलिपि में लिखी गई थी। मैं लियो टॉल्सटाय द्वारा लिखित वार एंड पीस के बारे में जानता हूं। मैं वह पूरी सूची जांच रहा था जो पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई है।

बांबे हाई कोर्ट। फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने शाहजहांपुर से छात्रा की गुमशुदगी की खबरों पर संज्ञान लिया

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ आरोप लगाने के बाद गायब छात्रा की खबरों पर स्वतः संज्ञान ले लिया है। बुधवार को वकीलों के एक समूह ने शीर्ष कोर्ट से संज्ञान लेने का अनुरोध किया था। शुक्रवार को जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ इसपर सुनवाई करेगी।

छात्रा ने वीडियो क्लिप में चिन्मयानंद पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद छात्रा के लापता हो जाने पर शाहजहांपुर पुलिस ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एफआइआर दर्ज की। छात्रा के पिता ने पुलिस को सौंपी गई शिकायत में पूर्व केंद्रीय मंत्री पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। भाजपा नेता के वकील ने ब्लैकमेल की साजिश का दावा किया है। छात्रा के पिता ने कहा है कि 72 वर्षीय भाजपा नेता की शह पर उनकी बेटी को गायब कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुमुक्षु आश्रम के प्रधान भी हैं। यह छात्रा आश्रम संचालित कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा है।

बुधवार को वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और छात्रा के कॉलेज के प्रिंसिपल को नोटिस जारी करने का आग्रह किया था ताकि उसका पता लगाया जा सके। वकीलों ने छात्रा और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है।

पुलिस ने सील किया छात्रा का कमरा

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर

पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाकर अचानक लापता होने वाली छात्रा का कमरा तीन दिन बाद गुरुवार को पुलिस ने सील कर दिया। साथ ही हॉस्टल के मुख्य दरवाजे पर ताला डाल दिया। छात्रा के परिजनों का कहना था कि कमरे में कुछ सुबूत हो सकते हैं। कमरा सील नहीं किया गया तो सुबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। प्रकरण में स्वामी चिन्मयानंद पर छात्रा के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज है।

मुमुक्ष आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद के कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा वहीं हॉस्टल में रहती थी। कॉलेज में ही पार्ट टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नौकरी भी करती थी। हालांकि छात्रा का घर शाहजहांपुर में ही है, मगर परिवार की आर्थिक हालत देख उसे हॉस्टल में रहने की अनुमति दे दी गई थी। बता दें छात्रा को तलाशने को पुलिस की पांच टीमें लगाई गई हैं। इनमें से तीन टीमें दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। 24 अगस्त को छात्रा की लोकेशन दिल्ली में ही मिली थी। 24 अगस्त को छात्रा का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह गंभीर आरोप लगा रही। दुष्कर्म और शारीरिक शोषण किए जाने की बात भी कही। इसके बाद से वह लापता है। इस बीच छात्रा के परिजनों ने 27 अगस्त को स्वामी चिन्मयानंद पर उसके अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था।

वहीं, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने शाहजहांपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर उन्हीं के कॉलेज की छात्रा के अपहरण की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। डीएम शाहजहांपुर व एसपी से तत्काल रिपोर्ट तलब की है।

अनंत सिंह दो दिन की पुलिस रिमांड पर, वकील से कर सकेंगे मुलाकात

जागरण संवाददाता, पटना : एके-47 बरामदगी मामले में मोकामा (पटना, बिहार) विधायक अनंत सिंह दो दिन पुलिस की रिमांड में रहेंगे। बाढ़ की कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि रिमांड के दौरान 24 घंटे में विधायक अपने वकील से एक बार मिल सकते हैं। रिमांड मिलने के बाद गुरुवार पटना पुलिस की टीम बेउर जेल में बंद विधायक को निकालकर पूछताछ के लिए गुप्त स्थान पर ले गई।

रिमांड के दौरान पुलिस टीम बाहुबली विधायक अनंत सिंह से उनके बाढ़ स्थित पैतृक घर में मिली एके-47 और ग्रेनेड के बारे में जानकारी हासिल करेगी। बरामद हथियार और विस्फोटक कब और कहां से लाए गए, किसने दिए, कितने में खरीदे गए, इनका इस्तेमाल कहां- कहां किया गया, ये सारे सवाल पुलिस उनसे पूछना चाहती है। पुलिस ने घर से बरामद एके 47, कारतूस और ग्रेनेड के मामले में अनंत सिंह पर बाढ़ थाने में मामला दर्ज किया है। अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। बुधवार को बाढ़ कोर्ट में अनंत सिंह की रिमांड को लेकर पुलिस और विधायक के वकीलों ने अपनी-अपनी दलील पेश की थी। इसके बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया।

पुरी के ऐतिहासिक एमार मठ पर चला बुल्डोजर

जेएनएन, पुरी : पुरी स्थित श्रीजगन्नाथ भगवान के श्रीमंदिर के आसपास अनधिकृत निर्माण को हटाने पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इन्कार के बाद लगभग 900 साल पुराने ऐतिहासिक एमार मठ को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। कोर्ट ने मंदिर परिसर के 75 मीटर के दायरे में स्थित सभी अनधिकृत निर्माण को हटाने के आदेश दिए हैं।

ओडिशा के सबसे धनी मठों में से एक एमार मठ श्रीमंदिर के सिंह द्वार के सामने है और उसके 75 मीटर के दायरे में आता है। बुधवार दोपहर बाद शुरू प्रशासन की कार्रवाई में पहले इस चार मंजिला मठ के सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित रघुनंदन लाइब्रेरी को तोड़ा गया है। इस कार्य में दस से अधिक ब्रेकर एवं बुल्डोजर लगाए गए हैं। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर दस प्लाटून पुलिस बल तैनात है। एहतियातन स्नेक हेल्पलाइन के सदस्यों को भी बुलाया गया है। परिसर में मौजूद दुकानों सहित अन्य सामान को पहले ही हटा दिया गया था। कर्मचारियों के फिलहाल बगला धर्मशाला में रहने की व्यवस्था की गई है, मगर वे लोग स्थायी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने एमार मठ के साथ ही सात और पुराने मठों को तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है।

मठ के अंदर मिला सुरंगनुमा घर : एमार मठ को तोड़ते समय गुरुवार को जमीन के अंदर सुरंगनुमा घर पाया गया है। मठ से कई साल पहले 400 से अधिक चांदी की ईंट मिल चुकी हैं। ऐसे में इस सुरंगनुमा घर के बारे में लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है। लोगों को लगता है कि 12वीं सदी के इस मठ में काफी मात्रा में गुप्त धन छिपा हुआ है। मठ के महंत राजगोपाल रामानुज दास महाराज यह जगह छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वे मठ के अंदर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं।

ओडिशा के तटीय शहर पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर के आसपास क्षेत्र में सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। सोमवार को मंदिर के 75 वर्ग मीटर क्षेत्र बनी इमारतों, मंदिरों और अन्य निर्माणों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। कई प्राचीन मंदिर भी इसकी चपेट में आए हैं। एएनआइ

सेना को चीन निर्मित डोंगल की आपूर्ति पर भेल की पूर्व अधिकारी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

▸ सीबीआइ ने आपूर्ति में 54 लाख से अधिक का माना घोटाला

▸ चार आरोपितों के खिलाफ जारी हुए थे गैर जमानती वारंट

सेना को चीन में बने डोंगल (इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होने वाला उपकरण) सप्लाई करने के आरोप में सीबीआइ ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) की पूर्व डिप्टी मैनेजर मधु शर्मा को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। सीबीआइ कोर्ट ने चार सितंबर तक मधु को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में सीबीआइ कोर्ट ने चार आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

सीबीआइ के लोक अभियोजन अधिकारी हरिमोहन ने अदालत को बताया कि 2012-13 में सेना ने भेल को पहाड़ी क्षेत्र के लिए हाई फ्रीक्वेंसी वाले एक हजार डोंगल की सप्लाई का ऑर्डर दिया था। सेना के तमाम उपकरण की सप्लाई भेल से होती है। भेल कुछ उपकरण बाहरी कंपनियों से बनवाती है। क्वालिटी चेक करने के बाद उसे सेना को सप्लाई की जाती है।

कंपनी के तत्कालीन अधिकारियों और डिप्टी मैनेजर मधु शर्मा ने चीन में बना डोंगल दो कंपनियों से लेकर सेना को सप्लाई कर दिया। 2015 में भेल के ही एक अधिकारी ने मामले की जांच की तो पता चला कि सेना को घटिया किस्म के डोंगल की सप्लाई करते हुए निजी लाभ कमाया गया है। विभागीय जांच के बाद अधिकारी ने सीबीआइ जांच की सिफारिश की।

सीबीआइ ने 26 जून 2015 को रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच की तो लगभग 54 लाख रुपये का घोटाला सामने आया। मामले में मधु शर्मा सहित चार के अलावा डोंगल सप्लाई करनेवाली दो कंपनियों को आरोपित माना। इस मामले में सीबीआइ ने 28 जून को चार्जशीट अदालत में पेश की। सीबीआइ टीम ने छापा मारते हुए दिल्ली से मधु शर्मा को गिरफ्तार गुरुवार शाम अदालत में पेश किया।

आइएस मॉड्यूल मामले में कोयंबटूर में छापेमारी

कोयंबटूर, प्रेट्र: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने आतंकी संगठन आइएस के केरल-तमिलनाडु मॉड्यूल मामले में गुरुवार को यहां पांच जगहों पर छापेमारी की। इसके लिए एनआइए कोर्ट, एर्नाकुलम ने वारंट जारी किया था।

▸ एनआइए ने केरल-तमिलनाडु मॉड्यूल मामले में की कार्रवाई

▸ एजेंसी ने इसी साल मई में दर्ज किया है मामला

एनआइए के बयान के अनुसार, 'आरोपितों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान एक लैपटॉप, पांच मोबाइल फोन, चार सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, आठ सीडी-डीवीडी और बड़ी संख्या में संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए। जब्त डिजिटल उपकरणों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा।' एनआइए ने बताया, 'संदिग्धों से गिरफ्तार लोगों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। उनसे आइएस (इस्लामिक स्टेट) के षड्यंत्रों और उनकी भूमिका के बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है।'

एजेंसी ने इसी साल मई में मामला दर्ज किया है। एनआइए को सूचना मिली थी कि कुछ लोग आइएस के आतंकी विचारों को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं। उनका उद्देश्य एक आतंकी समूह बनाकर दक्षिण भारत और खासकर केरल तथा तमिलनाडु में हिंसक वारदातों को अंजाम देना है।

एनआइए के अनुसार, 'कुछ आरोपित श्रीलंका में हुए ईस्टर धमाकों के मास्टरमाइंड जहरान हाशिम और उसके सहयोगियों के साथ सोशल मीडिया के जरिये संपर्क में थे। इसी सिलसिले में पूर्व में की गई छापेमारी में एनआइए ने शहर से मुहम्मद अजरुद्दीन और शेख हिदायतुल्ला को गिरफ्तार किया था।

इससे पहले पुलिस ने कहा था कि गुरुवार को संदिग्धों के ठिकानों पर की गई छापेमारी तमिलनाडु में जारी हालिया आतंकी अलर्ट के सिलसिले में है। उसने कहा था कि संदिग्धों का संबंध लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के उन छह आतंकियों से है, जो पिछले ही सप्ताह श्रीलंका होते हुए तमिलनाडु में प्रवेश करने के बाद राज्य के विभिन्न शहरों में फैल चुके हैं।

बंगाल में नया मॉड्यूल तैयार करने की फिराक में था बांग्लादेशी आतंकी संगठन

जागरण संवाददाता, कोलकाता

जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) बंगाल में नया मॉड्यूल तैयार करने की फिराक में था। इस बाबत उसने काम करना भी शुरू कर दिया था। गत मंगलवार को कोलकाता पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के हत्थे चढ़े जेएमबी के शीर्ष कमांडर एजाज अहमद ने पूछताछ में यह सनसनीखेज जानकारी दी।

उसने बताया कि वह उत्तर बंगाल को आतंक का गढ़ बनाने की कोशिश कर रहा था। इस बाबत उसने पिछले साल में कई बार उत्तर बंगाल का दौरा किया था। वह मुर्शिदाबाद जिले में मॉड्यूल को मजबूत कर रहा था। इसी तरह उत्तर दिनाजपुर जिले में भी नया मॉड्यूल तैयार कर रहा था। उत्तर दिनाजपुर में इटाहार मॉड्यूल और मुर्शिदाबाद में लालगोला मॉड्यूल तैयार किया जा रहा था। इसमें जेएमबी के अंतरराष्ट्रीय नेता सलाउद्दीन सालेहिन भी सक्रिय भूमिका निभा रहा था।

आतंकियों की भर्ती की जा रही थी : रायगंज, बालुरघाट, इस्लामपुर, ईटाहार से शुरू करके दक्षिण दिनाजपुर व मालदा जिलों की विभिन्न जगहों पर आतंकियों की भर्ती शुरू की गई थी। एजाज बंगाल में आतंकी गतिविधियां देखने के लिए उपयुक्त व्यक्ति भी तलाश रहा था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जेएमबी ने इससे पहले उत्तर बंगाल में कभी अपना मॉड्यूल तैयार नहीं किया था। मालदा से बांग्लादेश में घुसपैठ करने के बावजूद उसने यह कदम नहीं उठाया था।

कौन है एजाज : वीरभूम जिले के पारुई के रहने वाले 30 साल के एजाज को एसटीएफ ने गत मंगलवार को गिरफ्तार किया था। आंतकी कौसर के पकड़े जाने के बाद एजाज को भारत में जेएमबी का शीर्ष कमांडर बनाया गया था।

पोखरण फायरिंग रेंज में टैंक का बैरल फटा

जागरण संवाददाता, जयपुर: राजस्थान के सीमावर्ती जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास के दौरान टैंक का बैरल फट गया। बताया जाता है कि सेना के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले टैंक-90 'भीष्म' टैंक का बैरल जोरदार धमाके के साथ फट गया। बताया जाता है कि गोला, टैंक के बैरल में ही रह जाने से यह हादसा हुआ। अलबत्ता, असल वजह क्या रही है, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। हादसे के दौरान किसी जवान के हताहत होने की बात सामने नहीं आई है।

सैन्य सूत्रों के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है कि सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले टैंक 'भीष्म' का बैरल फटा हो। सेना ने इसकी जांच शुरू कर दी है। हादसा बुधवार देर शाम को उस समय हुआ, जब टी-90 रूसी युद्धक टैंक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में टैंक फायरिंग प्रैक्टिस में हिस्सा ले रहा था। टी-90 युद्धक टैंक एक खास प्रकार का टैंक है, जो रात में भी दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। सेना पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास के दौरान इन टैंकों की मारक क्षमता का परीक्षण कर रही है।

बढ़ी परेशानी

2200 करोड़ रुपये की परियोजना का सीएम ने किया था बुधवार को उद्घाटन, नहर टूटने से खेतों में भर गया पानी, नष्ट हो गई फसल

42 साल बाद मिली नहर महज 12 घंटे में ही टूट गई

जेएनएन, गिरिडीह

करीब 42 साल बाद झारखंड में कोनार सिंचाई परियोजना का सपना साकार हुआ। हजारीबाग, गिरिडीह और रामगढ़ के किसान फूले नहीं समा रहे थे कि अब उनके खेतों को पानी मिलेगा। दोगुनी आय, उन्नत फसलों के सपने तैर ही रहे थे कि सब चकनाचूर हो गया। बुधवार को उद्घाटन के महज 12 घंटों के अंदर 2200 करोड़ रुपये की लागत से बनी कोनार सिंचाई परियोजना का एक हिस्सा गिरिडीह स्थित बगोदर के घोसको गांव में भरभरा कर गिर गया। सैकड़ों एकड़ खेत पानी से भर गए। फसल नष्ट हो गई। एक घर क्षतिग्रस्त हो गया। एक किसान की चारदीवारी टूट गई। जो किसान खुशियां मना रहे थे वे अब अपने खेतों की बदहाली देख मातम मना रहे हैं। डैम से पानी का प्रवाह रोकने के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका।

घटना के बाद सरकार ने आनन-फानन में जांच के लिए टीम बना दी और 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा। इधर, मुख्य विपक्षी दल झामुमो ने इसे भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए जांच की मांग की है। लेकिन इंजीनियरों की हास्यास्पद दलीलें सामने आई हैं। कहा गया, चूहों ने संभवतः तटबंध में छेद कर दिया जिससे यह घटना हुई।

गिरिडीह जिले के बगोदर में कोनार नहर टूटने के बाद आसपास के क्षेत्र में नहर का बहता पानी। इस नहर का उद्घाटन बुधवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया था। जागरण

> कोनार नहर परियोजना के नहर टूटने एवं फसल नष्ट होने की घटना की जांच के लिए मुख्य अभियंता अग्रिम योजना जल संसाधन विभाग रांची के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी गई है, जिसे 24 घंटों के भीतर अपना प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया है।
>
> **–अरुण कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।**

रात बारह बजे हुआ हादसा : मुख्यमंत्री रघुवर दास के उद्घाटन करने के बाद बुधवार को कोनार डैम से पानी छोड़ा गया तो घोसको कैनल तक पानी लबालब भर गया था। कैनल से कुछ दूर आगे मिट्टी से बनी मेढ़ पानी का दबाव सह नहीं सकी। रात 12 बजे टूट गई। महज एक घंटे के भीतर बगोदर स्थित घोसको के अलावा बरवाडीह, प्रतापपुर एवं घटैया गांव के किसानों को इससे नुकसान हुआ है। नजदीक स्थित एक घर भी क्षतिग्रस्त हो गया। सुबह लोगों ने खेतों को लबालब भरे देखा तो हुजूम इकट्ठा होने लगा।

पंजाबी फिल्म कौम दे हीरे के प्रसारण को हरी झंडी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के आदेश को हाई कोर्ट ने किया रद

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा सार्वजनिक स्क्रीनिंग के लिए जारी प्रमाणपत्र को वापस लेने के आदेश को रद करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पंजाबी फिल्म 'कौम दे हीरे' के प्रसारण का रास्ता साफ कर दिया। आरोप है कि फिल्म में सतवंत सिंह, बेअंत सिंह व केहर सिंह द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का गुणगान किया गया है।

न्यायमूर्ति विभू बाखरू की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब विशेषज्ञों ने फिल्म का लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार कर इसे हरी झंडी दे दी है तो फिर यह कहना सही नहीं है कि इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। आदेश जारी करने से पहले याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। पहले फिल्म को ए ग्रेड दिया गया था, लेकिन बाद में सरकार ने फिल्म के प्रसारण पर रोक लगा दी थी।

याचिका के अनुसार, फिल्म के निर्माता साईं सिने प्रोडक्शन ने सीबीएफसी के अगस्त 2014 के सर्टिफिकेशन को चुनौती दी थी और सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश पर फिल्म को जारी प्रमाण पत्र वापस लिया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रमाण पत्र जारी करने के बाद सेंसर बोर्ड के पास इसे वापस लेने का तथ्यात्मक व कानूनी आधार नहीं है। याचिका के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय व सीबीएफसी ने कहा है कि सिनेमैटोग्राफी एक्ट-1952 व केंद्र सरकार के आदेश पर प्रमाणपत्र वापस लिया गया है। सीबीएफसी के चेयरमैन के पास अधिकार नहीं है कि जारी प्रमाणपत्र का वह रिव्यू कर सकें। उन्होंने कहा कि रिवाइजिंग कमेटी द्वारा दो बार फिल्म देखने के बाद सीबीएफसी की तरफ से प्रमाणपत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि रिवाइजिंग कमेटी के फैसले को चेयरमैन बदल सके।

माया से मुक्ति ही मोक्ष का द्वार खोलती है

पाकिस्तान का प्रलाप

कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के रोने-धोने और साथ ही उसके धमकाने एवं उकसाने वाले रवैये पर भारत ने यह कहकर एक तरह से उसकी अनदेखी ही की कि वह गैर जिम्मेदारी का परिचय देकर माहौल खराब करने का काम कर रहा है। जम्मू-कश्मीर के मामले में भारत सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद पाकिस्तान जिस तरह अपनी बौखलाहट का अभद्र प्रदर्शन कर रहा है उससे उसकी जगहंसाई ही हो रही है। हैरानी यह है कि वह इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि चीन को छोड़कर अन्य कोई प्रमुख देश उसका रुदन सुनने को तैयार नहीं। कम से कम अब तो पाकिस्तान को यह आभास हो ही जाना चाहिए कि वह इस छलावे में जी रहा था कि कश्मीर उसका है और एक दिन उसे हासिल करके रहेगा। इस छलावे के चलते ही उसने अपनी सेना को अपने पर हावी होने दिया। चूंकि पाकिस्तान ने इस सच का सामना करने से जानबूझकर इन्कार किया कि कश्मीर पर उसका अधिकार नहीं बनता और वह उसे छल-बल से हासिल नहीं कर सकता इसीलिए अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह करे तो क्या करे? इसी बौखलाहट में वह कभी भारत को सबक सिखाने की धमकी दे रहा है तो कभी दुनिया को कोस रहा है। बेहतर हो कि आम पाकिस्तानी अपनी सरकार और साथ ही अपनी सेना से यह साधारण सा सवाल पूछें कि क्या जम्मू-कश्मीर संबंधी अनुच्छेद 370 उनसे पूछकर या फिर उनकी सलाह से बनाया गया था? इसे तो भारत ने विशेष परिस्थितियों में अपने स्तर पर बनाया था और जब यह देखा कि उससे नुकसान ज्यादा और फायदा कम है तो हटा लिया। आखिर इस पर पाकिस्तान अथवा अन्य किसी देश को हाय-तौबा क्यों मचाना चाहिए?

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान जिस तरह आसमान सिर पर उठाए हुए है उससे तो यही साबित होता है कि यह अनुच्छेद जाने-अनजाने उसके हितों की ही पूर्ति अधिक कर रहा था। यह सही है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी सेना की कठपुतली अधिक हैं, लेकिन उनमें इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि वह भारत को धमकाकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। भारत को झुकाने-डराने का ख्याली पुलाव पकाने के पहले उन्हें पाकिस्तान की छवि और साथ ही दयनीय आर्थिक दशा पर भी गौर करना चाहिए। चूंकि अपने सैन्य अफसरों के मुकाबले इमरान खान भारत से कहीं भली तरह परिचित हैं इसलिए वह इस हकीकत से भी दो-चार होंगे कि आज का भारत हर मामले में पाकिस्तान से बीस है। वह और उनके फौजी जनरल यह समझें तो बेहतर कि पाकिस्तान का हित भारत से संबंध सुधारने और उससे मिलकर चलने में है।

मुकदमों का बोझ

इस समय पटना हाईकोर्ट में केवल आपराधिक मामलों की संख्या एक लाख से अधिक है। साठ हजार के करीब सिविल वाद हैं। जाहिर है कि हाईकोर्ट तक मामला जिला न्यायालयों से गुजर कर आता है। इससे इस बात का आकलन हो सकता है कि जिला कोर्ट में भी लंबित मामलों की सूची कितनी लंबी होगी? जिला स्तर पर हाईकोर्ट का यह निर्देश रहता है कि मध्यस्थता केंद्र में वैसे मामले भेजे जाएं जो सुलह योग्य हैं, लेकिन इसकी गति धीमी है। काउंसिलिंग सेंटर में भी 12 सदस्यों की समिति है जो दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास करती है। इस कड़ी में विधिक सेवा प्राधिकार की भूमिका पहचानकर इसका गठन किया गया है। इसके तहत काउंसिलिंग सेंटर, मध्यस्थता केंद्र, निरंतर लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत के गठन का प्रावधान है। जिन जिलों में इनकी सक्रियता है, वहां लंबित मामले कम हैं। स्थायी लोक अदालत आदेश तक पारित कर सकती है। निरंतर लोक अदालत भी समझौता कराकर मामले को निष्पादित कर सकती है। लगभग पूरे देश में ऐसी व्यवस्था है। न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों को इस पर और बल देना चाहिए। यह स्वागत योग्य है कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एपी शाही ने स्वयं पहल कर बहुत पुराने मुकदमों के निपटारे की चिंता की है। अभी दैनिक जागरण में एक ऐसे ही पुराने मामले का जिक्र छपा है। पटना हाईकोर्ट के 12वें मुख्य न्यायाधीश बी. रामास्वामी के कार्यकाल में दर्ज हुए भोजपुर के भूमि विवाद की सुनवाई 42वें मुख्य न्यायाधीश एपी शाही अभी कर रहे हैं। महज पांच एकड़ भूमि के मालिकाना हक को लेकर 1964 से अदालत में लंबित इस मामले के निपटारे की पहल स्वयं मुख्य न्यायाधीश ने की है। रोचक है कि अपीलार्थी के वकील अनीशचंद्र सिन्हा से पहले उनके पिता दिवंगत जेसी सिन्हा इस मामले में पैरवी कर रहे थे। 1976 में उनकी मृत्यु के बाद इस समय अनीशचंद्र इस मामले को देख रहे हैं। केवल न्यायालय के भरोसे यह बोझ कम नहीं होगा। गांव, गांव की पंचायत, ग्राम कचहरी सबको अपनी भूमिका में आना होगा। आम आदमी को समझना होगा कि बहुत जरूरी न हो तो अदालत का समय न बर्बाद किया जाए। यह भी जरूरी है कि कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जाए। जो पद खाली हैं, उनको भरा जाए। बढ़ती आबादी के सापेक्ष जजों की संख्या में अपेक्षित विस्तार भी आवश्यक है।

चीन का चिंतित करने वाला रवैया

ब्रह्मा चेलानी

यदि भारत चीन की उकसाने वाली गतिविधियों की अनदेखी करता रहा तो उसके साथ वार्ता में भारतीय पक्ष खुद को कमजोर ही महसूस करेगा

मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा और उसे मिले संवैधानिक विशेषाधिकार समाप्त करना भारत के लिए ऐतिहासिक पड़ाव है। मोदी सरकार ने यह कदम केवल घरेलू कारकों को देखकर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पहलुओं को ध्यान में रखकर भी उठाया। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कश्मीर में मध्यस्थता के शिगूफे से लेकर पाकिस्तान की शह वाले अफगान तालिबान से अमेरिका की सौदेबाजी जैसे पहलू भी शामिल रहे। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद चीन ने जम्मू-कश्मीर मुद्दे के अंतरराष्ट्रीयकरण की पहल की। इसके लिए उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक विशेष, लेकिन अनौपचारिक बैठक बुलाई। उसने बहुत निर्लज्ज ढंग से इस विवाद में अपनी भूमिका पर पर्दा डाल दिया, जबकि वह जम्मू-कश्मीर के 20 प्रतिशत भूभाग पर अवैध रूप से कब्जा किए बैठा है। उसने इस मसले को केवल भारत-पाकिस्तान के मुद्दे के रूप में पेश किया। यह मानना पूरी तरह गलत होगा कि सुरक्षा परिषद में चीन की इस कवायद से कुछ हासिल नहीं हुआ। इस दावपेंच से पाकिस्तान और उसके पिट्ठुओं का हौसला बढ़ेगा। चीन की शरारत से जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों को भी मदद मिली।

भले ही सुरक्षा परिषद की बैठक का कोई ठोस नतीजा न निकला हो, लेकिन इस बैठक ने भारत की जम्मू-कश्मीर नीति को अंतरराष्ट्रीय चर्चा में ला दिया। बंद कमरे में हुई बैठक में इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बाद पहली बार सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर चर्चा हुई। चीनी षड्यंत्र भारत को यही स्मरण कराता है कि जम्मू-कश्मीर के मामलों में उसका दखल और बढ़ेगा। चीन की रणनीति ही यह है कि वह भारत की दुखती रग छेड़कर गतिरोध को चरम पर ले जाए। बीजिंग जम्मू-कश्मीर को भारत की बड़ी कमजोरी के रूप में देखता है। इसके उलट जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक बदलाव से भारत को जम्मू, कश्मीर एवं लद्दाख में चीन-पाकिस्तान की साठगांठ से निपटने में मदद मिलेगी। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर भारत ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े अपने सीमा विवाद को भी पाकिस्तान एवं चीन के साथ अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया।

अनुच्छेद 370 के चलते पाकिस्तान का रवैया यही रहा कि भारत जम्मू-कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है। चूंकि केवल स्थाई नागरिकों को ही राज्य में जमीन खरीदने की इजाजत थी इसलिए कश्मीर घाटी में इस्लामी कट्टरपंथी हावी हो गए। वहां से कश्मीरी पंडितों को जबरन भगा दिया गया। अपनी विविधता भरी नस्लीय एवं धार्मिक पहचान के साथ जम्मू-कश्मीर बहुलतावादी भारत का एक उम्दा प्रतीक था, मगर उसकी समन्वयकारी संस्कृति और परंपराओं पर जिहादी आघात से पूरा परिदृश्य बदल गया। 1989 के बाद नई दिल्ली में सत्तारूढ़ सरकारें इस रुझान को रोकने में असहाय रहीं। परिणामस्वरूप कश्मीर की विविधता भरी परंपराओं पर वहाबी और सलाफी रीति-रिवाज हावी होते गए। अनुच्छेद 370 की समाप्ति से भले ही कश्मीर घाटी में इस्लाम का अरबीकरण न रुके, लेकिन इससे भारतीय संघ में जम्मू-कश्मीर के वास्तविक रूप से एकीकरण की समस्या जरूर सुलझेगी। वास्तव में इस परिवर्तन से जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा संबंधी फैसलों पर केंद्र सरकार और मजबूती के साथ निर्णय कर सकेगी।

अवधेश राजपूत

जम्मू-कश्मीर में उठाए गए कदमों के आलोक में भारत ने अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला, मगर अब उसे आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय चुनौतियों पर ध्यान देना होगा। सरकार द्वारा आवाजाही और संचार के स्तर पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उससे संविधानप्रदत्त मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। सुरक्षा के मोर्चे पर जोखिम को देखते हुए ये प्रतिबंध चरणबद्ध ढंग से हटाए जा सकते हैं।

जहां हांगकांग की जनता लोकतंत्र के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही है, वहीं कश्मीर के हथियारबंद जिहादियों का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं और वे खलीफा का शासन स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में प्रशासन को घाटी के अस्थिर जिलों में एक विकेंद्रित और सुनियोजित रणनीति के तहत इस तरह प्रतिबंध लगाने चाहिए जिससे स्थानीय स्तर पर शांति स्थापित हो। इसके लिए पुरस्कृत और साथ ही दंडित करने वाला रवैया अपनाया जाना चाहिए।

चीन-पाकिस्तान की गहरी होती साठगांठ भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। चीन के संरक्षण में पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार जिहादी आतंक का इस्तेमाल करता रहेगा। भारत को पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय उनके असली आका यानी फौजी हुक्मरानों पर शिकंजा कसना होगा। 2016 में उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो या फरवरी में बालाकोट हमला, ये दोनों कार्रवाइयां आतंकी ठिकानों पर हुईं। इनसे उन फौजी हुक्मरानों का कुछ नहीं बिगड़ा जो भारत को हजार घाव देने की रणनीति को धार देने में जुटे हैं। पाकिस्तान के पीछे असल ताकत चीन है, जिसके खिलाफ भारत आवाज बुलंद करने में भी हिचकता है। वास्तव में भारत के खिलाफ भारी व्यापार अधिशेष का इस्तेमाल कर चीन अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ा रहा है। वह एक गोली दागे बिना ही अपने आक्रामक हित साध रहा है। भारत एक तरह से खुद अपने नियंत्रण के साधन मुहैया करा रहा है। भारत के दूरसंचार क्षेत्र में चीन का पहले ही वर्चस्व कायम हो चुका है और हुआवे पर भारत में 5जी परीक्षण के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय भारत कोई बीच का रास्ता तलाश रहा है।

अप्रैल 2018 में वुहान की खुमारी हफ्ते भर तक नहीं टिक पाई। फिर भी चीन के हालिया उकसावे के बावजूद वुहान जैसी वार्ता के लिए चीनी राष्ट्रपति अक्टूबर में भारत आएंगे जो शायद वाराणसी में होगी। इससे पहले चीन भारत को सीमा विवाद से जुड़ी वार्ताओं में उलझाने की मंशा दिखा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भारत कम से कम इतना तो कर सकता है कि वह प्रमुख क्षेत्रों में चीन की राह रोके। अगर भारत लगातार चीन की उकसाने वाली गतिविधियों की अनदेखी करता रहेगा तो अगले महीने जब मोदी चीनी राष्ट्रपति के साथ वार्ता के लिए बैठेंगे तो भारतीय पक्ष कमजोर महसूस करेगा। यही बात अजीत डोभाल पर भी लागू होगी जब वह सीमा वार्ता के लिए चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलेंगे।

जम्मू-कश्मीर भारत के लिए एक सेक्युलर पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मूलभूत मुद्दा है। कुछ समय के लिए कश्मीर घाटी में हालात खराब होते दिख सकते हैं जिससे भारत पर देसी-विदेशी आलोचकों के साथ ही मानवाधिकारवादियों का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि दीर्घ अवधि में भारत के साथ व्यापक जुड़ाव और विकास की गतिविधियां कश्मीर घाटी में हालात सामान्य बनाने में योगदान देंगी। भारत को बड़ा फायदा हासिल करने के लिए इस क्षणिक दुख को झेलना ही होगा।

(लेखक सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

जीएसटी को साकार करने वाले अरुण जेटली

सुशील कुमार मोदी

वह जेटली ही थे जिन्होंने जीएसटी के विचार को वास्तविकता में बदला एवं उसे जमीन पर उतारा

आधुनिक भारत के संभवतः सबसे बड़े कन्सेंसस बिल्डर यानी आम सहमति का निर्माण करने वाले पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वह काम किया जो सरदार पटेल ने भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए किया था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यदि अरुण जेटली न होते तो शायद भारत में जीएसटी लागू करना कठिन होता। भारत सरीखे संघीय गणराज्य में जीएसटी लागू किया जाना दुनिया के किसी भी अन्य देश से कठिन काम था। इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव तब हुआ जब राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति का नेतृत्व करते हुए हम लोगों ने यूरोप, कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में जीएसटी के अमल की व्यवस्था देखी। कनाडा को छोड़कर सभी देशों में केंद्र सरकार जीएसटी संग्रह करती है और उसे केंद्र और राज्य के बीच वितरित करती है, परंतु भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्यों, दोनों को जीएसटी संग्रह करने का अधिकार दिया गया। इस कारण यहां दोहरा जीएसटी लागू करना और कठिन काम था। भारत जैसे विविधता वाले देश में जीएसटी लागू करने के लिए दूरदृष्टि, अथक परिश्रम, विषयवस्तु पर गहरी पकड़ और सभी पक्षों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता आवश्यक थी। संयोग से ये सभी गुण अरुण जी में भरे पड़े थे।

अरुण जेटली के वित्त मंत्री बनने से पहले जीएसटी की चर्चा लगभग एक दशक से चल रही थी, परंतु इसमें कोई विशेष प्रगति इसलिए नहीं दिख रही थी, क्योंकि राज्यों को केंद्र सरकार पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। केंद्रीय बिक्री कर की दर घटाए जाने के कारण राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्रीय बजट में घोषणा भी की गई, परंतु केंद्र के आश्वासन के बावजूद क्षतिपूर्ति किसी को नहीं मिली। केंद्र के इस रवैये से सभी राज्य सशंकित थे कि जीएसटी अमल से होने वाली क्षति की भरपाई होगी भी या नहीं? वित्त मंत्री का प्रभार लेने के बाद अरुण जेटली ने सर्वप्रथम पूर्व सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा किया एवं राज्यों को इस मामले में क्षतिपूर्ति प्रदान की। इस एक कदम से राज्यों का भरोसा बढ़ा। इससे जीएसटी पर चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ाना आसान हुआ। अरुण जी ने संविधान संशोधन का जो प्रारूप रखा उसमें राज्यों को जीएसटी के कारण हुई क्षति को पांच वर्षों तक 14 प्रतिशत की निश्चित वृद्धि से पूरा किए जाने का प्रस्ताव शामिल किया। इस निर्णय ने जीएसटी के प्रति राज्यों की प्रमुख चिंता का निवारण कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य जीएसटी पर सार्थक चर्चा करने में दिलचस्पी लेने लगे।

केंद्र और राज्यों के बीच कुछ अहम मुद्दों पर असहमति के कारण 2014 तक कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई थी। राज्यों की चिंता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे जैसे-प्रवेश कर और पेट्रो उत्पादों को जीएसटी में समाहित करने को लेकर अरुण जी ने दिसंबर 2014 में राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक समूह से अलग से बैठक करते हुए इन मुद्दों को सुलझाया और नए संविधान संशोधन विधेयक का खाका तैयार किया। इस नए प्रारूप पर सभी की आम सहमति हासिल करने के लिए उन्होंने राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति की बैठक में भाग लिया और लंबे विचार-विमर्श के बाद उस पर आम सहमति बनाने में सफल हुए। इसी कारण नया संविधान संशोधन विधेयक संसद में सर्वसम्मति से पारित हुआ एवं राज्यों ने भी इसका समर्थन किया। जीएसटी लागू करने के लिए यह पहला आवश्यक, निर्णायक एवं महत्वपूर्ण कदम था, जिसके फलस्वरूप जीएसटी परिषद का गठन हो सका।

परिषद की शुरुआती बैठकों में व्यवसायियों पर केंद्र एवं राज्यों के दोहरे नियंत्रण और जीएसटी के अधीन कर दरों के बारे में व्यापक चर्चा के बाद ही ऐसी व्यवस्था का निर्माण अरुण जी के नेतृत्व में संभव हो सका जो सबको स्वीकार्य हो। इन चर्चाओं में उन्होंने बड़े-से-बड़े एवं छोटे-से-छोटे राज्य की हर बात को ध्यान से सुना, सभी से राय ली और जीएसटी परिषद द्वारा निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया। परिषद की बैठक के पूर्व केंद्र एवं सभी राज्यों के अधिकारियों की बैठक की व्यवस्था भी उनके द्वारा बनाई गई। इन बैठकों से छन कर विचार परिषद में आते थे, जिससे परिषद द्वारा निर्णय लिए जाने में काफी आसानी होती थी। इसी के साथ ज्यादा-से-ज्यादा मुद्दों पर चर्चा और निर्णय भी संभव हो पाता था।

कुछ विवादित मामलों में आमतौर पर अरुण जी मंत्री समूह बना देते थे, जिसमें हर विचारधारा के मंत्री शामिल होते थे। इस प्रकार के एक दर्जन से अधिक समूह बने थे और उनकी बैठकों में विवाद के सभी पहलुओं पर सांगोपांग विचार-विमर्श होता था। इससे एक मान्य निष्कर्ष भी निकल आता था जिसे परिषद द्वारा बहुधा स्वीकार कर लिया जाता था। इसके अलावा अरुण जी कई बार विवादित मामलों को अगली बैठक तक के लिए स्थगित करवा देते थे और राज्यों को नए सिरे से उन मामलों पर विचार करने का आग्रह किया करते थे। लॉटरी पर दोहरी कर दर की व्यवस्था, सरकार को प्रदान की गई सेवाओं, रेस्टोरेंट, ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर टैक्स की दरों के साथ टीसीएस/टीडीएस, ई-वे बिल जैसे जटिल मुद्दों को अरुण जी ने आसानी से सुलझा दिया, जबकि इसकी उम्मीद कम ही दिखती थी। इन सभी मामलों में उनकी सूझ-बूझ, मामले की समग्र समझ, उनके विधि के ज्ञान, सबको साथ लेकर चलने की उनकी प्रवृत्ति और दृढ़ इच्छाशक्ति कारगर सिद्ध हुई।

मैं बिना किसी हिचकिचाहट से यह कह सकता हूं कि वह अरुण जेटली ही थे जिन्होंने जीएसटी के विचार को वास्तविकता में बदला एवं उसे जमीन पर उतारा। यह कार्य उस दौर में और भी कठिन था जब जीएसटी परिषद में भाजपा शासित राज्यों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। केंद्र सरकार, 29 राज्यों और सात केंद्रशासित प्रदेशों के मिले-जुले स्वरूप में गठित जीएसटी परिषद में किसी मुद्दे पर मत विभाजन नहीं हुआ तो यह केवल और केवल अरुण जी की सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति के कारण संभव हो पाया। अरुण जी ने कांग्रेस, माकपा से लेकर तृणमूल तक के वित्त मंत्रियों का विश्वास हासिल किया। इसी का परिणाम था कि असंभव सा दिखने वाले जीएसटी को उन्होंने क्रियान्वित कर दिखाया।

(लेखक बिहार के उपमुख्यमंत्री हैं)

response@jagran.com

प्रसन्नता

प्रसन्नता मनुष्य के जीवन की सबसे अमूल्य निधि है। यह स्नेह, भाईचारे, प्रेम-सद्भाव और त्याग की प्रवृत्ति से मिलती है। हमारे जितने आराध्य देव महापुरुष हुए सबने यही उदाहरण प्रस्तुत किया। भगवान श्रीराम ने तो राजपाट त्याग जंगल जाना पसंद किया। यही कारण है कि भगवान श्रीराम के 14 वर्ष के वनवास पर ग्रंथ लिखे गए। वनवास के बारे में सब जानते हैं, जबकि उनके राजकाज के बारे में बहुधा कम लोग जानते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के कंस-वध और महाभारत की कथा से सब परिचित हैं और इसका खूब गुणगान भी होता है। वहीं शिवजी का परम भक्त रावण था, लेकिन उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि वह दूसरों के सुख, संपत्ति, यश-वैभव का अपहरण करता था। इसलिए जो दूसरों को कष्ट, यातना अपने सुखोपभोग के लिए देता है, वह अंततः कष्ट पाता है।

इसी तरह का उदाहरण कलियुग के साथ भी है। उसे अपने राज्य में घुसते देख परीक्षित ने रोका और कहा कि तुम शक्ल-सूरत से अत्यंत कुरूप हो, आखिर तुम कौन हो? कलियुग ने परिचय दिया और कहा कि हमें ज्यादा नहीं कुछ ही स्थान दे दीजिए। उसके अनुनय विनय पर परीक्षित ने स्वर्ण, जुआ (द्युत क्रीड़ा), छल और झूठ में स्थान की अनुमति दे दी। मौका पाकर कलियुग परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश कर गया। इस प्रकार जब मस्तिष्क में विकार घुस जाते हैं तो प्रसन्नता गायब हो जाती है। अतः मस्तिष्क में श्रेष्ठ महापुरुषों के चिंतन-मनन को स्थान देना चाहिए ताकि जीवन में प्रसन्नता बनी रहे। इसके लिए अच्छे-अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और उसे जीवन में अपनाना भी चाहिए, क्योंकि महापुरुषों ने कहा भी है कि मन भर ज्ञान से तोला भर आचरण श्रेष्ठ होता है।

इसके उलट वर्तमान दौर में प्रायः लोग भौतिक वैभव को प्रसन्नता का कारण मानते हैं। इसके चलते सारे आदर्श और सिद्धांत को तिलांजलि दे देते हैं। तनाव से अर्जित भौतिक साधन अंततः तनाव ही देगा। इसलिए इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

सलिल पांडेय

खेल संस्कृति का अभाव

अमृत कुमार

किसी देश की एकता के लिए जरूरी प्रेम और मैत्री की भावना भी खेलों से विकसित की जा सकती है

अमेरिका में सभी छात्रों के लिए खेल अनिवार्य है। हर साल वहां हजारों मेधावी खिलाड़ी चुने जाते हैं और उन्हें अलग-अलग केंद्रों में निखारा जाता है। चीन में खेल स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। वहां पांच लाख से अधिक खेल विद्यालय हैं जहां गांवों, कस्बों से लाकर मेधावी खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाता है। जबकि भारत में खेल विद्यालयों का अभाव तो है ही, स्कूलों में खेल भी अनिवार्य नहीं है। इससे खिलाड़ियों की प्रतिभा का ह्रास हो रहा है।

निश्चित ही भारत जैसे युवा देश के लिए यह चिंता का विषय है। देखा जाए तो इसके कई कारण हैं। दरअसल हाल के दिनों में स्मार्ट फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग में तेज वृद्धि आई है। छोटी उम्र में बच्चों के हाथों में मोबाइल आने के बाद वे अपना सारा समय इसमें ही गंवा दे रहे हैं। दूसरा कारण मैदानों की निरंतर कमी होना है। गांवों में तो आज भी खुली जगह बच्चों को खेलने के लिए आमंत्रण देती है, लेकिन शहर की घुटन भरी जिंदगी में निकटवर्ती कोई मैदान बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित नहीं रहा है। जिसके कारण बच्चे खाली समय में अनायास ही मोबाइल और कंप्यूटर के खेलों के शिकार हो जाते हैं। तीसरा कारण है खेलों को लेकर हमारे समाज की नकारात्मक सोच, जिसके तहत कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। चौथा कारण है अभिभावकों के पास समय का अभाव होना। रोजमर्रा की जिंदगी में धनार्जन करने की प्रवृत्ति ने हर किसी को व्यस्त कर दिया है। ऐसे में आज के मासूमों को कौन डिब्बा स्पाइस, सतोलिया, लुका छिपी, लगंड़ी, कबड्डी, खो-खो इत्यादि बचपन के इन खेलों के बारे में बताएगा? जिससे मासूम मन में इन खेलों के प्रति खेलने की जिज्ञासा उत्पन्न हो सके।

जाहिर है आज हमें ऐसी नीतियों का निर्माण करने की जरूरत है, जिससे देश में खेलों को सम्मानित मुकाम हासिल हो सके। खेल केवल मनोरंजन तक ही सीमित न हों, बल्कि यह एक करियर के तौर पर भी अपनाया जाए। इसके लिए हमें खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। और उसके विकास के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। इसके लिए सरकार को निजी, गैर सरकारी, सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। निजी संस्थाओं द्वारा शोध और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक उसी प्रकार क्या हम भी खिलाड़ियों को आर्थिक मदद और प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं करा सकते?

आज जरूरत है कि खेलों के प्रति युवा पीढ़ी का ध्यान आकर्षित किया जाए। उन्हें बताया जाए कि मोबाइल और कंप्यूटर पर क्रिकेट खेलने से कहीं अधिक मजा मैदान में जाकर क्रिकेट खेलने में है। आज बच्चों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने की जरूरत है। क्योंकि देश की एकता को बरकरार रखने के लिए भाईचारे, प्रेम और मैत्री की भावना इन्हीं खेलों से विकसित की जा सकती है। इसलिए देश में खेल संस्कृति को जीवित करने की जरूरत है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

स्वस्थ रहने का माध्यम हैं खेल

खेल संस्कृति विकसित करने का मंत्र शीर्षक से लिखे अपने लेख में तरुण गुप्त ने देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने पर बल दिया है। राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे लिए आकलन और संकल्प का दिवस होना चाहिए ताकि हम आकलन कर विश्लेषण करें कि खेल के स्तर पर हम कहां खड़े हैं और निष्कर्ष स्वरूप हमें कहां खड़ा होना चाहिए। ओलंपिक खेलों में भारत का दयनीय प्रदर्शन हमें आईना दिखाता है। आज भारत युवा शक्ति के रूप में उभर रहा है। खेलों में भी यदि हम महाशक्ति बनने का संकल्प लें तो उस संकल्प को पूरा करना कोई असंभव बात नहीं है, लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम सरकार को ग्राम से लेकर ब्लॉक स्तर, ब्लॉक स्तर से जनपद स्तर, जनपद से मंडल और मंडल से प्रदेश स्तर तक खेलों से संबंधित संसाधनों को जुटाना होगा, खेल के मैदान विकसित करने होंगे, क्योंकि बढ़ती आबादी से खेल के मैदान समाप्त हो रहे हैं। इसके साथ ही देश में कोचों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। सरकार को देश में स्तरीय कोच तैयार करने पर बल देना होगा, ताकि तेजी से आ रहीं खेल प्रतिभाओं को संभाला जा सके। जाहिर है हमें खेल संस्कृति विकसित करने के साथ-साथ संसाधन भी जुटाने होंगे।

सर्वजीत आर्या, कन्नौज

सुधरेंगी स्वास्थ्य सेवाएं

सरकार ने देश में 75 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इस फैसले से आने वाले दिनों में एमबीबीएस की 15,700 सीटें बढ़ेंगी। इस तरह देश में डॉक्टर की संख्या बढ़ेगी और देश में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में सुधार होगा। 75 मेडिकल कॉलेज के लिए 24 हजार 375 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ इससे बात नहीं बन सकती है। एक अनुमान के अनुसार देश में एक लाख मेडिकल सीटों की जरूरत है। फिट इंडिया अभियान को बढ़ाने तथा आयुष्मान योजना को आगे बढ़ाने में इन मेडिकल कॉलेजों की भूमिका काफी अहम हो सकती है।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

कुल्हड़ वाली चाय

चाय की खुशबू और जायका ढूंढते लोगों के लिए कुल्हड़ वाली महक एक अलग अहसास देती है। विलुप्त होते इस बेमिसाल विरासत की खातिर लालू यादव के तत्कालीन रेल मंत्रालय ने चाय के बहाने कुल्हड़ को वापस लाने का प्रयास किया था। मगर मरणासन्न कुल्हड़ उद्योग में जान फूकने की यह कोशिश नाकाफी साबित हुई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रेल मंत्रालय को पत्र लिख कर रेल, एयरपोर्ट, बस अड्डे और मॉल जैसे सार्वजनिक जगहों पर कुल्हड़ वाली चाय अनिवार्य करने की राय दी है। पर्यावरण और स्वास्थ्य को लक्ष्य मान कर लिखी गई चिट्ठी, मिट्टी उद्योग सहित परंपरागत कुल्हड़ चाय की परिपाटी को प्रोत्साहित करने में अवश्य सहायक होगी। शायद कुल्हड़ फिर से चाक से चौपाल तक नजर आए। मिट्टी से बनी कुल्हड़ हमारे सामाजिक जीवन की धरोहर है।

mkmishra75@yahoo.in

इमरान के हथकंडे फेल

अनुच्छेद 370 हटने का सीधा अर्थ कश्मीर में पाकिस्तानी दखलंदाजी बंद होना है। इसी वजह से पाक छटपटा रहा है। पाक के पीएम इमरान खान रोज नए-नए हथकंडे प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि उनकी किस्मत उल्टी चल रही है और इनके सभी दांव फेल होते जा रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर को भूल अपने कब्जे वाले गुलाम कश्मीर को बचाने में लग गया है।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

सस्ती हो चिकित्सा शिक्षा

दैनिक जागरण के 28 अगस्त के उप्र संस्करण में संपादकीय डॉक्टरों का असंतोष पढ़ा। सरकार डॉक्टरों से 70 साल की उम्र तक काम तो कराना चाहती है पर समीक्षा कर यह नहीं देखना चाहती कि उन्हें मिल रही सुख सुविधाएं व पारिश्रमिक पर्याप्त हैं या नहीं। ऐसी स्थिति में सरकार कब तक जबरन डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में रोक कर रख सकती है? सरकार को चाहिए कि वो उनकी सुख सुविधाओं को काम के अनुसार बढ़ाए, साथ ही साथ चिकित्सा की शिक्षा को निजी हाथों में कम से कम सौंपे। सरकारी स्तर पर ही चिकित्सा शिक्षा की सस्ती व्यवस्था हो।

सतीश त्यागी काकड़ा, इंदिरापुरम

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

कितना कामयाब रहा जी-7 शिखर सम्मेलन

आजकल

विवेक ओझा
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार

इसी माह की 24 से 26 तारीख के दौरान फ्रांस के बायरिट्ज में जी-7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका सदस्य नहीं होने के बावजूद भारत को भी आमंत्रित किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में अनेक वैश्विक मसलों पर इसके सदस्य देशों के नेताओं ने अपना पक्षा रखा। बदलते वैश्विक परिदृश्य में इस सम्मेलन में लिए गए फैसलों और उससे निकले महत्वपूर्ण संकेतों को समझना हमारे लिए भी आवश्यक है

फ्रांस के बायरिट्ज में 45वें जी-7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाह थी जिसका कारण था कि यह ऐसे देशों के बीच की बैठक थी जिन्हें भारत पाकिस्तान कश्मीर विवाद, रूस-यूक्रेन विवाद, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, चीन की एक देश दो प्रणाली नीति और हांगकांग में चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शन, लीबिया संकट, ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम, उत्तर कोरिया के मुद्दे, अमेजन के जंगलों में लगी आग और अन्य पर्यावरणीय मुद्दे, यूरोप में आर्थिक मंदी, विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं की संरक्षणवादी नीतियों के विरोध के प्रश्नों पर ठोस निर्णय लेना था। इस सम्मेलन से अपेक्षाएं इसलिए ज्यादा थी कि इसका एक सदस्य ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के प्रयास में है और उसका भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लंबित है, जिस पर लोगों की निगाह है। दूसरे महत्वपूर्ण देश अमेरिका ने अपनी संरक्षणवादी नीतियों से विकासशील देशों को परेशान कर रखा है। अमेरिका के रुख की ओर भी लोगों की नजर होगी। तीसरे प्रमुख देश रूस पर अमेरिका ने काटसा एक्ट के तहत आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा है, और दोनों देशों ने नाभिकीय हथियारों को खत्म करने संबंधी 1987 की आइएनएफ ट्रीटी को 2019 में खत्म कर दिया है। फ्रांस की कुछ अपनी प्राथमिकताएं हैं। ऐसे में जी-7 शिखर सम्मेलन अपने मकसद में कितना सफल रहा, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

बायरिट्ज उद्घोषणा के मुख्य पहलू

जी-7 देशों ने कहा कि वे मुक्त और निष्पक्ष वैश्विक व्यापार के लिए प्रतिबद्ध हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए काम करेंगे। जी-7 ने अपने वित्त मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था और उससे जुड़ी चुनौतियों पर निगाह रखें। अंतरराष्ट्रीय कर प्रशासन में सुधार कर वैश्विक कंपनियों द्वारा करों की चोरी, ब्लैक मनी और मनी लांड्रिंग जैसी समस्याओं से निपटने के लिए बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग यानी बीईपीएस प्रोजेक्ट को मजबूती दी जाए। जी-7 देशों ने विश्व व्यापार संगठन में सुधार की बात की है, खासकर बौद्धिक संपदा के प्रभावी तरीके से संरक्षण, विवादों के जल्द समाधान और अनुचित व भेदभावकारी वाणिज्यिक उपायों और गतिविधियों पर लगाम लगाने पर जोर दिया गया है।

जी-7 देशों ने इस बात पर प्रतिबद्धता जाहिर कि है कि 2020 तक ओईसीडी के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक करारोपण में सुधार किया जाएगा। साथ ही विनियामक अवरोधों को दूर करके कर प्रणाली को आधुनिकीकृत किया जाएगा। जी-7 की बैठक में क्षेत्रीय स्थिरता को विश्व व्यवस्था की स्थिरता की जरूरत मानते हुए कहा गया है कि जी-7 देश यह चाहते हैं कि ईरान कभी भी नाभिकीय हथियार संपन्न राष्ट्र बनने की कोशिश न करे और मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग करे।

लीबिया के मुद्दे पर भी जी-7 देशों ने यही कहा कि वो लीबिया में स्थायी युद्धविराम होते देखना चाहते हैं। लीबिया की समस्या के राजनीतिक समाधान पर जोर दिया गया। इस मुद्दे पर जी-7 देशों ने लीबिया संघर्ष में संलग्न सभी पक्षों और क्षेत्रीय शक्तियों की सहभागिता वाले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन कराने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा जी-7 ने एक इंटर लिबियन कॉन्फ्रेंस को गठित करने में संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी यूनियन को समर्थन देने की बात की। इसके साथ ही जी-7 बैठक में राष्ट्रों ने हांगकांग में चल रहे आंदोलन के शांतिपूर्ण समाधान की बात की। जी-7 देशों ने खुलकर इस बात की पुनः पुष्टि की कि वर्ष 1984 में हांगकांग पर चीन-ब्रिटेन उद्घोषणा की बात और उसका महत्व माना जाना चाहिए और सभी पक्षों को हिंसा से बचना चाहिए।

> **वर्तमान में एक बड़े पर्यावरण संकट के रूप में अमेजन के वनों में लगी आग पर काबू पाने के उपायों पर चर्चा निरर्थक रही**

पर्यावरणीय मामले

जी-7 देशों में इस बैठक में सहमति बनी कि वो अमेजन के जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए 20 मिलियन डॉलर की त्वरित सहायता राशि देंगे ताकि अमेजन के वर्षावनों को बचाने के लिए वैश्विक पहल और रणनीति को बढ़ावा दिया जा सके। इस सहायता योजना की घोषणा 27 अगस्त को फ्रांस और चिली के राष्ट्रपतियों ने की। इसमें जी-7 देशों ने ब्राजील में वनों का दायरा बढ़ाने की बात की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने ब्राजील में जलवायु आपातकाल जैसे हालात का चित्रण करते हुए कहा कि हमें अमेजन के वनों के सवालों का जवाब देना होगा, जो आज जल रहे हैं। फ्रांस के इस प्रस्ताव पर कुछ समय यह दुविधा बनी रही कि ब्राजील इस पर क्या जवाब देगा। ब्राजील ने फ्रांस के राष्ट्रपति को कहा कि आपने हमारे यहां ऐसे हालात का चित्रण किया है कि उससे लगता है कि आप हमें एक उपनिवेश के रूप में या फिर हमारे साथ 'नो मैन्स लैंड' जैसा बर्ताव कर रहे हैं। ब्राजील और बोलिविया के अमेजन वर्षा वनों को आग से बचाने की सहायता राशि को लेने से ब्राजील ने अंतिम रूप से मना कर दिया है। साथ ही उसने फ्रांस को अपने आंतरिक मामलों पर ध्यान देने की नसीहत दी है। इस प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे पर जी-7 देशों में जो निर्णय लिया गया, शायद वो अब मूर्त रूप न ले पाए।

संप्रभुता खोने का डर

आज तमाम राष्ट्र विकास सहायता, कर्ज, अनुदान, अपने देश में किसी दूसरे देश और संगठन के मानवतावादी हस्तक्षेप से कतराने लगे हैं, उन्हें डर रहता है कि थोड़ी मदद लेकर उन्हें अपनी आर्थिक संप्रभुता से समझौता न करना पड़ जाए। चीनी असिस्टेंस सिंड्रोम (चीन द्वारा देशों की मदद कर उनका अपने मकसद के लिए दोहन करना) ने दुनिया के देशों को मदद लेने के संभावित परिणामों से डरा रखा है। वैसे भी ब्राजील एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जो ब्रिक्स देशों के अंग के रूप में अपने हितों के संरक्षण की चाह रखता है, जबकि जी-7 विकसित देश हैं, जो विकासशील देशों को अपने हितों की पूर्ति के लिए मोहरा बनाने की कला में माहिर रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि ब्राजील को यह सहायता राशि नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ब्राजील की पर्यावरण संरक्षण की अपनी नीति है। जी-20 के ओसाका समिट के दौरान ही दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े क्षेत्रीय संगठन मर्कोसुर और यूरोपीय संघ के बीच में 20 वर्षों से लंबित पड़ा मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ। इसे यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी ट्रेड डील कहा गया है। मर्कोसुर का सबसे प्रमुख सदस्य ब्राजील ही है।

यहां जानने योग्य बात यह भी है कि अगस्त माह में फ्रांस और आयरलैंड ने कहा कि वो इस मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि ब्राजील अमेजन की जंगल की आग से निपटने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाता। कई यूरोपीय देशों ने भी यह आरोप लगाया है कि ब्राजील की पर्यावरणीय नीतियां वनों की आग से निपटने की दिशा में कारगर साबित होती नहीं दिख रही हैं।

सम्मेलन में फ्रांस का मूल्यांकन

समिट से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ काम करने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हुआ भी तो आंशिक रूप में। अमेरिका चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर को खत्म कर व्यापारिक वार्ता शुरू करने का संकेत तो हुआ, लेकिन दोनों देश एक दूसरे के वस्तुओं और सेवाओं को कैसे भेदभाव रहित मार्केट एक्सेस देंगे इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं बना। ईरान के नाभिकीय मुद्दे पर अमेरिका का अड़ियल रवैया बना रहा। इस मामले पर ईरान के न्यूक्लियर डील के समर्थक फ्रांस की बात भी अमेरिका ने नहीं सुनी। अमेरिका का कहना था कि वह कुछ कठोर शर्तों पर ही ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से बैठक कर सकता है। उत्तर कोरिया के मुद्दे पर कोई ठोस बात नहीं हुई। यूरोप की कई अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक मंदी की स्थिति की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकलने पर अभी तक किसी निर्णय तक नहीं पहुंच सका है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दे पर नाटो सेनाओं की वापसी पर भी कोई ठोस बात नहीं हुई। ट्रंप ने सम्मेलन में इस बात पार जोर दिया कि रूस को जी-7 में फिर से सदस्य के रूप में शामिल होने दिया जाए, लेकिन अन्य सदस्य देशों में सहमति नहीं बन सकी।

जी-7 संगठन : संक्षेप में

यह संगठन सात औद्योगीकृत देशों का एक संगठन है। इसकी शुरुआत 1973 के तेल संकट के संदर्भ में हुई थी जब फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। इटली और कनाडा के जुड़ने के साथ 1975 में इसकी शुरुआत हुई। 1998 में रूस इससे जुड़ा और यह जी-8 बन गया था, पर 2014 में रूस के निलंबन के बाद यह जी-7 के रूप में ही बना रहा।

महत्वपूर्ण रही भारत की भागीदारी

भारत जी-7 का सदस्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जी-7 के सदस्य देश दुनिया की सात सबसे बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं और लोकतांत्रिक सरकारें हैं। दुनिया में आर्थिक चुनौतियों से निपटने में इनकी सबसे प्रभावी भूमिका है, क्योंकि वैश्विक मांग और आपूर्ति में इनका अहम योगदान है। वहीं भारत एक उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में इन सभी देशों के लिए सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में है। जी-7 के सभी सदस्य देश जी-20 के भी सदस्य देश हैं और भारत भी जी-20 का सदस्य देश है और इस फोरम पर अपनी अहम भूमिका निभाता है। जी-7 के सबसे प्रमुख सदस्य देश केवल अमेरिका को ही लें तो उसका भारत के साथ वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार 2018 में 142 बिलियन डॉलर का है। इस शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। कश्मीर मसले पर दोनों नेताओं के मध्य बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मसले पर भारत का पक्ष स्पष्ट किया और कहा कि भारत और पाकिस्तान के सभी मुद्दे द्विपक्षीय हैं। कश्मीर हमारा आपसी द्विपक्षीय मसला है और हम दोनों मिलकर इसे सुलझा लेंगे। उन्होंने कहा कि इस मसले पर हमें किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने से साफ इन्कार कर दिया और कहा कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है और ये दोनों देश मिलकर इसे सुलझा लेंगे। मोदी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दे हैं।

खरी-खरी

भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया है!

जवाहर चौधरी

'देखिए जी, लेन-देन की कोई बात न करें। भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो गया है। विभाग में आपसे कोई रिश्वत नहीं मांगेगा,' मुस्कराते हुए गोवर्धन बाबू ने बैठने की अनुमति प्रदान की। दो साल पहले इन्हीं से काम पड़ा था तो हजार रुपये लिए बगैर फाइल को छुआ तक नहीं था इन्होंने। तेवर ऐसे थे मानो सरयू पार वाले समधी हों। खैर, आज अपने से लग रहे हैं। मैंने तुरंत कहा, 'लेकिन चपरासी ने अभी दो सौ रुपये लिए मुझसे, तब फाइल आ सकी है आपकी टेबल पर!'

गोपाल ने लिए होंगे। दरअसल वो रिश्वत नहीं है। भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया है। रिश्वत देना-लेना मना है। उसने बताया नहीं कि दो सौ रुपये गऊ के चारे के लिए हैं! निबंध तो लिखे होंगे आपने पांचवीं कक्षा में! वैसे कहां तक पढ़े हैं आप?

गऊ माता तक... मतलब पांचवीं तक।

फिर क्या दिक्कत है। धरम का काम है। जहां भी मौका मिले पुण्य संचय करना चाहिए। पता नहीं कब बुलावा आ जाए। ऊपरवाला भी टेबल-कुर्सी लेकर बैठा है। चलिए...बताइये क्या काम है?

छोटा सा काम है जी। एक ऑर्डर रुका हुआ है। पता चला फाइल आगे नहीं जा रही है। आपके यहां से ओके हो जाए तो..!

बिलकुल हो जाएगा। कागज पूरे हैं आपके? मतलब फोर्मेलिटी कंप्लीट है। भगवान चाहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है।

वे हाथ जोड़ बोले, बड़ी मेहरबानी।

हाथ मत जोड़िए, इसकी जरूरत नहीं है। लोग देखेंगे तो समझेंगे कि रिश्वत मांग रहा हूं। भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो गया है। भगवान उधर हैं (लकड़ी के छोटे से सुंदर मंदिर में गऊ सहित बांसुरी बजाते भगवान मौजूद थे) वहां पांच सौ के तीन नोट चढ़ा दीजिए। हमने भी पांच गौएं पाल रखी हैं। समय की मांग है कि गौ पालन में सब योगदान करें। कोई जबरदस्ती भी नहीं है। आपकी फाइल यहां सुरक्षित है। जब गो-प्रेम जागृत हो तब चले आना, जल्दी नहीं है।

गो-प्रेम जागृत है जी! भला ऐसा कौन है जो गो-प्रेमी नहीं है।

उसने नोट चढ़ा दिए। गोवर्धन जी ने दराज से निकाल कर शक्कर के कुछ दाने हाथ पर धर दिए। प्रसाद है, लीजिए। मन प्रसन्न होना चाहिए, आस्था बड़ी चीज है, संसार तो आनी-जानी है। गऊ का महत्व जानते हो ना! पूंछ पकड़ लो तो वैतरणी पार हो जाती है। फाइल की भला क्या औकात कि एक टेबल पर अटकी रहे। लीजिए हो गया आपका काम।

ट्वीट-ट्वीट

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार कि उन्होंने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया मूवमेंट का आगाज किया। खेलेगा इंडिया, तभी तो खिलेगा इंडिया।
गौतम गंभीर@GautamGambhir

सभी ने इसे गलत अर्थों में ले लिया कि बंबई हाईकोर्ट ने 'वॉर एंड पीस' का संदर्भ दिया। वास्तव में यह 'वॉर एंड पीस इन जंगलमहल' नाम की किताब से जुड़ा मामला था। वैसे कोई भी साहित्य रखने से लोगों को अपराधी नहीं माना जा सकता।
मीनल बघेल@writermenal

हम जानते हैं कि पाकिस्तानी फौज कितनी क्रूर है। पूर्वी पाकिस्तान में उन्होंने दो लाख महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और तीस लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने हमारा घर लूटा और मेरे पिता को लगभग मार ही दिया था। आखिर अरुंधति रॉय ने कैसे कहा कि पाकिस्तानी फौज अपने लोगों पर हमला नहीं करती। 2011 में उन्होंने कैसे पाकिस्तानी फौज की तारीफ कर दी और इतने साल तक वह मुगालते में ही रहीं।
तसलीमा नसरीन@taslimanasreen

झारखंड डायरी

संगठन स्तर पर शून्य दल में अध्यक्षों की फौज

प्रदीप शुक्ला
स्थानीय संपादक, झारखंड

दिल्ली से लेकर प्रदेश तक भयंकर गुटबाजी का शिकार कांग्रेस ने आसन्न विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है, लेकिन धरातल पर उनकी यह कोशिश कितना असर छोड़ पाएगी, अभी इसका आकलन करना जल्दबाजी होगी। लोकसभा चुनाव के बाद से पार्टी में जो जूतम-पैजार मची हुई है, उसका असर यह कि आज कांग्रेस की जनता के बीच अगर चर्चा होती भी है तो सिर्फ पार्टी कार्यालयों पर कब्जे, बैठकों में एक-दूसरे की फजीहत, मारा-मारी से लेकर अपशब्दों के जरिये की जा रही अपने ही नेताओं की लानत-मलानत।

झारखंड में संक्रमण के दौर से गुजर रही कांग्रेस में अब नई जान फूंकने की कवायद चल रही है। इसके तहत आलाकमान ने प्रदेश नेतृत्व में फेरबदल किया है। इस उलटफेर में एक अध्यक्ष समेत पांच कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। कहा जा रहा है कि इस प्रयोग से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बेहतर परिणाम हासिल होगा, लेकिन इसके आसार फिलहाल कतई नहीं दिखते। झारखंड में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बीमारी दल की गुटबाजी है। कार्यकर्ता संगठन से दूर होते जा रहे हैं या अन्य दलों का झंडा ढो रहे हैं, लेकिन नेताओं की गुटबाजी कम नहीं हो रही है। कभी आपसी मतभेद में प्रदेश मुख्यालय में गोलीबारी तो कभी इनके समर्थकों का आपस में भिड़ जाना इसकी एक बानगी है। डॉ. अजय कुमार की विदाई विवाद की वजह से हुई। काफी तामझाम और उम्मीदों के साथ उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई थी। जल्द ही वे विवादों से घिर गए। तुनकमिजाज तेवर के कारण उनकी बदनामी भी हुई। दरअसल भारतीय पुलिस सेवा से राजनीति आजमाने आए डॉ. अजय कुमार इस माहौल में पूरी तरह ढल नहीं पाए। इस वजह से उन्हें समन्वय स्थापित करने में परेशानी हुई। नए अध्यक्ष को भी ऐसी ही मुश्किलें पेश आ सकती हैं। उन्हें मदद करने के लिए पांच नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

देखना होगा कि नई टीम विधानसभा चुनाव में कितना करामात दिखा पाती है? चुनाव में अन्य विपक्षी दलों संग तालमेल की चुनौती कांग्रेस के समक्ष है। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में तालमेल नहीं हो पाया था। नतीजन विपक्षी वोट बुरी तरह बिखर गए और भाजपा ने आसानी से सरकार बना ली। चुनाव बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे स्वीकार भी किया। तालमेल की कवायद लोकसभा चुनाव में आंशिक तौर पर सफल भी हुई। यह देखना होगा कि तमाम विरोधी दलों संग सीटों के तालमेल पर पार्टी कैसे सहमति बनाती है? लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर दावेदारी करने वाली कांग्रेस विधानसभा चुनाव में याचक की भूमिका में होगी। सबसे ज्यादा सीटों की दावेदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की है। सीट शेयरिंग का पेंच अवश्य फंसेगा। नवनियुक्त अध्यक्ष के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती होगी कि पहली अग्निपरीक्षा में खुद को साबित करें। चुनाव में इसके लिए बेहतर परिणाम देना होगा।

तगड़ी मोर्चाबंदी : झारखंड में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विपक्ष जहां गठबंधन को लेकर पस्त है, वहीं भाजपा ने शुरुआती तैयारियों में बाजी मार ली है। संगठन को चुस्त करने के साथ-साथ भाजपा ने बूथ स्तर तक पुख्ता तैयारी की है। चुनाव के मद्देनजर दो दौर की बड़ी बैठक हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास उन क्षेत्रों में लगातार कैंप कर रहे हैं जहां भाजपा अपेक्षाकृत कमजोर है। अब इन तैयारियों का अगला चरण आरंभ होने वाला है। 30-31 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह संताल परगना में प्रवास करेंगे। इस इलाके पर भाजपा की खास नजर है, क्योंकि यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रभाव वाला क्षेत्र है। लोकसभा चुनाव में दुमका संसदीय सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन को परास्त करने के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों नेताओं के दौरे में कुछ आश्चर्यजनक राजनीतिक घटनाक्रम हो सकते हैं। इशारा इस तरफ है कि कुछ विपक्षी दलों के विधायक भाजपा की शरण में आ सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा 12 सितंबर को प्रस्तावित है। वे यहां विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। भाजपा इसका श्रेय लेना चाहेगी, क्योंकि बिहार से पृथक होने के बाद यहां की विधानसभा भारी उद्योग निगम के भवन में चल रहा था।

पार्टी ने तमाम विभागों की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार भी बड़े पैमाने पर किया है। सरकार ने इन्हें इस स्तर पर प्रचारित करना आरंभ किया है कि जितना कार्य राज्य अलग होने के बाद 14 साल तक नहीं हुआ, वह इस सरकार के कार्यकाल के दरम्यान हुआ। यह देखना दिलचस्प होगा कि आम लोगों को यह दावा कितना प्रभावित करता है। राज्य में आधारभूत संरचना निर्माण के क्षेत्र में काम तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसे और रफ्तार दिए जाने की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में भाजपा के पास गिनाने को सरकार की उपलब्धियां होंगी, जिससे वह विपक्ष के प्रचार तंत्र का मुकाबला कर सकेगी।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आरबीआइ से मिले फंड से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी?

हां	76.00
नहीं	16.0
कह नहीं सकते	8.00

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या फिट इंडिया अभियान लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

मोबाइल के गेम में बच्चों को उलझाय,
सखियों के संग बैठकर गप्पें रहीं लड़ाय।
गप्पें रहीं लड़ाय यही है नया जमाना,
खोखो-कुश्ती और कबड्डी हुआ पुराना।
मोदी जी किस भांति तजें हम यह स्टाइल,
जब घर-घर में हाथ-हाथ पहुंचा मोबाइल!
- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

कला की आड़ में एजेंडा!

पीयूष द्विवेदी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

यह सही है कि भारत में सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि उसके साथ ही नैतिकता की भी एक मर्यादा होती है और उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए

बीते पंद्रह अगस्त को चर्चित वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' का दूसरा सीजन प्रसारित हुआ। इसका पहला भाग पिछले साल जून में आया था, जिसे समीक्षकों की सराहना और दर्शकों का रुझान तो मिला था, लेकिन साथ ही इसकी विषयवस्तु और सामग्री को लेकर कई सवाल भी उठे थे। गाली-गलौज भरे संवाद, वीभत्सता की सीमा तक हिंसा एवं अश्लील दृश्यों के कारण ये वेब सीरिज सवालों के घेरे में आई ही थी, कहानी में मौजूद धर्म और राजनीति से संबंधित मनमानी व्याख्याओं एवं टिप्पणियों ने भी इसके पीछे की नीयत को संदिग्ध बनाने का काम किया था। अब जब इसका दूसरा सीजन आया है तो यह भी सवालों के घेरे में ही नजर आता है।

सेक्रेड गेम्स के इस सीजन की कहानी हिंदू आतंकवाद की कोरी धारणा पर आधारित है, जिसका केंद्र गुरुजी (पंकज त्रिपाठी) का चरित्र है। गुरुजी पहले भाग में भी थे, लेकिन उन्हें कम संवाद और दृश्य मिले थे। मगर इस सीजन में सब प्रमुख चरित्रों का सूत्र गुरुजी के ही हाथ में दिखाया गया है। गुरुजी का एक बड़ा-सा आश्रम है जिसकी आड़ में ड्रग्स का कारोबार चलता है और वहां जाने वाले भक्तों को नशे से सम्मोहित कर लिया जाता है। उनके साथ अप्राकृतिक यौन क्रियाएं की जाती और करवाई जाती हैं। गुरुजी धरती पर पुनः 'सत्ययुग' लाना चाहते हैं और इसके लिए उनका तरीका यह है कि वर्तमान जगत को नष्ट कर दिया जाए। उनका मानना है कि अभी दुनिया के अलग-अलग भागों में जो संघर्ष चल रहा है, उसे और बढ़ाया जाए जिससे दुनिया के खत्म होने की प्रक्रिया तेजी से बढ़े। गुरुजी की इस योजना की एक प्रमुख कड़ी मुंबई में परमाणु विस्फोट करना है, जिससे भारत-पाकिस्तान सहित बाकी दुनिया में भी संघर्ष पैदा हो और विनाश की प्रक्रिया तीव्र हो जाए। यहां तक कि भारत विरोधी आतंकियों से भी गुरुजी के शिष्य अपने मिशन को पूरा करने के लिए मिल जाते हैं।

जाहिर है गुरुजी के चरित्र के माध्यम से यह वेब सीरिज हिंदू आतंकवाद की निराधार धारणा को स्थापित करने के प्रयास में दिखती है। मगर दिक्कत यह है कि जब आप सत्य से परे केवल अपने दुराग्रहों से उपजी किसी धारणा को स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो उसमें अतार्किकता और कृत्रिमता आ जाती है। यहां भी यही हुआ है।

गुरुजी को पूरी साजिश का सूत्रधार बनाए रखने के चक्कर में कहानी कई स्थानों पर एकदम अतार्किक हो गई है। गुरुजी की हत्या के बाद गायतोंडे के कान में जादुई ढंग से जब-तब उनकी आवाज गूंजते रहना और उसी के प्रभाव में उसका बिना पूरी साजिश का खुलासा किए आत्महत्या कर लेना इस अतार्किकता का ही उदाहरण है। जिस तरह से आश्रम में नशे के द्वारा सम्मोहित कर लोगों को सत्ययुग लाने के मिशन के लिए तैयार किया जाता है, वह भी विचित्र ही लगता है। असल में गुरुजी के चरित्र को सर्वशक्तिमान दिखाने के अंधोत्साह में कहानी कई तकनीकी खामियों का शिकार हुई है।

धार्मिक प्रतीकों को लेकर भी सेक्रेड गेम्स-2 में कई आपत्तिजनक बातें दिखती हैं। 'अहम् ब्रह्मास्मि' इस मंत्र का गुरुजी जाप करते हैं। ये यजुर्वेद से निकला एक महामंत्र है, जिसका अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसे महामंत्र का जाप गुरुजी अपनी अप्राकृतिक यौन क्रियाओं के दौरान भी करते हैं, जो कि भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात ही है। इसी तरह 'भगवान' शब्द को लेकर अनेक आपत्तिजनक संवाद इस वेब सीरीज में मिलते हैं। ये संवाद इतने अनुचित और आपत्तिजनक हैं कि यहां जिक्र तक नहीं किए जा सकते। इसी तरह सरताज सिंह का गुस्से में अपना कड़ा निकालकर फेक देना भी अनुचित लगता है, जिसे लेकर भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा की तरफ से मुकदमा भी कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली ये सब बातें वेब सीरीज की मूल कहानी से कोई ताल्लुक नहीं रखतीं और न ही उसमें कोई अतिरिक्त प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अगर ये बातें इस वेब सीरीज में न होतीं तो भी इसकी कहानी पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता यानी कि इनसे बचा जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद इन चीजों को वेब सीरीज में रखा जाना निर्माता-निर्देशकों की नीयत पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

यह ठीक है कि देश में सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके साथ नैतिकता की एक मर्यादा भी होती है। यह अपेक्षा भी होती है कि आप अपनी इस स्वतंत्रता का उपयोग किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं करेंगे। मगर दुर्भाग्यवश सेक्रेड गेम्स के दोनों ही सीजनों में कमोबेश यह किया गया है।

बात इतने पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि इस वेब सीरीज में यह स्थापित करने की भी पूरजोर कोशिश की गई है कि देश में मुसलमान बड़ी बुरी दशा में हैं। इंस्पेक्टर माजिद को मुसलमान होने के कारण घर न मिलने, कामकाज के दौरान अक्सर उस पर शक किए जाने जैसे प्रसंग हों या साद नामक मुस्लिम लड़के को सरेआम मार दिया जाना हो या यह संवाद कि 'मुसलमान को उठाने के लिए वजह की जरूरत होती है क्या?' इन सब चीजों के माध्यम से यही धारणा गढ़ने की कोशिश हुई है कि भारत में मुस्लिम समुदाय बड़ी बुरी स्थिति में है।

इस वेब सीरीज के निर्देशक अनुराग कश्यप अभी हाल ही में मॉब लिंचिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने वाले 49 लोगों में शामिल रहे थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने जिन पूर्वाग्रहों के आधार पर वह पत्र-अभियान चलाया था, इस वेब सीरीज में उन्हीं पूर्वाग्रहों को परोस दिया है।

कितना विचित्र है कि आज दुनिया में खुलेआम जिस मजहब के नाम पर आतंकवाद चल रहा है, उसके विषय में खुलकर अनुराग कश्यप कुछ नहीं कहते, पर जो हिंदू आतंकवाद कहीं किसी रूप में अब तक सिद्ध नहीं हुआ है, उसकी एक कपोल-कल्पित कहानी बना डालते हैं। इसी तरह मॉब लिंचिंग जैसी विशुद्ध आपराधिक समस्या का सांप्रदायीकरण कर डालते हैं। ये सब चीजें समाज में गलत संदेश देने वाली हैं। इनसे बचा जाना चाहिए था।

7.28 फीसद ही महिला पुलिसकर्मी हैं देश में कुल पुलिसकर्मियों में। सरकार ने तय किया है कि हर राज्य में 33 फीसद महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए, लेकिन किसी भी राज्य में यह संख्या पूरी नहीं है। सबसे अधिक 12.90 फीसद तमिलनाडु में हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 30 अगस्त 2019

कुल्हार को लाखों गैलन पानी का वरदान दे गई रेलवे लाइन

संदीप चंसोरिया, कुल्हार

रेलवे को तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए मुरुम (बजरी) की जरूरत थी और ग्रामीणों को खेती के लिए पानी की। एक तरकीब ने दोनों की जरूरतों को पूरा कर दिया। यह सफल प्रयोग मध्य प्रदेश के भोपाल से करीब 150 किलोमीटर दूर विदिशा जिले के छोटे से गांव कुल्हार में हुआ। वर्तमान में गांव के छह तालाबों में करीब 60 लाख क्यूबिक फीट पानी जमा हो चुका है।

जल संरक्षण

यह एक गांव की तस्वीर है। ऐसा ही बदलाव बीना से भोपाल के बीच रेलवे लाइन के किनारे के अनेक गांवों में देखने को मिलता है, जो कुल्हार गांव में हुई पहल के बाद हुआ है। दरअसल, वर्ष 2010 में बीना-भोपाल रेलखंड में तीसरी रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ था। यह काम देश की जानी मानी निर्माण कंपनी एल एंड टी कर रही थी। रेल लाइन बिछाने के लिए हार्ड मुरुम की जरूरत थी, जो इस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध थी। कंपनी ट्रैक के नजदीक से ही मुरुम खोदकर बिछा रही थी। कुल्हार के पूर्व सरपंच वीरेंद्र मोहन शर्मा को मुरुम खोदाई के जरिए गांव में जल संरचनाएं तैयार करवाने की तरकीब सूझी। उन्होंने अपने साथी सुरेंद्र सिंह दांगी को साथ लेकर निर्माता कंपनी के अधिकारियों के सामने प्रस्ताव रखा कि वे गांव में जहां-जहां जगह चिह्नित करें, वहां तालाबनुमा संरचना में खोदाई कर दें, तब तो गांव से कंपनी को मुरुम मिलेगी अन्यथा मुरुम नहीं दी जाएगी।

भोपाल में रेलवे की लांड्री में धुलते कपड़े। नईदुनिया

- रेलवे लाइन के किनारे दिख रहे लबालब तालाब, उत्कृष्ट उदाहरण बना मध्य प्रदेश का कुल्हार मॉडल

वीरेंद्र मोहन शर्मा | कौशलेंद्र विक्रम सिंह

चूंकि कंपनी को मुरुम चाहिए थी, इसलिए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। नतीजन गांव की सरकारी जमीन पर छह तालाब तैयार हो गए। कंपनी को गांव के एक ओर पांच और दूसरी ओर एक तालाब की संरचना के लिए जगह मुहैया करवाई गई। पंचायत के अधीन सरकारी जमीन पर तैयार होने वाली सभी छह संरचनाओं का कुल क्षेत्र करीब तीन लाख वर्गफीट था, जो औसत 20 फीट गहराई तक खोदी गईं। इस पूरे काम में चार से पांच साल का समय लगा। औसतन 20 फीट गहराई वाले सभी छह तालाबों का कुल क्षेत्रफल 6 लाख वर्गफीट है, जिनमें बारिश का वो पानी जमा होने लगा है, जो पहले बह जाता था। इसकी मात्रा करीब 60 लाख क्यूबिक फीट यानी 38 मिलियन गैलन है। गांव के एक ओर पांच तालाब तैयार किए गए हैं। इनकी डिजाइन एक-दूसरे को जोड़कर तैयार की गई है। लिहाजा, जब सबसे ऊपर का तालाब ओवरफ्लो होता है तो उसका पानी दूसरे तालाब में स्वतः पहुंच जाता है। इस तरह सभी तालाब भरने के बाद ही पानी बहता है, हालांकि सभी तालाबों के ओवरफ्लो होने की स्थिति अब तक नहीं बनी है। जब कुल्हार में तालाब बनकर तैयार हो गए तो उन्हें देखकर बीना-भोपाल के बीच रेलवे लाइन से लगे गांवों के ग्रामीणों ने भी इस तरह की संरचनाएं तैयार करवाने में रुचि दिखाई। ग्रामीणों ने स्वयं की जमीन से कंपनी को मुरुम देकर तालाब तैयार करा लिए। वीरेंद्र कहते हैं, अगर सभी तालाबों के चारों ओर पाल बांध दी जाए और पानी निकासी के लिए नहर व्यवस्थित कर दी जाए तो ये तालाब आगे कई साल बने रहेंगे। इन्हें पर्यटन का केंद्र बनाने के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। विदिशा के जिलाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की जलशक्ति योजना में अब विदिशा जिले के शामिल होने की पूरी संभावना है। कुल्हार मॉडल का सर्वे कर रिपोर्ट भेजी जाएगी।

जल से बदल रहा कल

अब बीना से भोपाल ट्रेन से आते समय तालाबनुमा कई संरचनाएं दिखाई देती हैं। कुल्हार में करीब 15 हजार हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। इन तालाबों के बनने के बाद कई किसान दो से तीन फसलें तक लेने लगे हैं। गांव की करीब 750 एकड़ जमीन पूरी तरह सिंचित हो गई है। इससे लगभग एक हजार क्विंटल अनाज का उत्पादन बढ़ने का अनुमान है।

मप्र के विदिशा में कुल्हार में रेलवे ट्रैक के किनारे तैयार किया गया तालाब। नईदुनिया

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/positive-news

पैसों के पीछे भागते कोचिंग सेंटर्स को दिखा रहे आईना

बिहार के भागलपुर में प्रतियोगियों को पढ़ाते हुए गोपाल कृष्ण झा। जागरण

- बिहार के भागलपुर और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से दो समर्पित शिक्षकों की कहानी
- भागलपुर के युवाओं पर 'आशीर्वाद' बन बरस रहा गोपाल झा का जुनून
- सूखे और बेरोजगारी की मार झेल रहे बुंदेलखंड में उम्मीदें जगाते अखिलेश शुक्ल

जागरण विशेष

जेएनएन, नई दिल्ली

बिहार के भागलपुर में गोपाल कृष्ण झा और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अखिलेश शुक्ल साधनहीन युवाओं के कर्णधार बन बैठे हैं। ये वाकई ऐसे शिक्षक हैं, जो उन धनलोलुप शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों को आईना दिखा रहे हैं जिनके लिए धन ही एकमात्र सरोकार है। गोपाल और अखिलेश बिना कोई फीस लिए युवाओं का भविष्य गढ़ने में जुटे हुए हैं। इनके मार्गदर्शन में अनेक युवाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में बाजी मारी और बड़े अफसर बने हैं। यह सिलसिला सालों से चल रहा है।

चार हजार युवाओं ने पाई सरकारी नौकरी : भागलपुर की गलियों में गोपाल कृष्ण झा और उनका शैक्षणिक संस्थान आशीर्वाद एक-दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। 19 वर्षों से चल रहे इस संस्थान के करीब चार हजार युवा विभिन्न सरकारी नौकरियां प्राप्त कर चुके हैं। गोपाल बताते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे अपने पांच दोस्तों के साथ मिलकर 2000 में इस संस्था की शुरुआत उन्होंने की थी। स्वयं 2006 में प्रतियोगी परीक्षा में बैठे तो नगालैंड में खुफिया विभाग में चयन हो गया, पर संस्था में अपनी आवश्यकता को उन्होंने तरजीह दी और वापस लौट आए। छात्रों को निःशुल्क पढ़ाने का कार्य फिर शुरू कर दिया। आजीविका भी जरूरी थी, लिहाजा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) में जब भर्ती निकली तो परीक्षा दी और नौकरी हासिल की। इस नौकरी में उन्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। आज यहां करीब 1700 छात्र-छात्राएं बगैर किसी शुल्क के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। गोपाल आज भी किराए के मकान में रहते हैं। पिता ने शहर में ही थोड़ी जमीन खरीदी थी, उसी पर एक कमरा बनवा लिया, अस्थाई शेड डालकर बिजली-बत्ती लगा दी। इसी में कक्षाएं चलती हैं। हाल ही बिहार में दारोगा भर्ती में यहां के 26 छात्रों का चयन हुआ है। बिहार सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय में 48 प्रतियोगी चयनित हुए हैं, जबकि अब तक 500 से अधिक युवा सहायक स्टेशन मास्टर और लोको पायलट की नौकरी पा चुके हैं।

पांच साल से निःशुल्क पढ़ा रहे अखिलेश : सूखे और बेरोजगारी की मार झेल रहे बुंदेलखंड की धरती पर आज से पांच साल पहले की गई पहल आज युवाओं की जिंदगी संवार रही है। तत्कालीन जिलाधिकारी संध्या तिवारी ने कलेक्ट्रेट में जरूरतमंद युवाओं को निःशुल्क कोचिंग देने के लिए 'नई पहल' स्टडी सेंटर शुरू कराया था। संध्या ने सेवा भाव से पढ़ाने वाले अफसरों एवं शिक्षकों की टीम बनाई। इसमें प्रमुख थे परिषदीय स्कूल के शिक्षक अखिलेश शुक्ल, जिन्हें इस स्टडी सेंटर की जिम्मेदारी दी गई, जिसे वह आज भी निःशुल्क निभा रहे हैं। स्टडी सेंटर से अब तक सैकड़ों युवा सरकारी नौकरी पा चुके हैं। यहां पढ़े गौरव राज्य लोक सेवा आयोग (पीसीएस) की परीक्षा पास कर हाल ही गन्ना आयुक्त के पद पर तैनात हुए हैं। सौरभ, शिवम व क्रांति का चयन एडीओ पंचायत पद पर हुआ है।

(भागलपुर से शंकर दयाल मिश्रा और हमीरपुर से अनुराग मिश्रा की रिपोर्ट पर आधारित।)

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/jagran-special

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते अखिलेश शुक्ल। जागरण

मप्र में बाघों के लिए कर्नाटक की तर्ज पर बनेगी फोर्स

तैयारी ▶ राज्य सरकार ने केंद्र को भेजे तीन प्रस्ताव, 60 फीसद राशि केंद्र तो 40 फीसद राशि राज्य करेगा खर्च

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर सीएम कमलनाथ ने कहा था, बाघों की सुरक्षा के लिए उठाए जाएंगे कड़े कदम

नईदुनिया, भोपाल

टाइगर स्टेट का तमगा वापस लेने के बाद मध्य प्रदेश अब कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि वह बाघों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। शिकार पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश में कर्नाटक की तर्ज पर टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को तीन प्रस्ताव भेजे हैं। इनमें फोर्स के लिए जवानों की भर्ती और पुलिसकर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने का प्रस्ताव भी शामिल है।

सरकार 60 फीसद राशि देने को तैयार : वर्ष 2018 की गिनती के मुताबिक, प्रदेश में 526 बाघ हैं। यह संख्या देश के किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। अब सरकार बाघों की सुरक्षा को लेकर चिंता में है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर कहा था कि बाघों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसी के बाद सरकार ने टाइगर स्ट्राइक फोर्स के गठन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। सूत्र बताते हैं कि राशि के मामले में केंद्र सरकार 60 फीसद देने को तैयार है। अब राज्य सरकार को 40 फीसद राशि देने के लिए अंडरटेकिंग देना है। इसके बाद फोर्स के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी।

तीन प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित : पुलिस के पास स्टाफ की कमी है। इसे देखते हुए यह माना जा रहा है कि विभाग अपने स्तर पर जवानों की भर्ती करेगा। हालांकि, अभी तीन प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं। इनमें फोर्स का गठन खुद करने, पुलिस से प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ लेने और एसटीएफ वाइल्ड लाइफ से ही काम चलाने के प्रस्ताव शामिल हैं।

फोर्स के लिए केंद्र सभी राज्यों से कह चुका है : उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में केंद्र ने सभी राज्यों को फोर्स गठित करने को कहा था। तब केंद्र सरकार इसके लिए 50 फीसदी राशि देने को तैयार थी, लेकिन राज्य सरकार ने तब फोर्स गठन का फैसला नहीं लिया और कर्नाटक सरकार ने पहले ही साल गठन कर लिया था।

छह कंपनी की जाएंगी तैनात : मध्य प्रदेश में छह टाइगर रिजर्व हैं और सभी में एक-एक यानी छह कंपनी तैनात की जाएंगी। एक कंपनी में 100 जवान रहेंगे, जो पार्क के एंट्री प्वाइंट से लेकर बफर और कोर एरिया में सक्रिय रहेंगे। यह व्यवस्था लागू होने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से फोर्स औपचारिकताएं पूरी किए बगैर किसी को भी पार्क में घूमने की इजाजत नहीं देगी, क्योंकि फोर्स गठन की शर्त में यह भी शामिल है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) सीधे इसकी मॉनिटरिंग करेगी।

शिकार पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए मप्र सरकार उठाने जा रही है अहम कदम। प्रतीकात्मक

इसलिए टाल रहे अफसर

वन विभाग के अफसर फोर्स का गठन करने से कतरा रहे हैं। दरअसल, अफसरों को डर है कि फोर्स का गठन हुआ तो पार्क की पूरी सुरक्षा सैनिक संभाल लेंगे और फिर अफसरों की मनमानी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अभी फील्ड डायरेक्टर की सहमति से पार्क में कोई कहीं भी घूम सकता है।

हाई कोर्ट में चल रहा मामला

फोर्स के गठन का मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। वन्यप्राणी मामलों के जानकार एवं आरटीआइ एक्टिविस्ट अजय दुबे पांच साल से इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दुबे ने बताया कि इस मामले में लोकसभा की संसदीय समिति राज्य सरकार की खिंचाई कर चुकी है। वे बताते हैं कि इस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम असम में हुआ है।

फोर्स के गठन का प्रस्ताव दिया है। राशि को लेकर दोनों सरकार के बीच अंडरटेकिंग के बाद जवानों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। यदि भर्ती करना पड़ी तो वह भी करेंगे, लेकिन पहले सरकार से अनुमति मिल जाए।

– यू. प्रकाशम्, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन

बेबी फीडिंग रूम वाला देश का पहला स्मारक बना ताजमहल

जागरण संवाददाता, आगरा : दुनिया के सात अजूबों में शुमार ताजमहल की शान में एक नगीना और जुड़ गया। ताज देश का पहला बेबी केयर एवं फीडिंग रूम (शिशु देखभाल एवं स्तनपान कक्ष) की सुविधा वाला स्मारक बन गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रह्लाद सिंह पटेल ने गुरुवार को इसका उद्घाटन किया। उन्होंने देश की सभी प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में यह सुविधा देने की घोषणा की।

ताजमहल देखने आने वाली माताओं को अब बच्चों को स्तनपान के लिए किसी कोने की आड़ नहीं लेनी होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के आगरा सर्किल ने रॉयल गेट के बायीं तरफ स्थित बरामदा में बेबी केयर एवं फीडिंग रूम बनवाया है। करीब 2.5 लाख रुपये की लागत से बने वातानुकूलित रूम में महिलाओं के बैठने को सोफा, कुर्सी, स्टूल और सामान रखने की व्यवस्था की गई है। उद्घाटन करते हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि देशभर के स्मारकों में महिलाओं के लिए इस सुविधा की शुरुआत ताजमहल से की गई है। हमारी कोशिश होगी कि देश के सभी प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर यह सुविधा हो। इस मौके पर सांसद प्रो. एसपी सिंह बघेल मौजूद रहे।

आगरा किला, फतेहपुर सीकरी में भी बनाए जाने हैं रूम : आगरा किला में दीवान-ए-आम से पूर्व दायीं तरफ बने बुक सेंटर के सामने रूम बनाया जाएगा, जबकि फतेहपुर सीकरी में पंचमहल या जोधाबाई कांप्लेक्स के पास बेबी फीडिंग रूम बनेगा। फतेहपुर सीकरी प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में शामिल है।

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफॉर्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

फलस्तीन की तस्वीर कश्मीर के नाम से वायरल

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

जेएनएन, नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की बाढ़ आ गई है। इसी संदर्भ में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में घायल बच्चे और उसकी मां को देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर कश्मीर की है।

विश्वास टीम ने अपनी पड़ताल में यह वायरल हो रहा दावा फर्जी पाया। असल में, यह तस्वीर 2009 में फलस्तीन में हुए इजरायल के मिसाइल हमले के घायल पीड़ितों की है।

पड़ताल : हमने सबसे पहले इस तस्वीर को Yandex रिवर्स इमेज में अपलोड करके सर्च किया। सर्च के नतीजों से यह साफ हो गया कि यह तस्वीर कश्मीर की नहीं है। हमने एक-एक करके इन लिंक को खंगालना शुरू किया। हमें GettyImages की वेबसाइट पर यह तस्वीर मिली। इस तस्वीर के साथ हेडलाइन दी गई थी: Palestinians Attend Funeral Of Five Young Balalusha Sisters. हेडलाइन का हिंदी अनुवाद होता है: पांच युवा बालालुशा बहनों के अंतिम संस्कार में उमड़ी फलस्तीनियों की भीड़। तस्वीर के साथ दिए गए विवरण के अनुसार अबालिया, गाजा पट्टी- दिसंबर 29- समीरा बालूशा (34) (दाहिने) अपनी बची हुई बेटी इमान (15) और बेटे मोहम्मद (15 महीने) के साथ बैठी है। अपनी बेटी जौहर बालूशा (4 साल) और उसकी 4 बहनों के शवों को देखने का इंतजार कर रही है, जो 29 दिसंबर, 2008 को हुए उत्तरी गाजा में इजरायली मिसाइल हमले में मारे गए थे। जौहर बालूशा और उसकी चार बहनें एक इजरायली हवाई हमले के दौरान मारे गए थे जब वे अपने बेडरूम में एक साथ सो रहे थे। इससे हमें यह पता लगा कि यह तस्वीर कश्मीर की नहीं है। जानकारी की पुष्टि करने के लिए हमने थोड़ी और पड़ताल की। हमें अल-जजीरा की खबर का एक लिंक मिला जिसमें इस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। यह खबर 7 जनवरी 2009 को प्रकाशित की गई थी। इस खबर की हेडलाइन थी: In the US, Gaza is a different war. हेडलाइन का हिंदी अनुवाद होता है: अमेरिका में, गाजा एक अलग जंग है

अब हमने इस तस्वीर की पुष्टि करने के लिए, दैनिक जागरण के जम्मू-कश्मीर के स्टेट एडिटर अभिमन्यु कुमार शर्मा से बात की। उन्होंने हमें बताया, यह तस्वीर कश्मीर के पीड़ितों की नहीं है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही कश्मीर को लेकर कई फर्जी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, यह पोस्ट भी उन्ही में से एक है।

अब हमने इस पोस्ट को वायरल करने वाले यूजर "Sardar Saqib Shaheen" के फेसबुक अकाउंट की सोशल स्कैनिंग करने का फैसला किया। यूजर को 4,072 लोग फॉलो करते हैं और यह एक विशेष समुदाय से जुडी खबरों को ही पोस्ट करते हैं।

वायरल हो रही तस्वीर का असली रूप

क्या हो रहा है वायरल?

सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर "Sardar Saqib Shaheen" नाम के यूजर एक पोस्ट अपलोड करते हैं। इस पोस्ट में एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक घायल बच्चे और उसकी मां को देखा जा सकता है। इस तस्वीर के साथ डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है:

Faces tell the story !!
India's brutality has turned Kashmir into a living hell...
Pray for kashmir..
Stand for kashmir..
#wewantfreekashmir

झूठी खबर और अफवाहों की हकीकत जानने के लिए वाट्सएप करें: 9205 270 923

देश का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक तैयार

ट्रायल सफल

मनाली के गुलाबा में बनाया ट्रैक, गुरुवार को किया गया ट्रायल, प्रकृति वाटिका पर दो करोड़ रुपये खर्च कर रही प्रदेश सरकार

जागरण संवाददाता, मनाली

हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली के पर्यटन स्थल गुलाबा में नौ हजार फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनकर तैयार हो गया है। गुरुवार को ट्रैक का सफल ट्रायल किया गया। इस ट्रैक की दूरी 350 मीटर है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसे विधिवत रूप से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यह ट्रैक अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण खेल संस्थान मनाली के निदेशक कर्नल नीरज राणा की देखरेख बना है। स्काई साइकिलिंग ट्रैक से सरकारी राजस्व को भी मजबूती मिलेगी और सैलानियों को भी साहसिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिल सकेगा।

प्रदेश सरकार गुलाबा की वादियों में प्रकृति वाटिका का निर्माण कर रही है, जिस पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। वन, परिवहन एवं खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने 20 जुलाई को इसकी आधारशिला रखी थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शीघ्र ही प्रकृति वाटिका का शुभारंभ करेंगे। गुलाबा की इस प्रकृति वाटिका में 450 मीटर लंबी जीप लाइन भी बनाई गई है। इन दोनों ट्रैक पर अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान के निदेशक कर्नल नीरज राणा ने सफलता पूर्वक ट्रायल किया। वन विभाग ने इस संस्थान के सहयोग से पूरे सुरक्षा मानकों को देख इसे तैयार किया है। स्थानीय पंचायत पलचान के आठ लड़कों को संस्थान के अनुभवी प्रशिक्षक प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, जो इनका संचालन करेंगे। वाटिका में भव्य प्रवेश द्वार सहित पार्किंग, टिकट बुकिंग कक्ष, वॉकिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, रोप क्रॉस, पिकनिक एरिया, टावर सहित ट्री हाउस, ट्री ग्रोव, लॉन, योग एवं मेडिटेशन, प्राकृतिक झरना, रेस्तरां और शॉपिंग कांप्लेक्स, शौचालय, फूलों का बगीचा, कैंपिंग साइट, एटीवी ट्रैक, स्नो गेम्स, जीप लाइन और रैपलिंग जैसी साहसिक गतिविधिया करवाई जाएंगी।

हिमाचल प्रदेश के गुलाबा में नौ हजार फीट की ऊंचाई पर बना देश का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक। एएनआइ

450 मीटर लंबी जीप लाइन का भी ट्रायल

कर्नल नीरज राणा ने बताया कि स्काई साइकिलिंग ट्रैक नौ हजार फीट की ऊंचाई पर बनकर तैयार हुआ है। उन्होंने बताया कि 350 मीटर स्काई साइकिलिंग सहित 450 मीटर लंबी जीप लाइन का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया है। डीएफओ नीरज चड्डा ने बताया कि इसे जल्द ही आम लोगों सहित पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा।

लुप्त हो रही चिनल भाषा को एएमयू के शोधार्थी देंगे शब्द

कमलेश वर्मा, कुल्लू

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहुल-स्पीति में बोली जाने वाली चिनल भाषा को अब शब्द मिलेंगे। लुप्त हो रही चिनल पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के शोधार्थी शोध कर रहे हैं। प्रो. इम्तियाज हसनैन के नेतृत्व में चार शोधार्थी काम कर रहे हैं। शोध के बाद चिनल का शब्दकोष बनाया जाएगा। केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर ने यह काम एएमयू को सौंपा है।

चिनल भाषा संस्कृत से मेल खाती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शोधकर्ता डॉ. फारूक मीर अहमद व तीन अन्य लोग शोध कर रहे हैं। लाहुल की पट्टन वैली से छह साल पहले शोध की शुरुआत की थी। इसके लिए किताबों और पौराणिक गीतों का रिकॉर्ड जुटाया। भाषा के ज्ञाताओं से जानकारी इकट्ठी की।

फारूक मीर के अनुसार, 1996 के यूनेस्को के रिकॉर्ड के अनुसार लाहुल के 750 लोग चिनल भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन नए शोध के अनुसार यूनेस्को की रिपोर्ट गलत है। अब शोध में पाया गया है कि लाहुल-स्पीति के 28 गांवों के लगभग 2900 लोग चिनल का प्रयोग करते हैं। ये लोग उन शब्दों को संजोकर रखे हुए हैं, जो इंडो-आर्यन भाषाओं में शामिल थे। उन्होंने कहा कि शोध का उद्देश्य शब्दकोष और ज्ञानकोष बनाना है, जो हिंदी, अंग्रेजी और चिनाली में होगा। यूनेस्को की 2001 की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में 2570 भाषाएं लुप्त होने के कगार पर हैं, जिनमें 192 भाषाएं भारत की हैं।

वरिष्ठ साहित्यकार छेरिंग दोरजे के अनुसार, चिनल भाषा लाहुल में एक विशेष समुदाय द्वारा बोली जाती है। पहले यह चंबा में भी बोली जाती थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ स्थानों में भी इसका प्रयोग होता है।

हम भाषाओं को भूल रहे हैं। लाहुल के एक विशेष समुदाय ने संस्कृत के साथ मेल खाती चिनल भाषा को सदियों से जीवित रखा है। लाहुल की संस्कृति भी विशुद्ध रूप से इसी भाषा से ओत-प्रोत है।

–डॉ. फारूक मीर अहमद, शोधकर्ता

दैनिक जागरण

सबरंग

प्लान वीकेंड के

नई दिल्ली, शुक्रवार, 30 अगस्त, 2019

सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें :sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

इस बार यहां चलें

नव मलिका

मोहिनीअट्टम पसंद करने वालों के लिए यह कार्यक्रम यादगार पल होगा। कार्यक्रम जयाप्रभा मेनन की नई दिल्ली में इंटरनेशनल अकादमी आफ मोहिनीअट्टम के दस साल का सफर पूरा होने पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कीर्थना नैयर, आध्र नैयर, रोहिनी सरीखी कलाकार प्रस्तुति देंगी।

- **कहां** : त्रिवेणी कला संगम, नई दिल्ली
- **कब** :30 अगस्त, शाम साढ़े छह बजे
- **प्रवेश** :निश्शुल्क

दिल्ली का महाराजा

18वां गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा भी बिखरेगी। जल ही जीवन है थीम पर आधारित गणेश महोत्सव में गणेश प्रतिमा एवं पंडाल की सजावट तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर की गई है।

- **कहां** :डीडीए मिनी स्टेडियम, लक्ष्मी नगर, दिल्ली • **कब** :2 से 12 सितंबर। सुबह साढ़े दस बजे से
- **प्रवेश** :निश्शुल्क

ओवी हॉरर शो

फेलिसिटी थिएटर, अनिकेत पाटिल द्वारा निर्देशित भारत के पहले हिंदी हॉरर नाटक ओवी का प्रीमियर होने जा रहा है। यह एक किशोरी की कहानी है जिसके माता-पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं। चाचा उसे एक अनाथालय में भेज देते हैं, जहां वह अजीब सी घटनाओं का अनुभव करती है।

- **कहां** :कमानी ऑडिटोरियम, मंडी हाउस, नई दिल्ली • **कब** :7 एवं 8 सितंबर, शाम चार एवं सात बजे से
- **प्रवेश** :टिकट 400 से 2900 रुपये तक

हुस्न-ए-गजल

गजल कला के दो रूपों संगीत और कविता को जोड़ती है। हुस्न-ए-गजल काव्य संरचना और मेलोडिक संरचना के लिए आवश्यक दो प्रमुख पहलुओं को उजागर करती है। शकील अहमद की खूबसूरत आवाज में यह प्रस्तुति दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है।

- **कहां** :मल्टीपरपज हॉल, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली
- **कब** :31 अगस्त, शाम छह बजे
- **प्रवेश** :निश्शुल्क

थियेटर फिल्म फेस्टिवल में कुछ इस अंदाज में मंच साझा करेंगे बॉलीवुड सितारे नसीरुद्दीन शाह व पंकज कपूर

थियेटर फेस्टिवल

मंच के रंग

सिनेमा के कुछ वो चेहरे जिन्हें बगैर देखे महज आवाज सुनकर हर कोई पहचान लेता है। जिनकी फिल्म में अलग छाप नजर आती है। जिनके अभिनय में हर दृश्य में, हर डायलाग में थियेटर की झलक नजर आती है। ऐसे कलाकार थियेटर फिल्म फेस्टिवल में आपके समक्ष साक्षात मंचन करेंगे। जहां नसीरुद्दीन शाह आइंसटीन बने नजर आएंगे तो पंकज कपूर भी अलग अंदाज में दिखाई देंगे। सबरंग के इस अंक में तीन दिवसीय नाट्य उत्सव की विशेष प्रस्तुतियों से रुबरू करा रहे हैं संजीव कुमार मिश्र :

एक थियेटर कलाकार में अभिनय को पेश करने की अलग तकनीक होती हैं। फिर चाहे वह बालीवुड भी चला जाए लेकिन उनकी रगो में जुनून रंगमंच का ही होगा। उत्साह वही थियेटर वाला होगा। जब-जब अवसर मिलेगा वह कलाकार लौटकर...रंगमंच पर कला के रंग दिखाएंगे। नाटक खेलेंगे। वैसे भी दिल्ली में थियेटर प्रेमियों की कमी नहीं। यह दीवानगी ही है जो एक से बढ़कर एक थियेटर फेस्टिवल नाट्य जगत की नींव को और सशक्त बना रहे हैं।

दिल्ली थियेटर फेस्टिवल दो शानदार संस्करणों के आयोजन के बाद एक बार फिर हाजिर है। तीसरे संस्करण में प्रसिद्ध अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, विनय पाठक, सुमित व्यास समेत अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी व अन्य कलाकार नाटक खेलेंगे। 30 अगस्त से आगाज होने वाले इस दिल्ली थियेटर फेस्टिवल में दिल्ली और गुरुग्राम में तीन दिनों में आठ नाटकों का मंचन होगा।

दिल्लीवालों का पसंदीदा : नाट्य प्रेमियों के उत्साह का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीते दो संस्करणों में थियेटर हॉल खचाखच भरे थे। आयोजक संस्था अल्केमिस्ट लाइव के सीओओ प्रभु टोनी कहते हैं कि पिछले आयोजनों की सफलता के साथ इस बार भी हम दर्शकों के लिए काफी कुछ खास नाटकों का मंचन कराने जा रहे हैं इस सीजन की शुरुआत सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में ड्रीम्ज सहर नाटक खेले जाने के साथ होगी। इसके अलावा ओराना-गुरुग्राम और प्यारे लाल भवन दिल्ली में भी नाटकों का मंचन होगा। ये आयोजन एक ऐसा मंच बन गया जहां नाटक खेलने वालों को भी और नाट्य प्रेमियों को भी ग्लोबल प्लेटफार्म मिल पा रहा है। अभिनेता पंकज कपूर भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। कहते हैं, मुझे खुशी है कि इस तरह के उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं क्योंकि यह दिल्ली के दर्शकों को समृद्ध करेगा और हम लोगों के सामने थियेटर से जुड़े रहने के अधिक अवसर प्रदान करेगा। वहीं सुमित व्यास की मानें तो उन्हें लगता है दिल्ली उन्हें पसंद करती है। वैसे भी दिल्ली के दर्शकों में सामान्य तौर पर कलाकारों के प्रति कुछ अलग तरह की गर्मजोशी होती है। उत्साह होता है। मैं भी बहुत उत्साहित हूं नाटक के मंचन को लेकर भी और दर्शकों का प्यार पाने को भी।

नसीरुद्दीन शाह बनेंगे आइंसटीन: थियेटर फेस्टिवल का प्रमुख आकर्षण नसीरुद्दीन शाह अभिनीत आइंसटीन है। शाह इस नाटक में वही आइंसटीन के किरदार में नजर आएंगे। विज्ञान के प्रति उनकी दीवानगी और पैशन को दर्शकों के सामने नसीरुद्दीन बेहद संजीदगी के साथ प्रस्तुत करेंगे। आइंसटीन साधारण से दिखने वाले महान वैज्ञानिक थे, लेकिन लाखों छात्रों की प्रेरणा भी बने। जिनका काम असाधारण, सिर पर बड़े-बड़े बाल, बदन पर जैकेट, बिना सस्पेंडर की पतलून, पांवों में बिना मोजों के जूते, खोलते समय न उन्हें ढीला करना पड़े न पहनते समय उन्हें कसना पड़े। कुछ इसी तर्ज पर नसीरुद्दीन शाह का गेटअप भी दिखाई देगा। बड़े लंबे सफेद बाल, सफेद मूछ व पैंट-शर्ट। गंभीर मुद्रा, विज्ञान को लेकर जुनूनी अंदाज। अपने एक्सपेरीमेंट के प्रति सजग। मतलब आपको साक्षात नसीरुद्दीन के रूप में आइंसटीन मंच पर नाटक खेलते नजर आएंगे। इस नाटक का लेखन गैबरियल इमैनुअल ने जबकि निर्देशन नसीरुद्दीन शाह ने खुद किया है। इस नाटक में शाह की बेहतरीन अदाकारी को दुनिया सलाम कर चुकी है।

कब और कहां :31 अगस्त- ओराना गुरुग्राम में शाम सात बजे से।
कब और कहां : 1 सितंबर - सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में शाम साढ़े चार एवं रात आठ बजे।
प्रवेश : 1000 रुपये, बुक माइ शो से ऑनलाइन बुकिंग

दिखेगी गजब की मिस्ट्री : ड्रीम्ज सेहर की कहानी पंकज कपूर द्वारा निभाई गई। जो कि प्रोफेसर संजय मिश्रा के इर्द-गिर्द घूमती है। छुट्टी मनाने कसौली जाते हैं। एक दिन मॉर्निंग वॉक करते समय इनकी मुलाकात एक महिला, साहेर (सुप्रिया पाठक कपूर) से होती है। सेहर, अपनी बहन निशा की तलाश कर रही है। और कुछ अजीब आकर्षण से आकर्षित होकर, मिश्रा भी उसकी खोज में शामिल हो जाते हैं। निशा, जिसकी तलाश शुरू होती है पीले कपड़ों में घुटनों तक लंबे बाल वाली लड़की के रूप में। नाटक में एक दृश्य जो दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ता है वो है पहाड़ी शहर की कल्पना। जिसे लोअर मॉल और कसौली के अपर मॉल वाले क्षेत्रों के रूप में साइनेज के रूप में दिखाया गया है। सेहर की मिस्ट्री जानने के लिए तो आपको नाटक ही देखना पड़ेगा। इसका निर्देशन एवं लेखन पंकज कपूर ने किया है। पंकज इसमें अभिनय भी करेंगे।

कब : 30 अगस्त
कहां :सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम, रात आठ बजे।
प्रवेश :500 रुपये, बुक माइ शो से ऑनलाइन बुकिंग

भरी दोपहरी: इसका लेखन, निर्देशन एवं अभिनय पंकज कपूर ने किया है। इसकी कहानी शुरू होती है लखनऊ की गलियों में स्थित उस आलीशान महल से, जिसमें अम्मा बी रहती हैं। संगीत और प्रकाश का बेहतर सामंजस्य इस नाटक में देखने को मिलेगा। इसकी कहानी अम्मा बी के जरिए अकेलेपन से स्वयं की खोज की यात्रा की कहानी है। दरअसल, लाल हवेली की 'अम्मा बी', जुम्मन व उसके दोस्त नत्थू, अम्मा बी के भाईजान सक्सेना जी, सबीहा और अमेरिका में बसे उनके पुत्र जद्दू (जावेद), के मुख्य किरदारों के साथ लाल हवेली में अम्मा बी के अकेलेपन की साथी, उनके आंगन में उतरती दोपहर की धूप, के इर्दगिर्द घूमती कहानी दर्शकों के दिलों को छू लेगी।

कब :31 अगस्त
कहां :सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम, दोपहर 2 बजे।
प्रवेश :500 रुपये, बुक माइ शो से ऑनलाइन बुकिंग

पिता-पुत्र के रिश्ते की कहानी : रजत कपूर निर्देशित और विनय पाठक अभिनीत नथिंग लाइक लियर की कहानी पिता-पुत्री के रिश्ते को केंद्र में रखकर लिखी गई है। यह विलियम शेक्सपीयर की कहानी किंग लियर पर आधारित है। नब्बे मिनट के नाटक में विनय पाठक की अदाकारी दर्शकों को बांधकर रखती है। कहते हैं, जितनी बार अभिनय करता हूं, नाटक नया सा लगता है। नाटक, एक मसखरे की आंखों के माध्यम से राजा को देखता है। मंच पर एक एकल अभिनेता, एक जोकर, एक पूरी जिंदगी मंचित होती है।

कब :1 सितंबर
कहां :प्यारे लाल भवन, शाम सात बजे।
प्रवेश :750 रुपये, बुक माइ शो से ऑनलाइन बुकिंग

वाइट रैबिट, रेड रैबिट: सुमित व्यास स्टारर वाइट रैबिट, रेड रैबिट का मंचन 25 से अधिक भाषाओं में दुनियाभर में हो चुका है। इस नाटक में ना तो पढ़ने की जरूरत है ना रिहर्सल की। जरूरत है तो सिर्फ लगन की। इस नाटक को मार्क वाट्सन, टॉम बासडेन, अनुराग कश्यप, अली फैजल, रिचा चड्ढा समेत अन्य मुख्य भूमिका निभा चुके हैं। इसमें अभिनय किसी भी अभिनेता के लिए रोमांच से कम नहीं। सोलेमानपुर ने इस नाटक की कहानी उस तनाव के दौर में लिखी थी जब उन्हें इरान से सिर्फ इसलिए नहीं जाने दिया गया क्यों कि उन्होंने सेना ज्वाइन करने से इन्कार कर दिया था।

कब :31 अगस्त
कहां :प्यारे लाल भवन, रात आठ बजे।
प्रवेश :500 रुपये, बुक माइ शो से ऑनलाइन बुकिंग

गर्दिश में तारे: सैफ हैदर हसन निर्देशित गर्दिश में तारे रिश्तों को लेकर बनाए जाने वाले नाटकों की ट्रिलॉजी का हिस्सा है। निर्देशक गुरुदत्त की गायक पत्नी गीता दत्त के साथ रहे तनावपूर्ण रिश्ते को दिखाया गया है। आरिफ जकारिया और सोनाली कुलकर्णी गुरुदत्त एवं गीता दत्त के दर्द, करुणा, जादू और संगीत बयां करेंगे।

कहां :31 अगस्त
कब : सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम, रात आठ बजे।
प्रवेश :500 रुपये, बुक माइ शो से ऑनलाइन बुकिंग

पनीर वाली चटपटी लिट्टी

जायका

गुरुग्राम निवासी पारुल शुक्ला एमबीए करने के बाद कारपोरेट कंपनी में प्रतिष्ठित पद पर नौकरी कर रही थीं। लेकिन बचपन से ही उन्हें खाने-खिलाने का कुछ ऐसा शौक था कि जब तक वह किसी डिश पर प्रयोग कर उसे नया रूप नहीं दे देती थीं, उनका किसी और काम में मन ही नहीं लगता था। लिहाजा उन्होंने नौकरी छोड़ दी और रेस्त्रां चलाने लगीं। अब वह होम शेफ और फूड ब्लॉगर हैं। ब्लॉग 'हंग्री-ऑबजर्वर' के तहत वह रोजाना फूड प्रेमियों को नई-नई डिशेज से रूबरू करवाती हैं। वजन बढ़ने के कारण उन्होंने जायकों को स्वास्थ्यवर्द्धक बनाने की दिशा में शोध व प्रयोग किए और अब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही डिशेज तैयार करती हैं।

साउथ इंडियन प्लेट में बिहार की लिट्टी: है न हैरान करने वाली बात। साउथ इंडियन थाली में बिहार की लिट्टी। जी हां, अप्पम के प्लेट में लिट्टी बनाकर पारुल ने बेहतरीन हेल्दी एक्सपेरीमेंट किया है। इसके गुण को और बढ़ाने के लिए इसमें पनीर मिलाया गया है। गेहूं के आटे में नमक, अजवाइन व घी मिलाकर उसे अच्छी तरह गूंथ लिया जाता है। फिर अदरक-लहसुन पेस्ट, नमक, गरम मसाला, हरा धनिया और कद्दूकस किए हुए पनीर को अच्छी तरह मिलाकर इसे भरा जाता है। उसके बाद अप्पम के सांचे में डालकर उसे पकाया जाता है। इसके साथ पके हुए टमाटर, कटे प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक व कच्ची घानी सरसों तेल की कुछ बूंदें डालकर मसल कर सलाद तैयार किया जाता है। पारुल के मुताबिक यह टेस्टी मील कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर से भरी हुई होती है। जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद उपयुक्त है।

ओट्स और चिया सीड्स खीर

ओट्स व चिया सीड्स की खीर: स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग अक्सर मीठा खाने से परहेज करते हैं। ऐसे में पारुल डेजर्ट में भी हेल्दी विकल्प दे रही हैं। गुड़-मखाने और इमली के प्रयोग से वह डेजर्ट तैयार करती हैं। इसमें खास है ओट्स व चिया सीड की खीर। कभी सामान्य भोजन में शामिल न किए जाने वाले चिया सीड्स को वजन घटाने से लेकर विभिन्न पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। लिहाजा पारुल ने इसे डेजर्ट में शामिल कर लिया है और ओट्स के साथ चिया सीड्स को दूध में उबालकर लजीज खीर बनाती हैं। पारुल कहती हैं कि प्रोटीन, कैल्शियम और फैट का सही कॉम्बीनेशन इस डिश को हेल्दी बनाता है।

सब्जियों से गुणों में लिपटा रंग-बिरंगा रैप: गेहूं के आटे में पालक या चुकंदर मिलाकर गूंथने पर अलग-अलग रंग का आटा तैयार हो जाता है। इससे रैप की कवरिंग तैयार होती है। इसमें भरने के लिए शिमला मिर्च, गाजर, मशरूम और प्याज को कड़ाही में हल्का भूनकर उसमें चिली सॉस, सिरका, टोमैटो सॉस और नमक मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। आटे को रोटी के आकार में बेलने के बाद उसमें फिलिंग भरकर ग्रिल किया जाता है।

यह व्यंजन खास तौर पर बच्चों के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर बच्चे हरी सब्जी नहीं खाना चाहते हैं। इस तरह रंग-बिरंगे रैप में लिपटी सब्जियों को वे चाव से खाएंगे।

प्रियंका दुबे मेहता

शेफ पारुल शुक्ला

कला प्रदर्शनी

आइटीओ प्यारेलाल भवन में आयोजित कला प्रदर्शनी में पेंटिंग में छिपे भाव को समझते दर्शक। जागरण

रंगों में लिपटी भावों की अभिव्यक्ति

भावों की इतनी मनमोहक अभिव्यक्ति, रंगों का ऐसा अद्भुत संयोजन कि दर्शक एकटक कैनवस को निहारते जा रहे थे। मानों उसके अंदर छिपे गूढ़ भावों को जानने-समझने की कोशिश कर रहे हों। इन आकृतियों को कैनवस पर उकेरते समय एक कलाकार के मनोभाव, उसकी कल्पनाशीलता को महसूस कर रहे हों। प्यारेलाल भवन स्थित आर्टिजन आर्ट गैलरी में आयोजित रासा साहूमिक कला प्रदर्शनी दर्शकों के दिलोदिमाग में कुछ इसी अंदाज में उतर रही थी। इस प्रदर्शनी में 39 से भी ज्यादा कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं। प्रदर्शनी में मंदिरों में भगवान के चित्र, पुरातन कथाओं पर आधारित कलाकृतियां, नौ रस, विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले भावों पर आधारित कलाकृतियां इतनी शानदार थीं कि दर्शकों के पांव इन्हें देखने के लिए अपने आप ठहरते जा रहे थे।

नारी अस्तित्व की दास्तां: गैलरी में प्रवेश करते ही दर्शक सबसे पहले इप्सिता द्विवेदी की कलाकृतियों से रूबरू हुए। यहां सीता, शिखंडी, आहिल्या और द्रौपदी की जीवंत कलाकृतियां देख दर्शक उनके जीवन चरित्र में खो गए। ये चारों भले ही विभिन्न काल खंड में प्रासंगिक थीं, लेकिन इनकी जिंदगी की कहानी काफी हद तक एक जैसी ही थी। पुरुषों के वर्चस्व और महिला अधिकारों को लेकर संघर्ष इनकी नियती बनी।

इप्सिता की ही शक्तिरूपा कलाकृति नारी की व्यथा को बयां करती है। नारी, जिसे हमेशा पुरुषों को हीरो साबित करने के लिए महज एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया। राजा- महाराजाओं की ऐसी कहानियां बड़े गर्व के साथ सुनाई जाती हैं, जिसमें उन्होंने स्त्री को अपना सम्मान बता युद्ध किया। इन कहानियों से अक्सर यही पता चलता है कि बिना पिता या पति के एक स्त्री का अपना कोई अस्तित्व नहीं।

नवरस में जीवन का हर रस: दर्शक इन कलाकृतियों को निहारते हुए जब कुछ आगे बढ़े तो निधि भाटिया की कलाकृति से उनका सामना हुआ। उनकी कलाकृति इनर स्ट्रेंथ स्त्री के भीतर की ताकत को बयां कर रही थी। निधि ने एक गकलाकृति में युवती के सिर पर जंगल के राजा शेर की कलाकृति बनाई हुई थी, जो किसी भी युवती के इनर स्ट्रेंथ के भाव को प्रदर्शित कर रही थी। जबकि उनकी नवरस कलाकृति मानों जिंदगी की किताब थी। इसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, वीभत्स, क्रोध, भय, वीर, अद्भुत और शांत रस को दर्शाया गया था।

कला प्रदर्शनी में लगी एक पेंटिंग। जागरण

> क्यूरेटर चांदनी गुलाटी कहती हैं कि जिंदगी भावों के बिना अधूरी है। यह भाव ही है जो हमें जिंदगी का एहसास कराते हैं। इन्हीं भावों को अपने भीतर समेटे हुए थी यह कला प्रदर्शनी।

वहीं हरमन तनेजा की चाय पर चर्चा कलाकृति भी मानवीय स्वभाव को समेटे हुए थी। रुचिका बत्रा की कलाकृति पांचवा पैर पुरुष और महिला के बीच के अंतर को प्रदर्शित कर रही थी तो श्वेता की बेमिसाल टेंपल फोटो आर्ट ने दर्शकों का दिल जीत लिया। बकौल श्वेता 2012 में दक्षिण भारत में मंदिरों के भ्रमण के दौरान उन्होंने कई फोटो खींची थी। जब घर आकर देखा तो वे बेमिसाल लगीं और इनकी प्रदर्शनी लगाने का विचार मन में आया। प्रदर्शनी में त्रिची, पुडुचेरी मंदिर के शिव पार्वती समेत भगवान गणेश आदि की फोटो लगाई गई थी।

संजीव कुमार मिश्र

नृत्य संगीत महोत्सव

सितार वादक स्वर्गीय उमाशंकर मिश्र की याद में आयोजित इस नृत्य संगीत महोत्सव में कथक नृत्यांगना मृणालिनी की शानदार प्रस्तुति होगी। इसमें सितार पर मीरा प्रसाद अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति से समां बांधेंगी तो तबला पर शैलेंद्र मिश्र इनका साथ देंगे। तो इस वीकेंड परिवार के साथ नृत्य संगीत का लुत्फ उठाने को तैयार हो जाएं।

- **कहां** :स्टेन ऑडिटोरियम, इंडिया हैबिटेट सेंटर, दक्षिणी दिल्ली • **कब** :1 सितंबर, शाम सात बजे • **प्रवेश** :निश्शुल्क

लेबनान फूड फेस्टिवल

लेबनानी जायके के यदि आप शौकीन हैं तो एक छत के नीचे जायकों की विविधता आपका इंतजार कर रही है। सलेक्ट सिटी वॉक, लिटिल जिजो के साथ मिलकर लेबनान जायका फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है, जिसमें वेज शवर्मा, नॉन वेज शवर्मा, वेज एवं नॉनवेज मनकीस जायके सर्व किए जाएंगे।

- **कहां** :लिटिल जिजो, सलेक्ट सिटी वॉक, दक्षिणी दिल्ली • **कब** :16 सितंबर तक, दोपहर 12 से रात 10 बजे तक
- **शुल्क** : 449 रुपये से शुरू

दिल्ली-6 वाले

अगर आप लजीज जायकों के शौकीन हैं तो दिल्ली-6 वाले का रुख कर सकते हैं। जहां रॉयल रोल्स, ताजा तंदूर समेत नॉनवेज की बेमिसाल वैरायटी उपलब्ध है। अगर आप वेज खाते हैं तो भी आपके लिए काफी कुछ लाजवाब है। शाही टुकड़ा, स्पेशल खीर यहां की बहुत ही प्रसिद्ध है।

- **कहां** :घटा मस्जिद रोड, दरियागंज, पुरानी दिल्ली
- **कब** :दोपहर 2 से रात 11 बजे तक
- **शुल्क** : प्रति दो व्यक्ति 300 रुपये

नियामक संस्थाओं को स्वतंत्र होना चाहिए : कांत

नई दिल्ली, प्रेट्र : नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि नियामक संस्थाओं को सरकार से स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उन्हें भारत के विकास में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। कांत ने यह बात 'द पॉलिसी डायलॉग फॉर फ्यूचर इंडिया' प्रोग्राम में कही। कार्यक्रम में वर्ल्ड बैंक के भारत में कंट्री डायरेक्टर जुनैद कमाल अहमद ने कहा कि नियामक संस्थाओं को सरकार का महज विस्तार नहीं होनी चाहिए और नियामक संस्थाओं को मार्केट सुधार में योगदान देना चाहिए।

एयर इंडिया का विनिवेश तय समय पर होगा। सरकार भारत को एयरलाइन मेनटेनेंस के हब के रूप में विकसित करना चाहती है।
— हरदीप सिंह पुरी
नागरिक विमानन मंत्री

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल
37,068.93	10,948.30	₹ 40,220	₹49,050	₹71.80	$ 59.91
▼ 382.91	▼ 97.80	▲ ₹250	▲ ₹200	▲ ₹0.03	

सरकार को सरप्लस देने से आरबीआइ के आपात फंड में आई कमी

केंद्र को पैसा हस्तांतरित करने के बाद छह साल के न्यूनतम स्तर पर आया फंड, 30 जून 2019 को घटकर हुआ 1.96 लाख करोड़ रुपये

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार को रिकार्ड सरप्लस ट्रांसफर करने के बाद रिजर्व बैंक का कांटिन्जेंसी फंड यानी आपात फंड घटकर 1.96 लाख करोड़ रुपये पर आ गया है। आरबीआइ आकस्मिक संकट से निपटने के लिए कॉन्टिंजेंसी फंड रखता है। सरकार को अतिरिक्त राशि ट्रांसफर करने के बाद यह फंड घटकर छह साल के निचले स्तर पर आ गया है।

आरबीआइ की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के मुताबिक 30 जून, 2019 को आरबीआइ का आपात फंड घटकर 1.96 लाख करोड़ रुपये रह गया है, जबकि 30 जून 2018 को यह 2.32 लाख करोड़ रुपये था। आरबीआइ आरबीआइ ने इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के संबंध में जालान समिति की सिफारिशों के आधार पर अतिरिक्त रिजर्व सरकार को ट्रांसफर करने का फैसला किया था। वैसे रिजर्व बैंक ने

आरबीआइ के सरप्लस फंड पर राजनीतिक रार चलती रही है। प्रतीकात्मक

अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि 30 जून 2019 की स्थिति के मुताबिक आरबीआइ की मजबूती कायम है। उल्लेखनीय है कि जालान समिति की सिफारिशें स्वीकारने के बाद आरबीआइ ने सरकार को चालू वित्त वर्ष में पौने दो लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का फैसला किया है जिसमें 1.23 लाख करोड़ रुपये डिविडेंड है जबकि 52,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त रिजर्व की राशि है।

आरबीआइ ने विकास दर में गिरावट को उतार-चढ़ाव का चक्र: आरबीआइ रिजर्व बैंक ने जीडीपी ग्रोथ में सुस्ती को उतार-चढ़ाव का चक्र करार दिया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि नीतियां बनाने वालों और सरकार की प्राथमिकता निवेश और उपभोग को बढ़ाने की होनी चाहिए।

आरबीआइ ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.9 परसेंट कर दिया है। बैंक का कहना है कि इकोनॉमी में मौजूदा धीमापन स्ट्रक्चरल के बजाय उतार-चढ़ाव का चक्र जैसा है। आरबीआइ ने माना कि इस धीमेपन की असल समस्या का मर्ज ढूंढ़ना मुश्किल है। वैसे आरबीआइ ने निजी निवेश और उपभोग को बढ़ाने के लिए उपाय करने का सुझाव दिया है। सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ श्रम और भूमि कानून में सुधार करने चाहिए।

शुक्रवार को आरबीआइ वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी करेगा। माना जा रहा है कि पहली तिमाही में विकास दर 5.7 परसेंट या इससे कम रह सकती है। पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में विकास दर 5.8 परसेंट थी।

बहरहाल आरबीआइ के अलावा कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भी चालू वित्त वर्ष में पूरे साल के दौरान भारत की विकास दर का आंकड़ा सात प्रतिशत या उससे नीचे ही रखा है।

छह साल के निचले स्तर पर आपात फंड

वर्ष	फंड (लाख करोड़ रु)
2013-14	2.21
2014-15	2.21
2015-16	2.20
2016-17	2.28
2017-18	2.32
2018-19	1.96

एनबीएफसी के कर्ज में 20 परसेंट की गिरावट

रिजर्व बैंक ने गुरुवार को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि आइएलएंडएफएस मामले के बाद से एनबीएफसी सेक्टर की तरफ से वाणिज्यिक क्षेत्र में दिए जाने वाले कर्ज वित्तीय वर्ष 2018-19 में 20 परसेंट तक गिरकर 9.34 लाख करोड़ पहुंच गया, जो कि वित्त वर्ष 2018 में 11.60 लाख करोड़ रुपये था।

प्राइवेट व विदेशी बैंक प्रमुखों के लिए नए वेतन नियम जल्द

विदेशी व निजी बैंकों के प्रमुख अधिकारियों के लिए रिजर्व बैंक जल्द नई नीतियों की घोषणा करेगा। शीर्ष बैंकों ने वर्ष 2012 में इन बैंकों के प्रमुख अधिकारियों व निदेशकों व कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन जारी की थी।

एनपीए घटकर हुआ 9.1 परसेंट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकार और आरबीआइ की कोशिश से बैंकों के एनपीए अनुपात का स्तर घटकर वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में घटकर 9.1 परसेंट रह गया है। वित्त वर्ष 2017-18 में यह एनपीए का अनुपात 11.2 परसेंट था। खास बात यह है कि नये एनपीए बनने के मामलों में भी कमी आ रही है। आरबीआइ की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 में कहा गया है कि शुरुआती कठिनाइयों के बाद इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एक गेमचेंजर साबित हो रहा है। धीरे-धीरे रिकवरी बेहतर हो रही है।

बैंक फ्रॉड मामले 15 परसेंट बढ़े

मुंबई, प्रेट्र : वित्तीय वर्ष 2018-19 मे बैंक फ्रॉड के मामले 15 परसेंट बढ़कर 6,801 हो गए। वहीं, इनमें फंसी रकम में 73.8 परसेंट बढ़कर 71,542.93 करोड़ रुपये हो गई है। वित्त वर्ष 2017-18 में 5,916 केस दर्ज किए गए थे, जिनमें फंसी कुल रकम 41,167.93 करोड़ रुपये थी। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में पीएसबी व प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में वित्तीय धोखाधड़ी के मामले सर्वाधिक दर्ज किए हैं।

आकलन ▸ रेटिंग एजेंसी ने कहा, केंद्र सरकार का प्रोत्साहन पैकेज देर से आया, अभी और सुधार की है जरूरत

ऑटो सेक्टर को सरकारी मदद नाकाफी : फिच

चालू वित्त वर्ष में वाहन बिक्री 11.5 परसेंट घटने का लगाया अनुमान

नई दिल्ली, प्रेट्र : रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूसंस ने गुरुवार को कहा है कि ऑटो सेक्टर में लगातार आ रही गिरावट व मंदी को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन पैकेज व उपाय नाकाफी हैं और इनकी घोषणा काफी देर से की गई है। इसके चलते चालू वित्त वर्ष में ऑटो सेक्टर में आई सुस्ती को रोक पाना संभव नहीं लग रहा। इसके साथ ही रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्तीय वर्ष में वाहन बिक्री में गिरावट 11.8 परसेंट रहने का अनुमान व्यक्त किया है। फिच की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को ऑटो सेक्टर में मंदी को रोकने के लिए जीएसटी दरों में कटौती, स्क्रैप पॉलिसी में सुधार के साथ ही अन्य उपायों की घोषणाएं करनी होंगी।

गौरतलब है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई सुस्ती व बिक्री में गिरावट को रोकने के लिए पिछले शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश बढ़ाने, बीएस-4 मानक वाले वाहन की बिक्री, जीएसटी में कटौती, एनबीएफसी सेक्टर में कर्ज संबंधी रियायतों व पैकेज की घोषणा की थी।

हालांकि रेटिंग एजेंसी का कहना है कि सरकार की तरफ से प्रोत्साहन पैकेज व अन्य घोषणाएं उसकी गंभीरता व सेक्टर में सुधार को लेकर सरकार की गंभीरता व इच्छाशक्ति को दर्शाता है। जिससे आगे सरकार द्वारा बेहतर पैकेज व सुधार की उम्मीद की जा सकती है।

प्रोत्साहन नीतियों में सुधार की दरकार

फिच की रिपोर्ट के अनुसार, देश के ऑटो सेक्टर पर सीधे ध्यान केंद्रित करने वाली प्रोत्साहन नीतियों व बैंकिंग सेक्टर में कर्ज देने संबंधी नीतियों में सुधार की जरूरत है। साथ ही एजेंसी का कहना है कि वर्ष 2020 से बीएस-4 वाहनों की बिक्री व स्क्रैप पालिसी को लेकर सरकार को निवेशकों व सेक्टर की संभावित चिंताओं को दूर करने की दरकार है।

वाहनों की खरीद के लिए लोन देने वाली एनबीएफसी की पिछले वर्ष से हालत बेहद खस्ता है। बैंकिंग सेक्टर द्वारा लोन देने के आंकड़ों में कमी के चलते वाहनों की बिक्री पर असर पड़ा है। हालांकि सरकार की घोषणाओं में इन कंपनियों को लोन सरलता से मुहैया कराने संबंधी घोषणाएं की गई हैं। लेकिन इसमें कहीं अधिक सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि इन कंपनियों का योगदान तकरीबन ऑटो सेक्टर में वाणिज्यिक वाहनों की खरीद में 55, यात्री कारों में 30 व दोपहिया वाहनों की बिक्री में 65 परसेंट तक है। बैंकिंग सेक्टर में लोन मुहैया कराने में बाधाओं के चलते नए वाहनों की बिक्री पर असर डाल रही है। जिसमें सुधार की अत्यंत आवश्यकता है।

ऑटो सेक्टर के लिए यह दौर बेहद चुनौतीपूर्ण है। हर किसी की निगाह इस क्षेत्र पर लगी है। फाइल

फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए एमजी मोटर व डेल्टा इलेक्ट्रानिक्स में करार

नई दिल्ली, प्रेट्र : एमजी मोटर्स ने गुरुवार को डेल्टा इलेक्ट्रानिक के साथ इलेक्ट्रानिक वाहनों के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना संबंधी करार की घोषणा की। करार के तहत डेल्टा इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट वाहन पार्किंग (घरों व कार्यालयों) के पास एमजी मोटर्स के उपभोक्ताओं को चार्जिंग प्वाइंट्स मुहैया करवाएगी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व ही एमजी मोटर्स ने वर्ष 2020 में अपने पहले मॉडल जेडएस ईवी को भारतीय बाजार में लांच करने की घोषणा की है। गुरुवार को इस करार की घोषणा करते हुए एमजी मोटर्स (इंडिया) के चीफ कमर्शियल आफिसर गौरव गुप्ता ने कहा कि डेल्टा के साथ हमारा करार कंपनी को एक नया मुकाम देने के साथ ही भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक अच्छा माहौल मुहैया कराएगा।

आइसीआरए ने कहा, यात्री वाहन बिक्री में सात परसेंट तक गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र : वाहन सेक्टर में आई सुस्ती के चलते देश में यात्री वाहनों की बिक्री में चार से सात परसेंट गिरावट की आशंका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आइसीआरए ने अपनी रिपोर्ट में व्यक्त की है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की तरफ से किए गए उपायों की घोषणा के बावजूद वित्तीय वर्ष में लगातार वाहन बिक्री में गिरावट व मंदी गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि ऑटो इंडस्ट्री ने चालू वित्त वर्ष के शुरुआती चार महीनों में बिक्री में 21.6 परसेंट गिरावट होने की बात कही है। इंडस्ट्री ने बीएस-4 वाहनों की अनिवार्यता को लेकर चिंताओं के बीच कर्ज मिलने में असमर्थता को इसकी वजह बताया

अमेरिकी उत्पादों पर अब और शुल्क नहीं बढ़ाएगा चीन

बीजिंग, एएफपी : अमेरिका और चीन में जारी ट्रेड वार के नरम होने के संकेत मिल रहे हैं। चीन से आ रही खबरों के मुताबिक वह फिलहाल अमेरिका पर जवाबी शुल्क नहीं बढ़ाएगा। दोनों बड़ी इकोनॉमी में जारी ट्रेड वार के चलते ग्लोबल मंदी की आशंका जताई जा रही है।

बीते सप्ताह चीन और अमेरिका ने एक-दूसरे पर नए सिरे से शुल्क लगाकर ट्रेड वार को और भड़का दिया था। सबसे पहले चीन ने 75 अरब डॉलर की अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके बाद अमेरिका ने कुल 550 अरब डॉलर के चीनी उत्पादों पर शुल्क की दरें बढ़ा दी थीं।

चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन के पास जवाबी कार्रवाई करने के पर्याप्त साधन हैं, लेकिन वर्तमान हालात में हमें चीन की वस्तुओं पर पहले से बढ़ाए गए शुल्क को हटाने पर बातचीत करनी चाहिए और ट्रेड वार को बढ़ने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका के साथ राजनयिक स्तर पर प्रतिरोध दर्ज करा रहा है। जाओ ने कहा कि ट्रेड वार का बढ़ना चीन और अमेरिका दोनों देशों के हित में नहीं है।

बीते हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वार को लेकर नरम-गरम प्रतिक्रिया दिखाई थी। पहले उन्होंने अमेरिकी कंपनियों से चीन छोड़ने की तैयारी करने को कहा, लेकिन बाद में ट्रेड वार को नरम करने के संकेत दिए थे। जी-7 देशों की बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ बातचीत शुरू करने की घोषणा की थी। ट्रेड वार के चलते वैश्विक स्तर पर आई आर्थिक सुस्ती को लेकर दुनियाभर के नेताओं ने चिंता जताई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत कई नेताओं ने ट्रंप को मनाने की भरसक कोशिश की थी।

ट्रंप द्वारा बातचीत की घोषणा का असर दुनियाभर के शेयर बाजारों पर दिखा था। इसके बाद वाल स्ट्रीट में सुधार देखा गया था, लेकिन चीन द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाने पर निवेशकों के बीच फिर से निराशा देखी गई। अब ट्रेड टॉक को लेकर चीन की ओर से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। जाओ ने कहा कि दोनों देश इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं।

चीन-अमेरिका में जारी है ट्रेड वार। प्रतीकात्मक

- चीन ने कहा है कि ट्रेड वार तेज होने से दुनियाभर को हो रहा नुकसान
- ट्रंप ट्रेड टॉक की बात पहले कह चुके हैं

एफडीआइ नीति में बदलाव के बाद एपल खोलेगी स्टोर

- कंपनी पहले ऑनलाइन स्टोर खोलने की योजना बना रही है
- एफडीआइ पॉलिसी में सुधार के बाद सिंगल ब्रांड रिटेल स्टोर खोलने में पहले के मुकाबले होगी आसानी
- एफडीआइ नियमों में ढील से भारत का मोबाइल फोन मार्केट बड़ा होने की उम्मीद

नई दिल्ली, प्रेट्र : कैबिनेट द्वारा एफडीआइ पॉलिसी में नए सुधारों की घोषणा के बाद दिग्गज अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एपल ने भारत में रिटेल स्टोर खोलने की इच्छा जाताई है। कंपनी की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि एपल अपने भारतीय ग्राहकों के लिए ग्लोबल स्तर के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर खोलने पर विचार कर रही है।

सरकार ने इसी बुधवार को सिंगल ब्रांड रिटेल के लिए एफडीआइ पॉलिसी में ढील देने की घोषणा की थी। सरकार ने सिंगल ब्रांड रिटेल के लिए बाजार में अनिवार्य रूप से स्टोर खोलने के प्रावधान को हटा दिया है, साथ ही लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स को भी आसान कर दिया गया है।

एपल ने भारत सरकार की पहल का स्वागत किया। फिलहाल इसको भारतीय बाजार में वनप्लस और सैमसंग जैसे ब्रांड्स से प्रतिस्पर्धा करनी है। वनप्लस प्रीमियम सेक्शन में सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड बनकर उभरा है। पहले यह स्थान एपल के पास था। कंपनी ने आने वाले दिनों में कुछ और नई घोषणाएं करने की बात भी कही है।

सूत्रों का कहना है कि आइफोन निर्माता पहले ऑनलाइन स्टोर खोलेगी। इसके बाद यह बाजार में अपने स्टोर लेकर आएगी। उद्योग जगत की संस्था इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एशोशिएशन (आइसीईए) ने कहा है कि एफडीआइ नियमों में ढील दिए जाने के बाद भारत का मोबाइल फोन मार्केट और बड़ा होने की उम्मीद है। इससे एपल, वनप्लस और ओप्पो जैसे ब्रांड्स को सीधे उनके मालिकाना हक वाले स्टोर खोलने का मौका मिलेगा। मौजूदा नियमों के मुताबिक एपल और दूसरी फर्में फ्रेंचाइजी आधारित रिटेल स्टोर के जरिए अपने उत्पाद बेचती हैं। गौरतलब है कि एपल पिछले कई वर्षों से भारत में रिटेल स्टोर खोलने की तैयारियों में जुटी हुई है।

भारत को एडीबी की ओर से मिलेगी 12 अरब डॉलर की सहायता

नई दिल्ली, प्रेट्र : एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि वह भारत सरकार को उसकी फ्लैगशिप योजनाओं के लिए फंड उपलब्ध कराएगा। मल्टीनेशनल बैंक ने पाइप्ड वाटर फार ऑल और रोड सेफ्टी जैसी योजनाओं के लिए 12 अरब डॉलर की सहायता देने की बात कही है। यह धन तीन वर्षों में जारी किया जाएगा। एडीबी के प्रेसीडेंट ताकेहिको नाको ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद यह बात कही है।

मुलाकात के दौरान मोदी और नाको में नई टेक्नोलॉजी के प्रमोशन और रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पंप से सिंचाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियों, सस्टेनेबल टूरिज्म और प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। नाको ने कहा कि एडीबी भारतीय इकोनॉमी को पांच ट्रिलियन डॉलर बनाने के विजन में भारत सरकार के साथ है। भारत को एडीबी की सॉवरेन लेंडिंग बीते साल तीन बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। ये फंड ट्रांसपोर्ट, अर्बन, सिंचाई, स्किल डेवलपमेंट आदि कामों में खर्च की गई। नाको ने कहा है कि एडीबी आगामी तीन सालों में 12 बिलियन डॉलर देने को तैयार है। इसमें से तीन बिलियन डॉलर सॉवरेन ऑपरेशन तथा एक बिलियन डॉलर प्राइवेट सेक्टर में निवेश के जरिए दिया जाएगा।

भारत पिछले पांच वर्षों से एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सबसे तेज विकास करने वाली इकोनॉमी है। इसने इन वर्षों के दौरान 7.5 परसेंट की ग्रोथ रेट के साथ विकास दर्ज किया है। नाको ने कहा कि भारत वित्त वर्ष 2019 के दौरान वैश्विक रुझान के इतर सात परसेंट की ग्रोथ रेट दर्ज करेगा तथा 2020 में यह 7.2 परसेंट की दर से विकास करेगा।

बैठक के दौरान एशियाई विकास बैंक के प्रमुख ने कहा कि भारत सरकार को इकोनॉमी प्रबंधन पर ध्यान देना होगा और सुधार कार्यक्रमों को जारी रखना होगा। ग्रामीण इकोनॉमी को सुधारने के साथ ही जॉब क्रिएशन पर भी जोर देना होगा। नाको ने भारत सरकार द्वारा किए गए लेबर लॉ, भूमि अधिग्रहण सुधार जैसे कार्यों की तारीफ की। एडीबी सेकेंडरी एजुकेशन और यूनिवर्सल हेल्थ जैसे कार्यक्रमों में भी सहायता कर रहा है।

मोदी के साथ एडीबी प्रमुख नाको। प्रेट्र

- राशि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में खर्च की जाएगी
- ट्रांसपोर्ट, अर्बन, सिंचाई, स्किल डेवलपमेंट आदि कामों में खर्च भी खर्च होगी रकम

गौतम थापर सीजी पावर के चेयरमैन पद से बर्खास्त

- कंपनी में बड़े पैमाने पर घोटाले की बात सामने आई है
- पद से हटाए जाने के बाद थापर ने खुद को निर्दोष बताया है

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन ने कंपनी के संस्थापक गौतम थापर को चेयरमैन के पद से हटा दिया है। बीते सप्ताह कंपनी के बोर्ड ने कथित घोटाले की जांच करने का फैसला किया था। पद से हटाए जाने के बाद थापर ने कहा कि कंपनी में ना तो किसी तरह का घोटाला और ना ही फंड का गलत प्रयोग हुआ था।

कंपनी ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि बोर्ड ने कंपनी की वर्तमान हालत को देखते हुए गौतम थापर को चेयरमैन के पद से हटा दिया है। कंपनी ने बताया है कि यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि निवेशक और कर्जदाता पूरी तरह से नया प्रबंधन चाहते हैं। बोर्ड शुक्रवार को कंपनी के नए चेयरमैन का चयन करेगा। सूत्रों ने बताया कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों में से एक को नॉन एक्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। कंपनी ने इसी महीने की 20 तारीख को वित्तीय अनियमितताएं होने की बात कही थी। चेयरमैन पद से हटाए जाने के पहले थापर इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से बच रहे थे।

थापर की सफाई : थापर ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि 19 अगस्त को हुई बोर्ड की बैठक के बाद आने वाली रिपोर्ट परेशान करने वाली है। मैं कहूंगा कि रिपोर्ट फैक्ट पर आधारित नहीं है। मैं शेयरधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कहना चाहूंगा कि कंपनी फंड के साथ किसी तरह की अनियमितता नहीं बरती गई है। फंड का प्रयोग बोर्ड की अनुमति के बाद ही किया गया है। उन्होंने कहा कि 2015 से अब तक प्रमोटर द्वारा कर्जदाताओं को चुकाए गए 4,000 करोड़ रुपये को धोखेबाजी नहीं कहा जा सकता है। इससे पहले कंपनी ने नियामकों को दी जानकारी में स्वीकार किया था कि इसके संचालन में कई तरह की वित्तीय अनियमितताएं बरती गई हैं। इसमें कुछ असेट कोलेटरल तौर उपलब्ध कराए गए और फंड कंपनी के पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों द्वारा छिपाया गया। कुछ देनदारियों का भी पता चला है।

मायूसी

बैंकिंग, फाइनेंस व ऑटो शेयरों ने बाजारों को खींचा नीचे, फार्मा कंपनियों और कोल इंडिया के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए

शेयर बाजारों पर फिर सुस्ती का दौर

मुंबई, एएनआइ : घरेलू शेयर बाजारों में पिछले दो लगातार कारोबारी सत्रों की गिरावट से ऐसा लगने लगा है कि इस सप्ताह सोमवार और मंगलवार को हुई बड़ी बढ़त तात्कालिक थीं। बुधवार के बाद गुरुवार को भी बीएसई और एनएसई सुस्ती के साए में रही। दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 382.91 अंक यानी 1.02 परसेंट की गिरावट के साथ 37,068.93 पर बंद हुआ। एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 97.80 अंक यानी 0.89 परसेंट की गिरावट के साथ 10,948.30 पर बंद हुआ। यूएस-चीन ट्रेड वार और घरेलू चिंताओं के बीच बाजार में सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग का दौर रहा। हालांकि सरकार ने एफडीआइ पॉलिसी में सुधारों की घोषणा की, लेकिन यह सुधार बाजार को प्रभावित करने में नाकाम रहे।

सेंसेक्स में लिस्टेड बैंकिंग, फाइनेंस, एनर्जी, ऑटो, एफएमजीसी सेक्टर के शेयर में 1.92 परसेंट तक गिरावट दर्ज की गई। वहीं हेल्थकेयर, मेटल, रियल्टी, पॉवर, ऑयल एंड गैस और टेलीकॉम सेक्टर के शेयर में 1.92 परसेंट तक बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी में लिस्टेड अधिकतर शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। पीएसयू के शेयर में 2.5 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। वहीं फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर में 1.8 परसेंट, प्राइवेट बैंकों के शेयर में 1.5 परसेंट और ऑटो सेक्टर के शेयर में 0.4 परसेंट की गिरावट देखी गई।

मूडीज द्वारा यस बैंक की रेटिंग घटाने के चलते इसके शेयर 3.3 परसेंट की गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक के शेयर 2.2 परसेंट तक गिर गए। एसबीआइ के शेयर 3.3 परसेंट की गिरावट के साथ 275.50 रुपये प्रति शेयर पर आ गए। इसके अलावा एचडीएफसी, आइटीसी, रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स के शेयर में भी गिरावट दर्ज की गई।

दिन के कारोबार में सन फर्मा, भारती इन्फ्राटेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता और कोल इंडिया के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। एशिया के अन्य प्रमुख बाजारों में हैंग सेंग, कोस्पी और निक्केई गिरावट के साथ बंद हुए वहीं शंघाई कंपोजिट इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ।

एफडीआइ पालिसी में बदलाव का असर शेयर बाजार में नजर नहीं आया है। प्रतीकात्मक

जल्द से जल्द होगा एयर इंडिया का निजीकरण

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार एयर इंडिया का निजीकरण करने के लिए तैयार है और कंपनियां तथा संभावित खरीदार इसके अधिग्रहण में रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिग्रहण कम से कम समय में बेहतर समझौते के साथ पूरा किया जाएगा। मंत्री के मुताबिक एयर इंडिया को खरीदने वाले इसे निजी कंपनियों के नियमों के मुताबिक चला सकेंगे।

संसद ने इसी महीने की तीन तारीख को एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल, 2019 में संशोधन को मंजूरी दी थी। सरकार ने कहा था कि वह एयर इंडिया का निजीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि इसका कर्ज क्षमता से ज्याद बढ़ गया है।

गौरतलब है कि सरकार ने पिछले वर्ष भी एयर इंडिया के विनिवेश की तैयारी की थी। लेकिन उस वक्त उसे एक भी खरीदार नहीं मिल पाया। जानकारों के मुताबिक विनिवेश के लिए सरकार ने कई ऐसी शर्तें रखी थीं, जिनका संभावित खरीदार पालन करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। उनमें सबसे प्रमुख थे - विनिवेश के बावजूद कंपनी पर सरकार का नियंत्रण और कर्मचारियों की संख्या में कमी नहीं करने की बाध्यता। माना जा रहा है कि अब सरकार विनिवेश की प्रक्रिया पूरी कर लेने के लिए ऐसी कई शर्तों से किनारा कर सकती है।

बिकने के लिए तैयार एयर इंडिया। फाइल

दो महत्वपूर्ण घोषणाएं जल्द : सीतारमण

गुवाहाटी, प्रेट्र : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इंडस्ट्री को बड़ी राहत देने के लिए सरकार दो और महत्वपूर्ण कदम जल्द उठाने जा रही है। उनका कहना था कि खपत के माध्यम से ही इकोनॉमी को गति दी जा सकती है। सरकार ने खर्च को बढ़ावा देने का फैसला किया है और इसी के तहत पिछले सप्ताह ऑटो सेक्टर को राहत देने के लिए कई कदमों की घोषणा भी की है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने सभी लंबित जीएसटी रिफंड 30 दिनों के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे भविष्य के जीएसटी रिफंड मामलों का पूर्व निर्धारित समय-सीमा यानी 60 दिनों में निपटारा करें।

सीतारमण ने कहा, 'अगर हम दुनियाभर से तुलना करें, तो हम अभी भी सबसे तेज गति से विकास कर रही इकोनॉमी हैं। हम समझते हैं कि इकोनॉमी को गति देने के लिए खपत को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है।' उनसे पूछा गया कि आरबीआइ से मिली रकम का सरकार क्या उपयोग करेगी, तो उन्होंने कहा कि अभी यह तय नहीं किया गया है।

8,600 हो जाएगी अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या घटकर यदि तालिबान के साथ शांति समझौता हो जाता है। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कही। उन्होंने कहा कि लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान में हमेशा मौजूद रहेगा।

सेना की कठपुतली है पाकिस्तान सरकार

पड़ोसी देश पाकिस्तान में सेना की ही हुकूमत चलती है। साल दर साल आई तमाम प्रमाणिक रिपोर्टों में इस सच्चाई को बताया गया। अब अमेरिकी कांग्रेस (संसद) की स्वतंत्र अनुसंधान विंग कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस (सीआरएस) की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यकाल में देश की विदेश और सुरक्षा नीतियों पर पाकिस्तानी सेना हावी रही है। इससे पहले इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान भी उन्हें सेना की कठपुतली बता चुकी हैं। आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने वाली पाक सेना के इशारों पर सरकारें चलती रही हैं। जिस भी प्रधानमंत्री ने सेना का विरोध किया उनको या तो फांसी दे दी गई या तख्तापलट कर दिया गया। 72 साल के पाकिस्तान के इतिहास में जब-जब मुल्क पर संकट आया। तब-तब सेना ने लोकतंत्र को कुचल कर देश की कमान अपने हाथों में ले ली। फील्ड मार्शल अयूब खान से लेकर याहया खान तक और जियाउल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ तक कुल 35 साल तक पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुल्क पर राज कर चुके हैं।

खत्म किया लोकतंत्र

लोकतंत्र में नियम-कानून, चुनाव, न्यायपालिका ताकतवर होती है, लेकिन सेना इन सबका अस्तित्व अप्रासंगिक कर दिया। नागरिकों के अधिकारों को ताख पर रखते हुए नौकरशाह के साथ गठजोड़ बनाकर सेना सत्ता की केंद्र बिंदु बन गई। नतीजा ये हुआ की पाकिस्तान में सेना सर्वेसर्वा हो गई।

युद्ध की आग में झोंका देश को

सेना के प्रभाव में पाकिस्तान के भारत के साथ चार युद्ध (1947, 1965, 1971, 1999) हुए। चारों ही युद्धों में पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई और अंतत: 1971 में पाकिस्तान दो भागों में टूट गया। नया देश बना बांग्लादेश। इस बीच पाकिस्तान में न तो उद्योग धंधे खड़े हो पाए और न ही कृषि पर ध्यान दिया गया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका से मिले खैरात के पैसों से पाकिस्तान में सेना और नौकरशाह वर्ग तो बहुत अमीर हो गया, लेकिन जनता गरीबी से नीचे जीवन जीने को मजबूर हो गई।

धार्मिक कट्टरता की आग में झोंका

जनरल जिया उल हक ने पाकिस्तान को न केवल धार्मिक कट्टरता की आग में झोंक दिया बल्कि कश्मीर को भी सुलगाने का काम किया। अपने शासनकाल में कट्टरता के जो कांटे उन्होंने बोए, वही आज पाकिस्तान के पैरों में चुभ रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की की राह से मुड़कर आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़ा। जनरल जिया उल हक ने 1973 में जो संवैधानिक प्रावधान किए थे। उन्होंने यह व्यवस्था की कि कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति देश का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। तख्तापलट के बाद जिया उल हक ने राष्ट्रपति पद संभाला तो संविधान को ठुकराते हुए शरिया कानून को लागू किया। आज पाकिस्तान बदहाली के जिस मोड़ पर है, वहां तक पहुंचाने में जिया उल हक की नीतियां जिम्मेदार बताई जाती हैं।

युवाओं को आतंक के रास्ते पर धकेला

बेरोजगार युवकों को फौज ने पैसे का लालच देखकर अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ आतंक के रास्ते पर धकेल दिया, जिससे गरीबी, भूखमरी और आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान पहचाना जाने लगा।

अर्थव्यवस्था पर सेना का कब्जा

पाक सेना 20 अरब डॉलर से अधिक की 50 वाणिज्यिक संस्थाओं को चलाती है। इनमें पेट्रोल पंपों से लेकर विशाल औद्योगिक संयंत्रों, बैंकों, बेकरियां, स्कूल, विश्वविद्यालय आदि शामिल हैं। सेना देश के सभी विनिर्माण का एक-तिहाई और निजी संपत्तियों का सात फीसद तक नियंत्रण करती है।

प्रधानमंत्री को दी फांसी

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही जनरल जिया उल को चीफ ऑफ ऑर्मी स्टाफ बनाया था। मगर उसी जनरल ने मौका मिलते ही 5 जुलाई 1977 को न केवल प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्तापलट कर सैन्य शासन लागू कर दिया, बल्कि उन्हें जेल भेजकर फांसी पर भी लटका दिया। जिया ने तख्तापलट के पीछे तर्क देते हुए कहा था कि जुल्फिकार अली भुट्टो के कार्यकाल में पाकिस्तान के हालात खराब हो चले थे, लिहाजा सैन्य शासन जरूरी था।

न्यूज गैलरी

पीएम मौरिसन से ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने मांगी मदद

सिडनी : चीन में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ऑस्ट्रेलियाई लेखक यांग जुन ने प्रधानमंत्री स्कॉट मौरिसन से मदद की गुहार लगाई है। बीजिंग स्थित उच्चायोग के एक अधिकारी के जरिये भेजे अपने संदेश में यांग ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से आग्रह किया है कि उसे जल्द-से-जल्द चीन के चंगुल से निकालने में मदद करें। यांग ने कहा है कि वह जल्द-से-जल्द ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। यांग को जासूसी के शक में इस साल जनवरी में चीन में हिरासत में ले लिया गया था। चीन ने पिछले सप्ताह यांग को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की थी। जासूसी के आरोप को खारिज करते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मौरिसन ने गुरुवार को कहा, 'यह सरासर झूठ है। हम अपने नागरिक के लिए खड़े होंगे। हम यह अपेक्षा करते हैं कि उनके (यांग) मानवाधिकार को सुरक्षित रखा जाएगा।' (एएफपी)

नेपाली सेना ने मोटापे के कारण रोका अफसरों का प्रमोशन

काठमांडू : नेपाल की सेना ने मोटापे के कारण अपने सात अफसरों पर कार्रवाई की है। तीन वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का प्रमोशन रोक दिया गया जबकि चार अफसरों को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन पर जाने से रोक दिया गया। स्थानीय मीडिया में छपी एक रिपोर्ट में नेपाली सेना के प्रवक्ता बिज्ञान देव पांडेय के हवाले से कहा गया है कि जांच में जिन सैन्य अधिकारियों का वजन अधिक पाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सातों सैन्य अधिकारियों का बीएमआइ (बॉडी मास इंडेक्स) मानक से ज्यादा था। नेपाल की सेना ने अपने कर्मियों के लिए पिछले साल 15 फरवरी में स्वास्थ्य मानक तय किए थे। विभिन्न आयुवर्ग के लिए अलग-अलग बीएमआइ तय किया गया है। सैन्य कर्मियों को खुद को फिट बनाने के लिए तीन माह से तीन साल तक का समय दिया गया है। (प्रेट्र)

एक और दावेदार अमेरिकी राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर

वाशिंगटन : अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की रेस से एक और डेमोक्रेट दावेदार किर्सटेन गिलिब्रांड ने अपना नाम वापस ले लिया है। वर्तमान में न्यूयॉर्क से सीनेटर व डेमोक्रेटिक पार्टी से टिकट पाने की होड़ में शामिल गिलिब्रांड ने अपने चुनावी अभियान में पर्याप्त समर्थन व चंदा नहीं जुटा पाईं। गिलिब्रांड के चुनावी अभियान के मैनेजर जेस फासलेर ने बताया कि सितंबर में होने वाली चुनावी बहस में हिस्सा लेने की कोई संभावना नहीं देखते हुए उन्होंने रेस से अपना नाम वापस ले लिया है। (रायटर)

इंडोनेशिया में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारत को फूंका

जकार्ता : इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में पिछले दो हफ्तों से जारी हिंसा के बीच गुरुवार को प्रांत की राजधानी जयपुरा में उग्र प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी इमारत में आग लगा दी। इंडोनेशिया से आजादी की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय असेंबली की इमारत को आग के हवाले कर दिया और आसपास के होटलों और दुकानों पर पत्थर बरसाए। ये लोग अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जारी नस्लवाद को खत्म करने की मांग कर रहे थे। बीते दिन पापुआ के सुदूर देइयाई में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के भिड़ंत में एक जवान और दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। (एएफपी)

हवाई क्षेत्र बंद करने का समय मर्जी से तय करेंगे : पाक

विदेश मंत्रालय ने कहा ▶ अभी तक नहीं लिया गया है कोई फैसला

हर पहलू पर गौर करने बाद ही उठाया जाएगा कदम

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की फाइल फोटो। एएफपी

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान ने कहा है कि वह भारत के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने संबंधी आदेश देने का समय अपनी मर्जी से चुनेगा। लेकिन अभी तक इस आशय का फैसला नहीं लिया गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुहम्मद फैसल ने गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि उच्च स्तर पर इस मुद्दे के संबंध में चर्चा की गई है। बुधवार को पाकिस्तान ने कराची के आसमान से गुजरने वाले तीन हवाई मार्गों को 31 अगस्त तक के लिए बंद करने आदेश दिया था। इस कदम का उसने कोई कारण नहीं बताया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के एक दिन पहले दिए गए बयान के बाद यह टिप्पणी की है। विदेश मंत्री ने कहा था कि भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने का फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। विचार-विमर्श में कदम के हर पहलू पर ध्यान देने के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। विदेश मंत्री ने कहा था कि हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह मुद्दा नहीं उठा था, लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री इमरान खान ही लेंगे।

इससे पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने मंगलवार को ट्विटर पर घोषणा की थी कि सरकार भारत के लिए अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही भारत द्वारा अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए पाकिस्तानी भूमि मार्ग के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाना विचाराधीन है।

भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट में जैश-ए-मुहम्मद के आतंकी प्रशिक्षण शिविर को ध्वस्त किए जाने के बाद पाकिस्तान ने फरवरी में अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद कर दिया था। उसने 27 मार्च को नई दिल्ली, बैंकाक और कुआलालंपुर को छोड़ अन्य विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोल दिया था। 15 मई को पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए प्रतिबंध की सीमा 30 मई तक बढ़ा दी थी। सभी नागरिक विमानों के लिए 16 जुलाई को हवाई क्षेत्र खोल दिया था।

गजनवी मिसाइल का किया सफल परीक्षण

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान ने भारत से ताजा तनाव के बाद सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। परमाणु क्षमता वाली इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर तक है। इस बीच, भारत ने कहा कि वह पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण से पहले से वाकिफ था।

पाकिस्तानी सेना के मुताबिक पाक नागरिक उड्डयन ने विगत बुधवार को कराची एयरस्पेस के तीन वायुमार्गों को 31 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया है। इससे समझा जा रहा था कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के परीक्षण रेंज में एक मिसाइल का परीक्षण कर रही है। इस बीच, भारत के विदेश मामलों के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया है कि पाकिस्तान के इस मिसाइल परीक्षण से भारत पहले से अवगत था। विश्वास बहाली के कदमों के तहत यह जानकारी मिली थी।

पाकिस्तानी सेना के मीडिया प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने गुरुवार को बताया कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के लांच का वीडियो ट्विटर पर जारी किया गया है। गजनवी मिसाइल परमाणु हथियार समेत कई तरह के हथियारों से लैस किया जा सकता है।

इमरान के समय में भी सुरक्षा नीतियों पर हावी है सेना : अमेरिका

▶ **प्रधानमंत्री बनने से पहले खान के पास शासन का कोई अनुभव नहीं**

वाशिंगटन, प्रेट्र : प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यकाल में भी पाकिस्तानी सेना का देश की विदेश और सुरक्षा नीतियों पर दबदबा कायम है। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है।

सांसदों के लिए यह रिपोर्ट द्वि सदस्यीय कांग्रेस रिसर्च सर्विस (सीआरएस) द्वारा तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पद पर आसीन होने से पहले खान के पास शासन का कोई अनुभव नहीं है। विश्लेषकों ने कहा है कि चुनाव के दौरान नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल करने के इरादे से पाकिस्तानी सुरक्षा सेवा ने घरेलू राजनीति में हेराफेरी की थी। कई युवाओं, शहरी, मध्यम वर्ग के मतदाताओं को प्रेरित करने वाला साबित हुआ खान का 'नया पाकिस्तान' विचार भ्रष्टाचार विरोध और 'कल्याणकारी राज्य' तैयार करने पर जोर देता है। ऐसा राज्य जो बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराता है। लेकिन देश के गंभीर आर्थिक संकट के कारण उनका हर प्रयास व्यर्थ साबित हो रहा है। देश को नए विदेशी कर्ज और सरकारी मितव्ययिता की जरूरत है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'अधिकांश विश्लेषकों ने पाया है कि पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान विदेश और सुरक्षा नीतियों पर अपना दबदबा बनाए हुए है।' रिपोर्ट पेश करने वाला सीआरएस अमेरिकी कांग्रेस की अनुसंधान शाखा है। समय-समय पर यह सांसदों के लिए रुचि के मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार करता रहता है। केवल अमेरिकी सांसदों को फैसलों की जानकारी से संपन्न करने के लिए तैयार की गई रिपोर्टों को अमेरिकी कांग्रेस की अधिकृत रिपोर्ट नहीं माना जाता है।

पाकिस्तान ने कहा, कश्मीर मामला है शीर्ष एजेंडा

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के मुताबिक, कश्मीर मुद्दे का हल उसकी विदेश नीति के एजेंडा में शीर्ष पर है। पाक विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल नेकहा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ हमेशा ही द्विपक्षीय वार्ता का समर्थन किया है, लेकिन भारतीय नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं है। गौरतलब है कि भारत जनवरी 2016 में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा पठानकोट एयरबेस पर हमला किए जाने के बाद से पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। नई दिल्ली का कहना है कि वार्ता और आतंकवाद साथ-साथ नहीं चल सकते। फैसल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के मुताबिक कश्मीर का हल हमारी विदेश नीति की बुनियाद है। उन्होंने यह भी कहा कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की बैठक में शरीक होने के लिए जिनेवा की यात्रा करेंगे।

भारत ने कहा, जाधव को तत्काल काउंसलर एक्सेस दे पाकिस्तान

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह पूर्व नौसैनिक अफसर कुलभूषण जाधव को तत्काल, प्रभावी और निर्बाध तरीके से काउंसलर एक्सेस दे। साथ ही वह पड़ोसी मुल्क से कूटनीतिक जरिए से संपर्क में है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि भारत कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान के संपर्क में है। अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले के आधार पर भारत सरकार ने भारतीय नागरिक जाधव को तत्काल और प्रभावी तरीके से राजनयिक पहुंच (काउंसलर एक्सेस) देने को कहा गया है। इससे पूर्व गुरुवार को ही 49 वर्षीय जाधव को काउंसलर एक्सेस देने के वादे के करीब पांच हफ्ते बाद पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुहम्मद फैजल ने कहा कि जाधव को काउंसलर एक्सेस देने के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान संपर्क में हैं।

ध्यान रहे विगत 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान को निर्देश दिया था कि वह बिना किसी देरी के भारत को इस मामले में राजनयिक पहुंच प्रदान करे और जाधव की सजा पर प्रभावी तरीके से पुनर्विचार करे। पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने विगत एक अगस्त को कहा था कि कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस अगले दिन दे दिया जाएगा। लेकिन दो अगस्त को होने वाली बैठक भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के चलते हो ही नहीं सकी थी। तब पाक ने भारत के सामने कुछ शर्तें रख दी थीं जिसमें पाकिस्तानी अधिकारियों की मौजूदगी में जाधव को काउंसलर एक्सेस देने की बात कही गई थी। जो भारत को मंजूर नहीं थी।

सुनवाई के बीच पाकिस्तानी जज को मिला तबादले का आदेश

▶ **मामले की सुनवाई भी तत्काल रोकने को कहा गया**

▶ **वरिष्ठ वकील ने कहा, तानाशाही के दौरान भी ऐसा नहीं हुआ**

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में एक अजीबो-गरीब वाकया सामने आया है। लाहौर की विशेष अदालत के जज बुधवार को जब एक चर्चित मामले की सुनवाई कर रहे थे, तभी उन्हें वाट्सएप पर अपने तबादले की सूचना मिली। उन्हें सुनवाई बीच में ही रोकने को कहा गया था।

मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए गठित लाहौर की विशेष अदालत के जज मसूद अरसद ने कहा, 'मुझे मेरे वाट्सएप पर अभी एक संदेश मिला है। मुझे अपना काम बंद करने के लिए कहा गया है। मेरा तबादला लाहौर हाई कोर्ट में कर दिया गया है। इसलिए मैं कार्यवाही जारी नहीं रख सकता।' अरसद ने बचाव और अभियोजन पक्ष के वकीलों से उस समय यह बात कही जब वह पाकिस्तान के विपक्षी दल पीएमएल-एन की पंजाब इकाई के अध्यक्ष और पूर्व कानून मंत्री राना सनाउल्ला के खिलाफ नशीले पदार्थ की बरामदगी से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे थे। वाट्सएप पर तबादले का संदेश मिलने के दौरान वह अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किया गया एक वीडियो देख रहे थे। यह वीडियो सनाउल्ला की कार से 15 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी से संबंधित था। जज ने हालांकि पाया कि वीडियो से हेरोइन की बरामदगी स्थापित नहीं होती। इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ वकील ने कहा, 'इमरान सरकार की ओर से थोपे गए फर्जी मामले को अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका। जज सनाउल्ला को जमानत देने का मन बना रहे थे कि तभी सरकार ने उनका तबादला कर दिया। यह अप्रत्याशित है और शायद मुल्क में तानाशाही के दौरान भी कभी ऐसा नहीं हुआ था। पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास के लिए यह काला दिन है।' जज अरसद ने जब वाट्सएप पर तबादले की जानकारी दी तो उसे सुनकर कोर्ट रूम में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। सनाउल्ला के वकील आजम तरार ने कहा, 'अब सरकार यह फैसला कर रही है कि किस मामले की सुनवाई कौन जज करे। जिस तरीके से मामले की सुनवाई रोकी गई, वह गंभीर सवाल खड़े करने वाली है।'

'विरोधियों से बदला ले रहे इमरान' : पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की प्रवक्ता मरयम औरंगजेब ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने सनाउल्ला मामले में जज का तबादला कर न्याय व्यवस्था पर हमले का काम किया है। वह फासीवादी हैं।

चीन ने हांगकांग में भेजी अपनी सेना

हांगकांग, रायटर : हांगकांग में पूर्ण लोकतंत्र की मांग को लेकर आंदोलनकारियों की 'लांग मार्च' की योजना के दृष्टिगत चीन ने सेना को सक्रिय कर दिया है। आठ से दस हजार सैनिकों को चीन से हांगकांग भेजा गया है, जो जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए बिना देरी के हरकत में आ जाएं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि सेना हांगकांग में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देगी और वहां की संपन्नता को बरकरार रखेगी। चीन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को नकारते हुए हांगकांग में अराजकता के लिए अमेरिका और ब्रिटेन को जिम्मेदार ठहराया है। हांगकांग में मौजूद प्रमुख देशों के राजनयिकों की हालात पर नजर है।

चीन ने हांगकांग में सैन्य टुकड़ियां भेजे जाने को नियमित प्रक्रिया बताकर तैयारियों पर पर्दा डालने की कोशिश की है लेकिन यह भी कह दिया है कि हालात बिगड़ने पर वह ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकेगा। हांगकांग में अधिकारों की मांग को लेकर तीन महीने से आंदोलन जारी है। आंदोलन के चलते एशिया के इस प्रमुख व्यापार केंद्र में कारोबारी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं और बाहरी लोगों का आना कम हुआ है। अब आंदोलनकारी विशाल लांग मार्च निकालकर अपनी बात कहना चाह रहे हैं। माना जा रहा है कि इसमें लाखों लोग शामिल हो सकते हैं।

चीन का सिरदर्द बन चुके प्रत्यर्पण विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए हांगकांग में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की कई टुकड़ियां भेजी गई हैं। सरकारी मीडिया शिन्हुआ ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां और वाहन हांगकांग की सीमा में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह कदम नई रैलियों और प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। एपी

ब्रिटेन में संसद निलंबन का मामला

याचिका दायर कर ब्रेक्जिट विरोधी प्रचारक मिलर ने कहा, संसद का निलंबन रद किया जाए, 24 घंटे के भीतर दस लाख से ज्यादा लोगों ने किया समर्थन

भारतीय मूल की जीना ने जॉनसन के फैसले को दी चुनौती

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन में संसद को निलंबित करने के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के फैसले के खिलाफ भारतीय मूल की ब्रेक्जिट विरोधी प्रचारक जीना मिलर ने न्यायिक समीक्षा याचिका दायर की है। जीना ने इससे पहले प्रधानमंत्री टेरीजा मे सरकार की संसद की राय लिए बगैर ब्रेक्जिट प्रस्ताव की स्वीकृति की प्रक्रिया के विरोध में भी याचिका दायर की थी। इसमें उन्हें सफलता मिली थी और टेरीजा सरकार संसद में ब्रेक्जिट प्रस्ताव लेकर आई थी, हालांकि वह प्रस्ताव वहां गिर गया था।

जीना मिलर ने कहा कि 14 अक्टूबर तक संसद को निलंबित रखने का प्रधानमंत्री का फैसला उनकी कायरता की निशानी है। यूरोपीय यूनियन छोड़ने की तारीख 31 अक्टूबर से पहले सांसदों को इस मसले पर चर्चा का समय दिया जाना चाहिए। सरकार के फैसले के खिलाफ जीना की ऑनलाइन याचिका को कुछ ही घंटों के भीतर दस लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल गया, जो किसी याचिका पर विचार के लिए पर्याप्त संख्या है। जीना ने कहा है कि सही सोच वाले ब्रिटिश नागरिक, जो कानून के राज में विश्वास रखते हैं और दुनिया में ब्रिटेन का सम्मान और लोकतांत्रिक परंपराएं बनाए रखना चाहते हैं, वे सरकार के फैसले के विरोध में उनकी याचिका का समर्थन करें।

जीना मिलर ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह नौ सितंबर से पहले उनकी याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुनाए। इससे निर्धारित समयानुसार नौ सितंबर, 2019 से संसद सत्र शुरू हो सकेगा और तब सरकार को ब्रेक्जिट का मसौदा संसद के समक्ष रखना होगा।

विरोधियों से सरकार को भी खतरा : ऐसा नहीं कि संसद को निलंबित कर प्रधानमंत्री जॉनसन ने ब्रेक्जिट का मैदान मार लिया है। विरोधी भी हार नहीं मान रहे। हाउस ऑफ कॉमंस में सत्ता पक्ष के ब्रेक्जिट समर्थक नेता जैकब रीस मॉग ने कहा है कि हमारे पास दो विकल्प हैं। हम सरकार बदल सकते हैं या कानून बदल सकते हैं। यह कार्य 31 अक्टूबर से पहले या उसके बाद भी हो सकता है। जैकब सत्ता पक्ष में हैं लेकिन ब्रेक्जिट को लेकर सरकार की रणनीति के खिलाफ हैं।

लंदन में गुरुवार को रेडियो और टेलीविजन स्टूडियो से बाहर निकलतीं भारतीय मूल की ब्रेक्जिट विरोधी प्रचारक जीना मिलर। रायटर

ब्रेक्जिट से यूरोपीय देशों में भी चिंता

लंदन, एपी : ब्रेक्जिट को लेकर ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन में हो रही तनातनी ने प्रमुख यूरोपीय देशों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अमेरिका और चीन की ट्रेड वार से जूझ रहे इन देशों पर आने वाले महीनों में मंदी का साया गहराने की आशंका पैदा हो गई है। बिना शर्त ब्रेक्जिट का नकारात्मक असर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय माना जा रहा है। यह आशंका सरकार की अंदरूनी खुफिया रिपोर्ट में भी जताई जा चुकी है। लेकिन यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी के लिए भी कम चुनौतियां नहीं हैं। पिछले कई तिमाहियों से उसकी अर्थव्यवस्था में गिरावट का सिलसिला बना हुआ है, ब्रेक्जिट को लेकर जैसा असमंजस है उसमें यह सिलसिला कई तिमाहियों तक बरकरार रह सकता है। कमोबेश यही हाल इटली की अर्थव्यवस्था का है। वहां भी गिरावट का दौर चल रहा है और आने वाली तिमाहियों में यह दौर बना रह सकता है। यूरोप के ज्यादातर देशों में निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था है। ट्रेड वार के चलते दुनिया में मंदी गहराई तो निश्चित रूप से इन देशों का निर्यात प्रभावित होगा। निर्यात कम हुआ तो अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आएगी।

सैनिकों के बच्चों को भी अब स्वत : अमेरिकी नागरिकता नहीं

▶ **ट्रंप प्रशासन ने कड़े किए नागरिकता संबंधी नियम**

वाशिंगटन, रायटर : ट्रंप प्रशासन ने विदेश में तैनात अमेरिकी नागरिकों के बच्चों के लिए भी नागरिकता के नियम कड़े कर दिए हैं। नए नियमों के तहत विदेश में तैनाती के दौरान जन्मे अमेरिकी कर्मचारियों या सैनिकों के बच्चे भी अब स्वतः नागरिकता नहीं पा सकेंगे। 29 अक्टूबर से लागू होने वाले नए नियमों के तहत विदेश में तैनात अमेरिकी सैनिकों या अन्य संघीय एजेंसियों के कर्मचारियों को अपने बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के लिए अब औपचारिक तौर पर आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होगा। मौजूदा नियम के तहत विदेश में तैनाती के दौरान जन्मे अमेरिकी नागरिकों के बच्चों को भी कानूनी तौर पर अमेरिकी नागरिक माना जाता है।

नए नियमों का विरोध : अमेरिका में नागरिकता संबंधी नए नियमों का विरोध शुरू हो गया है। सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई संगठनों ने संसद से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि सैनिक परिवार इस नियम की वजह से परेशान ना होने पाएं।

जन्म के आधार पर भी नागरिकता

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

खत्म करने की तैयारी : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में कहा था कि वह अमेरिका में जन्म लेने वाले उन बच्चों के नागरिकता के अधिकार को खत्म करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं, जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं। अमेरिकी संविधान में देश में जन्म लेने वाले ऐसे बच्चों को भी नागरिकता देने की गारंटी दी गई है, जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं।

> अवॉर्ड मांगे नहीं जाते। अवॉर्ड की भीख नहीं मांगी जाती। जो हकदार हैं, सरकार उन्हें अवॉर्ड देती है।
> — अशोक ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के पुत्र

रोहित को करना पड़ेगा इंतजार : गंभीर

नई दिल्ली : रोहित शर्मा भारतीय टेस्ट टीम में लगातार जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी फॉर्म तो कभी कुछ और चीजों की वजह से वह टेस्ट टीम से अंदर-बाहर होते रहे हैं। हालांकि, वेस्टइंडीज दौरे पर रोहित को टेस्ट टीम में चुना गया है, लेकिन पहले टेस्ट मैच में हिटमैन रोहित को मौका नहीं मिल सका। गौतम गंभीर ने कहा कि रहाणे और हनुमा के अच्छे प्रदर्शन की वजह से रोहित को इंतजार करना पड़ेगा।

दीपा मलिक को मिला खेल रत्न, समारोह में नहीं पहुंचे बजरंग

इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वालीं पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बनीं वेस्टइंडीज में टेस्ट सीरीज खेल रहे रवींद्र जडेजा भी समारोह में नहीं पहुंच सके

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: पैरालंपिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वालीं पहली भारतीय पैरा एथलीट और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गईं, लेकिन इसी पुरस्कार को हासिल करने वाले पहलवान बजरंग पूनिया अभ्यास की प्रतिबद्धताओं के कारण यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में शिरकत नहीं कर पाए।

दीपा ने 2016 रियो पैरालंपिक में गोला फेंक के एफ-53 वर्ग में रजत पदक जीता था। उन्हें एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन पूनिया के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया था, जो कजाखस्तान में होने वाली आगामी चैंपियनशिप की तैयारियों में जुटे हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता बी साई प्रणीत, महिला क्रिकेटर पूनम यादव, एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता हेप्टाथलीट स्वप्ना बर्मन, फुटबॉलर गुरप्रीत सिंह संधू, दो बार की विश्व रजत पदक विजेता मुक्केबाज सोनिया लाठेर, एशियन गेम्स के रजत पदक विजेता घुड़सवार फवाद मिर्जा, मोटर स्पोर्ट्स के दिग्गज गौरव गिल और कबड्डी कप्तान अजय ठाकुर उन 19 खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया।

पूनिया के अलावा क्रिकेटर रवींद्र जडेजा, एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता गोला फेंक एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर और 400 मीटर स्पर्धा के रजत पदक विजेता मुहम्मद अनस समारोह में अर्जुन पुरस्कार लेने नहीं आ सके। जडेजा इस समय भारतीय टेस्ट टीम के साथ वेस्टइंडीज दौरे पर हैं। दूसरी ओर तूर और अनस इस समय लखनऊ में चल रही राष्ट्रीय-अंतरराज्यीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं।

खेल मंत्री किरण रिजिजू, मानव संशाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, खेल सचिव राधेश्याम जुलानिया, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान, भारतीय ओलंपिक महासंघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा और महासचिव राजीव मेहरा उन कुछ पदाधिकारियों में से हैं जो समारोह में मौजूद रहे।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अर्जुन अवॉर्ड ट्रॉफी लेती महिला पहलवान पूजा ढांडा • प्रेट्र

> मैं बहुत खुश हूं। यह पूरी यात्रा दिव्यांगता और दिव्यांग लोगों में छिपी हुई क्षमता के प्रति लोगों के नजरिये को बदलने के बारे में कहीं ज्यादा रही है। मुझे लगता है कि यह पुरस्कार दिव्यांग महिला एथलीटों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनने वाला है। स्वतंत्र भारत में एक महिला एथलीट को पैरालंपिक में पदक जीतने में 70 साल लग गए। **दीपा मलिक**, खेल रत्न

> राष्ट्रीय खेल दिवस के खास मौके और तीन बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर हॉकी इंडिया सभी एथलीटों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता है। ध्यानचंद भारतीय खेल जगत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे। **हॉकी इंडिया**

> यह मेरे लिए सपने के सच होने जैसा है। मैं मेरे नाम की सिफारिश करने के लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को धन्यवाद देती हूं। यह पुरस्कार मुझे भविष्य में और भी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। **स्वप्ना बर्मन**, अर्जुन अवॉर्डी

> मैं यह पुरस्कार अपने उन सीनियरों को समर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे लिए इसे संभव बनाया। यह पुरस्कार भारत के भविष्य की पीढ़ी के लिए है। मुझे उम्मीद है यह उन्हें प्रेरित करने के लिए स्त्रोत का काम करेगा। **गुरप्रीत सिंह संधू**, अर्जुन अवॉर्डी

द्रोणाचार्य अवॉर्ड लेते संजय भारद्वाज, अर्जुन पुरस्कार ग्रहण करती सोनिया लाठेर, पूनम यादव और द्रोणाचार्य पुरस्कार लेते संदीप गुप्ता • सभी फोटो प्रेट्र

पुरस्कार विजेताओं की सूची

राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार : दीपा मलिक (पैरा एथलेटिक्स), बजरंग पूनिया (कुश्ती)

अर्जुन पुरस्कार : रवींद्र जडेजा (क्रिकेट), मुहम्मद अनस याहिया (एथलेटिक्स), गुरप्रीत सिंह संधू (फुटबॉल), सोनिया लाठेर (मुक्केबाजी), चिंगलेनसना सिंह कंगुजम (हॉकी), एस भास्करन (बॉडी बिल्डिंग), अजय ठाकुर (कबड्डी), अंजुम मौदगिल (निशानेबाजी), बी साई प्रणीत (बैडमिंटन), तेजिंदर पाल सिंह तूर (एथलेटिक्स), प्रमोद भगत (पैरा स्पोर्ट्स- बैडमिंटन), हरमीत राजुल देसाई (टेबल टेनिस), पूजा ढांडा (कुश्ती), फवाद मिर्जा (घुड़सवारी), सिमरन सिंह शेरगिल (पोलो), पूनम यादव (क्रिकेट), स्वप्ना बर्मन (एथलेटिक्स), सुंदर सिंह गुर्जर (पैरा स्पोर्ट्स- एथलेटिक्स) और गौरव सिंह गिल (मोटर स्पोर्ट्स)।

द्रोणाचार्य पुरस्कार (नियमित श्रेणी) : मोहिंदर सिंह ढिल्लों (एथलेटिक्स), संदीप गुप्ता (टेबल टेनिस) और विमल कुमार (बैडमिंटन)।

द्रोणाचार्य पुरस्कार (आजीवन श्रेणी) : संजय भारद्वाज (क्रिकेट), रामबीर सिंह खोकर (कबड्डी) और मेजबान पटेल (हॉकी)।

ध्यानचंद पुरस्कार : मनोज कुमार (कुश्ती), सी लालरेमसंगा (तीरंदाजी), अरूप बसक (टेबल टेनिस), नितेन किर्तने (टेनिस) और मैनुअल फ्रेडरिक्स (हॉकी)।

कमाल की दीपा

- इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को हासिल करने वाली दूसरी पैरा एथलीट बन गईं दीपा
- पैरालंपिक का दोहरा स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक एथलीट देवेंद्र झाझरिया को 2017 में इससे सम्मानित किया गया था
- दीपा 49 साल की उम्र में इस पुरस्कार को पाने वाली सबसे उम्रदराज एथलीट भी बन गईं
- मलिक चौथी बार में भाग्यशाली रहीं, क्योंकि पिछले तीन साल उनके नाम की अनदेखी की गई, जिस पर उन्होंने सवाल उठाए और फैसले की आलोचना की थी

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार

- यह हर साल 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर दिए जाते हैं
- प्रशस्ति पत्र के साथ खेल रत्न में 7.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि और अर्जुन पुरस्कार में पांच लाख रुपये दिए जाते हैं
- खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कारों के अलावा राष्ट्रपति ने कोचों को द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार, तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किए

वीर बजरंग

- 65 किलोग्राम भार वर्ग में खेलने वाले पहलवान बजरंग एशियन गेम्स में स्वर्ण, विश्व चैंपियनशिप में रजत, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण जीत चुके हैं
- अगले साल कजाखस्तान में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए जॉर्जिया में तैयारी कर रहे हैं
- हरियाणा के झज्जर से आने वाला यह पहलवान 2015 में अर्जुन अवॉर्ड और इसी साल पद्मश्री पुरस्कार हासिल कर चुका है
- अपने वर्ग के विश्व के नंबर वन पहलवान बजरंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त को मानते हैं अपना गुरु

खेल मंत्री ने दी हॉकी के जादूगर को श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के मौके पर गुरुवार को खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इस महान हॉकी खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दी।

रिजिजू ने कहा, 'आज हर कोई जानता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। उन्होंने लंबे समय तक हमें सम्मान दिलाया। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने वैश्विक स्तर पर जाकर भारत को सम्मान दिलाया। वह हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। मैं बेहद खुश और गर्व महसूस कर रहा हूं कि सभी पूर्व ओलंपियन हॉकी खिलाड़ियों ने एक साथ ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी।'

> मैं हॉकी के जादूगर को और उन सभी खिलाड़ियों के लिए सम्मान प्रकट करता हूं जो हमारे देश के लिए जोश और जुनून के साथ खेले। **शिखर धवन**, भारतीय बल्लेबाज

> हॉकी के जादूगर महान ध्यानचंद को जन्मदिवस पर हृदय से श्रद्धांजलि। खेल दिवस के मौके पर सभी साथी खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं। **रानी रामपाल**, कप्तान, भारतीय महिला हॉकी टीम

तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार: अपर्णा कुमार (लैंड एडवेंचर), स्वर्गीय दीपांकर घोष (लैंड एडवेंचर), मनीकंदन (लैंड एडवेंचर), प्रभात राजू कोली (वाटर एडवेंचर), रामेश्वर जांगड़ा (एयर एडवेंचर), वांग्चुक शेरपा (लाइफ टाइम अचीवमेंट)।

> हॉकी के जादूगर महान मेजर ध्यानचंद को जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि। खेल दिवस पर उन सभी खिलाड़ियों को भी श्रद्धांजलि, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से भारत को गौरवान्वित किया। **वीवीएस लक्ष्मण**

एनसीए प्रमुख द्रविड़ जूनियर टीम को नहीं देंगे कोचिंग

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ अब भारत-ए और अंडर-19 टीम को कोचिंग नहीं देंगे। द्रविड़ को इस साल राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) का प्रमुख बनाया गया था। सितांशु कोटक को भारत-ए और पारस महांब्रे को अंडर-19 टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। हालांकि, इन दोनों को अगले कुछ महीनों के लिए ही यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

द्रविड़ को 2015 में दोनों टीमों का मुख्य कोच बनाया गया था। तब से वह इन पदों पर काबिज थे। सौराष्ट्र के पूर्व बल्लेबाज कोटक भारत-ए के मुख्य कोच और बल्लेबाजी कोच की भूमिका निभाएंगे। वह टीम में भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रमेश पोवार के साथ काम करेंगे, जिन्हें गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण कोच बनाया गया है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज महांब्रे सितंबर में कोलंबो में होने वाले एशिया कप में अंडर-19 टीम के मुख्य और गेंदबाजी कोच होंगे। उन्होंने भारत-ए और अंडर-19 टीम में लंबे समय तक द्रविड़ के साथ काम किया है। उन्हें पूर्व भारतीय बल्लेबाज ऋषिकेश कानितकर और अभय शर्मा का साथ मिलेगा। इन दोनों को बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण कोच नियुक्त किया गया है।

क्रिकेट डायरी

- सितांशु भारत-ए और महांब्रे अंडर-19 टीम के मुख्य कोच
- अगले कुछ महीनों तक इन दोनों के पास रहेगी जिम्मेदारी

भास्कर बने दिल्ली क्रिकेट टीम के मुख्य कोच: दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने पूर्व क्रिकेटर केपी भास्कर और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा को दिल्ली की सीनियर पुरुष टीम का क्रमशः मुख्य कोच और गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। डीडीसीए ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर यह जानकारी दी।

प्रेरणास्त्रोत बनेगा देश को फिट रखने का अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री किरण रिजिजू की पहल को पूरे खेल जगत ने सराहा, दिग्गज बोले, अब भारत के लोगों को मिलेगी सेहतमंद जिंदगी जीने की प्रेरणा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर फिट इंडिया अभियान की घोषणा की। इस घोषणा के बाद से ही भारतीय खेल जगत, सिनेमा जगत से जुड़े लोगों ने इस अभियान का समर्थन किया। पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में भी मौजूद रहे। वहीं देश के जो प्रतिष्ठित लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सके उन्होंने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर अपनी बात कही और इस अभियान का खुलकर समर्थन किया।

फिट रहे इंडिया | हिट रहें हम

भारतीय स्टार महिला एथलीट हिमा दास ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री किरण रिजिजू को फिट इंडिया अभियान की शुरुआत करने के लिए बधाई। चलिए इस शानदार अभियान का हिस्सा बनते हैं। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने लिखा कि खेल मेरी जिंदगी में मेरे सबसे बड़े शिक्षक में से एक रहा है। इस खेल दिवस पर चलिए फिटनेस और अपने सपनों को पूरा करने का प्रण लेते हैं।

अभिनेता अनुपम खेर ने लिखा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री किरण रिजिजू के खेल दिवस पर लांच किए गए फिट इंडिया अभियान का समर्थन करने का प्रण लेता हूं। भारतीय महिला क्रिकेटर पूनम यादव ने अर्जुन पुरस्कार लेने के बाद लिखा कि चलिए खेल खेलते हैं, फिट रहते हैं। खुद पर कुछ समय बिताइए। फिल्म निर्देशक करण जौहर ने लिखा कि फिट इंडिया अभियान लांच करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री किरण रिजिजू को बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अभियान भारतीय लोगों को प्रेरणा देगा और वे सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अभिनेत्री मल्लिका शेरावत ने अपनी योगा की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि रोज योगा करने से मैं खुद को फिट रख पाती हूं।

अभिनेत्री शिल्पा शेटटी ने रिजिजू को बधाई देते हुए लिखा कि यह सपना एक दिन हकीकत में बदलेगा। इस शानदार शुरुआत के लिए बधाई। अभिनेता वरुण धवन ने लिखा कि यह बेहद ही शानदार अभियान है।

तेंदुलकर ने वृद्धाश्रम में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया

मुंबई, आइएएनएस: भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर गुरुवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यहां बांद्रा स्थित सेंट एंथोनी वृद्धाश्रम में पहुंचे। ट्विटर पर साझा किए गए 45 सेकेंड के वीडियो में तेंदुलकर को वृद्ध महिलाओं के साथ कैरम खेलते और हंसी-मजाक करते हुए देखा जा सकता है। तेंदुलकर ने ट्वीट किया कि सेंट एंथोनी वृद्धाश्रम में इन बेहतरीन महिलाओं के साथ समय बिताया। उनका प्यार पाकर धन्य महसूस किया। कैरम के लिए वे सभी बहुत उत्साहित थीं।

वृद्ध महिलाओं के साथ कैरम खेलते सचिन • प्रेट्र

ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट से बड़े : सहवाग

मुंबई, प्रेट्र : भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने गुरुवार को कहा कि ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसी बहु खेल प्रतियोगिताएं क्रिकेट प्रतियोगिताओं से बड़ी हैं। यहां एक किताब के विमोचन के दौरान सहवाग ने कहा कि अन्य खिलाड़ियों को क्रिकेटरों की तुलना में बेहद कम 'सुविधाएं' मिलती हैं।

सहवाग ने कहा कि मैं हमेशा से सोचता रहा हूं कि ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स क्रिकेट प्रतियोगिताओं से बड़े हैं। इन खिलाड़ियों का काफी अच्छी तरह ख्याल रखा जाता है, उन्हें अच्छा खाना और पोषक तत्वों के अलावा फिजियो और ट्रेनर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन, जब मैं उनसे मिला और उन्हें जानने का मौका मिला, मैंने महसूस किया कि जो भी सुविधाएं हमें (क्रिकेटरों को) मिलती हैं, इन खिलाड़ियों को उनका 10 या 20 प्रतिशत भी नहीं मिलता। इसके बावजूद वे पदक जीत रहे हैं। हमें जो मिल रहा है वह उससे कहीं अधिक के हकदार हैं क्योंकि वे भारत के लिए पदक जीत रहे हैं।

वीरेंद्र सहवाग • प्रेट्र

भारत की ओर से 1999 से 2013 के बीच 104 टेस्ट और 251 वनडे मैच खेलने वाले सहवाग ने कहा कि क्रिकेटर अपने कोचों को उतना श्रेय नहीं देते, जितना अन्य खिलाड़ी देते हैं। क्रिकेटरों के जीवन में कोचों की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन हम उन्हें पर्याप्त श्रेय नहीं देते। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप देश के लिए खेलना शुरू करते हो तो क्रिकेटर अपने कोचों को भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें उनसे मिलने और बात करने का अधिक मौका नहीं मिलता, लेकिन अन्य खेलों में उन्हें शुरू से अंत तक कोचों की जरूरत होती है।

विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक ने जुआन को सीधे सेटों में हराया, फेडरर को फिर पहला सेट गंवाने के बाद मिली जीत

कंधे में दर्द के बावजूद जोकोविक तीसरे दौर में पहुंचे

नोवाक जोकोविक • एएफपी

न्यूयॉर्क, एएफपी: गत विजेता नोवाक जोकोविक ने कंधे के दर्द के बावजूद बारिश से प्रभावित यूएस ओपन ग्रैंडस्लैम टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में प्रवेश किया, जबकि रोजर फेडरर ने एक और धीमी शुरुआत करते हुए कदम आगे बढ़ाए।

शीर्ष रैंकिंग के खिलाड़ी जोकोविक पिछले पांच ग्रैंडस्लैम में से चार अपने नाम कर चुके हैं और कुल 16 खिताब जीतने वाले इस धुरंधर ने अर्जेंटीना के 56वीं रैंकिंग के जुआन इग्नासियो लोंडेरो पर 6-4, 7-6, 6-1 से जीत हासिल की। सर्बियाई खिलाड़ी जोकोविक ने अपने बायें कंधे की चोट के बारे में कहा, 'इससे निश्चित रूप से मेरी सर्विस और बैकहैंड पर असर पड़ रहा था। मेरी सचमुच काफी परीक्षा हुई। दर्द के साथ खेलना आसान नहीं था, लेकिन आपको उम्मीद करनी होती है कि आपको कुछ मौके मिलें और कुछ शॉट भाग्यशाली रहें।' अब जोकोविक का सामना हमवतन दुसान लाजोविक और अमेरिका के डेनिस कुडला के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा। हालांकि, इस चोट से उनके प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा, 'इस तरह की चुनौती मेरे सामने पहली बार नहीं आई है। मैं बर्फ का पैक इस्तेमाल करूंगा। देखते हैं क्या होता है।'

वहीं, 20 बार के ग्रैंडस्लैम विजेता फेडरर 2008 के बाद पहली यूएस ओपन ट्रॉफी जीतने की उम्मीद लगाए हैं, जिन्होंने 2004 से 2008 तक लगातार यहां खिताब जीते थे। उन्होंने 99वीं रैंकिंग के दामिर जुमहुर पर 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 से फतह हासिल की। स्विट्जरलैंड के तीसरी वरीय खिलाड़ी एक बार फिर पहला सेट गंवाने के बाद मैच जीत पाए। इससे पहले उन्होंने भारतीय क्वालीफायर सुमित नागल के खिलाफ शुरुआती मुकाबले में भी पहला सेट गंवाया था। 38 साल के इस खिलाड़ी ने कहा, 'जब आप लगातार मैचों में पहला सेट गंवा देते हो तो यह थोड़ा निराशाजनक होता है, विशेषकर शुरुआती मैचों में। मैंने पहले सेट में इतनी सारी गलतियां कीं। लेकिन, आप सिर्फ बेहतर ही कर सकते हो, जो आगे बढ़ने के लिए अच्छी चीज है।' अब वह फ्रांस के 25वीं वरीय लुकास पोउली और ब्रिटेन के डैन इवांस के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से भिड़ेंगे।

वीनस बाहर, सेरेना तीसरे दौर में

न्यूयॉर्क : अमेरिका की महिला टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स को यहां यूएस ओपन में महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा, जबकि सेरेना विलियम्स अगले दौर में जगह बनाने में कामयाब रहीं। पांचवीं वरीय यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने सीधे सेटों में वीनस को 6-4, 6-4 से पराजित किया। सेरेना ने दूसरे दौर के एक कड़े मैच में वाइल्डकार्ड के जरिये टूर्नामेंट खेलने वाली हमवतन 17 वर्षीय केटी मैकनेली को 5-7, 6-3, 6-1 से शिकस्त दी। वीनस मैच की शुरुआत से ही स्वितोलिना के खिलाफ परेशानी में नजर आईं। हालांकि, उन्होंने किसी भी स्तर पर मुकाबले को एकतरफा नहीं होने दिया। दूसरे सेट में 39 वर्षीय वीनस ने कुल पांच मैच प्वॉइंट बचाए। दूसरी ओर, सेरेना के खिलाफ मैकनेली ने दमदार शुरुआत की और पहले सेट को जीतकर सभी को चौंका दिया। पूर्व विश्व नंबर एक सेरेना ने किसी प्रकार का उलटफेर नहीं होने दिया और अगले दो सेट जीतकर तीसरे दौर में जगह बना ली। तीसरे और निर्णायक सेट में उन्होंने केवल एक गेम गंवाया। सेरेना ने कहा, 'मैंने पहले दो सेटों में कई गलतियां कीं। आप इतनी गलतियां करके टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। मैं जानती हूं कि मुझे अच्छा खेलना है और मैं यह कर सकती हूं।' मैकनेली का जन्म भी नहीं हुआ था जब सेरेना ने 1999 में अपना पहला यूएस ओपन का खिताब जीता था। वहीं, दूसरी वरीय ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने अमेरिका की लॉरेन डेविस को सीधे सेटों में 6-2, 7-6 से हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई। अमेरिका की 10वीं वरीय मेडिसन कीज ने दूसरे दौर में चीन की जु लिन का सफर 6-4, 6-1 से समाप्त किया।

सेरेना • यूएसए टुडे स्पोर्टस

टीवी चैनल पर विज्ञापन देकर कश्मीर के क्रिकेटरों को बुलावा

विकास अबरोल, जम्मू: जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) की टीम 22 अगस्त से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शुरू हुई विजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाई लेकिन अब राज्य संघ ऐसा कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता है। जेकेसीए ने 24 सितंबर से शुरू होने वाली विजय हजारे क्रिकेट प्रतियोगिता में हर हालत में जम्मू-कश्मीर की टीम को भेजने के लिए अभी से कमर कस ली है।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में मोबाइल और इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद होने से कश्मीर के खिलाड़ियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जेकेसीए अपने सभी खिलाड़ियों से संपर्क नहीं कर पा रही है। जेकेसीए के सीईओ आशिक अली बुखारी ने प्रशासक सीके प्रसाद के साथ बैठक कर अब कश्मीर के स्थानीय टीवी चैनलों में विज्ञापन देकर संपर्क करना शुरू कर दिया है। इन विज्ञापनों के माध्यम से कश्मीर संभाग के क्रिकेटरों से आग्रह किया जा रहा है कि वे लैंडलाइन फोन के माध्यम से ही उनसे संपर्क करने की जल्द से जल्द कोशिश करें ताकि आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र में टीम के लिए जम्मू या फिर राज्य से बाहर किसी स्थान पर कैंप लगाया।

भारत की नजर क्लीन स्वीप पर

- विंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट आज से
- भरोसे पर खरा उतरना चाहेंगे रिषभ पंत

किंग्सटन (जमैका), प्रेट्र : भारतीय टीम शुक्रवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान वेस्टइंडीज के खिलाफ 'क्लीन स्वीप' के इरादे से उतरेगी, जबकि युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत टीम प्रबंधन के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे।

पहला टेस्ट 318 रन से जीत चुकी भारतीय टीम सबीना पार्क में दूसरे मैच में प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगी। दूसरी ओर मेजबान टीम पांच दिवसीय क्रिकेट की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकी है। भारत के गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने कहा, 'यहां परिस्थितियां अच्छी हैं और पिच भी अच्छी लग रही है। हमें एक और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।' पहले मैच में जसप्रीत बुमराह ने छह और इशांत शर्मा ने आठ विकेट लेकर वेस्टइंडीज की कमजोरियों की कलई खोल दी। उनका इरादा इस प्रदर्शन को बरकरार रखने का होगा। इतनी बड़ी जीत के बाद भारत अंतिम एकादश में बदलाव शायद ही करे, हालांकि पंत की फॉर्म चिंता का सबब है। 21 वर्षीय इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज को महेंद्र सिंह धौनी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, लेकिन उनके आउट होने के तरीके से टीम के लिए चिंता पैदा हुई है। इस दौरे पर उन्होंने 00, 04, नाबाद 65, 20, 00, 24 और 07 रन बनाए हैं। अनुभवी रिद्धिमान साहा के ड्रेसिंग रूम में लौटने और कोना भरत के प्रतीक्षा सूची में होने से अब पंत मौके को हल्के में नहीं ले सकते। पहले टेस्ट की दूसरी पारी में उनके पास बिना किसी दबाव के खुलकर खेलने का मौका था, लेकिन वह खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। टी-20 सीरीज में एक अर्धशतक को छोड़कर वह कोई कमाल नहीं कर सके। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल भी पहले टेस्ट में फॉर्म में नहीं थे, लेकिन उन्हें एक और मौका मिलने की उम्मीद है। भारतीय मध्य क्रम ने पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें अजिंक्य रहाणे ने एक अर्धशतक और एक शतक लगाया। हनुमा विहारी ने भी दूसरी पारी में 93 रन बनाए, जिसके मायने हैं कि रोहित शर्मा को अंतिम एकादश में जगह पाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन पहले मैच में काबिले तारीफ रहा। इशांत और बुमराह ने खास तौर पर बेहतरीन गेंदबाजी की। मुहम्मद शमी भी प्रभावी दिखे और रवींद्र जडेजा ऑलराउंडर के रूप में काफी उपयोगी रहे। अरुण ने कहा, 'विकेट मिलने पर कोई भी तेज गेंदबाज फॉर्म में माना जाएगा। इशांत और बुमराह का मनोबल इस प्रदर्शन से काफी बढ़ा होगा। शमी भी अच्छे फॉर्म में दिखे।' वेस्टइंडीज के लिए पहले मैच में कुछ भी अच्छा नहीं रहा। दोनों पारियों में उसका एक भी खिलाड़ी अर्धशतक भी नहीं बना सका। हेटमायर और शाई होप असरदार नजर नहीं आए, जबकि रोस्टन चेज भी फॉर्म में नहीं थे। वेस्टइंडीज के लिए एक ही राहत की बता रही कि शेनॉन गेब्रियल और केमार रोच ने उम्दा गेंदबाजी की।

भारत : विराट कोहली (कप्तान), केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, पुजारा, रहाणे, हनुमा विहारी, रिषभ पंत, रवींद्र जडेजा, मुहम्मद शमी, इशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रिद्धिमान साहा, अश्विन, उमेश यादव, भुवनेश्वर।

वेस्टइंडीज : होल्डर (कप्तान), क्रेग ब्रेथवेट, डेरेन ब्रावो, शमारह ब्रूक्स, कैंपबेल, चेज, रकहीम कार्नवाल, शेन डॉवरिच, शेनॉन गेब्रियल, हेटमायर, होप, कीमो पॉल और केमार रोच।

उच्चायुक्त के घर डिनर

किंग्सटन : वेस्टइंडीज के दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम ने बुधवार को यहां भारतीय उच्चायुक्त एम सेवला नाइक के निवास पर आधिकारिक डिनर किया। बीसीसीआइ ने एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, 'भारतीय टीम के सदस्यों ने जमैका में भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर आधिकारिक डिनर में हिस्सा लिया।'

सर्वश्रेष्ठ स्पैल में से एक था बुमराह का स्पैल : अरुण

भरत अरुण ● फाइल फोटो, प्रेट्र

किंग्सटन, प्रेट्र : भारत के गेंदबाजी कोच भरत अरुण को लगता है कि हालात को भांपने की जसप्रीत बुमराह की काबिलियत अद्भुत है और वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरुआती टेस्ट में दूसरी पारी में उनका पांच विकेट चटकाना भारत के 'तेज गेंदबाजी के सर्वश्रेष्ठ स्पैल' में से एक था। बुमराह को विश्व कप के बाद एक महीने का ब्रेक दिया गया था। वह एंटीगा में पहली पारी के दौरान थोड़े धीमे दिखे थे, लेकिन उन्होंने दूसरी पारी में वापसी करते हुए आठ ओवरों में सात रन देकर पांच विकेट हासिल किए।

अरुण ने कहा, 'बुमराह सोच समझकर गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज हैं। वह हालात से वाफिक रहते हैं और अच्छी तरह सामंजस्य बिठा लेते हैं। अगर आप (पहले टेस्ट की) दूसरी पारी में उनकी लेंथ देखोगे तो उन्हें अच्छा मूवमेंट मिल रहा था। मैंने किसी भारतीय का लंबे समय बाद इस तरह का स्पैल देखा। यह तेज गेंदबाजी का सर्वश्रेष्ठ स्पैल था।' उन्होंने कहा कि कोच की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करनी होती है कि रणनीति का क्रियान्वयन 'संपूर्ण' तरीके से किया गया हो, क्योंकि फिर नतीजा अपने आप ही सही रहता है। बुमराह ने पहली पारी में 18 ओवर में पांच रन देकर एक विकेट लिया था। अरुण ने कहा, 'देखिए, विकेट तो नतीजा होता है, लेकिन मैं हमेशा नतीजे को नहीं देखता। मैं क्रियान्वयन में लाए गए हिस्से को अहम मानता हूं और पहली पारी के बाद बुमराह से इसी पर चर्चा हुई थी। पहली पारी में उनका क्रियान्वयन थोड़ा कम रहा क्योंकि उनकी गेंदबाजी की शैली को देखते हुए उन्हें पिच करना चाहिए था। विकेट लेना चिंता की बात नहीं थी क्योंकि सही लाइन एवं लेंथ में गेंदबाजी करने की प्रक्रिया अंत में आपको विकेट दिलाएगी। वह लगातार 140 की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं और उनका एक्शन इस तरह का है कि बल्लेबाज को यह समझने में थोड़ा समय लगता है कि वह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं।

कपिल को पीछे छोड़ सकते हैं इशांत

किंग्सटन, आइएएनएस : भारतीय टीम शुक्रवार को जब यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में उतरेगी तो तेज गेंदबाज इशांत शर्मा के पास एशिया के बाहर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में कपिल देव से आगे निकलने का मौका होगा। एशिया के बाहर सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों में इशांत, कपिल के साथ दूसरे पायदान पर काबिज हैं। दोनों ने एशिया से बाहर 45-45 टेस्ट मैच खेले हैं और 155-155 विकेट लिए हैं। अगर वह एक विकेट और लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इस सूची में कपिल से आगे निकल जाएंगे। दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले 50 मैचों में 200 विकेट के साथ इस सूची में पहले पायदान पर बने हुए हैं।

97 टेस्ट मैच खेले गए हैं भारत व वेस्टइंडीज के बीच। इनमें से भारत ने 21 व वेस्टइंडीज ने 30 मैच जीते। 46 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे

50 टेस्ट मैच कैरेबियाई सरजमीं पर हुए हैं दोनों टीमों के बीच। इनमें से भारत ने आठ व वेस्टइंडीज ने 16 टेस्ट जीते। 26 टेस्ट ड्रॉ रहे

12 टेस्ट हुए हैं सबीना पार्क स्टेडियम में भारत व वेस्टइंडीज के बीच। इनमें से दो भारत, जबकि वेस्टइंडीज ने छह टेस्ट जीते। चार टेस्ट ड्रॉ रहे

इशांत शर्मा ● फाइल फोटो, एएफपी

इलावेनिल ने जीता स्वर्ण पदक

रियो डि जेनेरियो, प्रेट्र : तेजी से उभर रहीं इलावेनिल वलारिवान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शीर्ष पर रहते हुए अपना पहला सीनियर विश्व कप स्वर्ण पदक जीता, लेकिन अंजुम मौदगिल और अपूर्वी चंदेला यहां आइएसएसएफ राइफल/पिस्टल चरण की स्पर्धा में पदक नहीं जीत सकीं। यह 20 साल की इलावेनिल का सीनियर स्तर पर पदार्पण वर्ष है। उन्होंने फाइनल में 251.7 का स्कोर बनाते हुए स्वर्ण जीता। ग्रेट ब्रिटेन की सेओनेड मैकिंटोश ने 250.6 के स्कोर के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत अब इस साल महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व कप के चार स्वर्ण पदकों में से तीन जीत चुका है।

गुजरात की इलावेनिल एशियन चैंपियन होने के साथ ही जूनियर विश्व कप की स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। चीनी ताइपे की लिय यिंग शिन ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने यहां मौजूद टोक्यो 2020 ओलंपिक के दो कोटा में से एक स्थान हासिल किया। दूसरा कोटा स्थान ईरान को मिला। भारत पहले ही इस स्पर्धा में ओलंपिक कोटा हासिल कर चुका है। इलावेनिल ने क्वालीफिकेशन दौर में प्रभावित करते हुए 629.4 का स्कोर बनाया। अंजुम ने 629.1 का स्कोर बनाया। ये दोनों आठ महिलाओं के फाइनल में क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर रही थीं।

द. अफ्रीका के खिलाफ टी-20 टीम से धौनी आउट

- द. अफ्रीका के साथ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा, बुमराह, भुवनेश्वर, कुलदीप, चहल को दिया गया आराम

मुंबई, प्रेट्र : अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी-20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी। टीम में हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है। भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और युजवेंद्रा सिंह चहल को आराम दिया गया है। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को टीम में जगह नहीं मिली है। राहुल चाहर और दीपक चाहर को टीम में बनाए रखा गया है। बता दें कि दीपक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टी-20 मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की थी, जिसका इनाम उन्हें एक बार फिर टीम में चयन के साथ मिला है। इसके अलावा उनके भाई राहुल का भी वहां संतोषजनक प्रदर्शन रहा था।

वेस्टइंडीज दौरे पर गई टीम में हार्दिक पांड्या शामिल नहीं थे। उन्हें आराम दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भारतीय टीम में पांड्या का आना और भुवनेश्वर का जाना, एकमात्र बदलाव है। विंडीज दौरे पर धौनी ने आराम मांगा था लेकिन दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय चयन समिति ने धौनी को टीम से बाहर रखने का फैसला किया। पहला मैच 15 सितंबर को धर्मशाला में, दूसरा मैच 18 सितंबर को मोहाली में और तीसरा मैच 22 सितंबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। इसके बाद तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी।

टीम : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उप कप्तान), शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, मनीष पांडे, रिषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, क्रुणाल पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, राहुल चाहर, दीपक चाहर, नवदीप सैनी और खलील अहमद।

भारत-ए ने दक्षिण अफ्रीका-ए को 69 रन से हराया

तिरुवनंतपुरम, एएनआइ : शिवम दुबे (नाबाद 79) और अक्षर पटेल (नाबाद 60) के अर्धशतकों के बाद युजवेंद्रा सिंह चहल के पांच विकेटों की मदद से भारत-ए ने गुरुवार को यहां खेले गए पहले अनाधिकारिक वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका-ए को 69 रनों से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। मैदान गीला होने के कारण मैच को 47-47 ओवरों का कर दिया गया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका-ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत-ए ने एक समय 206 रन के स्कोर तक अपने छह विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद दुबे और पटेल ने सातवें विकेट के लिए 121 रनों की अविजित साझेदारी करके भारत-ए को छह विकेट पर 327 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। दुबे ने 60 गेंदों पर तीन चौके और छह छक्के जबकि पटेल ने 36 गेंदों पर छह चौके और तीन छक्के लगाए। उनके अलावा शुभमन गिल ने 46, कप्तान मनीष पांडे ने 39, इशान किशन ने 37 और अनमोलप्रीत सिंह ने 29 रनों का योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका-ए की ओर से ब्यूरेन हेंड्रिक्स और जोर्न फोर्तुन ने दो-दो जबकि एनरिक नॉर्जे तथा जूनियर डाला ने एक-एक विकेट लिया। भारत-ए से मिले 328 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका-ए टीम 45 ओवर में 258 रन पर ऑलआउट हो गई।

टेस्ट में एक ही तरह की गेंद का हो इस्तेमाल

गौतम गंभीर
फिलक

सच कहूं तो अभी भी मुझे विश्व कप फाइनल, एशेज के तीसरे टेस्ट या कहा जाए तो बेन स्टोक्स के प्रदर्शन से बाहर आने में वक्त लगेगा। दो महीनों में यह दूसरी बार हुआ जब बेन ने मुश्किलों में अपना जादू दिखाया। लोग अभी भी उनके विश्व कप फाइनल की पारी की बात कर रहे थे और उन्होंने यह टेस्ट शतक लगा दिया।

मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट के रोमांच को जीना चाहते हैं हेडिंग्ले टेस्ट को फॉलो करें। यह स्टोक्स साथ ही ईसीबी के अच्छे टेस्ट विकेट बनाने की वजह से हो पाया है। भारत और वेस्टइंडीज की टीम भी शुक्रवार से मैदान में उतरेंगी। हमेशा की तरह मैं अच्छे विकेट की उम्मीद करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह पहले टेस्ट की तरह सपाट पिच नहीं होगी। टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि सपाट पिच की जगह अच्छी पिच तैयार की जाएं। मैं पारंपरिकता का बड़ा प्रशंसक हूं लेकिन अरबों लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए नई सोच की जरूरत है। एक अच्छी पिच के साथ अच्छी क्वालिटी की गेंद का भी इस्तेमाल होना चाहिए। मैं वित्तीय मजबूरियां समझ सकता हूं, लेकिन यह देखकर अजीब लगता है कि एक ही तरह की क्रिकेट में कई तरह की ब्रांड की गेंदों का इस्तेमाल होता है। हो सकता है कि आइसीसी टेस्ट क्रिकेट में गेंद के इस्तेमाल के लिए पैरामीटर तय करे और गेंद निर्माताओं के लिए टेंडर जारी करे। जो भी यह टेंडर हासिल करे वह आइसीसी का गेंदबाजी साझेदार हो सकता है।

रविचंद्रन अश्विन जैसे स्पिनर रोमांचित होंगे अगर उन्हें किसी भी ब्रांड की गेंद मिले। उनके वेस्टइंडीज में पहले टेस्ट में बेंच पर बैठने पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता सिवाए इसके कि मैं यह देखकर बेहद निराश था। मैं रोहित शर्मा को शामिल नहीं करने के फैसले को भी नहीं पचा पाया, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास अब जमैका में भी जगह बनाने का कोई मौका नहीं है। अजिंक्य रहाणे और हनुमा विहारी ने टीम में अपनी जगह बना ली है। मैं यह देखकर खुश हुआ कि इशांत विकेट ले रहा था। वह बेहद अच्छा इंसान है और ईमानदार है। उसका रवैया कप्तान के लिए अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि वह दूसरे टेस्ट में भी ऐसा ही प्रदर्शन करेगा और टीम इंडिया के लिए लगातार विकेट लेने वाला गेंदबाज बनेगा। पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था जबकि मेजबान टीम कुछ खास नहीं कर पाई थी। वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी ने पहले टेस्ट में निराश किया। यह कहना गलत होगा कि यह एक युवा टीम है, लेकिन मैं पूर्व वेस्टइंडीज बल्लेबाजों के इस कथन पर जरूर हामी भरूंगा जिसमें वे कई बार कहते दिखे हैं कि इस टीम का प्रदर्शन बेहद साधारण है। ऐसे में वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ियों पर इस मामले में अच्छे से विचार करना होगा। तब ही वेस्टइंडीज क्रिकेट एक बार फिर ऊंचाईयां छू सकेगा।

विविध

भारतीय मूल के डॉक्टर के विकसित रोबोट से होगी सर्जरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में होगा इसका क्लीनिकल ट्रायल
- मशीन की लागत कम होने से देश में सस्ती होगी रोबोटिक सर्जरी

कैंसर सहित विभिन्न बीमारियों के इलाज में रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी यह तकनीक बहुत महंगी है। अच्छी बात यह है कि अमेरिका में कार्यरत भारतीय मूल के कार्डियक सर्जन डॉ. सुधीर श्रीवास्तव ने रोबोट तैयार किया है, जो मौजूदा रोबोटिक मशीन से सस्ता है। चीन में एनिमल पर इसका ट्रायल भी हो चुका है। जल्द ही देश के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में भी इसका क्लीनिकल ट्रायल होगा। इससे आने वाले दिनों में देश में रोबोटिक सर्जरी सस्ती होगी। यह जानकारी प्रोस्टेट कैंसर पर आयोजित प्रेसवार्ता में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉ. सुधीर कुमार रावल ने दी।

उन्होंने कहा कि डॉ. श्रीवास्तव इस रोबट को विकसित करने के लिए अमेरिका से चीन गए। अमेरिका में खर्च अधिक आता इसलिए उन्होंने चीन में रोबोट तैयार किया और साफ्टवेयर भारत के विशाखापत्तनम में तैयार हुआ। इस रोबोट का इस्तेमाल हर प्रकार की सर्जरी में संभव होगा। प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी में भी इसका इस्तेमाल होगा। रोबोट से सर्जरी के कई फायदे हैं। इसमें दर्द कम होता है। सर्जरी में रक्त स्राव कम होता है व मरीज की रिकवरी तेजी से होती है। असल परेशानी यह है कि रोबोट की कीमत करीब 14 करोड़ है। अभी एक ही कंपनी इसे बनाती है। इसलिए देश के कुछ गिने चुने अस्पतालों में यह सुविधा है। मशीन महंगी होने के कारण इस तकनीक से सर्जरी भी महंगी है। प्रोस्टेट कैंसर की रोबोटिक सर्जरी के लिए 3.50 लाख लिया जाता है। अभी हम अमेरिकन रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो दिन बहुत दूर नहीं है, जब भारतीय मूल के डॉक्टर द्वारा बनाए जा रहे रोबोट से सर्जरी होगी। इसकी यहां कीमत करीब चार करोड़ होगी। इसलिए सर्जरी का खर्च तीन लाख से कम हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि एक तो मौजूदा रोबोटिक मशीन बहुत महंगी है। साथ ही 10 सर्जरी के बाद यह मशीन खुद लॉक हो जाती है। इसके बाद कुछ उपकरण बदलने पड़ते हैं, जिस पर दो से ढाई लाख का खर्च आता है। तभी यह दोबारा काम करती है। कई और कंपनियां भी रोबोटिक मशीन लाने वाली हैं।

सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट पर घिरी सरकार, कैप्टन पर चौतरफा हमला

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

- कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य प्रताप बाजवा बोले, विरोधाभासी बयान दे रहे कैप्टन अमरिंदर

श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में सीबीआइ से सभी केस वापस लेने को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधियों ने उन पर चौतरफा हमला बोल दिया है। उनकी अपनी ही पार्टी के राज्य सभा सदस्य और पूर्व प्रदेश प्रधान प्रताप सिंह बाजवा ने स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम के डीजीपी प्रबोध कुमार द्वारा सीबीआइ को लिखे पत्र और अदालत में सीबीआइ से केस वापस लेने की कार्यवाही को परस्पर विरोधी बताया है। दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी स्पीकर बीर दविंदर सिंह ने मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा से इस्तीफे की मांग की है।

प्रताप बाजवा ने कहा कि एक ओर तो सरकार ने जनवरी में सीबीआइ से केस वापस लेने की नोटिफिकेशन जारी कर दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने भी मान लिया था। लेकिन अब एसआइटी के प्रमुख ही सीबीआइ को पत्र लिखकर कह रहे हैं कि वह कुछ नए एंगल पर जांच करें जिसके बाद सीबीआइ ने भी ट्रायल कोर्ट में अपनी ही क्लोजर रिपोर्ट को लंबित करने की याचिका दायर कर दी है।

बाजवा ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि पंजाब सरकार ने सीबीआइ से इन मामलों की जांच वापस लेने के बाद भी छह महीने तक फाइलें वापस लेने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर से पूछा है कि वह बताएं कि पंजाब सरकार ने बेअदबी के मामलों की फाइलें सीबीआइ से कब मांगी?

सीबीआइ ने अदालत में स्पष्ट कहा है कि सरकार ने उससे जांच के संबंध में कभी भी संपर्क नहीं किया तो कैप्टन किस बात पर यह दावा कर रहे हैं कि एसआइटी अब इन मामलों की जांच कर रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर प्रबोध कुमार के नेतृत्व में एसआइटी अब बेअदबी के मामले की जांच कर रही है तो प्रबोध ने अब सीबीआइ को फिर से जांच करने के लिए क्यों लिखा? एसआइटी ने अब तक सीबीआइ से केस की फाइल वापस क्यों नहीं ली? क्या सीएम को इस मामले में गुमराह किया गया है कि मामलों की जांच सीबीआइ नहीं, एसआइटी कर रही है या वह वास्तविक स्थिति से अवगत होते हुए लोगों को इस मामले में गुमराह करते रहे।

कैप्टन बादल परिवार से हुए समझौते को निभा रहे : दविंदर

पूर्व डिप्टी स्पीकर बीर दविंदर सिंह ने कहा है कि पंजाब विधानसभा द्वारा सभी केस वापस लेने का प्रस्ताव जब पारित कर दिया था तो डीजीपी प्रबोध कुमार ने सीबीआइ को केसों की जांच जारी रखने का पत्र क्यों लिखा? उन्होंने आरोप लगाया कि इससे साफ जाहिर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कई दिशाओं पर काम कर रहे हैं। एक तरफ वह बादल परिवार से हुए अपने समझौते को निभा रहे हैं और दूसरी ओर डेरा सिरसा को भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के खिलाफ न माफी योग्य अपराध से मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं।

सीएम से पूछे बिना डीजीपी पत्र नहीं लिख सकते : खैहरा

पंजाबी एकता पार्टी के प्रधान व विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने ने आरोप लगाया कि इस मामले में सीएम बादल परिवार को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कहा कि एक डीजीपी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वह सीएम से बिना पूछे इतने महत्वपूर्ण मामले में सीबीआइ डायरेक्टोरेट को पत्र लिखे।

बैक्टीरिया करेगा पानी साफ

चंद्रशेखर वर्मा, ग्रेटर नोएडा

पानी को साफ करने के लिए बनाया गया बैक्टीरिया। इस प्रदर्शन इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया। जागरण

- पानी में डालने पर 15 से 21 दिनों में करेगा साफ, पाउडर के रूप में है मौजूद

घरों व उद्योगों से निकलने वाले गंदे सीवरेज के पानी को अब कुछ ही दिनों में साफ किया जा सकेगा। इसके लिए न कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा और न ही कोई भारी-भरकम सिस्टम। पानी को साफ करने का यह काम एक बैक्टीरिया करेगा। गंदे सीवरेज पानी को किसी जगह जमा करना पड़ेगा और इसमें बैक्टीरिया को डालना होगा। 15 से लेकर 21 दिनों के बीच गंदा पानी उपयोग करने योग्य हो जाएगा। इसे साफ-सफाई, टॉयलेट, पौधों को पानी आदि देने के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। इस बैक्टीरिया का नाम बेक्टा कल्ट एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) रखा गया है। यह पाउडर के रूप में मौजूद होता है। इसे इंडिया एक्सपो मार्ट में चल रहे जल संरक्षण सम्मेलन में लगाए गए स्टॉल में प्रदर्शित किया गया।

कंपनी के क्षेत्रीय सेल्स मैनेजर कुलदीप झा ने बताया कि अक्सर उद्यमी महंगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के चलते अपने यहां इसे नहीं लगाते। इससे यहां से निकलने वाला गंदा विषैला पानी नदियों में जाकर उसे प्रदूषित कर रहा है। इससे कई नदियों में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो गई है। इनमें रहने वाले जलीय जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। हमने पाउडर के रूप में एक बैक्टीरिया तैयार किया है। इसको गंदे पानी में डालने से यह अपना काम करना शुरू कर देता है। यह अपशिष्ट पदार्थ को धीरे-धीरे खाने लगता है। ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाता है और साफ पानी ऊपर रहता है। इससे पानी में बॉयलोजिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (सीओडी) की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा कई इलाकों में सीवरेज सिस्टम नहीं होते। इसके लिए लोग अपने घरों में टॉयलेट के लिए बाहर सेप्टिक गड्ढा बनाते हैं। इसके भर जाने पर लोगों को दूसरा गड्ढा खोदना पड़ता है। इस बैक्टीरिया को अगर गड्ढे में डाल दिया जाए तो यह सारे मल को साफ कर देगा और गड्ढा नहीं भरेगा।

बैक्टीरिया है पूरी तरह जैविक : इस बैक्टीरिया के पाउडर को बनाने में किसी तरह के रसायन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस वजह से पूरी तरह से जैविक है। कुलदीप झा ने बताया कि अगर इसे किसी बंजर भूमि में डाल दिया जाए तो खेती की जा सकती है। इसकी लागत भी कम है। एक किलोग्राम पाउडर की कीमत 1,250 रुपये है। एक किलो पाउडर करीब दो हजार लीटर पानी को साफ कर सकता है।

नहीं बना शौचालय तो मायके चली गई बहू

जागरण संवाददाता, कुशीनगर : विशुनपुरा ब्लाक के डिबनी गांव में शौचालय नहीं बनवाने से नाराज एक बहू ससुराल छोड़ मायके चली गई।

दरअसल, डिबनी निवासी प्रद्युम्न का विवाह 18 मई को रामनगर मिश्रौली निवासी श्रीकिशन दयाल की बेटी सुनीता चौहान से हुआ था। सुनीता इंटरमीडिएट तक पढ़ी है। विवाह के पूर्व ही ससुराल में शौचालय बनाने की बात हुई थी लेकिन ससुराल वालों ने शादी के तीन माह बीतने पर भी शौचालय नहीं बनवाया तो उसने ससुराल छोड़ने का फैसला कर लिया।

सुनीता की सास विमला ने कहा कि वह गरीब है। करीब 10 वर्ष पहले पति का निधन हो चुका है। छोटे लड़के प्रद्युम्न की शादी तीन माह पूर्व की थी। बहू ने शौचालय बनवाने की बात कही थी, लेकिन बन नहीं पाया। प्रधान व सचिव से मिलकर कई बार शौचालय की मांग की, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सीडीओ आनंद कुमार ने कहा यदि शौचालय की वजह से बहू मायके गई होगी तो प्रधान व सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

महिला कर्मचारी के ऊपर कार चालक ने किया हमला

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम

खेड़कीदौला टोल प्लाजा की एक महिला कर्मचारी के ऊपर कार चालक ने गुरुवार सुबह हमला कर दिया। टोल मांगने पर न केवल उसने न सिर्फ गालियां दीं, बल्कि हाथ पकड़कर चार-पांच थप्पड़ भी मारे। इसके बाद अन्य कर्मचारियों ने उसे दबोच लिया। सूचना मिलते ही खेड़कीदौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान गांव शिकोहपुर निवासी 23 वर्षीय राहुल के रूप में की गई। आरोपित को गुरुवार दोपहर बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया गया।

दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे स्थित खेड़कीदौला टोल प्लाजा की एक लेन के काउंटर के सामने सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर एक अल्टो कार पहुंची। महिला कर्मचारी ने टोल देने के लिए कहा तो उसने अपने आपको स्थानीय बताया। जब उससे टैग दिखाने के लिए कहा गया तो कहा कि नहीं है। उसकी कार भी दिल्ली नंबर की थी। उसके पास एक भी कागजात नहीं था जिससे कि पता चले कि वह स्थानीय है। इस पर कर्मचारी ने कहा कि टोल देना होगा। इससे गुस्से में आकर उसने गालियां देनी शुरू कर दीं। जब कर्मचारी ने विरोध किया तो वह कार से बाहर निकला और उनका हाथ पकड़कर चार-पांच थप्पड़ जड़ दिए। इसी बीच अन्य कर्मचारियों ने उसे दबोच लिया। इस वजह से कुछ देर तक टोल प्लाजा के नजदीक ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रही। पुलिस प्रवक्ता सुभाष बोकन ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसकी कार भी बरामद कर ली गई।

इधर, घटना से संबंधित वीडियो देखने से यह भी साफ है कि कार के नजदीक जो कर्मचारी खड़े थे उन्होंने मामले को संभालने का प्रयास नहीं किया। उसने कार में भी बैठे-बैठे गालियां दी थीं। यदि उसी समय उसे काबू कर लिया जाता या समझा दिया जाता तो मामला यहां तक नहीं पहुंचता।

दिल्ली- गुरुग्राम एक्सपेस वे स्थित खेड़कीदौला टोल प्लाजा पर कार चालक से टोल मांगने पर महिला कर्मचारी को बालों से पकड़कर बहार खीचकर मारपीट करता युवक। वीडियो ग्रैब

टोल कर्मियों पर पहले भी हो चुके हैं हमले

इसी साल 21 जून को खेड़कीदौला टोल प्लाजा पर कार्यरत एक अन्य महिला कर्मचारी के ऊपर गांव शिकोहपुर के ही रहने वाले मंजीत ने हमला किया था। उसी दिन रात को टोल मांगने पर एक कार चालक ने टोलकर्मी दिनेश के साथ न केवल मारपीट की बल्कि उनके ऊपर कार चढ़ाने का प्रयास किया था। यही नहीं एक टोलकर्मी को एक कार चालक टक्कर मारने के बाद तीन किलोमीटर तक बोनट पर उठाकर ले गया था। इनके अलावा भी कई कर्मचारियों के साथ मारपीट की जा चुकी है। टोल संचालन का काम देखने वाली कंपनी स्काईलार्क के जनसंपर्क अधिकारी कृपाल सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों के लिए टैग जारी है, जिनके पास भी टैग है उनसे टोल की मांग नहीं की जाती है। टोल पर अक्सर कोई न कोई बदमाशी करता है। जब मामला बड़ा होता है तो शिकायत दर्ज कराई जाती है।

मौसम विशेष

प. वि - पश्चिमी विक्षोभ
च. ह - चक्रवाती हवा का क्षेत्र
मॉनसून की अक्षिय रेखा
श्रीनगर 26/19, चंडीगढ़ 33/27, दिल्ली 37/29, जयपुर 33/26, लखनऊ 34/27, पटना 37/29, गुवाहाटी 34/27, अहमदाबाद 33/26, भोपाल 28/24, राँची 32/23, कोलकाता 33/27, नागपुर 29/25, मुम्बई 31/26, भुवनेश्वर 33/26, हैदराबाद 29/24, विशाखापत्तनम 29/28, पणजी 32/25, बंगलूरू 29/21, चेन्नई 36/25, पोर्ट ब्लेयर 30/24, अंडमान निकोबार 31/25, कोचीन 30/23, तिरुवनंतपुर 31/25
© Copyright Skymet Company 2015: All rights reserved.

राजस्थान की पूर्वी भागों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। पश्चिम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली में आंशिक बादलों के साथ मौसम गर्म रहेगा। इन राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उमस के साथ मौसम गर्म रहेगा। कुछ स्थानों पर वर्षा होगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	30/25/व	अहमदाबाद	34/26/व
कोलकाता	35/27/व	बड़ौदा	31/25/आंबा
चेन्नई	38/27/व	नागपुर	28/24/व
हैदराबाद	28/24/व	इन्दौर	27/22/आंबा
बंगलूरू	30/22/व	राँची	30/25/व
त्रिवेन्द्रम	32/25/आंबा	पटना	34/26/आंबा
गुवाहाटी	31/26/व	जमशेदपुर	30/25/आंबा
गंगटोक	19/12/आंबा	पुणे	25/22/आंबा

रहने के लिए आदर्श शहर मेलबर्न की स्थापना हुई

1835 में आज ही मेलबर्न शहर की स्थापना हुई थी। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका के एक सर्वे के अनुसार मेलबर्न दुनिया का शीर्ष रहने लायक शहर है।

मॉस्को-वाशिंगटन के बीच हॉटलाइन सेवा शुरू हुई

1963 में आज ही शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं के बीच मॉस्को-वाशिंगटन हॉटलाइन सेवा की शुरुआत हुई। इस सेवा के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व किसी भी मसले को लेकर सीधे संपर्क साध सकते थे। इस सेवा को रेड टेलीफोन के नाम से भी जाना जाता है।

हिंदी सिनेमा के सदाबहार नगमों में जान डाल देते थे शैलेंद्र

गीतकार शैलेंद्र का जन्म 1930 में आज ही पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था। 1949 में आई फिल्म बरसात के दो गानों से करियर की शुरुआत की। राज कपूर और शंकर-जयकिशन के साथ मिलकर कई यादगार गीतों की रचना की। 1951 में आई फिल्म आवारा में उनका लिखा गीत आवारा हूं, उस समय भारत के बाहर सबसे अधिक सराहा जाने वाला हिंदुस्तानी गीत बना। उनके गीत मेरा जूता है जापानी को 2016 की अंग्रेजी भाषा की फिल्म डेडपूल में दिखाया गया था। 14 दिसंबर, 1966 को नगमों के इस जादूगर का देहांत हो गया।

पानी के अंदर हाईवे, अंतरिक्ष में होटल, खुद को साफ रखने वाले घर, उड़ती हुई टैक्सियां

50 साल बाद ऐसा होगा हमारा जीवन

कल किसने देखा है? हम सबने देखा है। वर्तमान की तकनीकी पहुंच के आधार पर भविष्य की बुनियाद हमारे वैज्ञानिक रख चुके हैं। ब्रिटेन में जारी सैमसंग केएक्स 50 : द फ्यूचर इन फोकस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2069 तक हमारे रोजमर्रा के जीवन का बड़ी अद्भुत तकनीकों से साबका पड़ेगा। इन पूर्वानुमानों को तकनीकविद और भविष्यविदों ने तैयार किया है। शहरी इलाकों में उड़ने वाली टैक्सियां होंगी। ऊपरी वायुमंडल में दूरी को चंद मिनटों में नापने वाले रियूजेबल रॉकेट होंगे। पानी के अंदर हाईवे बनेंगे। भूमिगत ऊंची इमारतें होंगी। ऐसे घर होंगे जो खुद अपनी साफ-सफाई सुनिश्चित करेंगे। 3 डी प्रिंटिंग से कृत्रिम अंग तैयार होंगे। हमारे शरीर में ऐसे उपकरण लगेंगे जो उसकी दशा-दिशा के बारे में हमें आगाह करते रहेंगे। आइए एक नजर डालते हैं भविष्य की ऐसी ही तकनीकों पर:

पानी के भीतर हाईवे : एक सबसोनिक ट्यूब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनेगा जिसमें पॉड्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकेगा। इस माध्यम से एक घंटे में ब्रिटेन से स्वीडन और नार्वे पहुंचा जा सकेगा।

स्पेस होटल : अंतरिक्ष में छुट्टियां मनाने का सपना साकार होगा। ये होटल चांद या किसी और ग्रह की परिक्रमा करते हुए अपना खुद का गुरुत्व बल पैदा कर सकेंगे। अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने में कारगर साबित होगा।

भूमिगत ऊंची इमारतें : ये अर्थस्क्रैपर्स जमीन के नीचे कई मंजिला होंगी। भूकंप के असर से अछूती होंगी।

उड़ते हुए बस और टैक्सियां : जल्द ही उड़ती टैक्सियों का सपना साकार होगा। हाई पॉवर ड्रोन कॉप्टर जमीनी यातायात समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा।

शरीर का स्वास्थ्य बताने वाले उपकरण : हमारे शरीर में ऐसी चिप या छोटे उपकरण लगेंगे जो समय रहते किसी कमी या रोग से आगाह करेंगे।

खुद की सफाई करने वाले घर : एक बटन दबाने के साथ घर खुद को साफ कर लेंगे।

3डी प्रिंटिंग अंग : जरूरतमंदों के अंग प्रत्यारोपण की कमी दूर होगी।

होवरबोर्ड पर ऊंचाई पर खेल : हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों में आपने क्वीडिच स्टाइल 4 डी मैच खेलते देखा होगा। जल्द ही ऐसे ही मैच होवरबोर्ड पर हम आप भी खेलेंगे।

इधर-उधर की

आया था लूटने खुद लुटा

वाशिंगटन, एजेंसी : जैसे को तैसा कहावत तो सुनी ही होगी। कुछ ऐसा ही हुआ है वाशिंगटन में एक चोर के साथ। दरअसल, यहां एक चोर सड़क किनारे अपनी गाड़ी खड़ी कर दुकान में चोरी करने गया, लेकिन जब वापस लौटा तो उसी की गाड़ी चोरी हो गई। केनेविक पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने फेसबुक पेज पर इससे संबंधित एक वीडियो पोस्ट किया है। दरअसल गाड़ी के मालिक विलियम केली ने पुलिस को बताया कि उसकी पिकअप गाड़ी किसी ने चुरा ली। उसने चाबी गाड़ी के अंदर ही छोड़ दी थी। विलियम की शिकायत पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। इस दौरान जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि जो शख्स अपनी गाड़ी चोरी की शिकायत कर रहा था, असल में वह एक दुकान में चोरी करने के लिए आया था। पुलिस ने विलियम को जेल भेज दिया है।

मानव विकास की समझ बदलेगी 'एमआरडी'

बड़ी खोज ▸ इथोपिया में पुरातत्वविदों को मिली 38 लाख साल पुरानी मनुष्य की खोपड़ी

नेचर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ अध्ययन

अदीस अबाबा, एएफपी : इथोपिया में पुरातत्वविदों को 38 लाख साल पुरानी एक खोपड़ी का अवशेष मिला है, जो मनुष्य के विकास के बारे में हमारी वर्तमान समझ को बदल सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह किसी छोटे लूसी (प्राचीन मनुष्य की प्रजाति) का अवशेष होगा, जो मानव के विकास के संबंध में अब तक की अवधारणाओं को पूरी तरह बदल सकता है। नेचर नामक पत्रिका में इस खोपड़ी के बारे में विस्तार से बताया गया है। शोधकर्ताओं ने इस खोपड़ी को 'एमआरडी' के नाम दिया है।

क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के पुरातत्वविद योहानेस हैले सेलासी ने कहा कि यह खोपड़ी लगभग तीन लाख वर्ष से अधिक पुराने होमीनिड का जीवाश्म है। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के फ्रेड स्पूर ने कहा कि यह मानव विकास का एक और प्रतीक बनने के लिए तैयार है।

पहले भी मिल चुके हैं अवशेष : पुरातत्वविदों ने वर्ष 2001 में चाड में टूमई (सहेलंथ्रोपस टेडेंसिस की प्रजाति के जीव) के लगभग सात लाख वर्ष पुराने अवशेष खोजे थे, जिन्हें मानव वंश का पहला प्रतिनिधि माना जाता है। अर्डी (होमीनिड की एक अन्य प्रजाति) 1994 में इथोपिया में पाई गई थी और माना जाता है कि यह लगभग 45 लाख साल पुरानी है और लूसी के अवशेषों को इथोपिया में ही वर्ष 1974 में खोजा गया था, जो लगभग 32 लाख वर्ष पुराने हैं। लूसी को ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस भी कहा जाता है। यह सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला और सबसे अधिक अध्ययन की जाने वाली प्रारंभिक मानव प्रजाति है।

पुरातत्वविद योहानेस हैले सेलासी और म्यूजियम में रखा गया होमीनिड का जीवाश्म। फाइल

वर्नसो-मिल की साइट से मिले जीवाश्म : शोधकर्ताओं ने कहा कि पुरातत्ववेत्ताओं ने जो नई खोपड़ी 'एमआरडी' खोजी है, वह ऑस्ट्रेलोपेथेकस एनामेंसिस प्रजाति के जीवों से संबंधित है। फरवरी 2016 में पूर्वोत्तर इथोपिया के अफार क्षेत्र में वर्नसो-मिल की एक साइट पर खोदाई के दौरान लूसी के कुछ अवशेष मिले थे। पहली नजर में यह आधुनिक मनुष्यों की खोपड़ी की तरह ही दिखाई देती है। शोधकर्ताओं ने कहा कि ऑस्ट्रेलोपेथेकस के बारे में लोग अभी बहुत ज्यादा नहीं जानते। पुरातत्वविदों को इसका जो जीवाश्म मिला है, वह लगभग 39 लाख साल पुराना है

मिलेंगी अहम जानकारियां : शोधकर्ताओं ने कहा कि इन जीवाश्मों के मिलने से लाखों साल पहले विलुप्त हो चुके होमिनिड्स के बारे में कई अहम जानकारियां मिल सकती है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह खोज मानव विकास के बारे में मौजूद वर्तमान विश्वास को चुनौती दे सकती है।

हजारों वर्षों तक साथ रहे एनामेंसिस और एफरेंसिस : अध्ययन के सह-लेखक और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के स्टेफनी मेलिलो ने कहा कि पहले हमारा अनुमान था कि एनामेंसिस (एमआरडी) समय के साथ धीरे-धीरे एफरेंसिस (लुसी) में बदला होगा, लेकिन होमीनिड के जीवाश्मों के अध्ययन से पता चलता है कि इन दोनों प्रजातियों का अस्तित्व लगभग दस लाख वर्षों तक रहा। इसका मतलब है कि यह मानव विकास की हमारी समझ को बदल कर रख सकता है।

गगनयान मिशन में शामिल नहीं होंगी महिला अंतरिक्ष यात्री

- इसरो के अधिकारी बोले, भविष्य में बन सकती हैं मिशन का हिस्सा
- परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये की लागत आने की उम्मीद

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में किसी महिला अंतरिक्ष यात्री के होने की संभावना नहीं है। दरअसल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) संभावित अंतरिक्ष यात्रियों की खोज सशस्त्र बलों के टेस्ट पायलट में से कर रहा है और इनमें से कोई भी महिला नहीं है। नए विमानों का परीक्षण करने वाले अति दक्ष पायलट को टेस्ट पायलट कहा जाता है।

आम नागरिक हो सकते हैं मिशन का हिस्सा : अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फिलहाल इस मिशन में महिला के शामिल होने की संभावना नहीं दिखती। हालांकि महिलाओं के अलावा अन्य आम नागरिक भविष्य के मानव मिशन का हिस्सा हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसरो ने पहले मानव मिशन के लिए संभावित उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगले महीने तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। चुने गए उम्मीदवारों को नवंबर में प्रशिक्षण के लिए रूस भेजा जाएगा।

रूस और फ्रांस से हुआ है करार : पहले गगनयान मिशन को 2022 में तीन अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भेजने की योजना है। इन यात्रियों का चयन सशस्त्र बलों के टेस्ट पायलटों में से किया जाएगा। अधिकारी ने बताया, 'विभिन्न देशों की ओर से पहले भेजे मानव मिशन में भी टेस्ट पायलट को ही भेजा गया। इसलिए हम भी अपने मिशन में इस परिपाटी पर कायम रहना चाहते हैं। हम सशस्त्र बलों के टेस्ट पायलट को देख रहे हैं लेकिन उनमें कोई महिला टेस्ट पायलट नहीं है। भारत ने गगनयान मिशन में सहयोग के लिए रूस और फ्रांस से करार किया है।

मानव रहित विमान भेजे जाएंगे : गगनयान परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये की लागत आने की उम्मीद है। इनमें प्रौद्योगिकी विकास, यान के निर्माण और जरूरी आधारभूत ढांचे का विकास शामिल है। गगनयान के तहत दो मानव रहित और एक मानव मिशन को अंजाम दिया जाएगा। गौरतलब है कि गगनयान मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिए गए एक भाषण में की थी। वायुसेना के पायलट राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने 2 अप्रैल 1984 को प्रक्षेपित सोवियत संघ के यान सोयुज टी-11 के जरिये अंतरिक्ष यात्रा की थी।

शोध अनुसंधान

प्री-एक्लैंप्सिया की जटिलताओं से बचा सकता है समयपूर्व प्रसव

गर्भावस्था किसी महिला के जीवन का चुनौतीपूर्ण समय होता है। इस दौरान कुछ महिलाओं में प्री-एक्लैंप्सिया की स्थिति भी देखने को मिलती है। इसमें महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और मूत्र में प्रोटीन का स्तर ज्यादा हो जाता है। यह स्थिति ज्यादातर गर्भावस्था के आखिरी हफ्तों के दौरान बनती है। आमतौर पर प्री-एक्लैंप्सिया का पता लगने पर दवाओं के जरिये ही इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। हालिया अध्ययन के मुताबिक, ऐसी स्थिति में समयपूर्व प्रसव बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर किसी महिला में 34-37 हफ्ते के बीच कभी प्री-एक्लैंप्सिया का पता चले, तो 48 घंटे के अंदर ही प्रसव करा देना चाहिए। इस स्थिति में प्रसवपीड़ा के लिए दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। परिस्थिति को देखते हुए चिकित्सक ऑपरेशन के जरिये प्रसव (सिजेरियन) का रास्ता भी अपना सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा करना मां और बच्चे दोनों की सेहत के लिए अच्छा होता है। -एएनआइ

जलवायु आंदोलन की प्रेरणा बनीं स्वीडन की ग्रेटा

इंग्लैंड से एक याट पर सवार होकर न्यूयॉर्क पहुंचीं दुनिया की जानी-मानी 16 वर्षीय स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग का लोगों ने बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। वह यहां 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु एक्शन सम्मेलन को संबोधित करेंगी। ग्रेटा जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया में चल रहे 'फ्राइडे ऑफ फ्यूचर' आंदोलन की जनक हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में स्वीडिश संसद के सामने स्कूली बच्चों के साथ हड़ताल की थी। बाद में यह विश्वव्यापी मुहिम बन गई। ग्रेटा जलवायु को लेकर बूट इंडिया नामक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संदेश भेज चुकी हैं। शांति के नोबेल के लिए भी उनका नाम नामित किया जा चुका है। एपी

पंपकिन फेस्टिवल की जीवंत कलाकृति

जर्मनी में यूं तो पंपकिन (कद्दू) से जुड़े विभिन्न आयोजन होते हैं लेकिन ख्याति यहां के लुडविग्सबर्ग शहर में प्रतिवर्ष होने वाले दुनिया के सबसे बड़े पंपकिन फेस्टिवल की है, जो कि सितंबर से नवंबर में होता है। हालांकि इन दिनों मेकेरनिच कस्बे में पंपकिन की कलाकृतियों का आयोजन भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसमें कददू से विमान, बाज जैसी विभिन्न जीवंत कलाकृतियां बनाई गई हैं जिसे बड़ी उत्सुकता से लोग देखने पहुंच रहे हैं। एपी

स्क्रीन शॉट

सोनम कपूर की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम हारी सेमीफाइनल मैच?

बॉलीवुड में मेहनत के साथ भाग्य का होना भी जरूरी माना जाता है। भाग्य में यकीन करने वालों में सोनम कपूर भी शामिल हैं। सोनम भाग्य और किस्मत में यकीन तो करती ही हैं, साथ वह खुद को इतना लकी मानती हैं कि उनके न पहुंचने की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच हार गई। यह खुलासा सोनम ने बुधवार को मुंबई में अपनी आगामी फिल्म 'द जोया फैक्टर' के ट्रेलर लॉन्च पर किया। दरअसल, इस फिल्म में जोया का किरदार निभा रहीं सोनम कपूर 25 जून 1983 को पैदा होती हैं, जिस दिन भारत ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। उस दिन से उनके माता-पिता ने उन्हें घर और देश के लिए लकी मान लिया। जब सोनम से पूछा गया कि वह क्या असल जीवन में लकी हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि उनके नाम का मतलब ही लकी है। साथ ही यह भी बताया कि जब वह पैदा हुई थीं, तब उनके पिता अनिल कपूर अभिनीत फिल्म 'रामलखन' और 'तेजाब' जैसी फिल्में हिट हो रही थीं। सोनम बताती हैं कि कई ज्योतिषों ने जन्मपत्री पढ़कर ही बता दिया था कि जिस लड़के से उनकी शादी होगी, उसके लिए भी वह लकी चार्म होंगी। सोनम ने बताया कि उनके पापा जब मैनचेस्टर में भारत और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच देखने के लिए गए थे तब उन्हें भी बुलाया था, ताकि वह टीम के लिए कुछ भाग्य लेकर जाएं, पर ऐसा हो नहीं पाया। उस समय उन्हें डॉक्टर के पास जाना था और वह मैनचेस्टर मैच देखने नहीं पहुंच पाई थीं। हालांकि सोनम का मानना है कि लकी होने के साथ मेहनती होना भी जरूरी है, तभी लक काम कर पाता है। जीवन के बैंक में जितना डालेंगे, उतना वह वापस मिलेगा। 'द जोया फैक्टर' अनुजा चौहान के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में साउथ के सुपरस्टार दुलकर सलमान भी हैं। यह उनकी दूसरी हिंदी फिल्म होगी। फिल्म 20 सितंबर को रिलीज होगी।

सितंबर में मुंबई में होगा आइफा अवाड्र्स समारोह

इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी (आइफा) अवार्ड का आयोजन अभी तक विदेश में होता आया है। पिछली बार यह थाइलैंड में आयोजित हुआ था। पहली बार इस अवार्ड समारोह को मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। आइफा का यह 20वां संस्करण सितंबर में आयोजित होगा। इस साल 'अंधाधुंध' के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्टर का राष्ट्रीय अवार्ड जीतने वाले आयुष्मान खुराना की इस फिल्म को 13 श्रेणियों में नामांकित किया गया है। वहीं 'पद्मावत' और 'राजी' दस श्रेणियों में नामांकित हुई है। 'संजू' को सात व 'बधाई हो' को छह श्रेणियों में नामांकन मिला है।

अब कबीर बेदी भी डिजिटल पर आए...

डिजिटल और सिनेमा के बीच की अदृश्य दीवार अब खत्म हो चुकी है। अब फिल्मों के सितारे डिजिटल पर काम कर रहे हैं। अभिनेता कबीर बेदी भी अब डिजिटल पर डेब्यू करने जा रहे हैं। 'खून भरी मांग', 'मैं हूं ना' जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध कबीर बेदी एमएक्स प्लेयर के शो 'किसका होगा थिंकिस्थान 2' में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे, जो एक विज्ञापन एजेंसी का मालिक है और कंपनी को परेशानियों से निकालने का उसका तरीका काफी कमाल का है। यह किरदार कबीर बेदी के दिल के काफी करीब है, क्योंकि उनके मुताबिक, जब वह फिल्ममेकर बनने मुंबई आए थे, तब उन्होंने पांच साल तक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम किया था। इस शो ने उनकी पुरानी यादें फिर से ताजा कर दीं। शो में कबीर बेदी गेस्ट अपीयरेंस में होंगे। बारह एपिसोड वाले इस शो में मंदिरा बेदी, नील भूपलम भी होंगे। नील शो में एक ऐसे बॉस के किरदार में होंगे, जो ऑफिस राजनीति करता है। यह शो 6 सितंबर से शो शुरू होगा।

'गॉड ऑफ क्रिकेट' और वरुण धवन का कनेक्शन...!

'क्या लग रहे हैं सचिन सर, मैं हमेशा खुद को आपके बेहद नजदीक पाता हूं, जैसे पूरा देश महसूस करता है कि आप हमारे हैं। इसलिए भी कि 24 अप्रैल तारीख है और मुझे अभी भी बहुत काम करना है।' वरुण धवन ने इंस्टाग्राम पर सचिन तेंदुलकर के साथ अपनी तस्वीर शेयर कर यह पोस्ट तो डाली है, लेकिन अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि उन्हें आखिर करना क्या है? 24 अप्रैल सचिन का जन्मदिन है और वरुण इस तारीख को लेकर काफी पैशनेट दिख रहे हैं। वरुण ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि मेरा यह वीडियो गॉड ऑफ क्रिकेट से मिलने का है। सचिन ने भी वरुण और अभिषेक बच्चन के साथ ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सचिन बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। सचिन ने वरुण धवन की गेंदबाजी पर शॉट भी लगाए। वरुण ने इसे रीट्वीट किया है। पिछले साल 24 अप्रैल को सचिन ने अपनी जिंदगी पर बन रही एक और बायोपिक 'गॉड ऑफ क्रिकेट' का पहला पोस्टर रिलीज किया था। अब इस फिल्म से वरुण का कनेक्शन साफ नजर आ रहा है। सुना जा रहा है कि इस फिल्म में सचिन कैमियो करने वाले हैं।

अध्ययन

ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ शोध-बैठे रहने वाले लोगों के मुकाबले लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं हमेशा किसी काम में खुद को व्यस्त रखने वाले

लंबी उम्र जीना है तो रहें गतिशील

न्यूयॉर्क टाइम्स से

वाशिंगटन : स्वस्थ और निरोग रहने के लिए अक्सर लोग तमाम तरह के जतन करते हैं। कुछ लोग सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, कुछ जिम में जमकर पसीना बहाते हैं तो कुछ लोग योग और आसन करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कई बार लोगों पर इसका असर देखने को नहीं मिलता। अब एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि यदि आपको लंबा जीवन जीना है तो हमेशा गतिशील रहनाा होगा। इसके लिए आपको किसी खास एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही अपनी रसोई की साफ-सफाई कर सकते हैं या कोई अन्य छोटा-मोटा काम कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में पाया है कि ऐसे लोग जो हमेशा गतिशील रहते हैं, वह बैठे रहने वाले लोगों के मुकाबले स्वस्थ जीवन जीते हैं।

कम होगी मृत्यु दर : शोधकर्ताओं ने कहा कि खाली बैठने से अच्छा है कि आप कुछ-न-कुछ काम करते रहें। चाहे वह कितना ही मामूली क्यों न हो। यह आपको स्वस्थ तो रखेगा ही, साथ ही मृत्यु दर को भी कम कर सकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को मिल सकता है जो घरों में केवल बैठे रहते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि बैठे रहने से हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है और यह समय से पूर्व मृत्यु का प्रमुख कारण है। यह तो सभी जानते हैं कि व्यायाम से शरीर हृष्ट-पुष्ट रहता है। कई अध्ययनों में लंबे जीवन और व्यायाम के बीच निकट का संबंध पाया गया है, लेकिन यदि हम हमेशा गतिशील रहते हैं तो यह संबंध और मजबूत हो जाता है।

घर में खाना पका कर भी बढ़ाई जा सकती है उम्र।

ऐसे किया अध्ययन : यह अध्ययन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने ब्रिटेन और यूरोप के 36,383 लोगों को शामिल किया, जिसमें मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं और पुरुष शामिल थे। शोधकर्ताओं ने इन्हें दो वर्गों में बांटा। एक समूह को केवल बैठे रहने को कहा गया, जबकि दूसरे समूह से घर में खाना पकाने, रसोई की सफाई, बागवानी आदि का काम करने को कहा गया। साथ ही हर दिन प्रतिभागियों का बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआइ) माप कर उसका विश्लेषण किया। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय थे, वे गतिहीन समूह के लोगों की तुलना में ज्यादा स्वस्थ्य थे और उस समूह के लोगों की समय से पूर्व मृत्यु का जोखिम दूसरे समूह के मुकाबले 60 फीसद कम पाया गया। शोधकर्ताओं ने कहा कि अध्ययन के निष्कर्ष यह सुझाव देते हैं कि खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए।

छोड़ें आलस : ओस्लो में नार्वे स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज के प्रोफेसर उल्फ एकेलुड ने कहा कि अध्ययन के निष्कर्ष काफी उत्साहजनक हैं। केवल छोटा-मोटा काम करने से यदि असमय मृत्यु का जोखिम कम होता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा 'यदि आपको स्वस्थ रहना है तो मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि आप आलस छोड़कर एस्केलेटर की बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करें। बाइक की बजाय साइकिल का इस्तेमाल करें।'